



# ग्राम्य अर्थशास्त्र

३८९९

( उत्तर-प्रदेश के हाई-स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड की हाई-स्कूल-परीक्षा  
के अर्थशास्त्र के लिये स्वीकृत )

लेखक

पण्डित दयाशंकर दुबे, एम० ए०, एल-एल० बी०  
अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय

श्री शंकरसहाय सक्सेना, एम० ए०, बी० काम०  
प्रिंसिपल, महाराणा कालेज, उदयपुर तथा डीन, कामर्स-कैकल्टी  
राजपूताना विश्वविद्यालय

और

श्री महेशचंद्र, एम० ए०, बी० एस-सी (आनर्स), 'विशारद'  
अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय

---

प्रकाशक

नेशनल प्रेस  
इलाहाबाद

मुद्रक—आर्ट प्रिन्टर्स (अशोक-निवास), जीरो रोड, इलाहाबाद ।

## भूमिका

मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो अर्थशास्त्र के ज्ञान का प्रचार छोटे दर्जे के विद्यार्थियों में भी चाहते हैं। इसलिये मैंने अर्थशास्त्र सम्बन्धी कई विषयों पर पाठ अपनी 'बालबोध' पुस्तक में दिये। वह पुस्तक चार भागों में प्रकाशित हुई और कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश की प्रारम्भिक पाठशालाओं के लिए पाठ्य-ग्रन्थ के रूप में स्वीकृत रही। मुझे यह सचित करते हर्ष होता है कि इस पुस्तक के अर्थशास्त्र सम्बन्धी पाठों को अध्यापकों और विद्यार्थियों ने बहुत पसन्द किया। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि अर्थशास्त्र ऐसा सरल विषय है, जिसका ज्ञान छोटे बच्चों को भी प्रारम्भिक पाठशालाओं में आसानी से कराया जा सकता है।

अर्थशास्त्र का विषय सरल और महत्वपूर्ण होने पर भी उसे प्रारम्भिक पाठशालाओं के पाठ्य-ग्रंथों में अभी तक स्थान नहीं मिला। सन् १९१७ तक तो, जिस वर्ष मैंने बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की, अर्थशास्त्र को बी० ए० से नीचे दर्जे की परीक्षा के पाठ्य विषयों में स्थान नहीं दिया गया था। उन दिनों अर्थशास्त्र के विषय का पढ़ना बी० ए० क्लास से ही आरम्भ होता था। इन्टरमीडियट तक पढ़ने वालों को तो इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता था। कुछ वर्ष बाद अर्थशास्त्र को इन्टरमीडियट के पाठ्य विषयों की सूची में स्थान मिला और सन् १९४० में ग्राम्य अर्थशास्त्र को उत्तरप्रदेश को हाई-स्कूल-परीक्षा के पाठ्य विषयों की सूची में स्थान पहले-पहल मिला। ग्राम्य अर्थशास्त्र के पाठ्य क्रम के अनुसार ही यह पुस्तक तैयार की गई थी और इसका शीर्षक "ग्राम्य अर्थशास्त्र" रक्खा गया था। सन् १९०५ से पाठ्य विषय का नाम अर्थशास्त्र हो गया है। उसी के अनुसार प्रस्तुत पुस्तक की पाठ्य-सामग्री में यथोचित परिवर्तन व परिवर्द्धन कर दिया गया है। अतः यद्यपि पुस्तक का शीर्षक वही पुराना "ग्राम्य अर्थशास्त्र" है, पुस्तक वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार है। पुस्तक में इस बात का भी पूरा ध्यान रक्खा गया है कि अब भारत की सीमाएँ पहले-जैसी नहीं हैं और इसलिए यथा-संभव उदाहरण तथा समस्याएँ भारतीय सघ की हैं। पुस्तक का प्रस्तुत ग्यारहवाँ संस्करण इसकी उपयोगिता तथा प्रचार का द्योतक है। इस नवीन संस्करण में यथोचित सुधार तथा संशोधन किया गया है।



..( २० )

इसमें जमींदारी प्रथा की खुराइयों तथा जमींदारी उन्मूलन एक्ट का यथास्थान् उल्लेख कर दिया गया है । सहकारी समिति सम्बन्धी अध्यायों में भी उचित सुधार किया गया है ।

महाराणा कालेज उदयपुर के प्रिंसिपल श्री शंकरसहाय जी सक्सेना तथा श्री भद्रेशचंद जी के सहयोग से यह पुस्तक तैयार की गई है । हम लोग आशा करते हैं कि इस पुस्तक से हाई-स्कूल के विद्यार्थियों को ग्राम्य अर्थशास्त्र का विषय समझने में पहले से अधिक सहायता मिलेगी ।

अदि कोई सज्जन इस पुस्तक की त्रुटियों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित करेगा या इसको और भी अधिक उपयोगी बनाने के उपाय बतलावेंगे तो मैं उनका बहुत आभारी होऊंगा ।

“श्री दुवे निवास”

दासगज (प्रयाग)

१ जुलाई, १९५२

}

दयाशंकर दुवे

अर्थशास्त्र अध्यापक

प्रयाग विश्वविद्यालय

# विषय सूची

## पहला अध्याय

### अर्थशास्त्र के विभाग

अर्थशास्त्र क्या है ?—अर्थशास्त्र के विभाग—उत्पत्ति—उपभोग—  
उपभोग का महत्व—उपभोग का क्षेत्र—विनिमय—वितरण—साराश—अर्थ-  
शास्त्र के अध्ययन से लाभ—अभ्यास के प्रश्न १—१२

## दूसरा अध्याय

### परिभाषाएँ

धन या सम्पत्ति—केवल रुपया पैसा ही धन नहीं—धन-वृद्धि—धन  
और सुख—उपयोगिता—सीमान्त उपयोगिता—मूल्य—कीमत—आय—  
अभ्यास के प्रश्न १३—२३

## तीसरा अध्याय

### उत्पत्ति

उपयोगिता-वृद्धि—भूमि—भूमि के गुण—श्रम—श्रम के भाग—श्रम की  
उपयोगिता—श्रम विभाग—पूँजी—पूँजी की विशेषताएँ—पूँजी के भेद—  
प्रबंध—प्रबंधक के गुण—साहस या जोखिम—अभ्यास के प्रश्न २३—३६

## चौथा अध्याय

### भारतीय गाँव की खास पैदावारें

भारतीय कृषि का महत्व—भारतीय भूमि की पैदावार की कमी—  
पैदावार की कमी के कारण—खेतों का छोटे-छोटे और दूर-दूर होना—खेती  
में क्या करना पड़ता है ?—ग्रामीण उद्योग-धन्धे—अभ्यास के प्रश्न ३६—४८

## पाँचवाँ अध्याय

### घरेलू तथा स्थानीय उद्योग-धंधे

घरेलू उद्योग-धंधों की आवश्यकता—घरेलू उद्योग या बड़ी मात्रा के उद्योग—घरेलू उद्योग-धन्धों के भेद—हमारे स्थानीय उद्योग-धन्धे—बरतन बनाना—चटाई और टोकरी बनाना—गुड़ बनाना—चरखा कातना और कपड़ा बुनना—पशु-पालन—दूध का काम—मक्खन और घी—रस्सी बनाना—लकड़ी का काम—लोहार का काम—तेल पेरने का काम—जूते बनाना—फल, फूल और तरकारी पैदा करना—शहद को धन्धा—अन्य उद्योग-धन्धे—घरेलू उद्योग-धन्धे की कठिनाइयाँ—घरेलू उद्योग-धन्धे और सरकार—अभ्यास के प्रश्न

४६—६३

## छठा अध्याय

### आवश्यकताएँ

आवश्यकता का महत्व—आवश्यकता और इच्छा—आवश्यकता और उद्योग—आवश्यकता के लक्षण—आवश्यकताओं के भेद—आराम की वस्तुएँ—आवश्यकता की पूर्ति—आय-व्यय—व्यय के सिद्धांत—वचन—अभ्यास के प्रश्न

६३—७५

## सातवाँ अध्याय

### भारतीय रहन-सहन का दर्जा

रहन-सहन का दर्जा—भारतीय रहन-सहन का दर्जा—रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने के उपाय—पारिवारिक बजट—किसानों का खर्च—गाँव के मजदूर और उनका खर्च—गाँव के कारीगर का व्यय—अभ्यास के प्रश्न

७५—८४

## आठवाँ अध्याय

### भोजन कितना और कैसा हो ?

भोजन की आवश्यकता—चर्बी, प्रोटीन, चीनी और विटामिन—भोजन भेद—उपयुक्त भोजन की मात्रा—अभ्यास के प्रश्न

८४—८८

## नवाँ अध्याय

### विनिमय

वस्तुओं की अदला-बदली—माल की खरीद और विक्री—बाजार—  
बाजार का क्षेत्र—वस्तु की कीमत किस प्रकार निश्चित होती है—खेती से  
उत्पादन पदार्थों की कीमत—अभ्यास के प्रश्न ८६—१००

## दसवाँ अध्याय

### ग्रामीण फसल की विक्री

प्राक्कथन—विक्री की बातें—मंडी में फसल की विक्री—गाँव में बनी  
वस्तुओं की विक्री—ग्रामीण सड़क—सहकारी संस्थायें और विक्री—ग्रामीण  
बाजार—हाट—गाँव का मेला—हाट और मेले का महत्व—हाट और मेले  
का सङ्गठन—अभ्यास के प्रश्न १००—१०६

## ग्यारहवाँ अध्याय

### वितरण

वितरण क्या है ?—वितरण कैसे होता है—खेतों में वितरण—लगान—  
मजदूरी—सूद—वेतन—मुनाफा या लाभ—अभ्यास के प्रश्न १०६—१२१

## बारहवाँ अध्याय

### औद्योगिक मजदूर

गद्दी वस्तियाँ—बम्बई—कलकत्ता—मदरास—कानपुर—अहमदाबाद—  
कोयले के खानों के केन्द्र—औद्योगिक सुख - सुविधा—सरकारी प्रयत्न—  
मिल मालिकों के प्रयत्न—अन्य संस्थाओं के प्रयत्न—ट्रेड यूनियन—भारतीय  
ट्रेड यूनियनों की निर्बलता के कारण—अभ्यास के प्रश्न १२१—१२६

## तेरहवाँ अध्याय

### बटाई-प्रथा

बटाई-प्रथा क्या है ? बटाई की दर—बटाई-प्रथा के गुण-दोष—मजदूरी  
सम्बन्धी बटाई—बटाई और रीति-रिवाज—अभ्यास के प्रश्न १२६—१३६

**चौदहवाँ अध्याय****जमींदार और किसान**

स्थायी बन्दोबस्त—बंगाल का फ्लाऊड कमीशन—अस्थायी बन्दोबस्त—  
जमींदार और किसान—उत्तर-प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून—  
जमींदारी प्रथा के विनाश का प्रभाव—पटवारी के कागजात—शजरा  
मिलान—खसरा—स्याहा—बहीखाता जिन्सवार—खतौनी—खेवट—पट-  
वारी के अन्य कार्य—अभ्यास के प्रश्न १३७—१५०

**पन्द्रहवाँ अध्याय****ग्रामों की समस्याओं का दिग्दर्शन**

गाँवों की समस्याएँ—अभ्यास के प्रश्न १५०—१५४

**सोलहवाँ अध्याय****किसानों का निराशावादी दृष्टिकोण**

किसानों का निराशावादी दृष्टिकोण—अभ्यास के प्रश्न १५४—१५८

**सत्रहवाँ अध्याय****गाँव की सफाई**

ताल व पोखरे—खाद के गड्ढे—शौचस्थान—नाब्रदान तथा नालियों  
की समस्या—गाँव में हवा और रोशनी का प्रबन्ध—गाँव की सड़के—गाँव  
में कुशल दाइयों की समस्या—गाँव में सफाई और स्वास्थ्य की योजना—  
अभ्यास के प्रश्न १५८—१६८

**अट्ठारहवाँ अध्याय****ग्रामीण शिक्षा**

पाठशाला का पाठ्यक्रम—स्त्री-शिक्षा—ग्राम्य शिक्षक—सार्जेन्ट  
लीमी सव—प्रौढ शिक्षा—अभ्यास के प्रश्न १६८—१७८

## उन्नीसवाँ अध्याय

### मनोरंजन के साधन

गाँवों के खेल—भारतीय खेल—गाँव का स्काउट टुप—भजन—तथा भजन मंडलियाँ—नाटक तथा प्रहसन—रेडियो, मैजिक लैन्टर्न तथा सिनेमा-शो—ग्राम-सेवादल—घरों को अधिक आकर्षक बनाना—पर्व और त्यौहार—अभ्यास के प्रश्न १७८—१८६

## बीसवाँ अध्याय

### स्वास्थ्य-रक्षा के सिद्धान्तों का प्रचार

सफाई, हवा और रोशनी—शुद्ध और पौष्टिक भोजन—परिश्रम अथवा व्यायाम—विश्राम—रोग और उनसे बचने के उपाय की जानकारी—क्षयरोग या तपेदिक—चिकित्सा का प्रबन्ध—अभ्यास के प्रश्न १८६—१९५

## इक्कीसवाँ अध्याय

### पशु-पालन

गाँव में गाय और बैल का महत्व—गो वंश की अत्यन्त हीन दशा—गो वंश की हीन दशा के कारण—आवश्यकता से अधिक बैल—चारे की कमी—साइलेज बनाने के उपाय—गुणों के रोग—गाय बैलों की नस्ल सुधारना—भारत का विभाजन और पशुधन—जिला बोर्ड ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) द्वारा सहायता—सहकारी नस्ल सुधार समितियाँ—ग्राम सुधार विभाग—गऊशाला—गो-सेवा संघ—अभ्यास के प्रश्न १९५—२०७

## बाईसवाँ अध्याय

### खेती की उन्नति के उपाय

कृषि की गिरी हुई दशा—कृषि के आवश्यक साधन—भूमि—पूँजी—श्रम तथा संगठन—छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतों की समस्या—सामूहिक सहकारी खेती—पंचवर्षीय योजना—खाद की समस्या—हड्डो की खाद—हरी खाद—अन्य प्रकार की खाद—सिंदरी(बिहार) का कारखाना—भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाये रखने के दूसरे साधन—फसलों का हेर-फेर—पशुधन—खेती के यंत्र—सरकार का केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग—बीज—सिंचाई—वर्षा का जल—कुओं के द्वारा सिंचाई—उत्तरप्रदेश में ठ्यू व वेल—नहर के द्वारा सिंचाई—तालाब

—साख—श्रम और संगठन—फसलों के शत्रु—खेती की पैदावार बेचने की समस्या—गाँवों की सड़के—मड़ियों का पुनर्संगठन—किसान को सतर्क तथा परिश्रमी होना चाहिये—अभ्यास के प्रश्न २०८—२३२

### तेइसवाँ अध्याय

#### मुकदमेवाजी

मुकदमेवाजी—आकर्षक रह—पञ्चायत—अदालत—अभ्यास के प्रश्न २३३—२३६

### चौबीसवाँ अध्याय

#### ग्रामवासियों को ऋण-मुक्त करना

महायुद्ध और ऋण—कर्जदार होने के कारण—पैतृक ऋण—महाजन के लेन-देन करने का ढङ्ग—अनिश्चित खेती—बैलों की मृत्यु—सामाजिक तथा धार्मिक कृत्यों में अधिक व्यय करना—मुकदमेवाजी—लगान और मालगुजारी—सरकार द्वारा ऋण की समस्या को हल करने का प्रयत्न—ऋण परिशोध—कृतिपय प्रदेशों में ऋण समझौता-बोर्ड—महाजन लायसेन्स कानून—महायुद्ध और ग्रामीण ऋण—अभ्यास के प्रश्न २३६—२४७

### पच्चीसवाँ अध्याय

#### गाँव में आय के साधन और गमनागमन

ग्रामीण धन्वे—ग्राम उद्योग-सघ—गाँवों में आय के अन्य साधन—गाँवों में जाने की असुविधा—अभ्यास के प्रश्न २४७—२५०

### छब्बीसवाँ अध्याय

#### कृषि-विभाग के कार्य तथा खाद्य समस्या

कृषि-विभाग का संगठन और उसका कार्य—प्रादेशिक विकास योजना—भारत में खाद्य पदार्थों की कमी—पञ्चवर्षीय योजना—समाज विकास कार्यक्रम—अभ्यास के प्रश्न २५०—२६०

### सत्ताइसवाँ अध्याय

#### ग्राम और जिले का शासन

का शासन—ग्राम के मुख्य कर्मचारी—मुखिया—पटवारी—चौकीदार—देहाती बोर्ड और जिला कौंसिल—निर्वाचक और सदस्य—

जिजा, बोर्ड के कार्य—जिला बोर्डों की आय—सरकारी नियंत्रण—नागरिकों  
 भावों की आवश्यकता—जिले का शासन—शासन व्यवस्था में जिले का  
 स्थान—जिला मजिस्ट्रेट के कार्य—जिले के अन्य कर्मचारी—कमिशनर—  
 अभ्यास के प्रश्न २६०—२६८

## अठाइसवाँ अध्याय

### गाँव पंचायत

गाँव वालों का पारस्परिक सम्बन्ध—गाँवों की संस्थाएँ और उनका  
 महत्व—पंचायत—पंचायत की सफलता के उपाय—उत्तर प्रदेश का पंचायत  
 राज्य कानून—गाँव सभा—गाँव पंचायत के कार्य—गाँव पंचायत के कर—  
 पंचायत अदालत—अभ्यास के प्रश्न २६८—२७५

## उन्तीसवाँ अध्याय

### सहकारिता तथा सहकारी साख समितियाँ

सहकारिता के मूल-सिद्धान्त—भिन्न-भिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ—  
 उपभोक्ता सहकारी समितियाँ या उपभोक्ता स्टोर—सहकारी साख समितियाँ—  
 प्रारम्भिक कृषि सहकारी साख समितियाँ—कृषि साख समिति के उद्देश्य  
 समिति की सदस्यता—अपरिमित उत्तरदायित्व—समिति का प्रबन्ध—  
 समिति की पञ्चायत के कार्य—समिति की पूँजी—समिति के कार्यकर्ताओं  
 का अवैतनिक होना—समिति की साख निर्धारित करना—समिति द्वारा ऋण  
 देने का कार्य—समितियों का आय व्यय-निरीक्षण—कृषि सहकारी साख-  
 समितियों को मिली हुई सुविधायें—क्या कृषि-साख-समितियाँ सफल हो  
 रही हैं—बहु-उद्देशीय सहकारी समितियाँ—उत्तर प्रदेश में बहु-उद्देशीय  
 सहकारी समितियाँ—अभ्यास के प्रश्न २७५—२८२

## तीसवाँ अध्याय

### गैर-साख कृषि सहकारी समितियाँ

सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ, क्रय समितियाँ, विक्रय समितियाँ; विक्रय  
 समितियों का संगठन—भूमि की चक्रवन्दी करने वाली समितियाँ—चक्रवन्दी



समिति की स्थापना—सरकारी कृषि समितियाँ—रहन सहन-सुधार समितियाँ  
—उपभोक्ता सहकारी भंडार—सहकारी स्टोर्स ( भंडार ) के मुख्य-नियम—  
भारत में उपभोक्ता भंडार—भारत में भंडारों की असफलता के मुख्य  
कारण—मद्रास का ट्रिपलीकेन स्टोर—महायुद्ध और स्टोर—अभ्यास के  
प्रश्न २६२—३१२

## इकतीसवाँ अध्याय

### सहकारी समितियों के सघ

गारन्टी यूनियन—सुगरवाइजिंग यूनियन—प्रदेशीय सहकारी यूनियन—  
अभ्यास के प्रश्न ३१२—३१६

## बत्तीसवाँ अध्याय

### सेन्ट्रल सहकारी बैङ्क

साधारण सभा—बोर्ड आफ डायरेक्टर्स—कार्यशील पूँजी—अभ्यास  
के प्रश्न ३१६—३२०

## तैंतीसवाँ अध्याय

### प्रदेशीय सहकारी बैङ्क

प्रदेशीय सहकारी बैङ्क—अभ्यास के प्रश्न ३२१—३२४

## चौतीसवाँ अध्याय

सहकारिता आन्दोलन की दशा—अभ्यास के प्रश्न ३२४—३२७

# ग्राम्य-अर्थशास्त्र

पहला अध्याय

## अर्थशास्त्र के विभाग

अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले तुम अवश्य यह जानना चाहते हो अर्थशास्त्र क्या है ? इसको समझना कठिन है या सरल ? सबसे पहले इस अन्तिम प्रश्न को ही ले लें। विश्वास करो, तुमने भले ही अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम पहले न पढ़ा हो, परन्तु तुम अर्थशास्त्र के अनुसार काम करते रहे हो, तुमने अर्थशास्त्र के नियमों का अपने भरसक भली प्रकार उपयोग किया है। सोते, उठते, बैठते, पढ़ते, लिखते, दौड़ते, वस्तु खरीदते व-वेचते, फीस देते—सभी कार्यों में तुम अर्थशास्त्र के नियमों का पालन करते रहे हो। जिस विद्या का तुमने इस प्रकार उपयोग किया है उसको पाठ्य-विषय के रूप में पढ़ना उसी प्रकार सरल है जिस प्रकार मातृ भाषा बोलने वाले बालक को हिन्दी पढ़ना। अर्थशास्त्र दैनिक जीवन की विद्या है। और इसकी सरलता शीघ्र ही तुम्हें स्पष्ट हो जायगी।

अर्थशास्त्र कैसी विद्या है ? अगर तुम अर्थशास्त्र शब्द को ही ध्यान से समझो तो तुम्हारे मन में यह भाव अवश्य आएगा कि अर्थशास्त्र शायद “अर्थ का शास्त्र” है। “अर्थ” शब्द धन के लिए भी प्रयोग होता है और शास्त्र विधिपूर्ण विद्या को कहते हैं। इसलिए तुम सोच सकते हो कि शायद अर्थशास्त्र में धन सम्बन्धी अध्ययन विधिपूर्ण किया जाता है। तुम्हारा ऐसा सोचना बहुत कुछ ठीक है। व्यावहारिक जीवन में हमारा तुम्हारा क्या सभी का काम धन के बिना नहीं चलता। अतः धन के कमाने और खर्च करने आदि के सम्बन्ध में किसी विषय में विचार करना उचित ही है।

लेकिन हम तुम्हारा ध्यान अर्थशास्त्र के असली मतलब की ओर दिलाना चाहते हैं। ऊपर हमने तुम्हारे दिमाग में उठने वाले एक विचार की ओर

ध्यान दिलाया है। वह कुछ-कुछ वैसा ही है जैसा हम कहे कि “फाउन्टेनपेन” का मतलब है कि फाउन्टेन का पेन अर्थात् तालाब का कलम। अर्थशास्त्र के असली अर्थ जानने से पहले तुम यह सोचो कि अपने जीवन में तुम विभिन्न काम क्यों करते हो। इसी लिए न, कि तुमको खाने, पीने, पढ़ने, लिखने आदि की आवश्यकता मालूम पड़ती है। दर असल कुछ काम तो हम इसलिए करते हैं कि उनके बिना जीवित रहना सम्भव नहीं है। भोजन करना तथा पानी पीना ऐसे ही काम हैं। कुछ काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उनके बिना हम जीवन में वह तरक्की न कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। पढ़ना, लिखना, धन कमाना, ऐसे कामों के उदाहरण-स्वरूप गिनाए जा सकते हैं। और कुछ काम हम इसलिए करते हैं, क्योंकि हमारा मन कुछ इच्छाएँ प्रकट करता है। उदाहरणार्थ, हमको भूख ही मिटानी है तो हम नित्य दाल रोटी खा सकते हैं। हमको विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ बनेवाकर या खरीदकर खाने की क्या जरूरत? तुम्हें कहोगे कि पेट तो गाय-बैल भी भर लेते हैं अगर आदमी होकर हम ऐसा न करे तो गाय-बैल में और हममें अन्तर ही क्या रह जायगा। यही सही, मनुष्य होने के नाते तुम्हारी इच्छाएँ रहती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए भी तुम काम करते हो। अतः सच्चेपन से हम कह सकते हैं कि जीवन चलाने के लिए, जीवन सफल बनाने के लिए तथा मानवी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम काम करते हो। इसी बात को दूसरी प्रकार से भी कह सकते हैं। जीवित रहने, सफल बनाने अथवा अन्य कारणों से तुम्हारी आवश्यकताएँ बनती हैं। और उन्हें पूरा करने के लिए तुम विभिन्न काम करते हो। तुम उन्हें पूरा कर पाते हो या नहीं यह तो दूसरी बात है। परन्तु यह सत्य है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुम प्रयत्न अवश्य करते हो।

अर्थशास्त्र (Economics) क्या है?

अब अर्थशास्त्र क्या है इसको हम समझ सकते हैं। “अर्थशास्त्र वह जिसमें हम मनुष्य के उन प्रयत्नों का अध्ययन करते हैं जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है।”

कोई मनुष्य अधिक प्रयत्न करता है तो वह अपनी बहुत-सी

आवश्यकताओं ( Wants ) को पूरा कर लेता है और यदि वह थोड़ा ही प्रयत्न करता है तो उसकी कम आवश्यकताएँ ही पूरी हो सकेंगी। दूसरे शब्दों में पहला आदमी अमीर होगा और दूसरा गरीब। यही दशा एक देश की होती है। अगर किसी देश के लोग अधिक प्रयत्न करके प्रकृति से बहुत सी वस्तुएँ प्राप्त नहीं करते तो वह देश निर्धन रहेगा। अर्थशास्त्र में मनुष्य के इन प्रयत्नों का ही अध्ययन किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें यह भी मालूम हो सकता है कि हम निर्धन क्यों हैं और किस प्रकार धनी बन सकते हैं।

“संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ‘अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम मनुष्य के अपने पालन-पोषण के लिए किए गए प्रयत्नों का अध्ययन करते हैं।’”

उदाहरण के लिए विद्यार्थियों में से ऐसे बहुत से होंगे जिनके पिताजी नौकरी करके, वकालत या डाक्टरी से धन उत्पन्न करते हैं। क्या कभी तुमने यह भी सोचा है कि तुम्हारे पिताजी इन पैसों को कैसे पैदा करते हैं और इनको कैसे खर्च करना चाहिए? क्या यह अच्छा होगा कि तुम्हारे पिता जी तनख्वाह पाते ही सब रुपयों को खर्च कर दें? नहीं, क्योंकि ऐसा करने से महीने भर का खर्च कैसे चलेगा? क्या तुम्हारे पिता जी सब रुपयों को मुफ्त में ही बाँट देते हैं? क्या वे रुपये के बदले में कुछ नहीं लेते? जब तुम मंडी में अनाज खरीदने जाते हो तो रुपये के बदले में गेहूँ, चना, मटर, चावल आदि चीजें खरीदते हो। तुम लोगों में से बहुत से गाँवों के रहने वाले हैं। वहाँ किसान खेती करके अनाज की उत्पत्ति करते हैं। जब फसल कटकर खलिहान में आ जाती है तो उपज का थोड़ा सा हिस्सा तो खाने के लिए घर में रख लिया जाता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यापारी के हाथ बेच दिया जाता है, लेकिन एक बात और है। इन सबके पहले खलिहान पर—नाऊ, धोवी, मालगुजार, महाजन आदि का धावा होता है। शहर की तरह गाँवों में नाऊ, धोवी, बढ़ई वगैरह को नकद पैसा मिलता नहीं। घर पीछे उनका हिस्सा बँधा रहता है। फसल कट जाने पर अनाज में से पहले उनका हिस्सा निकाल देना पड़ता है। महाजन जिनसे किसान रुपया उधार लेते हैं सूद की जगह अनाज ही ले लेते हैं।

## अर्थशास्त्र के विभाग

ऊपर दिये हुए उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि हर एक मनुष्य जो अपने भरण-पोषण के लिए प्रयत्न करता है अर्थात् कोई धन्धा या पेशा करता है उसको सबसे पहले धन पैदा करना पड़ता है, फिर वह उसके बदले उन चीजों को मोल लेता है जिनकी उसको आवश्यकता है, फिर वह उनका उपभोग करता है अर्थात् काम में लाता है या खर्च करता है और यदि उसने कुछ और लोगों की मदद से धन की उत्पत्ति की है तो उनका हिस्सा बाँटना पड़ता है। सारांश यह है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिये हमें उसको चार विभागों में बाँट लेना चाहिए—

१—उत्पत्ति (Production)

२—उपभोग (Consumption)

३—विनिमय (Exchange)

४—वितरण (Distribution)

अब हम आगे इन चार विभागों के सम्बन्ध में विचार करते हैं।

### उत्पत्ति (Production)

हम ऊपर कह आए हैं कि अर्थशास्त्र हमें उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ बतलाता है, पर यह उत्पत्ति है क्या बला ? क्या केवल किसान ही का सम्बन्ध उत्पत्ति से है ? नहीं । दर्जों, बढ़ई, हलवाई सबके सब उत्पत्ति का कार्य करते हैं। जुलाहा क्या करता है ? वह रुई के रेशों को इस प्रकार बुन देता है कि कपड़ा तैयार हो जाता है। दर्जो उसी कपड़े को क्या करता है ? वह आपके बदन का नाप लेकर उस कपड़े को काट-छाँटकर इस प्रकार मिलाता है कि उसकी बनावट हुई कमीज व कोट आपके बदन पर ठीक फिट कर जाती है। इसी प्रकार हलवाई मैदा, खोवा, चीनी वगैरह को इस प्रकार मिला कर आग पर भून कर तैयार करता है कि मिठाई बन जाती है। बढ़ई लकड़ी और कुछ कीलों को इस प्रकार मिला देता है कि हमारा हल, खाट, कुर्सी या मेज बन जाती है। कुम्हार गीली मिट्टी को चाक पर प्रकार सेवारता है कि सकोरा, करई व हाँड़ी तैयार हो जाती है। को ही ले लो। वह थोड़े से बीजों में मनो अनाज पैदा करता है। कैसे ? वह बीज को एक खास ढंग से खेत में रखता है। फिर इस

प्रकार से खाद व पानी डालता है कि बीज उनके तथा हवा के अंशों को लेकर अपना वेप बदल डालता है। उसमें से एक छोटा सा पौधा फूटकर निकलता है और यह पौधा अन्त में अन्न के सैकड़ों दाने पैदा करता है। कहने को मतलब यह है कि कोई भी अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता। किसान से लेकर, जुलाहे और दर्जी तक सबके सब पहले से प्राप्त किसी वस्तु को इस प्रकार से रखते हैं कि उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। जहाँ पहले रुई हमारे बहुत कम काम की रहती है, वही रुई की कमीज या कोट को हम अपना बदन ढकने में उपयोग करते हैं। “इसलिये किसी वस्तु की उत्पत्ति से हमारा मतलब होता है उसे और उपयोगी बनाना। किसी चीज को पहले से अधिक उपयोगी बनाना ही धन की उत्पत्ति कहलाती है।”

मान लीजिये आपके खेत के छोर पर आपका एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा है। आप उसे बेचना चाहते हैं और श्याम आपको बीस रुपये देने को तैयार है। आपको दाम कम ज्ञेयता है और स्वयं पेड़ काटकर उसके तख्ते बना डालते हैं। इन तख्तों को आप तीस-पैंतीस रुपये में बेच सकते हैं। पर यदि आप इन तख्तों से चौखट, कुर्सी, चारपाई आदि बना डालिये तो आपको पचास रुपये भी मिल जायें तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन आपने इतने समय तक किया क्या ? उस पेड़ की लकड़ी को तो बड़ा ही नहीं दिया। उल्टा आप उसे काटते-छाँटते रहे। हाँ, आपने उस लकड़ी की उपयोगिता अवश्य बढ़ा दी। यहाँ पर आप किसी प्रकृति से प्राप्त की हुई वस्तु की उपयोगिता बढ़ाते रहे हैं लेकिन जब वकील साहब हमारा मुकदमा जीत जाते हैं, जब ब्राह्मण महाराज हमारे लिये कोई पूजा कर देते हैं अथवा जब पुलिस का आदमी हमारे जान-माल की रखवाली करता है, तब तो शायद किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन नहीं होता। उपयोगी तो ये सेवाये भी होती हैं, परन्तु ये ऊपर बताई हुई वस्तुओं से भिन्न हैं। इनसे हमारी विविध आवश्यकताएँ सीधी-सीधी पूरी होती हैं। पहले दिये गये उदाहरण अर्थात् किसान का अनाज पैदा करना, दर्जी का कोट सीना, बड़ई का हल बनाना आदि भौतिक ( Material production ) उत्पत्ति के उदाहरण हैं। लेकिन वकील, पुलिस, मास्टर वगैरह के कार्य अभौतिक उत्पत्ति ( Immaterial production ) के अन्तर्गत आ० अ० २

शामिल किये जाते हैं। भौतिक उत्पत्ति करते समय किसी वस्तु का रूप, स्थान आदि बदलकर उपयोगिता की वृद्धि की जाती है। अभौतिक उत्पत्ति के लिये सेवाकार्य किये जाते हैं, कि जिससे मनुष्य की आवश्यकता सीधे-सीधे पूरी हो जाती है।

### उपभोग (Consumption)

उत्पत्ति का अर्थ समझ लेने पर अब हम उपभोग के सम्बन्ध में विचार करते हैं। रामू किसी खेत में क्या बोवेगा, इससे अब हमसे बिल्कुल मतलब नहीं। वह स्वतन्त्र है। चाहे वह गेहूँ बोवे, चाहे चना, चाहे जौ या बाजरा। मान लीजिये वह गेहूँ बोता है। फसल के कट जाने पर किसान गेहूँ को काट माड कर घर में लाता है। घर वाले उसको पीस कर रोटियाँ पकाते हैं और तब कोई उसे खाते हैं। खाने से किसान की भूख मिट जाती है। उसे एक तरह का संतोष मिलता है और हम कहते हैं कि किसान ने रोटी का उपभोग किया। आमतौर पर उपभोग से किसी वस्तु का उपभोग करने या सेवन करने का मतलब निकाला जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में उपभोग के मतलब कुछ और ही होते हैं। मान लो तुम्हारे पास रोटी का एक टुकड़ा है। उसे तुम खा भी सकते हो और आग में डाल कर जला भी सकते हो। दोनों हालत में कहा जाता है कि रोटी का उपभोग हो गया लेकिन अर्थशास्त्र के मत से केवल जब रोटी खाई जाती है तभी उसका उपभोग समझा जाता है, अन्यथा नहीं। रोटी खाने से मनुष्य को एक प्रकार का संतोष मिलता है; लेकिन यदि रोटी आग में जला दी जाय तो किसी की आवश्यकता पूरी नहीं होनी और इसलिये किसी को संतोष नहीं मिलना। रोटी खाई जाय अथवा जलाई जाय दोनों हालत में उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। अतएव अर्थशास्त्र के अन्तर्गत जब किसी सेवा या वस्तु का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि मनुष्य की कोई आवश्यकता पूरी होती हो अर्थात् जिससे मनुष्य को किसी प्रकार का संतोष मिलता हो तभी हम कहते हैं कि उस सेवा या वस्तु का उपभोग किया गया। एक बात और, कभी कभी किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के पैदा करने में किया जाता है जैसे किसी कारखाने वाले का उपयोग। यहाँ पर देखना चाहिये कि कोयले के जलने से किसी भी की कोई इच्छा पूरी हुई या नहीं। उत्तर है कि हमारे देखते तो कोई

इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई देती। परन्तु कोयले से भाग बनती है जो उपयोगी है। हाँ, अगर जाड़े का दिन हो और आप कोयला जला कर आग तापे तो हम कहेंगे कि आपने कोयले का उपभोग किया, क्योंकि इस बार कोयला जलाने से आपकी ठंडक दूर करने की इच्छा पूरी हो गई।

### उपभोग का महत्व

उपभोग के सम्बन्ध में यह जानना जरूरी है कि इसी के लिये आदमी सब चीजें पैदा करता है और जितनी चीजें पैदा की जाती हैं उन सबका उपभोग किया जाता है। परन्तु किसी आदमी की एक समय में एक इच्छा तो होती नहीं। हर वक्त बहुत सी बातें उसके दिमाग में घूमा करती हैं और सबसे बड़ा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कौन सी इच्छा पहले पूरी की जाय। इसका साधारण सा उत्तर है। उस इच्छा को जिसको पूरा करने से सबसे अधिक सतोष या उपयोगिता ( Utility ) प्राप्त हो। लेकिन आमतौर पर आदमी क्या करते हैं? कौन सी वस्तुएँ आवश्यक ( Necessaries ) होती हैं, कौन आरामदायक ( Comforts ) और कौन गुलछरें उड़ाने के लिये बनाई जाती हैं? फिजूलखर्ची किसे कहते हैं? उपभोग में इन सब प्रश्नों पर विचार होता है। उससे यह भी पता लगता है कि जो वस्तु किसी गरीब किसान के लिये आरामदायक ( Comfort ) और विलासपूर्ण ( Luxuries ) हो वही जमींदार के लिये आवश्यक हो सकती है। अपनी आमदनी का विचार न कर-जो गरीब किसान रोज हलुवा-पूरी उड़ाता है उसे दुनिया भोग-विलासी कहती है। लेकिन जमींदार हलुवा-पूरी आवश्यक समझते हैं। उनके हिसाब से शर्मरी ठाट के अन्दर रेडियो, बिजली, मोटर आदि स्थान रखते हैं। इस बात से रहन-सहन के दर्जे की समस्या उठती है। एक मजदूर किस तरह की जिन्दगी बसर करता है; पचास-पाठ रुपये मासिक तनखाह पाने वाले क्लर्क साहब किस प्रकार रहते हैं; महीने में सौ दो सौ रुपये पैदा कर लेने वाले दूकानदार तथा उद्योग-धन्धे वाले कैपा जीवन व्यतीत करते हैं और हजार-पाँच सौ रुपये माहवार फटकारने वाले बाबू, डाक्टर या कलक्टर साहब किस मौज से रहते हैं, इन सब बातों का वर्णन व विवेचन रहन-सहन के दर्जे ( Standard of living ) के अन्तर्गत किया जाता है। जैसे-जैसे आवश्यकता



बढ़ती है वैसे ही वैसे मनुष्य अच्छी जिन्दगी बसर करने की कोशिश करता है और उसके रहन-सहन का स्तर ऊपर को उठता जाता है। इतना ही नहीं किसी देश के रहने वाले को किस प्रकार रहना चाहिये, वहाँ की सरकार को उपभोग ( Consumption ) के सम्बन्ध में किन-किन बातों में दखन देना चाहिये इत्यादि और भी बहुत बातें हमें उपभोग के अन्तर्गत ही माननी पड़ती हैं।

### उपभोग का क्षेत्र

अब हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि मनुष्य जो तरह तरह की वस्तुओं का उपभोग करता है, कहाँ तक उसके और देश के लिये लाभदायक है और किस हालत में वह हानिकर होना है। लगे हाथ इस बात का भी विचार किया जाता है कि मनुष्य कैसा रहता है और उसका रहन-सहन का दर्जा क्या होना चाहिये तथा उस दर्जे को बनाये रखने के लिए देश की सरकार को क्या करना चाहिये।

### विनिमय ( Exchange )

लेकिन सोचने की बात है कि आजकल कोई आदमी अपने आप मतलब की सारी वस्तुएँ नहीं उत्पन्न करता। कोई केवल मिसाली करता है तो कोई नौकरी, कोई मजदूर है तो कोई बढ़ई, कोई धोबी है तो कोई चमार। चमार के लिये यह बिलकुल जरूरी है कि जूते बेचने से आने वाले पैसों से आटा खरीदे और मजदूर-मजदूरी की रकम से दाल-चावल मोल ले। ऐसा क्यों होता है? बनिये के पास आटा इतनी अधिक मात्रा में रहता है कि वह आटे से पैसों को अधिक उपयोगी समझता है और हमारे चमार के पेट के लिये तो आटा जरूरी है ही। कहने का मतलब यह है कि दोनों ओर वालों को कुछ फायदा होता है तभी अदल-बदल होता है और जब दो वस्तुओं का अदला-बदला होता है तो एक वस्तु के कुछ वजन के लिये थोड़ी सी दूसरी वस्तु दी जाती है। उदाहरण के लिये हो सकता है कि बीस सेर गेहूँ के लिये दस सेर चावल मिले। इस प्रकार अर्थशास्त्र ( Economics ) की दृष्टि से दो सेर गेहूँ का मूल्य हुआ एक सेर चावल। आजकल गाँवों को छोड़कर शहरों में तो ऐसे उदाहरण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अधिकतर पैसे देकर हम तुम बाजार से तरकारी, मसाला आदि खरीद लाते हैं।

अगर सेर भर गेहूँ का मूल्य छः आना है तो हम कहेंगे कि गेहूँ की कीमत छः आना सेर है । वस्तुओं को इस तरह से देने-लेने का नाम विनिमय है । पहले जमाने में जब रुपये-पैसे का चलन नहीं था तो वस्तु से ही विनिमय होता था ।

विनिमय के साथ प्रश्न उठता है कि विनिमय के दर के सम्बन्ध में किस प्रकार यह निश्चित किया जाय कि एक रुपये के बदले में कितने सेर गेहूँ बेचा जाय अथवा एक मिर्जई को बनाने के लिये रामू गाजी दर्जी को कितना पैसा देवे । इसके अलावा विनिमय के अध्ययन से हमें पता चलता है कि किसान, कारीगर तथा व्यापारी माल को बाजार में लाकर किस प्रकार बेचते हैं । गाँवों के हाट और मेले-तमाशे कितना महत्व रखते हैं ।

### वितरण (Distribution)

उपभोग करने वाले की दृष्टि से तो हमने देख लिया कि वह किस प्रकार विनिमय करके किसी वस्तु का उपभोग करता है । अब हमें देखना चाहिये कि बेचने वाला विक्री से आने वाले धन में किस प्रकार अपना हिस्सा लेता है । क्या सारी रकम उसी की होती है अथवा कोई दूसरा भी उसमें साझीदार होता है । मान लीजिये किसान अपने अनाज को शहर वाले व्यापारी को दे देता है और वह उसे शहर के बाजार में जाकर बेचता है । बेचने से जो दाम आयेगा उसका किस प्रकार बँटवारा किया जाय । सोचने पर मालूम पड़ता है कि उत्पत्ति में जो शक्तियाँ मिलकर काम करती हैं उनके मालिक अनाज को बेचकर आने वाली रकम के हकदार हैं । इसलिये हमारी समस्या यह हो जाती है कि किस प्रकार से निगटारा किया जाय कि भूमि-मालिक को कितना लगान, मजदूर को कितनी मजदूरी व महाजन को कितना सूद मिले । परन्तु, यहाँ पर हम एक बात भूल जाते हैं । उसे साफ करने के लिए थोड़ी देर के लिये मिल-मालिक को ले लीजिये । वह मिल का बीमा कराये रहता है और हर साल बीमे की रकम देता है । इसके अलावा हर साल उसकी मशीनें कुछ न कुछ घिस जाती हैं । उसके लिये आने वाली रकम से कुछ निकालकर अलग कर लेना चाहिये । उन सब को काटकर जो बचता है जमीन के मालिक, मेहनत करने वाले मजदूर, धन लगाने वाले महा-

जन, प्रबन्धक व साहस प्रदान करने वाले मनुष्य के बीच बाँटा जाना चाहिए। परन्तु यह कोई जरूरी नहीं है कि पाँचों कार्य भिन्न-भिन्न व्यक्ति करें। हम जानते हैं कि मिल-मालिक रुपया भी लगाता है, प्रबन्ध भी करता है और साहस भी दिखाता है। इसी तरह किसान अधिकतर मेहनत भी करता है और अनाज पैदा करने के लिये पूँजी भी लगाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन पाँचों के बीच किस हिसाब से रकम का बँटवारा हो। इसका उत्तर हमें अर्थशास्त्र के वितरण विभाग से मिलता है।

यही नहीं, इस विभाग में यह भी विचार किया जाता है कि कहीं भूमि वाला इतना अधिक भाग तो नहीं लेता कि मजदूरों के पास बहुत कम रह जाए और उनकी हालत खराब हो जाये। इसके अलावा हमें यह भी मालूम होता है कि जमींदारों और किसानों के बीच में कैसा सम्बन्ध होना चाहिए। धन वितरण इस प्रकार न होना चाहिए कि जमींदार जो गिनती में किसानों से बहुत कम हैं गुलछरें उड़ावें और मर मर कर अनाज पैदा करने वाले किसान भूख और बेगार भुगतें। किसानों के पास कितना धन पहुँचना चाहिए ? क्या उनके लिये इतनी रकम काफी होगी जिससे उनके कुटुम्ब का काम चल जावे ? कहा जा सकता है कि देश की उन्नति के लिये यह जरूरी है कि हर एक देशवासी उन्नति करे अर्थात् प्रत्येक आदमी इतना धन पावे जिससे वह दूसरों को कम से कम हानि पहुँचाते हुए अधिक से अधिक लाभ उठावे।

## सारांश

अस्तु, हम जान गये कि अर्थशास्त्र उस विद्या का नाम है जो मिलजुल कर रहने वाले मनुष्यों के उन प्रयत्नों के बारे में विचार करती है जिनसे वे अपनी-अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करते और अर्थ (अर्थात् धन) या अन्य सामग्रियाँ उत्पन्न करते हैं। आदमियों के धन-सम्बन्धी उपायों का पूर्ण रूप से विचार करने के अलावा अर्थशास्त्र में देशों की आर्थिक दशा और उन्नति का भी ध्यान रखा जाता है। अर्थशास्त्र का न अधिकतर उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय और वितरण नामक चार-चार भागों में बाँट कर किया जाता है।

## अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ

अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें बहुत लाभ होता है। उसके अध्ययन से हम जान सकते हैं कि हमारा देश जिसको प्रकृति ने भरा-पूरा बनाया है—यहाँ की मिट्टी जलवायु पैदावार के लिए अच्छी है, यहाँ की खानों में खनिज पदार्थ भरे हैं, जंगलों में कीमती लकड़ी है, नदियों के जल से बिजली पैदा हो सकती है लेकिन फिर भी हमारा देश गरीब क्यों है ? उसकी गरीबी के क्या कारण हैं ? यहाँ के अधिकांश निवासियों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। पहनने को कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिए मकान नहीं मिलते और बीमारी में उनका इलाज नहीं हो पाता। देश को राजनैतिक आजादी मिले कई साल गुजर गए लेकिन कन्ट्रोल हटने का समय नहीं आता। वस्तुओं के भाव बढ़ते जाते हैं। राशन में जो अनाज पहले मिलता था वह घट रहा है। कपड़े की मिलें बन्द होने का डर बना रहता है। कपड़ा महँगा होता जा रहा है। घरों के किराए बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है ? क्या इस देश के प्राकृतिक साधन खतम हो गये हैं ? क्या भारत की शस्यश्यामला भूमि रेगिस्तान है ? क्या ईश्वर इससे क्रुद्ध है ? क्या हमारा भाग्य हमसे रूठा है ? अथवा क्या हम कामचोर बनते जा रहे हैं ? क्या हमें सब अपना-अपना काम मन लगा कर नहीं करते ? क्या हम इसलिए काम से मन चुराते हैं कि काम का फल कोई दूसरा भोगेगा ? क्या हम आजादी से यह मतलब समझने लगे हैं कि किसी भी प्रकार के अधिकार का दुरुपयोग करके भी धन कमाना चाहिये ? क्या आजादी के कारण हमारे नाँचे श्रेणी के भाई अब यकायक अमीरों जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं ? इस प्रकार के अनेकों प्रश्न तुम्हारे दिमाग में उठते होंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये सब प्रश्न आते हैं। हमारी वर्तमान गरीबी और आर्थिक कठिनाइयाँ कैसे दूर की जा सकती हैं। किस प्रकार हमारा देश धनी बन सकता है ? किस प्रकार हमारे देशवासी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं ? अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अतः इस अध्ययन से हमको बहुत बड़ा लाभ है।

## अभ्यास के प्रश्न

१—अर्थशास्त्र क्या है ? इसके अन्तर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है ?

२—अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए । व्यावहारिक जीवन में इसके अध्ययन से क्या लाभ है ?

३—आपके गाँव में या मुहल्ले में कितने अमीर और गरीब कुटुम्ब रहते हैं ?

४—अपने गाँव या मुहल्ले के भिन्न-भिन्न पेशे के ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कीजिए जो परिश्रम करके अपनी जीविका प्राप्त करते हैं । इसी सूची में उनका पेशा भी बतलाइए ।

५—ऐसी २० वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए जिनका उपयोग आपके मकान में प्रति सप्ताह होता है ।

६—आपके गाँव के साप्ताहिक हाट में अथवा आपके मुहल्ले के बाजार में जो वस्तुएँ विकती हैं उनकी सक्षिप्त सूची तैयार कीजिये ।

७—किसी गाँव में जाकर यह जानने का प्रयत्न कीजिये कि फसल के तैयार होने पर किसी एक किसान को बड़ई, लोहार, नाऊ इत्यादि को कितना अनाज देना पड़ा ।

८—अपने कुटुम्ब की एक मास की आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब रखिए और यह बतलाइए कि भोजन, कपड़ा, किराया, शिक्षा, दान-धर्म इत्यादि में कितनी रकम उस मास में खर्च हुई ?

९—यदि तुम्हारे गाँव में किसी को रुपये उधार लेने की जरूरत पड़ती है तो रुपया किससे उधार लिया जाता है और किस दर पर सूद दिया जाता है ?

१०—तुम्हारे गाँव में जमींदार और किसानों का संबंध कैसा है ? क्या किसान जमींदार से प्रेम करते हैं । यदि प्रेम नहीं करते तो उनके प्रधान कारण क्या हैं ?

११—उपभोग की परिभाषा लिखिये और उसका महत्व समझाइए ।

१२—अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं । उनका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए ।

## दूसरा अध्याय

### परिभाषाएँ (Definitions)

#### धन या सम्पत्ति (Wealth)

पिछले अध्याय में हम बतला आए हैं कि अर्थशास्त्र में धन-सबकी बातों का विवेचन रहता है। अब हम धन का अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। ससार में सर्वत्र रुपये की ही माया है। बिना रुपये के किसी की गुजर नहीं हो सकती। तुम शहर में जरूर गये होगे। वहाँ तुमने देखा होगा कि लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर घूम रहे हैं। फिटन, टमटम, मोटर, साइकिल दौड़ रही हैं। बड़ी-बड़ी दूकानों और कोठियों में लाखों रुपये का माल भरा हुआ है। अमीर आदमियों के ऊँचे-ऊँचे मकान बने हुए हैं। अमीर कौन कहलाता है? वह, जिसके पास खूब धन-दौलत होती है, जो बड़ी बढिया शानदार कोठी में रहता, तथा जिसके यहाँ बहुत से नौकर-चाकर होते हैं। लेकिन क्या अमीर आदमी की तमाम दौलत रुपये के रूप में ही रहती है? उत्तर है, नहीं। किसी मनुष्य के धन से उसका रुपया, जेवर, मकान, जमीन इत्यादि कीमती वस्तुओं का बोध होता है और वही मनुष्य धनवान् कहलाता है जिसके पास ये सब चीजें अधिक तादाद में होती हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में केवल इन चीजों को ही धन नहीं कहते। अर्थशास्त्र में हम उन वस्तुओं को धन के नाम से पुकारते हैं जिनको हम काम में ला सकते हैं और जो बेची जा सकती है अर्थात् जो विनिमय-साध्य हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ को ले लो। उसको पीसकर हम आटे की रोटियाँ पका सकते हैं और रोटियों के खाने से हमारी भूख मिट जायगी। अतएव गेहूँ उपयोगी है। गेहूँ को हम बेच भी सकते हैं। जरूरत होने पर हम गेहूँ देकर धोती का जोड़ा खरीद सकते हैं। रुपए के बदले में हम गेहूँ दे सकते हैं और धोती के बदले में रुपया। अतएव गेहूँ विनिमय-साध्य वस्तु है इसलिये अर्थशास्त्र के हिसाब से गेहूँ भी धन है। इस बात को और साफ करने के लिये हवा को ले लो। यह सबको मालूम है कि वायु हमारे लिये कितनी जरूरी है। इसके बिना हम एक घंटा भी नहीं जी सकते। इसलिये वायु की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। परन्तु क्या यह विनिमय-साध्य है? क्या

आप वायु के बदले कोई वस्तु ले सकते हैं ? वायु हर जगह मौजूद रहती है। इसलिये किसी को मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यह ईश्वर की देन है और हम इसे धन में नहीं गिन सकते। इसी तरह यदि आप नदी या तालाब से दो चार घड़ा पानी भर कर किसी वस्तु से बदला करना चाहेंगे तो कोई बदला नहीं करेगा। क्योंकि नदी या तालाब का पानी आसानी से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी वह आसानी से नदी से ले लेता है। इसलिये पानी हमारे लिए उपयोगी होते हुए भी धन नहीं कहला सकता, परन्तु यही जल राजपूताना के रेगिस्तान में धन कहलाने लगेगा, क्योंकि जल की कमी के कारण वहाँ पर तो सब इसे मोल लेने के लिये तैयार हो जायेंगे। गाय, बैल, मकान, लकड़ी, कड़ा, कोयला, पत्थर, पेड़, फल, फूल आदि सब वस्तुएँ सम्पत्ति या धन के स्वरूप में हैं। और जब ऐसी चीज सम्पत्ति हो सकती है तो इस हिसाब से हम कूड़ा, करकट, गोबर, राख, हड्डी आदि तक का गिनती सम्पत्ति में कर सकते हैं।

**केवल रुपया-पैसा (Money) ही धन (Wealth) नहीं—**

हम ऊपर कह आये हैं कि कुछ लोगों के हिसाब से रुपया-पैसा व सोना-चाँदी का ही नाम धन है। यह बिल्कुल गलत है। भारत में ऐसे भी कितने गाँव मिल जाते हैं जहाँ पर लोगों के पास रुपए नहीं हैं, लेकिन क्या उन गाँवों में अमीर और गरीब नहीं बसते ? तुम पूछ सकते हो कि फिर रुपया-पैसा आया कैसे ? इसकी क्यों-जरूरत पड़ी-? असली बात यह है कि बिना रुपए-पैसे के सम्पत्ति को बदला-बदली करने में बड़ा झुझझकावाट पड़ता है। मान लो तुम्हारे पास चना है और तुम्हें मिर्जई की जरूरत है। अब तुम्हें किसी ऐसे आदमी को तलाश करना पड़ेगा जिसके पास मिर्जई हो। खाल करो कि ऐसा मनुष्य मिल गया लेकिन वह मिर्जई के बदले में जूना माँगता है। अब दोनों आदमियों को एक तीसरे आदमी को ढूँढ़ना पड़ेगा जिसके पास जूना हो और जो जूते के बदले में चना लेना चाहता हो। इन्हीं सब झुझझकों को दूर करने के लिए रुपये-पैसे का रिवाज चला है। रुपए-पैसे ने से हम जान सकते हैं कि राम और श्याम में कौन अमीर है। हम कैसे ? हम इस बात का पता लगावेंगे कि राम का घर-बार, खेत-पात

कपड़ा-लत्ता आदि का क्या दाम है। मान लो सब मिलाकर चार हजार रुपया हुआ और श्याम के पास इस तरह से छः हजार का माल निकला तो हम कहेंगे कि श्याम राम से अमीर है। अस्तु, यह तै हो गया कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही रुपये-पैसे चलाए गए और केवल यही धन-स्वरूप नहीं है।

पर इन रुपये-पैसे द्वारा हम कोई वस्तु कब खरीदते हैं ? तुम कब गेहूँ खरीदते हो अथवा कब तुम्हारे पिता गाँव के चमार से जूता मोल लेते हैं ? उस समय जब कि उन्हें जूते की जरूरत मालूम पड़ती है। वह जूते के दाम क्यों देते हैं ? क्योंकि जूता हवा या जल की तरह ईश्वर की देन होकर काफी परिमाण में आमानी से नहीं मिल सकता। अर्थात् जूतों की संख्या परिमित है। इसके अलावा एक बात और है। जूता बनाने के लिए चमार को मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के बदले में कुछ देना जरूरी है। इसलिए वह दाम देकर चमार से जूता मोल ले आते हैं। अब तुम जान गए कि अर्थ-शास्त्र में धन कितने कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जो उपयोगी होती है, जिसकी संख्या परिमित होती है व जिसके प्राप्ति करने के लिए श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है अर्थात् जो वस्तु चिन्मय-साध्य है, उस वस्तु की गणना हम धन में करते हैं।

धन-वृद्धि (Increase of Wealth)



बीधा खेत है और तुम उससे अधिक से अधिक अनाज पैदा कर रहे हो, यदि तुमको और अधिक माल की जरूरत है तो इसका उपाय यही है कि तुम दस की जगह बारह-पन्द्रह बंधे जर्मन में खेती करो। उत्पत्ति बढ़ाने का दूसरा साधन है श्रम बढ़ाना। अगर खेत में काम करने वाले आठों मजदूर पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि उनकी संख्या बढ़ा कर दस या बारह कर दी जाय। धन या पूँजी का भी यही हाल है। जब आप धनोत्पत्ति की दो शक्तियों को बढ़ा रहे हैं तो आपको तीसरी को भी जरूर ही बढ़ाना पड़ेगा अन्यथा आपका काम नहीं बनेगा। अतएव धनी समृद्धि-शाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अधिक क्षेत्र में काम करें, अधिक मेहनत लगावे व अधिक पूँजी का उपयोग करें।

### धन और सुख (Wealth and Welfare)

वस्तु के उन्भोग से सतोष होता है और सुख की प्राप्ति होती है। गरीब मनुष्य के पास वस्तुओं की कमी रहती है, उसके पास सुख प्राप्त करने के साधनों का अभाव सा रहता है। गरीब को अधिक सुखी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके धन का परिमाण बढ़ाया जाय, उसको आमदनी में वृद्धि की जाय। इसी प्रकार आर्थिक उन्नति को जा सकती है। परन्तु धनी बनने और सुखी बनने में महान् अन्तर है। यह बात ठीक है कि धनी मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है। वह मोटर खरीद सकता है। दो चार लठैत और अन्य व्यक्तियों को नौकर रख सकता है। अच्छा-अच्छा खाना खा सकता है। परन्तु अमीर आदमी बदमाश और बदचलन भी हो सकते हैं। बुरे कामों में रुपया भी लुटा सकते हैं। समृद्धिशाली और सुखी बनने के लिए यह जानना जरूरी है कि रुपया किस प्रकार खर्च किया जाता है। सुखी जीवन व्यताने के लिये थोड़ी सी सादगी अख्तियार करनी पड़ेगी। यही नहीं, जान की भी जरूरत पड़ती है। क्या हुआ यदि आपको यकायक एक लाख रुपये को डों की लाटरी मिन गई। यदि आप मूर्ख हैं, यदि आपके लिये काला अक्षर भैंस बराबर है तो आप बड़ी जल्दी सब रुपया लुटा देंगे। दूसरी ओर अगर आप पढ़े-लिखे हैं, और आपको अर्थशास्त्र की बातें मालूम हैं तो आप उस उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि जिससे आपकी और देश की बनने लगे। यह भी याद रखना चाहिए कि धन होते हुए मनुष्य

दुखी हो सकता है। रुपए के लोभ में मरने वाला महाजन सदैव चिताग्रस्त रहेगा। धन रहते हुए भी कुचलन अथवा असंतुलित व अवांछनीय भोजन करने वाला व्यक्ति रोगग्रस्त और दुखी होगा। जिन परिणारों के बालक-बालिकाएँ अनुचित लालन-पालन के कारण बिगड़ जाते हैं उनमें भी धन रहते हुए माता-पिता दुखी रह सकते हैं। कृत्रिम जीवन व्यतीत करने वाले तथा इच्छाओं के गुलाम व्यक्ति भी दुखी ही रहते हैं।

### उपयोगिता (Utility)

अब प्रश्न उठता है कि आपको किस प्रकार रुपया खर्च करना चाहिये। आपको कौन-कौन सी वस्तुएँ खरीदनी चाहिये और कितनी! इससे भी मुख्य सवाल है कि आप क्यों किसी चीज को खरीदते हैं? क्योंकि आपको उसकी जरूरत रहती है, क्योंकि वह चीज आपके लिए उपयोगी है। मान लीजिये आप अपने गाँव के हाट में गए। वहाँ पर बहुत सी चीजें विक्राने के लिये आती हैं। कोई काड़ा खरीदता है, कोई गेहूँ-चना खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है तो कोई कुछ। आप भी कोई वस्तु पसन्द करके खरीद लेते हैं। परन्तु क्या आप बता सकते हैं कि आपने उनको क्यों खरीदा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये यह जानना जरूरी है कि किसी वस्तु की उपयोगिता क्या होती है। “कहा जाता है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उस वस्तु की चाह होती है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को किसी वस्तु के उपयोग से होने वाला तृप्ति का नाम उपयोगिता है।” इसका सम्बन्ध मन से होता है। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा या रुचि में कुछ न कुछ अन्तर जरूर रहता है। इसी लिए किसी एक चीज की उपयोगिता प्रत्येक आदमी के लिये बराबर नहीं होती और हम उपयोगिता का वर्णन किसी नाप या तौल से नहीं कर सकते। लोग किसी वस्तु का मूल्य तय करने में उस वस्तु की उपयोगिता का विचार जरूर करते हैं। मान लीजिये गन्ू किसान के सामने

पास खुरपी नहीं है और खेत से घास-फूस उखाड़ कर फेंकने के लिये उसे खुरपी की जरूरत है। अतएव खुरपी को मोल ले लेगा।

इसी तरह हम उत्पत्ति में भी करते हैं। हम किसी वस्तु विशेष को उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। हम केवल उपयोगिता को ही उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिये हल को ले लीजिये। बढई अपने औजारों की मदद से लकड़ी को काट-छाँट कर उसे हल का रूप देता है। ऐसा करने से लकड़ी की उपयोगिता बढ गई। काम आते-आते कई वर्षों के बाद हल टूट जाता है, उसकी उपयोगिता जानी रहती है। लकड़ी पड़ी रहती है पर हल काम का नहीं रहता।

### सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility)

हम ऊपर कह आये हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता भिन्न-भिन्न मनुष्यों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि उसी मनुष्य के लिए एक वस्तु की उपयोगिता एक दशा में कुछ हो सकती है तो दूसरी दशा में कुछ और। उदाहरण के लिये मान लो तुम्हो खूब जोर से भूख लग रही है। उस समय रोटी तुम्हारे लिये बहुत बड़ी उपयोगिता रखती है। पर एक रोटी खा लेने के बाद तुम्हारी भूख कुछ कम हो जाती है और दूसरी रोटी की उपयोगिता उतनी नहीं रह जाती जितनी कि पहली रोटी की थी। तीसरी रोटी की उपयोगिता दूसरी से भी कम होती है। अब यदि तीन रोटी में तुम्हारा पेट भर चला हो तो तुम सोचोगे कि चौथी रोटी ली जाय या नहीं। मान लिया तुमने चौथी रोटी ले ली। इसके खाने से तुम्हारा पेट बिल्कुल भर गया। यदि कोई तुम्हारे आगे दो चार रोटियाँ और डाल दे तो तुम्हारे लिये उनका मूल्य नहीं के बराबर है। पहली चार रोटियों से तुम्हारे पेट को पूरा सतोष मिल चुका, इसलिये तुम पाँचवीं व छठी रोटी को बिल्कुल नहीं खाओगे। उपयोगिता के घटने का एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है जब कोई मथुरा का चौबे भोजन करने बैठता है। जब वह खाकर उठने लगता है तो आप कहते हैं कि चौबे जी एक लड्डू और खा लें। चौबे महाराज सिर हिला देते हैं। इस पर आपका दोस्त हरी कि चौबे जी एक लड्डू खा लो तो एक आना पैसा देंगे। पैसे चौबे लड्डू लेकर खा जाते हैं। जब वह उठने लगते हैं तो

अबकी बार आपका दूसरा मित्र श्याम कहता है कि महाराज एक लड्डू और ले लो तो मैं आपको एक दुअन्न दीँ। महाराज राजी हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे लड्डू पर चौबे जी को चार आने और चौबे पर आठ आने दिये जाते हैं। पाँचवे लड्डू के लिये एक रुपया इनाम रक्खा जाता है किन्तु इस बार पेट जवाब दे देता है। चौबे जी ने अब तक जो चार लड्डू खाये उसकी उपयोगिता पहले खाये भोजन से कहीं कम थी। परन्तु उनकी उपयोगिता में जो कमी होती वह पैसों की उपयोगिता के कारण पूरी हो जाती थी और चौबे महाराज का पेट किसी तरह ठँस-ठाँस कर लड्डू को स्थान दे देता था। किन्तु अब पेट एक दम भर गया और चौबे महाराज उसे बिल्कुल नहीं खा सकते। इसलिये एक छोड़ यदि उन्हें दस रुपया भी दिया जाय तो वे उस पाँचवे लड्डू को न खायेंगे।

अर्थशास्त्र के हिसाब से ऊपर दिये गये उदाहरण में रोटी खाने वाले के लिये रोटियों की सीमान्त उपयोगिता चौथी रोटी की उपयोगिता के बराबर है। इसी प्रकार यदि मनोहर के पास बीस ग्राम हों तो ग्रामों की सीमान्त उपयोगिता बीसवें ग्राम की उपयोगिता के बराबर होगी। परन्तु ध्यान देने की बात है कि ग्रामों की सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अन्तर है। कुल उपयोगिता तो बीसों ग्रामों की उपयोगिता के जोड़ के बराबर है, किन्तु सीमान्त उपयोगिता केवल अंतिम ग्राम की उपयोगिता के बराबर होती है। यदि मनोहर के पास एक ही ग्राम होता तो कुल उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो जाती। परन्तु जैसे-जैसे वस्तु की संख्या या परिमाण बढ़ता जायगा वैसे ही उनकी सीमान्त तथा कुल उपयोगिता के बीच का फर्क भी बढ़ जायगा। उदाहरण के लिये यदि मेरे पास ३ ग्राम हैं। पहले ग्राम से मुझे ५ इकाई, दूसरे से ४ इकाई, तीसरे से २ इकाई उपयोगिता मिलती है तो २ इकाई तो सीमान्त उपयोगिता हुई और ११ इकाई कुल उपयोगिता हुई।

एक बात और। उन्व्युक्त चौबे जी वाले उदाहरण में पाँचवे लड्डू की उपयोगिता शून्य थी। मान लो चौबे जी उस लड्डू को अपने अंगोष्ठ में काँटते हैं। तब क्या दूसरे दिन भी चौबे जी यही कहेंगे कि उस उपयोगिता कुछ नहीं है और वे उसे नहीं खाएँगे? क्या न

व्यतीत होने के साथ-साथ जी का भोजन पच जायगा और चाँवे जी फिर भूखे होंगे। अतः समय-व्यतीत होने के साथ-साथ चाँवे जी के उस लड्डू की उपयोगिता बढ़ती जायगी। यदि तुम सोचो तो समय के साथ घटने-बढ़ने वाली उपयोगिता के अनेकों उदाहरण बता सकते हो।

### मूल्य (Value)

मान लो बाजार में तुमने गेहूँ और चना दोनों विकते हुए देखे और तुम दोनों को खरीदना चाहते हो। अब अगर तुम्हारे दिमाग से गेहूँ की उपयोगिता चने से दुगुनी है तो तुम एक रुपये में जितना गेहूँ लोगे उसी रुपये में उससे दुगुना चना माँगोगे। उदाहरण के लिये यदि तुम एक रुपये में दो सेर गेहूँ लोगे तो चार सेर चना माँगोगे। यदि कहीं तुम गेहूँ बेचने वाले होते और श्याम चने वाला तो तुम श्याम से फी सेर गेहूँ की जगह दो सेर चने माँगते। और यदि श्याम भी एक सेर गेहूँ के बदले दो सेर चना देने को राजी हो जाय तो दो सेर चना का मूल्य एक सेर गेहूँ समझा जायगा। इसी तरह यदि तुम अपनी गाय को बेच-बकरियाँ खरीदना चाहो और यदि तुम्हारी निगाह में गाय की उपयोगिता बकरियों से तिगुनी हो तो तुम एक गाय के बदले में तीन बकरियाँ माँगोगे। जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से अदला-बदली की जाती है तब पहली वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु कितनी दी जाय इसका निश्चय उपयोगिता द्वारा ही होता है। ऐसी दशा में अर्थशास्त्र के अनुसार एक गाय का मूल्य तीन बकरियाँ हुई, और एक-सेर-गेहूँ का मूल्य हुआ दो सेर चना।

मूल्य (Value) का जो अर्थ ऊपर दिया गया है उससे क्या नतीजा निकलता है ? इसके मतलब होते हैं कि यदि एक चीज का मूल्य बढ़ जायगा तो दूसरी का कम हो जायगा। मान लें जिनके कि पहले दो आम का मूल्य होता था एक खरबूजा। अब यदि किसी तरह आम की फसल आधी हो तो आम का मूल्य दुगुना हो जायगा यानी दो आम के बदले दो खरबूजे मिलेंगे या एक आम के बदले एक खरबूजा मिलेगा। आम का हो गया पर खरबूजे के मूल्य का क्या हाल है ? जहाँ पहले के लिए दो आम मिलते थे वहाँ अब एक ही आम मिलता है

अर्थात् खरबूजे का मूल्य आधा हो गया। एक बात और; यदि कहीं आम की फसल न बिगड़ती पर खरबूजों की संख्या दुगुनी हो जाती तब भी वही बात होती जो आमों के आधे रह जाने पर हुई थी। अर्थात् एक खरबूजे के लिए एक ही आम मिलता।

### कीमत (Price)

पुराने जमाने में जब रुपये पैसे का चलन नहीं था तब एक वस्तु दूसरी वस्तु से बदली जाती थी। उस समय मूल्य का बोलचाल था। परन्तु उसमें कठिनाई होती थी? यदि सुमेर को किसी वस्तु की जरूरत है तो उसे ऐसे मनुष्य को ढूँढना पड़ता था जिसके पास वह चीज हो जिसकी सुमेर को आवश्यकता है। इतना ही नहीं, उस मनुष्य को ऐसी वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिये जो सुमेर के पास है। इसके अलावा यह भी भगड़ा रहता कि हर एक अपनी चीजें बदलने को तैयार हो। मान लो सुमेर को एक कम्बल की जरूरत थी और कुवेर जिसके पास कम्बल है सुमेर का गर्म कोट लेना चाहता है। परन्तु सुमेर कोट देने को राजी नहीं हो तो अदला-बदली होना असम्भव है। जब से रुपये-पैसे का उपयोग होने लगा तब से ये सब बाधाएँ हट गईं। यदि तुम अपना सेर भर धी बेचकर चार सेर शक्कर खरीदना चाहते हो, तो केवल इस बात की जरूरत है कि तुम किसी के हाथ अपने धी को पाँच रुपयों में बेच दो और उन रुपये की जाकर शक्कर खरीद लो। ऐसी हालत में सेर भर धी का मूल्य हुआ पाँच रुपये और सेर भर शक्कर के एक रुपया चार आने। जब किसी वस्तु की इकाई का मूल्य इस प्रकार रुपये-पैसों में लगाया जाता है, तो वह मूल्य वस्तु की इकाई की कीमत कहलाता है। यदि हम एक गाय साठ रुपये में बेचते हैं तो गाय की कीमत हुई साठ रुपया। यदि हम उसको तीन बकरियों के एवज में बेचते हैं तो तीनों बकरियाँ कीमत न कहला कर गाय का मूल्य कहलाती हैं। मोटी बात यह है किसी चीज के बदले में जो चीज मिले वह उसका मूल्य है और उसकी इकाई के बदले में जो रुपया मिला वह उसकी कीमत है।

### आय (Income)

अब तक हम और किसी वस्तु की उपयोगिता, मूल्य और कीमत के बारे में बातें कर रहे थे। मान लो मुरली अनाज की दुकान रखता है। वह हर

समय रुपये के बदले गेहूँ, चना, मटर, जौ, बाजरा, मूँग, चावल आदि अन्न बेचा करता है। बेचने से जो रुपए आते हैं उन्हें वह एक कापी पर लिखता जाता है। महीने के आखीर में जोड़ लगाने से उसे मालूम पड़ जाता है कि महीने भर में उसे कितने रुपये मिले। इस आमदनी के योग से यदि हम वह रकम निकाल दें जिसका कि मुरली ने अनाज खरीदा था तो बची हुई रकम मुरली की आय कहलायेगी। इसी प्रकार क्लर्क साहब महीने भर काम करने के बाद पहली तारीख को अपना वेतन लेकर घर जाते हैं। परन्तु यह वेतन है क्या ? यह है क्लर्क साहब की महीने भर के काम की कीमत और अर्थशास्त्र में ऐसी कीमत को आय कहते हैं। मजदूरों को अपनी मजदूरी रोजाना, हर हफ्ते, पन्द्रहवें दिन अथवा महीने पर मिलती है। महीने भर में उन्हें कुल जितना रुपया मिलता है वही उनकी माहवारी आय होती है। आय रोजाना से लेकर सालाना तक हो सकती है। अर्थशास्त्र में आय से उस रकम का बोध होता है जो कोई मनुष्य किसी निश्चित समय में कमाता है। समय के किस परिमाण की आय निकाली जाय यह आय निकालने वाले की इच्छा पर निर्भर रहता है। अधिकतर आय से लोगों का मतलब माहवारी आय से रहता है। किन्तु कहीं कहीं सालाना आय की रिपोर्ट करनी पड़ती है। तुम्हें मालूम है कि भारत की सरकार तुम्हारी आय के ऊपर आयकर या इन्कमटैक्स लगाती है। इस आय के निकालने में मकान के किराये और बैंक में जमा सूद से लेकर कारबार का मुनाफा तक इसमें जोड़ लिये जाते हैं ?

### अभ्यास के प्रश्न

- १—‘विनिमय साध्य’ वस्तु किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित समझाइये। क्या जान विनिमय साध्य है ?
- २—निम्नलिखित वस्तुएँ किन दशाओं में धन समझी जावेगी ? गंगा-जल, यजमानी, रेल का टिकट, घर का कूड़ा-कचरा, कागजी मुद्रा, नोट, मनुष्य का शरीर, अस्पताल, सार्वजनिक पुस्तकालय।
- ३—कुछ ऐसी वस्तुओं का उदाहरण दीजिये जिनकी उपयोगिता किसी वस्तु के लिए समय के साथ बदलती जाती है।
- ४—अग्रलिखित वाक्यों की गलतियों को दुरुस्त कीजिए :—

- ( अ ) २० सेर गेहूँ की कीमत ८) है ।  
 ( ब ) पाँच सेर चावल की कीमत दस सेर गेहूँ है ।  
 ( स ) ५ गायों की कीमत १२५ रुपया है ।  
 ( ड ) एक सेर चना का मूल्य ६ आने है ।  
 ( क ) एक गज कपड़े का मूल्य बारह आना है ।

५—अपने कुटुम्ब की आमदनी का एक मास का हिसाब लिखिए और यह बतलाइए कि किन-किन जरियों से कितनी आमदनी प्राप्त हुई ।

६—यदि कोई मनुष्य अपने निजी मकान में रहता है तो उसको अपने मकान से वर्ष भर में क्या आमदनी होती है ?

७—आर्थिक उन्नति के क्या साधन हैं ? गरीब लोग अधिक सुखी कैसे हो सकते हैं ?

८—धनी लोग भी कभी दुखी पाए जाते हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

९—सादे जीवन का सुख की वृद्धि से क्या सम्बन्ध है ?

१०—सम्पत्ति या धन किसे कहते हैं ? विस्तार सहित लिखिए ।

## तीसरा अध्याय

### उत्पत्ति (Production)

#### उपयोगिता वृद्धि (Increase in Utility)

प्रत्येक मनुष्य को भोजन, कपड़ा आदि को जरूरत पड़ता है । इनके बिना उसका काम ही नहीं चल सकता । अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे तरह-तरह की वस्तुओं को बनाना या तैयार करना पड़ता है । मिल-जुल कर रहने वाले किसी भी मनुष्य को देख लो । वह हर समय इस बात का उपाय करता है कि उसे किसी प्रकार धन मिले । धन की उत्पत्ति करने के लिये आदमी दिन भर मेहनत करके जंगल से लकड़ी या घास काट कर लाता है, दूसरा किसी के यहाँ नौकरा करता है, तीसरा दूकानदार है तो चौथा डाक्टर । यह तो हम आपको पहले ही अध्याय में बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र में उत्पत्ति का क्या मतलब होता है और यह भी कह चुके हैं कि उत्पत्ति किस प्रकार की जा सकती है । कोई वस्तु उत्पन्न करने के मतलब होते हैं किसी प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाना । कुम्हार मिट्टी से बर्तन



बनाकर मिट्टी की उपयोगिता में वृद्धि करता है। बढई लकड़ी को काट-छाँट कर मेज-कुर्सी बनाता है। ऐसा करने से लकड़ी की उपयोगिता और बढ जाती है। इसी प्रकार के रूप-परिवर्तन द्वारा चना, मटर, गेहूँ आदि अनाज खेती से पैदा किये जाते हैं। खेती-बारी में अन्न पैदा करने का काम तो स्वयं प्रकृति करती है। मनुष्य तो केवल बीज, खाद, पानी आदि का प्रबन्ध करता है। परन्तु स्थान और अधिकार बदल देने से भी किसी की उपयोगिता बढाई जा सकती है। जहाँ जो सामान अधिक मात्रा में होता है वहाँ से जब उन्हें उन जगहों में ले जाया जाता है जहाँ उस सामान की मात्रा कम है, तो उसकी उपयोगिता बढ जाती है। लोहे, कोयले या पत्थर की अपने खान के पास या लकड़ियों की जंगल में उपयोगिता बहुत कम होती है। जब ये हाँ चीजे रेल या मोटर द्वारा बाजार में पहुँचा दी जाती हैं तो इनकी उपयोगिता बढ जाती है। इसी प्रकार अन्न, शाक, फलों को खेतों या बागों से बाजार में पहुँचा कर उनकी उपयोगिता बढाई जा रही है। जब हम किसानों से अनाज माल लेकर बाजार में किसी घर-गृहस्थी वाले आदमी के हाथ उसे बेच देते हैं तब भा उपयोगिता बढती है। क्योंकि किसान के अधिकार में तो इतना अनाज है कि उसके लिये उनकी उपयोगिता कम है लेकिन घर-गृहस्थी वाला आदमी खाने के लिये अनाज चाहता है और इसलिए उसके अधिकार में पहुँच जाने से अन्न अधिक उपयोगी बन जाता है। उसकी उपयोगिता बढ जाती है। उपयोगिता वृद्धि में समय भी सहायता करता है। नये चावल की प्रायः बहुत कम कदर होती है। यदि नया चावल साल दो साल रख छोड़ा जाय तो उसमें कुछ खास गुण आ जाता है और उसकी कदर या उपयोगिता बढ जाती है। इसी तरह घूम-माघ में बरफ को कोई नहीं पूछेगा। उसे किसी तरह गर्मियों तक रख सके तो उसकी बड़ी कदर होगा। मई-जून में गेहूँ का भाव बढ जाता है और बरसात में सूखी लकड़ी तेज विकती है। बिजापन के कारण भी वस्तु की उपयोगिता अधिक व्यक्तियों को महसूस होती है। अतः माँग घातो है। तब वस्तु दूर-दूर से बिक्री के लिये मँगाई जाती है। इस प्रकार हम वस्तु के स्थान और अधिकार परिवर्तन में याग देकर उसे बढा देते हैं।

इसके पहले कि हम इन शक्तियों पर विचार करें, हमें यह देख लेना चाहिए कि कुछ चुने हुये उदाहरणों में ऊपरोक्त शक्तियाँ किस प्रकार भाग लेती हैं ।

पहले रूप-परिवर्तन द्वारा होने वाली उपयोगिता वृद्धि (Increased utility) के साधनों को ही लीजिये; इस रीति से कच्चा माल पैदा किया जाता है । कच्चा माल बहुधा खेती से होता है । हमारे भारत में ज्यादातर लोग खेती करके ही अपना पेट पालते हैं । अच्छा, इनमें ऊपर बताए साधन या शक्तियाँ किस प्रकार काम आती हैं ? बिना भूमि के खेती नहीं हो सकती, और मेहनत करने वाले मनुष्य बिना खेती करेगा ही कौन ? किंतु जमीन और मनुष्य के होने से भा तो खेती नहीं हो सकती । उसके लिये बीज, हल, बैल, खाद आदि की भा आवश्यकता होती है । ये चीजें मनुष्य के धन हैं; परन्तु ज्यादा धन उत्पन्न करने के लिए काम में आने के कारण इनका नाम पूँजी हो जाता है । इससे साफ प्रकट है कि खेती करने के लिए भूमि, श्रम और पूँजा की आवश्यकता होती है ।

अब कारीगरी का एक उदाहरण लीजिये । तैयार माल भी रूप परिवर्तन द्वारा ही बनाया जाता है । दर्जों का काम लीजिए । वह कपड़े को काट-छाँट करके कपड़े सीता है । इसमें उसे सीने के लिए बैठने को स्थान (द्रुकान या मकान) चाहिये, यह भूमि है । उस पर बैठ कर वह मिलाई का काम करता है, इसमें उसे श्रम करना होता है । फिर उसे कपड़ा, सुई, डोरा आदि चाहिए, तभी तो वह कोट तैयार कर सकेगा । ये चीजें वह पहले कमाए हुये धन में बचत करके बचाता है और ये उसकी पूँजी हैं । इसी तरह से बटुई,

बनाकर मिट्टी आदि के कार्य पर विचार किया जा सकता है। अतएव तैयार छाँट कर सेज, श्रम और पूँजी तीनों की आवश्यकता पड़ती है।

बढ़ जाती है। हमने प्रबन्ध और साहस (Enterprise) का विचार नहीं आना देखा। आजकल के मशीन युग में अकेला-दुकेला आदमी धन पैदा करने तो स्वयंम नहीं करता। सैकड़ों हजारों आदमी एक ही कारखाने में काम करते प्रबन्ध आते हैं। ऐसी हालत में इस बात की बड़ी जरूरत होती है कि कोई कीर्पादमी इन हजारों आदमियों के काम की देख-रेख करे और यह निश्चय करे कि कितने आदमी कौन-सा काम करे, किस प्रकार की भूमि, श्रम और पूँजी लगाई जाय और कहाँ से कच्चा माल मँगाया जाय इत्यादि। इन सब बातों के लिये प्रबन्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार आजकल अमेरिका आदि देशों में खूब बड़े-बड़े खेतों में खेती की जाती है। यहाँ पर भी यह देखना पड़ता है कि खाद कहाँ से मँगाई जाय। कितनी खाद की जरूरत है। पानी का कैसा प्रबन्ध किया जाय इत्यादि।

इसके अलावा एक ऐसे व्यक्ति-समूह की जरूरत पड़ती है जो कारखाने में होने वाले या बड़े परिमाण से की जाने वाली खेती से आने वाले लाभ-हानि को सहने का बीड़ा उठाये। मजदूर अपना वेतन ले लेते हैं। प्रबन्ध करने वाला भी अपनी तनखाह लेता है। भूमि का मालिक केवल लगान मात्र चाहता है और पूँजी देने वाला सूद। इनमें से किसी को हानि-लाभ से कोई मतलब नहीं रहता। कारखाने के चलने या डूबने की जोखिम उस आदमी या कम्पनी पर रहती है जो उसके चलाने का साहस करती है तथा जोखिम उठाती है।

## भूमि (Land)

यह तो हमने देख लिया कि उत्पत्ति के पाँच साधन होते हैं—भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध और साहस। अब इन पाँचों पर अलग-अलग विचार करना भी जरूरी है। पहले भूमि को लीजिए। आमतौर पर इससे पृथ्वी तल का तलव निकाला जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र में भूमि से हमारा मतलब उन वस्तुओं से रहता है जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इस तरह से खान से निकाले जाने वाले पत्थर, लोहा, सोना आदि, जल, मछली, मोती, वायु, सर्प

गर्मी, रोशनी, जलवायु आदि सब चीजें हमके अन्तर्गत आ जाती हैं। याद रखने के योग्य दूसरी बात यह है कि प्रकृति का वही हिस्सा भूमि कहलाता है जिसका उत्पत्ति में प्रयोग होता है।

### भूमि के गुण

भूमि अपरिमित मात्रा में बढ़ाई-घटाई नहीं जा सकती है। बम्बई जाते समय थोड़ा सा समुद्र का भाग आता है। आज समुद्र के स्थान पर वहाँ धीरे-धीरे सूखी जमीन बढ़ रही है। इस प्रकार तो भूमि बढ़ाई जा सकती है। अन्यथा यदि हम चाहे कि आज संसार में जितनी भूमि में खेती होती है वह दुगुनी हो जाय तो यह असम्भव है। इसी प्रकार हम बलुही जमीन को गेहूँ की खेती के योग्य नहीं बना सकते। कहा जाता है कि तिब्बत के लामा मन-चाहा पानी बरसा सकते हैं और पश्चिमी देशों में भी विज्ञान के आधार पर ऐसे प्रयोग हुए हैं परन्तु आमतौर पर हम और आप पानी नहीं बरसा सकते।

सब भूमि एक समान भी नहीं होती। कोई जमीन बहुत उपजाऊ होती है, कोई कम और कोई बिल्कुल ही नहीं। किसी जमीन की मिट्टी चिकनी होती है किसी की बलुही। शहर के बाहर की जमीन खेती के योग्य होती है, परन्तु शहरों में जो जमीन पड़ी होती है वह अधिकतर पार्क, स्कूल, मकान या कारखाने के काम आती है। परन्तु यह तो हुआ आम भाषा में जमीन कही जाने वाली भूमि की बात। कोई भूमि जमीन है, कोई लोहा, कोई कोयला, कोई पानी और कोई प्रकाश। इसी से स्पष्ट है कि सब जमीन एक सी नहीं होती।

भूमि की उपजाऊ शक्ति की सीमा होती है—यदि हम खाद दिए बिना खेती करते चले जाएँ तो वह क्रमशः कम उपजाऊ हो जाएगी। यदि हम खेत को गहरा खोदें और खाद डालें तब भी हम खेत की उपज को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकते। यदि फी एकड़ दस मन गेहूँ होता है तो पचास मन का क्या कहना बीस मन गेहूँ पैदा करना आपके लिए एक समस्या हो जाएगी।

भूमि उत्पत्ति में स्वयं भाग नहीं लेती। खेत पड़ा रहता है। खान में कोयला पड़ा रहता है। सूर्य का प्रकाश संसार भर में बिखरा रहता है। किसान खेत से अनाज पैदा कर लेता है। मजदूर खान से कोयला निकाल

लेते हैं। धोवी धूस में कपड़ा सुखा लेता है। अंगूर पैदा करने वाला उसे सुखा कर किशमिश बना लेता है।

जब मनुष्य प्रकृति की देन पर अपना कब्जा कर लेता है तब वह दूसरों से उस कब्जे के कारण दाम माँगता है। दर असल वह दाम उसके कब्जे के होते हैं न कि उसकी भूमि के। परन्तु आमतौर पर हम कहते हैं कि भूमि का दाम यह है और खेत का लगान यह है। ऐसी कोमत भूमि की स्थिति तथा उपयोगिता पर निर्भर है।

विभिन्न कामों के लिए भूमि-सम्बन्धी विभिन्न विचार उठते हैं। खेती में भूमि के उपजाऊपन का ध्यान रहता है। किस खेत में क्या वस्तु अधिक उत्पन्न होगी। परन्तु व्यापार और कारखानों के काम में भूमि की उपजाऊ शक्ति का ख्याल नहीं किया जाता। कारीगर या कारखाने का मालिक यह देखता है कि जमीन किस जगह है। कारीगर अपनी दुकान बाजार के करीब खोलना चाहता है। मिल मालिक कारखाने को ऐसे स्थान पर चलावेगा जहाँ से खान और बाजार दोनों पास हों। मान लो तुम लोहे का कारखाना खोलना चाहते हो। तुम ऐसी जगह ढूँढ़ोगे जहाँ से लोहे की खान भी पास हो और तैयार माल को बाजार में पहुँचाने का सुभीता भी हो। इन्हीं कारणों से बड़े-बड़े शहरों में भूमि का मूल्य या किराया बहुत अधिक होता है।

### श्रम ( Labour )

यह तो हुई भूमि की बात। अब श्रम को लीजिये। किसान खेती करने में स्वयं भी मेहनत करता है और बैल से भी काम लेता है। किन्तु अर्थशास्त्र के अन्तर्गत बैल के कार्य को श्रम में नहीं गिनते। श्रम से हमारा मतलब मनुष्य द्वारा की हुई मेहनत से रहता है। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए फुटबाल, हाकी वगैरह खेल खेलता है। ऐसे खेलों में की गई मेहनत किसी प्रकार का वन नहीं पैदा करती। अतएव इसकी गिनती भा श्रम में नहीं की जाती। अब आपसे कोई पूछे कि श्रम से क्या समझने हो तो आपको कहना चाहिये कि श्रम से हमारा मतलब मनुष्य द्वारा की गई उस मेहनत से रहता है जो धन की उत्पत्ति में लगाई जाती है।

## श्रम के भाग (Division of Labour)

श्रम दो तरह के होते हैं :—शारीरिक व मानसिक। कुली, मजदूर, लोहार, बढ़ई आदि शारीरिक श्रम करते हैं; किन्तु डाक्टर, वकील, जज, मास्टर आदि मानसिक श्रम करते हैं। कुछ लोग दोनों तरह के श्रम करते हैं, परन्तु अर्थशास्त्र में श्रम के इस भेद को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। यदि कोई भेद माना जाता है तो वह उत्पादक और अनुत्पादक श्रम के बीच में होता है। मनुष्य किसी इच्छा की पूर्ति के लिए जो मेहनत करना है वह उत्पादक कहलाती है। उत्पादक और अनुत्पादक मेहनत को स्पष्ट करने के लिए मान लाजिये कि कोई आदमी बिना मतलब ही एक स्थान से मिट्टी खोदकर दूसरे स्थान पर जमा करता है, ऐसा श्रम अनुत्पादक कहलायेगा। हाँ, यदि पहले स्थान पर मिट्टी का ऊँचा ढेर लगा हो और दूसरे पर गड्ढा हो तो वह श्रम उत्पादक गिना जायगा क्योंकि ऐसा काम करने से गड्ढा पट गया और किसी के उसमें गिर जाने का डर जाता रहा। अस्तु, उत्पादक श्रम के दो भाग किये जाते हैं। बढ़ई लकड़ी से हल बनाता है, किसान खेत में अनाज पैदा करता है और लोहार लोहे से चाकू बनाता है। इस प्रकार का श्रम प्रत्यक्ष उत्पादक श्रम कहलाता है। किन्तु जगलों से लकड़ी लाने में जो श्रम पड़ता है, पंडितजी चेलों को पढ़ाने में मेहनत जो करते हैं अथवा परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने के हेतु जो विद्याध्ययन तथा परिश्रम करना पड़ता है वह परोक्ष उत्पादक कहलाता है क्योंकि उससे किसी वस्तु विशेष की उत्पत्ति नहीं होती।

हमारे देश की गरीबी देखते हुये श्रम का एक अन्य वर्गीकरण हो सकता है—कुशल श्रम तथा अकुशल श्रम। आजकल वायुयान, रेल तथा मोटर चलाने में तथा उन्हें बनाने के लिए, बड़ी-बड़ी इमारतें और पुलों के निर्माण में, बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाने और उनकी मरम्मत करने के लिये ट्रेनिंग प्राप्त अर्थात् कुशल श्रमिक चाहिये। भारत में इनकी कमी है। इसके विपरीत ईंट, गारा या ब्रोम्ड ढाने, ठेला खींचने, फावड़ा चलाने आदि कामों को कोई भी अर्थात् अकुशल श्रमिक कर सकता है। कुशल श्रमिकों की कमी के कारण देश की उन्नति रुक जाती है।

## श्रम की उपयोगिता ( Utility of Labour )

जिस प्रकार सब भूमि एक-सी उत्पादक नहीं होती उमी तरह सब श्रम एक-से उत्पादक नहीं होते । श्रम की उत्पादकता कई बातों के ऊपर निर्भर रहती है । मेहनत करने वाले यदि मजबूत, शिक्षित और ट्रेनिंग पाए हुये हैं तो उनकी उत्पादक शक्ति अधिक होगी । कार्यक्षमता आदमी को मिलने वाले खाने, उसके रहने के स्थान की आवहवा आदि बातों से सम्बन्ध रखती है, इसके अलावा यदि मजदूर गुलाम की तरह काम करते हैं तो उनका श्रम कम उत्पादक हो जाता है । इसलिए कारखानों में अच्छे कारीगरों और मजदूरों को हिस्सेदार बना लेते हैं । इसी प्रकार खेती में हिस्सेदार होते हैं । अर्थात् खेत में काम करने वालों का हिस्सा बँध जाता है । इससे काम करने वाले मन लगाकर काम करते हैं, और अधिक से अधिक माल उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं । चतुरता और बुद्धिमानी भी श्रम को और उत्पादक बनाती है । एक मामूली बढई जिस लकड़ी से एक भद्दा-सा बक्स बनाकर तीन चार रुपये को बेचता है, एक चतुर बढई उसी से एक अच्छी आलमारी बनाकर बेचने से दस पन्द्रह रुपये प्राप्त कर लेता है । जो श्रमजीवी बुद्धिमान् नहीं हैं, जिन्हें इस बात का पता नहीं है कि किस प्रकार सम्पत्ति की वृद्धि करनी चाहिये, उनका श्रम बहुत कम उत्पादक होता है ।

## श्रम विभाग ( Division of Labour )

उत्पादक के सम्बन्ध में श्रम की एक और बात जानने योग्य है । पुराने जमाने में आदमी अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वयं ही सब काम करता था । वही झोपड़ा बनाता, वही मछली मारता, वही तीर और धनुष बनाता और पहनने के लिए जानवरों को मार कर उनकी खाल खींचता । लेकिन समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य ने परिवार बसा लिया और कई परिवार मिलकर गाँवों में रहने लगे । इसके साथ ही इस बात का खयाल हुआ कि यदि एक आदमी एक ही काम करे तो और भी अच्छा हो । अतएव एक आदमी केवल अन्न पैदा करता है, एक केवल कपड़ा तैयार करता है, इत्यादि । इस प्रकार गाँव के किसान, लकड़हारे जुलाहे आदि का काम अलग-अलग हो जाता है । जैसे-जैसे उन्नति हुई एक पेशे के कई-कई भाग होने लगे । कपड़ा तैयार करने के लिए एक

आदमी केवल कपाम पैदा करना है, दूसरा कपाम को ओटता है अर्थात् रुई से विनौले अलग करता है, तीसरा सत को कातता है और चौथा केवल कपड़ा बुनता है। इसके बाद इन भागों के भी भाग किये जाते हैं। इस प्रकार से होने वाले श्रम के बँटवारे को श्रम-विभाग कहते हैं।

श्रम-विभाग से बहुत लाभ हैं। पहले तो कोई आदमी बड़ी जल्दी किसी विभाग का काम सीख सकता है। इसके अलावा श्रम-विभाग के अन्तर्गत एक ही काम करते रहने से आदमी खूब होशियार हो जाता है। फिर प्रत्येक विभाग में की जाने वाली क्रियाएँ इतनी सरल हो जाती हैं कि उनके करने के लिये मशीन का भली-भाँति प्रयोग किया जा सकता है। इन सब का परिणाम यह होता है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति करने में व्यय कम पड़ने लगता है।

श्रम-विभाग से कुछ हानि भी है। एक ही काम करते-करते वह काम नीरस सा लगने लगता है। उस काम के करने में फिर मन नहीं लगता। यही नहीं, यदि वह चाहे कि और किसी दूसरे पेशे को स्वीकार कर ले तो वह ऐसा नहीं कर सकता। तीसरे, इसके कारण उसे अपने शरीर के किसी एक अंग का ही अधिक उपयोग करना पड़ता है। फलतः उसका स्वास्थ्य गिर जाता है। कुछ भी हो, श्रम-विभाग के कारण श्रमी भारी और दुःखदायक कामों के करने से बच जाते हैं और उन्हें अब सप्ताह में केवल ४५-६० घंटे तक काम करना पड़ता है। बाकी समय वे अपनी शिक्षा, मनोरंजन और उन्नति के लिये लगा सकते हैं। इसी प्रकार यदि भागीय मजदूरों को भी शिक्षा व ट्रेनिंग मिले, उन्हें उचित मजदूरी दी जाय, नियत समय तक काम लिया जाय, उनके मनोरंजन और सुख-सुविधा की व्यवस्था की जाय तो वे भी अधिक क्षमतावान बन सकते हैं।



खर्च करता है, लेकिन काम नहीं करता, तो उसका अनाज रूमी धन पूँजी नहीं कहा जा सकता। यदि वह खाने के साथ खेती भी करता जाता है तो जो अन्न वह खाता है वह पूँजी स्वयं है। खेत में बीज बोने के दिन से लेकर और जब तक अनाज काटकर किसान के घर में आता है, इन बीच में कई महीने गुजर जाते हैं। तब तक किसान को खाने-पीने की चाहिये। मजदूरी चाहिये, हल, बैल आदि चाहिये। पहनने की कपड़े, रहने की घर तथा औजार आदि भी चाहिये। ये सब चीजें पहले से ही इकट्ठी करनी पड़ती हैं। इनमें अन्न-वस्त्र, बैल-बधिया, हल-फाल, घर-द्वार सब कुछ आ गया और इन सबकी गिनती पूँजी में करनी चाहिये।

### पूँजी की विशेषताएँ

बिना बचत के पूँजी नहीं हो सकती। किसान अपनी कमाई का कुछ भाग अलग निकालेगा तभी तो वह औजार मोल लेगा। कारखाने का मालिक लाभ का एक अंश अलग करेगा तभी तो वह नई मशीनें खरीदेगा।

पूँजी की दूसरी विशेषता यह है कि भौतिक पूँजी स्थायी नहीं होती। मशीन, औजार, हल आदि वस्तुएँ काम में आते-आते धिस जाती हैं और बेकार हो जाती हैं।

### पूँजी के भेद

आमतौर पर पूँजी के दो भेद करते हैं :—अचल पूँजी और चल पूँजी। किसान बार-बार उन्हीं बैलों, हल, फावड़ा, तथा कुदाली से काम लेता है। जुलाहा उमी करवे पर वर्षों कपड़ा बुनता है। मिल में उन्हीं मशानों से बीस पच्चीस साल तक काम लिया जाता है। यह सब बहुत समय तक काम आने वाली पूँजी के उदाहरण हैं और इनका नाम अचल पूँजी है।

इसके विपरीत जो पूँजी केवल एक बार के प्रयोग से खतम हो जाती है उसे अचल पूँजी कहते हैं। उदाहरणार्थ, खेती में बीज तथा जल, बढई की लकड़ी, मिलों का कच्चा माल आदि।

पूँजी की उत्पादकता उसके उपयोग करने के ढंग पर निर्भर रहती है। यदि बुद्धिमानी के साथ पूँजी लगाई जाती है तो अधिक सम्पत्ति पैदा होती है अन्यथा कम। यदि कोई जमान बलुई है तो उसमें आप चाहे जितनी डालिये और चाहे जितना पानी दीजिये, गेहूँ की पैदावार कभी अच्छी

न होगी। और आपने जो पूँजी उसमें लगाई है उसका आपको पूरा-पूरा बदला नहीं मिलेगा। परन्तु उसी पूँजी को यदि आप किसी उपजाऊ जमीन में लगाते तो उसकी उत्पादक शक्ति अवश्य बढ़ जाती। कहने का मतलब यह है कि खेती या व्यापार में जो पूँजी लगाई जाती है, उसके लगाने में यदि बुद्धिमानी, तजुबे और दूरन्देशी से काम लिया जाता है तो पूँजी की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है।

### प्रबन्ध (Management)

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आजकल के जमाने में भूमि, श्रम और पूँजी के ऊपर प्रबन्ध करने वाले का हाथ रहता है। प्रबन्ध के कार्य और श्रम में अन्तर है। श्रमी अधिकतर शारीरिक मेहनत करता है और प्रबन्धक को दिमाग से ज्यादा काम लेना पड़ता है। प्रबन्धक उत्पत्ति के लिये सबसे उन्मुख भूमि की खोज कर उस पर आवश्यक योग्यता वाले मजदूरों को श्रम-विभाजन के नियमों के अनुसार लगाता है। उसे नए-नए लाभदायक औजारों को इकट्ठा करना पड़ता है। वह समय के हिसाब से कच्चे माल को सस्ते से सस्ते दामों में खरीदता है। बाजार में लोग की बचि के मुताबिक माल बनवा कर वह इस माल को अच्छे-अच्छे दामों में बेचता है। कहने का मतलब यह है कि प्रबन्धकर्त्ता लोगों की बचि का खयाल रखकर, भूमि, श्रम और पूँजी को इस हिसाब और रूर में लगाता है कि कम में कम लागत में अधिक में अधिक बस्तु तैयार हो जाती है और इसको वह अपने अधिक मुनाफे के हिसाब से बाजार में बेच देता है।

का प्रबन्ध करता है। प्रबन्धक का उद्देश्य रहना है कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ करते रहना। यदि किसी मशीन का प्रयोग करने से खर्च में कमी होती है तो वह मजदूरों का खयाल किये बिना ही मजदूरों को घटा कर उस मशीन को कारखाने में मँगावेगा।

### साहस या जोखिम (Enterprise)

मान लो उत्पत्ति के उपरोक्त चारों साधन मौजूद हैं परन्तु सबको इस बात का शक है कि कार्य शुरू कर देने के बाद उनका भूमि का लगान, श्रम की मजदूरी, पूँजी पर सूद व प्रबन्धक का वेतन मिलेगा या नहीं। ऐसी हालत में उस समय तक उत्पत्ति का कार्यशुरू ही नहीं हो सकता जब तक कोई व्यक्ति साहस न करले, सबको इस बात का विश्वास न दिला दे कि काम असफल हो जाने पर भी वह लगान, मजदूरी, वेतन, सूद आदि चुकता कर देगा। लेकिन खाली विश्वास वाला होने से काम नहीं चलता। विश्वास दिलाने वाले की हालत ऐसी होनी चाहिये जिससे सब लोग उसकी बातों का विश्वास कर लें। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि विश्वास दिलाने वाला साहसी मनुष्य धन तथा अपनी बात दोनों का धनी हो। इसके अलावा साहसी को बुद्धिमान तथा दक्ष होना चाहिये, जिससे वह योग्य सहायक व प्रबन्धक को ढूँढ सके। यह तो हुए साहसी के गुण। अब देखना चाहिये कि साहसी और उत्पत्ति में हाथ बटाने वाले अन्य व्यक्तियों में कोई भिन्नता है या नहीं। सबसे बड़ा फर्क यह है कि भूमि के मालिक का लगान, श्रमिक की मजदूरी, महाजन का सूद और प्रबन्धक का वेतन बँधा हुआ होता है लेकिन साहसी को आने वाली रकम में से यह सब काट कर जो बचता है उसी से सतोष करना पड़ता है। यदि कुछ कमी पड़ती है, तो उसे स्वयं अपनी गॉँठ से लगाना पड़ता है। यह सब ठीक है लेकिन तिस पर भी किसान मनुष्य या कम्पनी को साहसी का बीड़ा उठाना ही पड़ता है। क्योंकि बिना साहस के न कोई व्यापार चालू किया जा सकता है और न चालू व्यापार बढ़ाया ही जा सकता है।

### अभ्यास के प्रश्न

१—उदाहरणों सहित समझाइये कि स्थान-परिवर्तन से उपयोगिता की किस प्रकार होती है ?

२—दूकानदार और व्यापारी वस्तुओं की उपयोगिता वृद्धि किस प्रकार करते हैं ?

३—समय परिवर्तन से उपयोगिता वृद्धि के उदाहरण दीजिये ।

४—क्या किसी वस्तु के विज्ञापन से भी उपयोगिता-वृद्धि होती है ?

५—क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसके अधिक उपयोग करने से उसकी उपयोगिता-वृद्धि होती है ?

६—यह समझाइये कि निम्नलिखित व्यवसायों में उत्पत्ति के साधनों का किस प्रकार उपयोग किया गया है :—

हलवाई की दूकान, कपड़े की दूकान, सूत कातना, कपड़े बुनना, गौशाला ।

७—श्रम और मनोरंजन का अन्तर समझाइये । यदि कोई व्यक्ति कविता करता है या गाता है तो उसका कविता करना या गाना श्रम कहलायेगा या मनोरंजन ?

८—उत्पादक और अनुत्पादक श्रम के भेद बतलाइये । यदि कोई विद्यार्थी परिश्रम करने पर भी अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसका श्रम उत्पादक कहलायेगा या अनुत्पादक ?

९—पडा, जमींदार, डाक्टर, पुरोहित, साधु, सिपाही इत्यादि के श्रम किन दशाओं में उत्पादक माने जा सकते हैं ?

१०—भारतीय मजदूरों की कार्य क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है ?

११—अर्थशास्त्र की दृष्टि से भूमि की विशेषताएँ तथा महत्व समझाइये ।

१२—क्या आपके गाँव में भूमि किमानों को काफी परिमाण में मिला जाती है ? यदि नहीं, तो कमी के प्रधान कारण क्या हैं ?

१३—चल और अचल पूँजी के भेद समझाइये । निम्नलिखित उद्योग-धन्यों की चल और अचल पूँजी लिखिये :—

गन्ने की खेती, कपास का कारखाना, मिठाई बनाना, खिलौना बनाना ।

१४—प्रचन्दक के कार्य का महत्व समझाइये । उनमें किन गुणों की आवश्यकता है ?

१५—भूमि ने अर्थशास्त्र में क्या अर्थ निभा जाता है ? उत्पत्ति में भूमि के महत्व को बतलाइये ।

१६—उत्पत्ति में जोखिम का क्या स्थान है ? निम्नलिखित व्यवसायों में जोखिम कौन उठाता है :—

बटाई पर की जाने वाली खेती, मिश्रित पूँजी वाला कम्पनी, कपड़े का कारखाना, चीनी का कारखाना ।

१७—उत्पत्ति के अर्थ समझाइये । उत्पत्ति के साधन बताइये । गाँव के उद्योग-धंधों में इन साधनों के महत्व की तुलना कीजिये ।

## चौथा अध्याय

### भारतीय गाँव की खास पैदावारें

#### भारतीय कृषि का महत्व

पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि उत्पत्ति करने में किन-किन शक्तियों से काम लेना पड़ता है । अब इन शक्तियों के सहयोग से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के बारे में कुछ जानना आवश्यक मालूम पड़ता है ।

भारत में अन्धसी प्रतिशत से अधिक लोग गाँव में रहते हैं । मत्तर प्रतिशत से अधिक लोग खेती द्वारा अपना पेट पालते हैं । अतः यह मानी बात है कि हमारे यहाँ गाँव और खेती मुख्य हैं । लेकिन सन् १९४७ से, जब कि देश का विभाजन हुआ था, खेती की समस्या अधिक महत्वपूर्ण बन गई है । हमारे देश में अन्न की कमी है । देश में कितना अन्न अथवा कोई भी कृषि पदार्थ कितना पैदा होता है, यह हम सही-मर्दी नहीं जानते । तब भी बहुत कुछ मालूम है । इससे हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमारे देश में अन्न, रुई और जूट की अति कमी है । अन्न की कमी के कारण किसान को जबरदस्ती अपना गल्ला सरकार के हाथ बेचना पड़ता है । इसी कारण शहरों में और कुछ देहातों में भी राशन पद्धति पर सरकार गलना देनी है । रुई की कमी के कारण कपड़ा भी एक प्रकार से राशन समान ही मिलता है । भोजन और वस्त्र की कमी का मूल कारण जब उपज की कमी है तब भारतीय की उन्नति अति आवश्यक है । अतः इसका ही पहले अध्ययन करना महत्वपूर्ण बन जाता है । भारतीय कृषि का अध्ययन कई प्रकार से

हो सकता है। हम पहले खेत की उपज की मोटी बात बतायेंगे, फिर एक जिले की उपज की और तब भारतीय उपज की।

यदि खेत की उपज के बारे में ही पहले कुछ विचारा जाय तो अनुचित न होगा। भारत में अधिकतर दो फसले होती हैं। एक खरीफ कहलाती है और दूसरी रबी। खरीफ की फसल जेठ मास से लेकर कार्तिक तक चलती है और बाकी छै महीनो में अर्थात् कार्तिक से वैसाख तक रबी की फसल होती है।

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में खरीफ की फसल बोने के पहले खेत में खाद डाल देते हैं। पानी बरसने के बाद खेत एक बार जोत दिया जाता है। खरीफ की फसल में यहाँ ज्वार, बाजरा, मक्का, सावाँ और कोदो, चावल, अरहर, मूँग, उरद, तिल व तिली बोई जाती है। मक्का और ज्वार के लिये खेत अक्सर दो बार जोते जाते हैं। बाजरे के लिये एक ही बार हल चलाने से काम निकल जाता है। ज्वार और मक्के को तो किसान कूँड़ी बनाकर बोते हैं। बाजरा, उरद और मूँग के बीज को बखेर कर बोते हैं। जब वर्षा नहीं होती तब खरीफ में एक-दो बार खेतों को सींचने की जरूरत पड़ती है और नहीं तो खरीफ की फसल के लिये सिचाई कोई खास जरूरी नहीं है। अरहर रबी की फसल के साथ वैसाख में काटा जाती है, बाकी सब चीजे भादों और कुआर में काट ली जाती है। रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, अलसी, सरसों, गन्ना और ऊख बोया जाता है। जिन खेतों में गेहूँ, जौ, सरसों इत्यादि चीजे बोई जाती हैं उनमें खरीफ की फसल नहीं पैदा की जाती बल्कि उन खेतों को एक बार जोत कर बरसात के पहले छोड़ देते हैं। बरसात में उनमें खूब पानी भरता है। गेहूँ वगैरह बोने के पहले फिर ये खेत दो-तीन बार जोत दिये जाते हैं। रबी में चना, मटर को तो बखेर कर बोते हैं बाकी सब अनाज कूँड़ी द्वारा बोये जाते हैं। रबी की सब फसले वैसाख के आखीर तक कट जाती हैं। अस्तु, इस प्रकार से इलाहाबाद जिले में पैदा होने वाले अन्नों में चावल, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, जौ, मकई मुख्य हैं। दालों में मूँग, उड़द, अरहर, मटर, मसूर आदि पैदा होती हैं। तेलहन की वस्तुओं में तिल, सरसों, या अलसी प्रधान हैं। इसके अलावा गन्ना और आलू को खेती होती है।

## भारतीय भूमि की पैदावार की कमी

इलाहाबाद जिले में जो उपज पैदा होती है, उनमें मेवा, मसाला, कपास, जूट, सन, चाय, तम्बाकू व पशुओं के चारे का नाम जोड़ दिया जाय तो भारत की सारी मुख्य उपज गिनती में आ जाती है। इन फसलों का विस्तृत वर्णन हमारी दूसरी पुस्तक “भारत का आर्थिक भूगोल” में किया गया है। मोटी तौर पर हम कह सकते हैं कि खेती से उत्पन्न पदार्थों की दृष्टि से भारत ससार भर में तीसरा गिना जाता है। ससार भर की सन की माँग का अधिकांश भारत ही पूरी करता है, लेकिन गेहूँ, कपास, चावल आदि की पैदावार में भी यह अच्छा स्थान रखता है। यहाँ के निवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सोचने से यहाँ की उपज कम मालूम पड़ती है। यही नहीं तुलना करने से पता चलता है कि प्रति एकड़ हम जितना गेहूँ, जौ, कपास, गन्ने आदि की उत्पत्ति करते हैं उतनी ही जमीन में उससे कई-कई गुना उपज अमेरिका और रूस वाले पैदा करते हैं। हमारे यहाँ फी एकड़ जितना गेहूँ पैदा होता है उसका चौगुना अमेरिका में और इससे भी अधिक रूस में पैदा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो मील-मील दो-दो मील के खेतों की खेती की जाती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ से आठ से दस गुना और बढ़िया गुन्ना जावा और हवाई द्वीप में उगाया जाता है। हमारे यहाँ की कई की खेती से भी अधिक माल अमेरिका वाले पैदा कर लेते हैं। चाहे जो उपज ले लीजिये हर एक में हम और देशों से पिछड़े हुये पाये जाते हैं।

### पैदावार की कमी के कारण

स्वभावतः प्रश्न उठता है कि आखिर किस कारण से भारत में और देशों की अपेक्षा उपज इतनी कम होती है। यह हम जानते हैं कि खेतों में उत्तम खाद देनी चाहिये; अच्छे बीज बोने चाहिये; उत्तम औजारों से खेत को जोतना-बोना-चाहिये तथा खेत की सिंचाई का पूरा प्रबन्ध रखना चाहिये। हमारे किसानों को पहले तो पर्याप्त खाद मिलती नहीं। यह आम रिवाज सा हो गया है कि गोबर की उपली पाय दी जाती है। ये कड़े ईंधन की जगह जलाने के काम में लाये जाते हैं। यदि इस उपली पायने की जगह खाद बनाई जाये तो बहुत अधिक फायदा

हो। इसके अलावा खाद डालने के पहले किसान खाद को खेतों में पहले से ढेरी लगा कर धूप में छोड़ देते हैं जिससे खाद का बहुत सा तत्व नष्ट हो जाता है। खाद के अलावा किसान जिन् बीजों को बोते हैं वे स्वस्थ और अच्छी हालत में नहीं होते। वैज्ञानिकों ने यह समझ लिया है कि दीर्घकाल की दृष्टि से प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, सनई की खाद, मलमूत्र की खाद अधिक उपयोगी है और कृत्रिम खाद अवाञ्छनीय होती है। फलस्वरूप उपज कम होती है।

किसान के पास बैल और औजारों की भी कमी है—बैल मरियल तथा रोगी होते हैं, उनसे खूब कसकर काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार कहीं भारी हलों से काम लिया जाता है तो कहीं हल्के हल से। इसके अलावा हल में खेत खोदने के लिये जो लोहे का फल लगा रहता है यह कहीं अधिक नुकीला होता है और कहीं साधारण। सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि हमारे हल ज्यादा गहराई तक नहीं खोद सकते और न मिट्टी को ही अच्छी तरह पलट सकते हैं, इसलिये जो पौधे उगते हैं उन्हें ऊपर की ही मतह से अपनी खुराक खींचनी पड़ती है। नीचे की जमीन ऐसी ही पड़ी रहती है। इससे भी पैदावार अच्छी नहीं होती है। यदि बढिया और उन्नत ढंग के हलों से काम लिया जाय तो खेत अधिक गहरे खोदे जा सकते हैं। ऐसा करने से नीचे की बढिया मिट्टी ऊपर आ जायगी और पैदावार अच्छी हो सकती है।

खेती करने के काम में सिंचाई का स्थान भी काफी ऊँचा है। लेकिन हमारे देश के कितने भागों में तो सिंचाई के पर्याप्त साधन ही नहीं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में नहरों का इन्तजाम है। नहरों से आबपाशी करने के लिए किसानों को खेत के हिसाब से दाम चुकाने पड़ते हैं। यहाँ पर पानी का बड़ा नुकसान होता है। पहले किसान खेतों में पानी पहुँचाने के लिए जो नालियाँ बनाते हैं वे इतनी बुरी हालत में होती हैं कि पानी फूट-फूट कर बाहर निकल जाता है। खेतों में क्यारियाँ नहीं बनाई जाती तथा सिंचाई टांक तरह से नहीं होती। चूँकि नहर ने आबपाशी करने की कीमत का पानी के परिमाण से कोई सम्बन्ध नहीं रखता इसलिए जरूरत से ज्यादा पानी खेतों में दिया जाता है जिससे खेतों का फसल का बड़ा धक्का पहुँचना है।



जिस प्रकार कम सिंचाई से उपज को धक्का पहुँचता है वैसे ही अधिक सिंचाई से भी उपज खराब हो जाती है। यदि उचित परिमाण में थोड़ी रूप सिंचाई की जाय तो फसल बहुत अच्छी होवे। और यह जरूरी है कि किसान इस बात का ज्ञान प्राप्त करे कि किस फसल के लिए कितने पानी की जरूरत है।

जिस तरह से मनुष्य बिना आराम किये लगातार काम नहीं कर सकता उसी प्रकार जमीनों से भी लगातार वैसी फसल नहीं पैदा की जा सकती। प्रायः जब एक फसल पैदा हो चुकती है तो जमीन में कुछ तत्वों की कमी पड़ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए समय की आवश्यकता होती है अर्थात् फौरन ही यह कमी ठीक नहीं की जा सकती। इसलिए कितने ही एक फसल के बाद उस खेत में कुछ नहीं बोते अर्थात् उसे परती छोड़ देते हैं। ऐसा करने से कुछ महीनों में जमीन उन पदार्थों को, जो उससे निकल जाते हैं, वायुमंडल द्वारा फिर से खींच कर जमा कर लेती है। यह कार्य तो ठीक है लेकिन इससे जमीन बेकार पड़ी रहती है। दूसरे भूमि को केवल परती छोड़ देने से ही खोये हुए सब तत्व वापस नहीं आ जाते। अगर खाद दी जाय तो इन तत्वों की उचित पूर्ति हो सकती है। खाद देने का उचित तरीका तो यह होगा कि परती छोड़ी हुई भूमि में बराबर दूरी पर फुट-छेद फुट गहरे गड्ढे खोद कर उनमें कूड़ा-ककट-गोबर भर-भर कर उन्हें ढक देवे। इससे साल भर में खाद बनकर जमीन में मिल जायगी। लेकिन अब तो विज्ञान के धुरन्धर विद्वानों ने यह हूँद निकाला है कि किस फसल के बाद कौन-कौन से तत्व नष्ट होते हैं। इसका सम्बन्ध फसलों के हेर-फेर से जोड़ा जा सकता है। प्रायः किसान फसलों को हेर-फेर से बोते हैं लेकिन वे उपरोक्त बताए सिद्धान्त को अच्छी तरह से नहीं समझते। किसी फसल के बाद जमान के सब तत्व तो निकल ही नहीं जाते और न हर एक फसल से वही तत्व नष्ट होते हैं। इसलिए अगर किसी फसल के बाद ऐसी फसल बोई जाय जिसमें उन्हीं तत्वों का जरूरत पड़े जो कि अभी जमान में मौजूद हैं तो बहुत अच्छा हो; चूँकि खोये हुए तत्व से अब हमारा कोई नहीं रहता इसलिये जमीन उनको अच्छी तरह से वायुमंडल के द्वारा सकती है। इससे तीसरी बार हम फिर से पहली फसल को बो सकेंगे।

उदाहरण के लिये मकई के बाद गेहूँ, ज्वार के बाद जौ, मसूर, मटर, गन्ना अलसी, कपास के बाद मकई बोई जा सकती है। गेहूँ के साथ-साथ दालें या तेलहन की वस्तुएँ बोई जा सकती हैं।

उपज में कमी होने का एक कारण यह भी है कि किसानों में शिक्षा का अभाव है। इसके अलावा वे निर्धन हैं। अतएव अच्छी बातों के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। पैसा हो तो भी क्या करे। बिना उपयुक्त शिक्षा पाये वह अच्छी तरह व्यय नहीं कर सकता। यदि किसान पढ़ा लिखा हो तो उसे वह भली भाँति समझाया जा सकता है कि कैसी खाद होनी चाहिये, कैसे फसलों के हेर-फेर से परती भूमि छोड़ने की आवश्यकता हटाई जा सकती है या अधिक पानी डालने से कौन से नुकसान होते हैं।

### खेतों का छोटे-छोटे और दूर-दूर होना

#### (Fragmentation of Land Holdings)

इन बुराइयों के अलावा एक और कमी है। भारत में बहुत से खेतों का क्षेत्रफल एक-एक दो-दो एकड़ भी नहीं है। कितने किसानों के खेत इससे भी छोटे होते हैं। किसी-किसी का क्षेत्रफल तो आधा ही एकड़ होता है अथवा इससे भी कम। इसके अलावा अनेक किसानों के पास बहुत से खेत होते हैं। लेकिन वह दूर-दूर होते हैं। इससे किसानों को बहुत शान्ति होती है। छोटे खेतों में अच्छे-अच्छे हलों और औजारों से काम नहीं लिया जा सकता है। हलों को खेत में घुमाने में ही बहुत सी भूमि बेकार चली जाती है। इन सब बातों से किसानों में लड़ाई-झगडा खूब होता है और प्रायः दिन अदालत के दर्शन किये जाते हैं। ऊपर हम बात का निष्कर्ष आया है कि खेतों का दूर-दूर होना बुरा है। खेतों के एक जगह न होने के कारण एक खेत से दूरे खेत में पानी ले जाने में बहुत सा समय व्यर्थ जाता है।

सब जगह पानी पहुँच जाय। खेतों के दूर रहने से एक ही कुआँ काम नहीं देता और दूर-दूर से पानी लाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। फिर यह सब को मालूम है कि जब फसल तैयार होने लगती है तो उसकी रखवाली की बड़ी जरूरत पड़ती है। यदि रखवाली न की जाय तो चिड़ियाँ, तोते, गाय, बकरी वगैरह पशु और पत्ती फसल को साफ कर दें। लेकिन अगर किसान का कोई खेत गाँव के इस कोने पर है और कोई उस कोने पर तो रखवाली ठीक तौर पर नहीं की जा सकती। खेती के एक जगह होने से एक ही आदमी ठीक खेत की देख-रेख कर सकता है और बहुत से रखवालों की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा पैदावार के मारे जाने का डर भी कम हो जाता है।

इसके अलावा खेत पास हों तो एक ही आदमी खेती के बहुत काम सँभाल लेवे। हरवाहे आदि काम करते रहते हैं, अकेला आदमी सब देख-भाल कर लेता है। दूर-दूर खेत होने से नौकर ठीक काम नहीं करते और अकेला आदमी सब जगह समय से ठीक देख नहीं पाता है। इससे खर्च भी अधिक हो जाता है और पैदावार को भी हानि होती है। फिर दूर-दूर की दौड़-धूप में शरीर को कष्ट होता है। एक जगह खेत होने से शरीर को भी आराम मिलता है। आदमी ही नहीं बैलों को भी आराम मिलता है तथा कटाई, ढोवाई इत्यादि में भी आसानी रहती है। और आपस में दूसरे किसानों से होने वाली लड़ाइयाँ भी कम हो जाती हैं।

ऊपर कही बुराइयों के कारण यह जरूरी है कि ये हानियाँ दूर की जायँ। इसका सीधा सा उपाय यह है कि हरेक गाँव में या कई गाँवों में मिलाकर सब खेतों का मूल्य अदाजा जाय और एक किसान के खेतों का जितना मूल्य हो उतने-उतने मूल्य के खेत एक स्थान में एक चक्र में कर दिये जायँ और भविष्य के लिये उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जाना बंद कर दिया जाय। जहाँ एक ही परिवार के दो-तीन आदमियों के पास कई छोटे-छोटे खेत हों वहाँ पर बेहतर होगा कि यदि उनमें समझौता करा कर वे खेत एक ही आदमी को दिलवा दिये जायँ। दूसरे आदमियों को उनके हिस्से का रुपया मिले। कई जगह ऐसा प्रयत्न सफलतापूर्वक किया जा चुका है और जगह भी ऐसा ही उपाय किया जा सकता है। सहकारी समितियों द्वारा

खेतों की चकवंदी कैसे की जा सकती है यह किसी अगले अध्याय में बतलाया जायगा ।

गाँवों में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास सब खेतों का क्षेत्रफल इतना कम है कि यदि वे चकवंदी द्वारा एक चक्र में भी कर दिये जावें तो भी खेती से हानि होना निश्चित है । जिन किसानों के पास तीन-चार एकड़ से कम क्षेत्रफल के खेत हैं उनको खेती से इतनी आमदनी नहीं हो सकती कि वे उससे अपने कुटुम्ब का जीवन-निर्वाह कर सकें । ऐसे किसानों की संख्या प्रत्येक गाँव में काफी अधिक रहती है । इनकी दशा तो तब सुधर सकती है जब गाँव के सब किसान मिलकर एक सहकारी समिति बना लें और सामूहिक रूप से खेती करें । इस प्रकार की सहकारी समिति में संगठन कैसे किया जा सकता है, यह किसी अगले अध्याय में बतलाया जायगा ।

### खेती में क्या करना पड़ता है ?

आप भारत के खेतों की खास फसलें, उनके कम होने के कारण और इन कारणों को दूर करने के उपाय तो जान गए । अब हम संक्षेप में यह भी बताना चाहते हैं कि आखिर खेती करने के लिए करना क्या-क्या पड़ता है अथवा भारत के किसान किम प्रकार खेती करते हैं । यह हम शुरू में ही बता चुके हैं कि भारत में अधिकतर दो फसलें होती हैं । एक खरीफ की फसल कहलाती है और दूसरी रबी की । पहली बरसान के शुरू से चलकर दिवाली तक जाती है और दूसरी दिवाली से होली तक में तैयार होती है । अस्तु, वर्षा आरम्भ होने से पहले किसान खेत में जगह-जगह ग्वाद की ढेरियाँ लगा देता है फिर जब पानी दो-तीन दिन बरस कर रुक जाता है

चार बार जोता जाता है। अन्य फसल बोने के पहले एक-दो बार जोतकर खेतों को छोड़ देते हैं। रबी की फसल में बीज बोने से पहले खेतों को दो तीन बार जोतना और उन पर पाटा चलाना पड़ता है। रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि चोजे बोई जाती हैं। बीज बोने के दो तरीके हैं। कुछ फसलों के बीज हाथ से खेत में छितरा कर फेंके जाते हैं जैसे बाजरा, उर्द, मूँग, चना, मटर आदि के बीज। मक्का, ज्वार, कपास आदि के बीज कूँड़ों के जरिये या नाली के जरिये बोये जाते हैं। कूँड़ की बोवाई में हल के द्वारा जो कूँड़ खुदता जाता है, उसमें एक आदमी दाना छोड़ता जाता है। नली की बोवाई में हल के पीछे एक लम्बा पनाली-दार वाँस बँधा रहता है। एक आदमी हल चलाता जाता है और दूसरा पोले वाँस में दाने छोड़ता चलता है। जिन खेतों की मिट्टी भुरभुरी होती है उसमें कूँड़ की बोवाई की जाती है। जिस जमीन में नीचे नमी और खुश्की होती है उसमें नाली की बोवाई होती है।

बोवाई के बाद सिंचाई की वारी आती है। अगर पौधों को पानी न मिले तो वे सूख जायँ और उमज मारी जाय। यों तो खरीफ को फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बोवाई के बाद कई महीने तक बरसात होती है। लेकिन जिस बार वर्षा नहीं होती उस बार खरीफ की फसल में और रबी की फसल में तो हमेशा ही सिंचाई करनी होती है। जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पर तो सिंचाई के लिये नहरें खोद दी गई हैं। लेकिन सब जगह तो नदियाँ होती नहीं। वहाँ पर अधिकतर कुओं से सिंचाई की जाती है। मोट द्वारा कुओं से पानी निकलते तो सब ने देखा होगा। इसमें चमड़े का बड़ा डोला होता है जो कुएँ में रस्सी बाँध कर डाला जाता है। इस मोट को कुएँ से खींचने का काम बैलों से लिया जाता है। एक आदमी बैलों को हाँकता हुआ दूर तक ले जाता है जिससे मोट ऊपर खिच आता है। एक दूसरा आदमी कुएँ पर रहता है जो मोट के ऊपर आ जाने पर उसमें से पानी उड़ेल लेता है। पानी नालियों के द्वारा खेत में पहुँच जाता है। जहाँ किसी तालाब से किमी ऊँचे पानी पहुँचाना होता है, वहाँ दो आदमी एक दौरी में पानी भर कर ले जाते हैं, कहीं-कहीं रहट से सिंचाई होती है। इसमें एक चरखी खम्भों की जगत पर लगाई जाती है। चरखी पर बँधी हुई एक रस्सी

में बहुत से डोल बँधे रहते हैं। एक डोल भर कर ऊपर आता है तो दूसरा कुँएँ में जाता है। इसमें एक ही आदमी बैल हाँकने को रहता है।

सिंचाई के अलावा किसान को खुर्रों से पौधों के आसपास उगने वाली घास को खोदकर फेंकना पड़ता है। इसको निराई कहते हैं। यदि ऐसा न किया जाय तो फसल के पौधों का खाना घास वगैरह बटा ले क्योंकि वह भी पौधों की तरह जमीन से खाना लेती हैं। बरसात में तो बड़ी जल्दी घास-फूस जम जाती है। इसलिये किसान दस-पन्द्रह दिन में निराई करता है। रबी की फसल में निराई की कम जरूरत पड़ती है।

जब फसल के खेत पक कर तैयार हो जाते हैं तो किसान हँसिया से काट कर गेहूँ, चना आदि को खलिहान में ले आता है। खलिहान उस लिपी-पुती जगह को कहते हैं जहाँ फसल साफ की जाती है। फसल के ऊपर बैल चला कर पहले पौधों को माँड़ा जाता है, जिससे भूसा और अनाज के दाने अलग हो जायें। माड़ने के पश्चात् हवा चलने पर उड़ोनी की जाती है। एक ऊँची तिपाई पर से दौरी में भर कर माँड़े हुये अनाज को नीचे गिराते हैं जिससे हल्का होने के कारण उड़ कर भुस दाने से अलग जा गिरती है। इसके बाद किसान अनाज और भुस को अपने घर टो ले जाता है।

### ग्रामीण उद्योग-धंधे

खेती के सम्बन्ध में हमने और सब बातों पर विचार कर लिया, परन्तु यह नहीं खयाल किया कि खेती करने में किसान बारहों महीने काम करता रहता है अथवा उसे कभी खाली भाँ बैठना पड़ता है। भारत में किसानों को आमतौर पर चार महीने से लेकर छे तक बेकार रहना पड़ता है। दूसरे महीने में तो उसका किसी तरह काम चल जाता है परन्तु बेकारी के समय के लिए वे कुछ बचाकर नहीं रख सकते। अतः उन्हें किसी ऐसे उद्योग-धंधे की आवश्यकता रहती है जो या तो खेती करने में सहायता पहुँचायें अथवा जो खेती पर निर्भर हों। उद्योग-धंधे न तो ऐसे होने चाहिये कि उन्हें छोट देने पर उनमें लगी हुई पूँजी जकटी पड़ा रहे और न ऐसे हों जिनमें किसी प्रकार की विशेष शिक्षा का ज़रूरत पड़े। उद्योग-धंधे ऐसे होने चाहिये जो मौक़े-मौक़े पर चालू किये जा सकें, जैसे चर्या काटना, लकड़ी व मिट्टी के ग्विलौन बनाना, तार के पिंजड़े बनाना, साबुन बनाना, हाथ का कागज बनाना,

चावल कूटना, गुड़ बनाना, दाल-दलना इत्यादि : इस दृष्टि से किसानों के लिये एक मुख्य उद्योग पशु-पालन का है। गाय-भैंस पालने से न केवल दूध-घी-दही का व्यापार होता है, बल्कि साथ ही साथ गाय-भैंस के बच्चे खेती के काम में आते हैं और गाय का गोबर और मूत्र खाद के काम आता है। बकरी भी पाली जा सकती है। बकरी का दूध पी लिया जाय और बकरे-बकरी बेचे जायें। काश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा अन्य ठंडो जगहों में भेड़ पालने तथा ऊन-उत्पादन का काम लिया जा सकता है। सुर्गी पालने और बच्चे तथा अडे बेचने का काम भी अच्छा है।

खेती के साथ में कम खर्च के साथ एक छोटा सा बगीचा लगाया जा सकता है जिसमें तरकारी, भाजी या फल-फूल पैदा किये जा सकते हैं। यदि किसान फलों को न बेच सके तो वह बाग को ठेके पर उठा सकता है। यदि गुलाब के फूल लगाये जायें तो गुलाबजल और गुलकन्द बनाना कठिन नहीं होना चाहिये।

ग्रामीण धंधे इस प्रकार के होने चाहिये कि जिनमें अधिक पूँजी की जरूरत न पड़े क्योंकि किसान के पास खेती के ही लिये पूँजी का टोटा रहता है, और न इस प्रकार के होने चाहिये कि जिनमें बहुत पेचीदा यंत्र और औजार काम में आते हों जिनको चलाने में किसान को कठिनाई हो या उनकी गाँव में मरम्मत न हो सके। धंधे इस प्रकार के होने चाहिये कि उनको जब भी चाहे छोड़ा जा सके और जब चाहे उन्हें फिर चलाया जा सके और उससे हानि न हो। कारण यह है कि किसान का धंधा तो खेती है। जब खेती को उसकी सेवाओं की आवश्यकता हो तो फिर उसको धंधा थोड़े समय के लिए छोड़ना होगा। धंधा जहाँ तक हो ऐसा हो कि उसके माल की आस-पास ही गाँवों में खपत हो सके।

शहद की मक्खी को पालकर शहद उत्पन्न किया जा सकता है। शहतूत के वृक्ष लगाकर रेशम के कीड़े पाले जा सकते हैं। अड़ी की पैदावार वाले प्रदेश में अड़ी के कीड़े पाले जा सकते हैं। इससे प्राप्त रेशम भी बेचा जा सकता है और उससे धागे भी बुने जा सकते हैं। खेती के अयोग्य जमीन पर लगा देने से लकड़ी मिल सकती है। इसके अलावा किसान रस्सी बटने, री बनाने, चटाई बुनने, पखा बुनने आदि का काम बखूबी कर सकते

हैं। अगर गाँवों में बिजली पहुँच जाय और उपर्युक्त छोटी मात्रा के उद्योग-धंधे खोल दिये जायें तो किसान अपने बेकारी के समय में इन धंधों में भी काम कर सकता है। अगर उन्हें कुछ शिक्षा तथा सहायता व सलाह मिले तो वे स्वयं भी मिलकर ऐसे धंधे कर सकते हैं। उनके अतिरिक्त नीचे लिखे धंधे भी ग्रामीण उद्योग-धंधे के रूप में चलाये जा सकते हैं। तेल घानी, कतार्ई गुड़ और शरकर बनाना, चमड़ा साफ करना इत्यादि।

ऊपर हमने केवल संक्षेप में बताया है कि किसान अपनी बेकारी के दिनों में कौन से काम कर सकता है। अगले अध्याय में इन धंधों तथा जूता बनाने का काम, लकड़ी के काम, लोहे के काम, मिट्टी के बर्तन बनाने के धंधे आदि के बारे में और खुल कर बतायेगे।

## अभ्यास के प्रश्न

१—शहर में रहने वाले अपने एक मित्र को पत्र लिखो और उसमें अपने गाँव की खरीफ की फसलों का वर्णन करो।

२—तुम्हारे गाँव में इस वर्ष रबी की कौन सी फसलें कितने रकबे में बोई गई हैं? अपना उत्तर देने में पटवारी के कागजों से सहायता ले सकते हो।

३—तुम्हारे गाँव में इस वर्ष गेहूँ की सबसे अच्छी फसल किस किसान के खेत में हुई? उस किसान से यह जानने का प्रयत्न करो कि एक एकड़ में कितना गेहूँ इस वर्ष उत्पन्न हुआ।

४—तुम्हारे गाँव में इस वर्ष गेहूँ की सबसे खराब फसल किस किसान के खेत में हुई? उसकी फसल खराब होने के क्या कारण थे?

५—तुम्हारे गाँव में जिन हलों का उपयोग किया जाता है उसका सचित्र वर्णन करो। हल कितनी गहराई तक जमीन खोदते हैं?

६—गहरी जोताई के लाभ समझाइये और बतलाइये कि आपके गाँव में कौन से नए हल का उपयोग विशेष रूप से लाभदायक होगा।

७—अपने गाँव की सिंचाई के तरीकों का वर्णन कीजिये। उनमें किन सुधारों की आवश्यकता है?



८—गोबर की खाद का महत्व समझाइये । गोबर की उपली बनाकर जला देने से जो हानियाँ हो रही हैं, उनको बतलाइये ।

९—आपके गाँव में फसलों को हेर-फेर किस प्रकार की जाती है ? इस प्रथा में क्या कोई सुधार की आवश्यकता है ?

१०—खेतों के दूर-दूर पर छोटे-छोटे दुकड़ों में बँटे हुए होने से जो हानियाँ होती हैं उनका दिग्दर्शन कराइये ।

११—अपने गाँव के सब से बड़े खेत का रकबा और सबसे छोटे खेत का रकबा लिखिये । साधारणतः कितने एकड़ रकबे के खेत आपके गाँ में अधिक हैं ?

१२—अपने गाँव में ऐसे किसानों का पता लगाइये जिनके पास ४ एकड़ से कम रकबे के खेत हों । उनकी एक वर्ष की आमदनी का पता लगाइये और यह जानने का प्रयत्न कीजिये कि वे अपना जीवन-निर्वाह बराबर कर पाते हैं या नहीं ।

१३—आपके गाँव के किसान उत्तम बीज प्राप्त करने के लिये किस प्रकार और कितना प्रयत्न करते हैं ? यदि सब किसान उत्तम बीज बोन लगे तो आपके गाँव की फसलों की उपज में कितनी वृद्धि हो सकती है ?

१४—अपने गाँव की किसी फसल की मँडाई का वर्णन कीजिये ।

१५—आपके गाँव में कृषि की दशा क्यों खराब है ? उसे सुधारने के लिये आप क्या उपाय करेंगे ?

१६—आपके गाँव के किसान प्रति वर्ष साधारणतया कितने दिन बेकार रहते हैं ? इन दिनों में वे क्या काम करते हैं ?

१७—अपने गाँव के घरेलू उद्योग-धंधों का वर्णन कीजिए । गाँव वालों लए उनका क्या महत्व है ?

---

## पाँचवाँ अध्याय

### घरेलू और स्थानीय उद्योग-धन्धे (Cottage Industries)

#### घरेलू उद्योग-धन्धों की आवश्यकता

खेती पर तो हम पूरी तरह विचार कर चुके । किन्तु केवल खेती से उत्पन्न वस्तुओं से हमारा काम न कभी चला और न चलेगा । पहले हमारे देश के उद्योग-धन्धों का माल योरोप तक में विकता था । परन्तु ईस्ट इंडिया-कम्पनी की उल्टी नीति तथा इंगलैंड में बड़े-बड़े कारखाने खुल जाने के कारण हमारे कारीगरों को धक्का पहुँचा । अतएव वे गाँव और खेती की ओर झुक पड़े । अधिक खेती के द्वारा इतने अधिक लोगों का पालन न हो सका और उनका रहन सहन गिर गया । तभी से बराबर अन्य उद्योग-धन्धों और खासकर ग्रामीण, घरेलू उद्योग-धन्धों की आवश्यकता बनी रहती है ।

#### घरेलू उद्योग या बड़ी मात्रा के उद्योग

वैसे तो हमको अनेक तरह का अन्य माल तैयार करना पड़ा है अर्थात् दस्तकारी और उद्योग-धन्धों का कार्य अखितयार करना पड़ता है । भारत में कुछ बड़े-बड़े कारखाने खुले हैं । कुछ लोगों का कहना है कि अगर इन कारखानों की संख्या बढ़ाई जाय तो लोगों को काम भी मिले और देश में मिलों के तैयार माल भी मिलें । परन्तु पिछले सौ साल में जितने बड़े उद्योग-धन्धे खुले हैं उनमें बीस लाख से अधिक मजदूर काम नहीं करते । इन उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के रास्ते में अनेकों कठिनाइयाँ हैं और अगर वे सब हल भी हो जायँ तो हमारा मतलब पूरा नहीं होगा । बड़े-बड़े कारखानों में बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है और यदि किसी तरह पूँजी इकट्ठा भी कर ली जावे तो मशीनों की आवश्यकता होगी । हमें यथेष्ट मशीन भी नहीं मिल रही हैं और न शीघ्र ही कोई आशा ही है । फिर बड़े कारखानों को चलाने के लिये विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा इंजीनियर इत्यादि की बहुत आवश्यकता है जिनकी आज देश में कमी है । इसके अतिरिक्त पिछले महायुद्ध ने हमें यह भी बतला दिया कि एक हाँ स्थान पर बहुत बड़े-बड़े कारखाने केन्द्रित कर देना देश को एक भयंकर खतरे में डालना है

क्योंकि आज हवाई युद्ध में बमों के द्वारा औद्योगिक केन्द्रों को नष्ट करना बहुत आसान है। अतः, आवश्यकता इस बात की है कि जो धन्धे छोटे रूप में चलाये जा सकते हैं उनको गृह-उद्योग-धन्धों के रूप में ही चलाया जावे। केवल यही कारण नहीं है जिनसे हमें गृह उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि यदि हम मान लें कि बड़े-बड़े कारखाने चलाए जा सकते हैं और बड़े धन्धे सफल हो सकते हैं तो भी वे बहुत थोड़े ही आदमियों को काम दे सकेंगे। भारत में लगभग ७५ प्रतिशत जनसंख्या खेती करती है। भूमि की कमी है। किसानों के पास इतनी कम भूमि है कि उस पर लाभदायक खेती हो नहीं सकती और न वे उतने से अपना पालन-पोषण ही कर सकते हैं। अब यदि हम बड़े-बड़े कारखाने ही स्थापित करेंगे तो बहुत थोड़े लोगों को काम मिल सकेगा। ऐसी दशा में गृह-उद्योग-धन्धों को स्थापित करना ही हमारे हित में होगा।

### घरेलू उद्योग-धन्धों के भेद

कुछ लोग घरेलू उद्योग-धन्धों के दो भाग करते हैं :—कृषि सहायक घरेलू उद्योग-धन्धे तथा स्वतंत्र घरेलू उद्योग-धन्धे। पहले वर्ग में ऐसे धन्धे रखे जाते हैं जिन्हें किसान अपने कृषि के साथ या फालतू समय में कर सकता है जैसे, पशुपालन, रस्सी बटना, चटाई बुनना, मुर्गी पालना, मधु मक्खी पालना, रेशम के क्रीड़े पालना, सूत कातना आदि। दूसरे वर्ग में वे उद्योग-धन्धे रखे जाते हैं जो अधिकतर स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, जुलाहा केवल बुनाई से पेट पालन करता है और चमड़े के काम से चमार। इससे यह न समझना चाहिये कि ये काम स्वतंत्र रूप से नहीं किये जा सकते हैं। अतः हम इस भेद को मुला कर नीचे मुख्य घरेलू उद्योग-धन्धों का वर्णन करेंगे।

### हमारे स्थानीय उद्योग-धन्धे

भारत में प्रचलित घरेलू उद्योग-धन्धे अनेकों हैं। लाख जो एक प्रकार के वृक्ष की गोंद है तथा जो 'वारनिश' करने और मोहर लगाने के में आती है, अब बड़े पैमाने में तैयार होने लगी है। पहले यह घरों में साफ की जाती तथा बनाई जाती थी। शहद और मोम की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है तब भी कुछ जगली और पहाड़ी जातियाँ इस काम

को करती हैं। साबुन फैक्टरी में भी बनता है और घरों में भी बनाया जाता है। बाजार में आपको घरेलू बने हुए बहुत से साबुन मिल सकते हैं। हाथी-दाँत की कारीगरी में तो भारत के शिल्पी मशहूर हैं। हाथी-दाँत का जितना बढ़िया और उत्तम काम होता है वह प्रायः अफ्रीका के हाथी-दाँत पर होता है। दिल्ली, मुर्शिदाबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, जयपुर वगैरह हाथी-दाँत की कारीगरी के लिये मशहूर हैं। रेशमी कपड़े का काम अब बहुत कम हो गया है। जापानी और बनावटी रेशम के कारण भारत का यह धधा बिल्कुल मारा गया। तब भी भागलपुर, मुर्शिदाबाद आदि स्थानों में अब भी रेशमी कपड़ा हाथ से तैयार किया जाता है। उत्तरी भारत और खास कर काश्मीर में अच्छा और बढ़िया ऊनी कपड़ा बनता है। हालाँकि उन के कारखाने खुल गये हैं तब भी मोटे कम्बल, दरियाँ, पट्टी और पश्मीना बनता है। काश्मीर के शाल बहुत मशहूर हैं। कारचोवी और कसीदे का काम उत्तर में बड़ी उन्नत दशा में है। तम्बाकू, काली मिर्च और इलायची साफ करना, सिरका डालना, सत निकालना, डबल रोटी और बिस्कुट बनाना वगैरह-वगैरह काम घरेलू उद्योग-धंधों में गिने जाते हैं। अब हम उत्तर-प्रदेश के कुछ उद्योग-धंधों का वर्णन करते हैं।

### बरतन बनाना

इस प्रदेश में बरतन बनाने का काम बहुत होता है। पीतल, ताँबा, कस्कुट और लोहा के बड़े अच्छे-अच्छे बरतन बनाये जाते हैं। बरतन बनाने का काम करने वालों को ठठेरा कहते हैं। मुर्शिदाबाद के कलई के बरतन बड़े मशहूर हैं। अब तो बरतन बनाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। धनी आदमी सैकड़ों बरतन बनाने वालों को नौकर रख लेते हैं और खूब तादाद में बरतन तैयार कराते हैं। यह तो हुआ धातु के बरतनों का हाल। अब मिट्टी के बरतनों के बारे में सुनिये। कुम्हार और कुम्हार के चाक से तो सभी परिचित होंगे। तुमने कुम्हार को अपने पत्थर के चाक घुमा कर उस पर रखी मिट्टी से सकोरा, करई, हँडिया, मटकी, घड़ा बनाते तो देखा ही होगा। वह किस सफाई के साथ अपनी उँगलियों को नचा कर अच्छी-अच्छी चीजें बना लेता है। हर एक गाँव

उन्हे अपनी माँ की तरह खाना देते हैं और न अच्छी जगह में उन्हें रखते ही हैं। इसके अलावा गाय भेसों की सफाई नहीं रखी जाती, फलस्वरूप ढोरोँ में अनेक रोग फैल जाते हैं और बहुतों की अकाल मौत हो जाती है। इन्हीं कारणों से ढोरोँ की नसले कमजोर होती जा रही हैं। पहले तो किसान गाय खरीदने में गलती करते हैं। गाय दुधार होनी चाहिये। इसके लिये यह जरूरी नहीं है कि गाय मोटी हो। गाय की खाल पतली तथा रोयें नरम और चिकने होने चाहिये। थन सीधे हों, न बहुत छोटे हों न बहुत बड़े। काली, लाल और भूरे रंग की गायें अक्सर अच्छी होती हैं।\*

### दूध का काम

गाय पालने से बहुत फायदे होते हैं। गाय का बछड़ा बड़ा होकर खेत जोतने के काम आता है। गाय का गोबर उम्ली, खद और घर लीपने में काम आता है। गाय के दूध के बगैर तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। कोई दूध पीता है। कोई उसका दही, मखन या मलाई-रबड़ी बनाकर खाता है। दूध का खोया बनाया जाता है। हम आगे किसी अध्याय में बतावेंगे कि दूध क्यों ताकतवर होता है। ताकतवर होने के कारण ही तो छोटे बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता है, लेकिन दूध से बमारियाँ भी बहुत सी फैलती हैं। दूध की सफाई में जरा सी लापरवाही करने से वह खराब हो जाता है। जरा भी सफाई की कमी होने से बैक्टीरिया नाम का एक कीड़ा दूध में पैदा हो जाता है, इससे दूध फौरन बीमारी का घर बन जाता है। हमारे गवाले दूध दुहने में बड़ी लापरवाही दिखाते हैं। न तो वे कभी थन को धोते हैं न अपने हाथों को दुहने के पहिले साफ करते हैं और न साफ-सुथरे कपड़े ही पहनते हैं। इनके अलावा बछड़े के दूध पी चुकने के बाद भी थन का धोना आवश्यक है। दुहने वाले को न तो खॉसने-छींकने की आदत होनी चाहिये और न कोई छूत का ही रोग हो। दुहने की जगह पर गर्द गुबार न पड़ना चाहिये। दूध का बरतन साफ मजा हुआ होवे और जब दूध बेचने के लिये ले जाया जावे तो बरतन हमेशा साफ कर लेना चाहिये। यह तो हुई दुहने के सम्बन्ध की बातें। अब दूध बेचने का तरीका सुनिये। हमारे देहाती गाई अगर सेर भर दूध होता है तो पाव डेढ़ पाव पानी मिला देते हैं। यही

नहीं विज्ञान के विद्वानों ने एक ऐसी मशीन निकाली है जिसमें डाल कर घुमाने से कच्चे दूध से मक्खन अलग निकल जाता है। बचे हुए दूध को मक्खनिया दूध कहते हैं। आजकल देहाती इस प्रकार पहिले से ही मक्खन निकाल कर तब दूध को बेचने लाते हैं। ऐसा दूध किसी काम का नहीं होता। हमारे हलवाई इसी दूध को खरीद कर बेचते हैं। इसी का दही जमाते हैं। चूँकि मक्खनिया दूध पतला और सार-रहित सा मालूम पड़ता है इसलिये इसको गाढ़ा बनाने के लिये थोड़ा सा अरारोट या तीखुर डाल देते हैं। अरारोट पडे दूध के दही के ऊपर मोटी मलाई जम जाती है। यह काम शहर में काफी किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि अधिक किसान दूध बेच कर कुछ पैसा कमा सकें तो उन्हें दूर-स्थित शहरों और नगरों में बिना बिगड़ा दूध ले जाने की सुविधा जरूरी है।

### मक्खन और घी

दूध से मक्खन और घी भी बनाया जाता है। ऊपर हमने मक्खनियाँ दूध का हाल बताते समय कच्चे दूध से मक्खन निकालने की एक तरीका बताया है। कच्चे दूध से मक्खन निकालने की जिस मशीन का जिक्र ऊपर आया है वह अभी हमारे गाँव तक नहीं पहुँची है। शहर में ही उसका उपयोग किया जाता है। तुमने पिछली बार जो मक्खन मोल लिया होगा वह इसी तरह बनाया गया था। दूध को आग पर पका कर मथने से भी मक्खन निकल आता है; लेकिन शहर वाले पकाने के ऋगड़े में नहीं पड़ते। गाँवों में जो घी तैयार किया जाता है उसके लिये पहले दूध को उबालते अथवा पकाने हैं। पके हुये दूध में थोड़ा सा पहले का रखा हुआ दही डाल कर रख देने से नात आठ घंटे में दूध जम कर दही बन जाता है। इस को मथनी से गूँस मथते हैं। मथने से मक्खन ऊपर तैरने लगता है और निकाल लिया जाता है। मक्खन निकालने के बाद जो दूध या पदार्थ बचा रहता है उसे मछा कहते हैं। मछ कर निमाले मक्खन को नैग भी कहते हैं। नैग कच्चे दूध से निकाले मक्खन से वही अधिक अच्छा और स्वादिष्ट होता है।

तैयार हो जाता है। मक्खन एक-दो दिन से अधिक नहीं ठहरता। दूध का भाग रहने से उसमें बदबू आने लगती है और वह खराब हो जाता है। इसलिए मक्खन ताजा खाया जाता है। घी बनाने में खराब होने वाला भाग पहले ही जल जाता है। इसलिए घी बहुत दिनों तक रहता है। घी और मक्खन दोनों शरीर को ताकत पहुँचाते हैं। लेकिन ये बहुत अधिक हजम नहीं किये जा सकते। मक्खन को लग घी से अधिक लाभदायक मानते हैं। आजकल बिकनेवाले घी में नारियल या दूसरी चीजों का तेल भी मिला देते हैं। इसके अलावा आजकल तरह-तरह के बनावटी घी चल निकले हैं। जैसे घास का घी, कोकोजम इत्यादि। बहुत से लोग मक्खन को अच्छी तरह नहीं तपाते हैं बल्कि आधा पक्का आधा कच्चा ही बेचते हैं। इसीलिए तुमने कभी किसी को घी के बारे में कहते सुना होगा कि घी में मट्टा है। आजकल शहर में अच्छा घी मिलता ही नहीं। हाँ गाँव में अच्छा घी मिल जाता है। इसलिए आजकल घी मोल लेते समय उसे अच्छी तरह देख कर लेना चाहिए।

### रस्सी बनाना

तुमने देखा होगा कि गाय दुहते समय ग्वाला अक्सर गाय के पिछले पैर रस्सी से बाँध देता है। पतली डोर को रस्सी कहते हैं और मोटी को रस्सा। किसानों का तो बिना रस्सी रस्से के काम ही नहीं चल सकता। घर में, खेत में, गाड़ी की जाली बनाने में, बोझा बाँधने में उसे रस्सी की जरूरत पड़ती है। मूँज के, घास के, नारियल के जटाओं के, सन के, सरपत के तथा और-और चीजों के भी रस्से बनाये जाते हैं। मूँज की महीन बटा रस्सी को बाध कहते हैं और यह खटिया बुनने के काम आती है। घास और मूँज की रस्सी बनाने के पहले उसे पाना में भिगोते हैं। अच्छी तरह भाग जाने पर इन्हें खूब कूटते हैं। जब उनके डारे-डोरे अलग हो जाते हैं तब उनमें से चार-चार छे-छे रेशे हाथों में लेकर ऐंठते और आपस में मिलाते चलते हैं। एक लम्बी रस्सी तैयार हो जाने पर उसे दोहरा-तेहरा करके और मोटा व मजबूत बना लेते हैं। सन की रस्सी बनाने के लिये पहले सन के पौधों को सड़ा कर सुखाया है, तब सन अलग कर लेते हैं और उसे बट कर रस्सी तैयार करते हैं। हमारे यहाँ के किसान सन को गंदे पानी में सड़ाते हैं जिससे वह मैला

जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ के सन में कूड़ा भी होता है। फिर वे यों ही सन के लच्छे बना डालते हैं जिससे रेशों के उलझ जाने पर उन्हें पुलझाने में बड़ी मेहनत पड़ती है। मूँज की रस्सी मजबूत होती है और पानी पड़ने पर बिगड़ती नहीं। लेकिन सन की रस्सी पानी में रहने से ठीक नहीं रहती। नावों को बाँधने के लिए जो बड़े-बड़े रस्से बनाये जाते हैं वे मूँज के हों होते हैं।

### लकड़ी का काम

रस्सी के अलावा दूसरी चीज है लकड़ी, जिसके बिना किसानों का काम नहीं चल सकता। गाँव में बढई का होना जरूरी है। हल, जुआ, पालकी, खिड़क़, दरवाजा बढई द्वारा ही तैयार होते हैं। डावट, खडाऊँ और खुरपा, कुल्हाड़ा व बसूला का बेट भी वही बनाता है। लकड़ा के जो कुछ भी काम बन सकते हैं वे बढई की ही दस्तकारी के नमूने हैं। लेकिन बढई एक ही दो चीजों के बनाने में अपना हुनर दिखाते हैं। जो सब बातों में अपनी टाँग अड़ाते हैं वे किसी बात में निपुण नहीं हो पाते। गाँव के बढई को हल तथा ब्रैलगाड़ियाँ तो जरूर ही बनानी पड़ती हैं। कोई बढई हल बनाने में होशियार होता है; कोई गाड़ी बनाने में। इसके अलावा उत्तरी भारत में लकड़ी पर चिताई का काम देखने में आता है। कारीगर लकड़ी पर ऐसे उम्दा-उम्दा बेल बूटे बनाते हैं तथा ऐसी नक्काशी करते हैं कि देखते बनता है। इसमें शासम, साल व आबनूस की लकड़ी अधिकतर काम में लाते हैं। नागपुर तथा अन्य जगहों में चिताई का काम बहुत अच्छा होता है। बनारस का तरफ लकड़ों के खिलौने बनाकर उस पर हल्के रंग से चित्रकारी की जाती है और फिर एक खास किस्म की वारनिश कर दी जाती है। ये खिलौने काफी अच्छे होते हैं।

### लोहार का काम



के बड़े-पड़े कारखाने खुल जाने से लोहार का बहुत काम घट गया है। तब भी लोहार देहान में अपना स्थान रखता है।

### तेल पेरने का काम

लोहार की तरह तेली का हाल है। गाँव में तेल जलाने के काम में आता है। तिल्ली का तेल जलाया भी जाता है और खाया भी। सरसों, अलसी, महुआ आदि और भी कितनी चीजों का तेल निकलता है। गाँव में एक तेली अवश्य होता है। तेल पेरना और बेचना ही उसका काम होता है। तिल्ली कोल्हू में पेली जाती है। पत्थर की एक बड़ी सी ओखली मैन में गड़ी होती है। ओखली के पास ही एक लकड़ी का खम्भा रहता है। उसमें लकड़ी का बड़ा सा कोल्हू बाँध देते हैं, जिसमें वह सधा रहे। ओखली में तिल्ली डालकर बैल कोल्हू के साथ ओखली के चारों ओर घुमाते हैं। ऐसा करने से तिल्ली कोल्हू के नीचे पिसती है और उसमें से तेल निकलता है। पत्थर में छेद होता है। तेल इस छेद से जमीन में रक्खे हुये एक बर्तन में गिरता जाता है। तेल निकल जाने पर तिल्ली की खली हो जाती है। खली जानवरों को खिलाई जाती है, जिससे वे दूध अधिक दें। अब तो कहीं-कहीं आयल एजिन मशीनों द्वारा तेल निकाला जाता है। इसके चालू करने में खर्च तो ज्यादा जरूर होता है लेकिन देशी कोल्हू में जितना तेल दिन भर में निकलता है उतना तेल एंजिन के जरिये आधा घंटे में निकल आता है।

### जूते बनाना

जिस तरह गाँवों में जुलाहा, बूढ़ई, लुहार आदि रहते हैं, वैसे ही चमार भी रहता है। अगर इनमें से कोई भी गाँव छोड़ दे तो सब लोगों को तकलीफ होगी। चमार हमारे लिए नए-नए जूते बनाता है और फटे-पुराने जूतों की मरम्मत करता है। गाँव का चमार खेती भी करता है और खेती से फुरसत मिलने पर जूता बनाने का काम कर लेता है। यों तो गाँव का चमार घोड़ों पर की काठी और बैल हाँकने के लिए चमड़े के तस्मे वगैरह बनाता है। शहरों में चमड़े के बक्स और मशक वगैरह बनाये जाते हैं। लेकिन गाँव का अधिकतर जूते ही बनाता है। तुमने देहाती जूता तो देखा ही होगा। रो में अब पश्चिमी ढंग के फैशनदार जूते के चल जाने से देहाती जूतों को कोई नहीं पूछता। लेकिन अंग्रेजों के आने के पहले सब कोई देहाती जूता

पहनते थे। हमारा देहाती जूना बड़ा मजबूत तथा अच्छा होता है। इससे पहले तो पैर में गर्मी नहीं पहुँचती है। फिर भी यह जल्दी पहना और उतारा जा सकता है। ये जूते ऐसे बनाये जाते हैं कि इन्हें पहनने और उतारने में हाथ न लगाना पड़े। जूता, गाय, बैल आदि जानवरों की खाल का बनाया जाता है। जानवर के मर जाने पर चमार उसकी खाल को निकाल लेते हैं। खाल को पहले धूप में अच्छी तरह सुखाते हैं जिससे वह खूब कड़ी हो जाती है। इसके बाद खाल के रोएँ साफ कर दिये जाते हैं। फिर खाल को कमाते हैं। जूता बनाते समय पैर का नाप लेकर चमार उसी तरह हमारे पैर का जूता तैयार कर देता है जिस तरह दर्जी नाप लेकर हमारा कोट या कमीज सी देता है। अब तो जूता बनाने के बड़े-बड़े कारखाने खुल गए हैं, जिनमें बड़े उम्दा-उम्दा सस्ते जूते बनाए जाते हैं। भारतीय कारखानों में बने जूतों में कानपुर, आगरा या बाटा कम्पनी (कलकत्ता) के जूते मशहूर हैं। अब हम कुछ ऐसे उद्योग-धन्धों का वर्णन करेंगे जो गाँवों में खोले जा सकते हैं।

### फल-फूल और तरकारी पैदा करना

हमने पिछले अध्याय में फल, फूल और तरकारी-भाजी के बाग लगाने के काम की चर्चा की थी। यदि किसान उरज की खेती के साथ एक छोटा सा बाग लगा ले तो उसे फल और तरकारी खाने को मिलेगी ही, उन्हें बेच कर वे कुछ पैसे भी पा सकेंगे। फूलों से किसान का घर तो महक ही उठेगा। उससे खुशबूदार जल, इत्र तथा गुलाब से गुलकद बनाया जा सकता है। कुछ फूल के पेड़ बंजर भूमि में भी फूल सकते हैं और तरकारी की वाटिका में किसान के घर का गंदा पानी काम आ सकता है। परन्तु यदि वाटिका किस न के घर से मिली नहीं है तो गन्दे पानी को वाटिका तक ढोना पड़ेगा। फूलों से पूर्ण लाभ उठाने के लिये किसान को उचित शिक्षा, ट्रेनिंग तथा सहायता देने की आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु किसान गाँव में फल व तरकारी किसके हाथ बेचेगा? अगर वह किसी शहर के पास है तब वह उसे शहर ले जाकर अथवा शहर के विक्रेताओं के हाथ उन्हें बेच देगा। अगर ऐसा नहीं है तब बिना यातायात के प्रबन्ध के वह पैसे नहीं कमा सकता।

### शहद का धन्धा

ऊपर फूलों का जिक्र आया था। फूलों के बीच अगर शहद की मक्खी

पाल कर छत्ता लगवाया जाय, तो शहद पैदा किया जा सकता है। लेकिन छत्ते के लिए फूल की वाटिका आवश्यक है। अब तो लकड़ी के ऐसे बक्स मिलते हैं कि उनमें शहद की मक्खियाँ पालकर शहद निकालने के लिये न तो मक्खियों को उड़ाना पड़ता है और न छत्ते को तोड़ना। इस धन्धे में झूट भी कम होता है। पूँजी भी कम लगती है और जगह भी कम घिरती है। शहद अधिक पौष्टिक भोजन भी है। परन्तु इस धन्धे की सफलता के लिये भी किसान को शिक्षा तथा बिक्री में सहायता आवश्यक है। दक्षिण भारत में डाक्टर स्पेंसर हैच तथा दूसरे ईसाई मजहब वालों की मेहनत के कारण गाँवों में इस धन्धे का काफी प्रचार हुआ है।

### अन्य उद्योग-धन्धे

उपर बताए गए कुछ घरेलू उद्योग-धन्धों के अलावा अभी बहुत से और धन्धे हैं। मध्यप्रदेश में वर्धा नगर में एक “अखिल भारतीय ग्राम उद्योग सघ” है। उसका उद्देश्य गाँवों की हालत सुधारना है। उसकी देख-रेख में नीचे लिखे ग्राम उद्योग चल रहे हैं :—

धान से चावल निकालना, आटा पीसना, गुड बनाना, तेल निकालना, शहद की मक्खियाँ पालना, मछली पालना, दूध का काम, कम्बल बनाना, रेशम का माल बनाना, सन की कताई और बुनाई, कागज बनाना, चटाई बनाना, कपियाँ बनाना, पत्थर की कारीगरी, साबुन बनाना, चमड़ा तैयार करके उससे तरह तरह की वस्तुएँ बनाना इत्यादि।

### घरेलू उद्योग-धन्धे की कठिनाइयाँ !

घरेलू उद्योग-धन्धों की मुख्य कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं :—

(१) काम करने वालों को अच्छे कच्चे पदार्थ, जैसे सूत, लोहे की चद्दर तथा तॉन्वा-पीतल उपयुक्त भाव में नहीं मिलते।

(२) उसके पास पूँजा को कमा है। वे जिस महाजन से कर्ज लेते हैं उसके चंगुल में फँस जाते हैं। फिर या तो उन्हें अपना माल सस्ते दामों पर महाजन के हाथ बेचना पड़ता है या अधिकांश कमाई महाजन को सूद के रूप में देनी पड़ती है।

पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण खरीदार की पसंद बदल गई। खरीदार की पसंद पहले जैसी बननी है और न कारीगरों को नए

डिजाइन आदि बताने का उपयुक्त और पर्याप्त प्रबन्ध है। शिल्प शिक्षा का विशेष प्रबन्ध भी अपर्याप्त है।

(४) घरेलू उद्योग-धन्धों के माल को उचित कीमत पर अच्छे बाजार और विदेशों में जहाँ उनकी माँग अधिक है, बेचने की विशेष सुविधा भी नहीं है।

### घरेलू उद्योग-धन्धे और सरकार

हमने इस अध्याय में कुछ खास उद्योग-धन्धों के बारे में तो खुल कर बताया है और कुछ के बारे में संक्षेप में हाल बह दिया है। जिन धन्धों का अच्छी तरह बताया है उनका गाँव से अधिक सम्बन्ध है।

इसका यह मतलब नहीं है कि गाँव में गाँव से अधिक सम्बन्ध रखने वाले धन्धों की ही उन्नति की जाय। अगर सरकार पहले से योजना बनाकर गाँवों में कृषि के साथ उद्योग-धन्धों की व्यवस्था और उन्नति करे तो घरेलू उद्योग-धन्धों द्वारा साबुन, कागज, कंवी, बटन, सुरक्षित झिले फल, हाथ के बिने कपडे आदि अनेकों पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं। वह गाँवों के लिये उपयुक्त धन्धे चुन सकती है। उनको चालू करने की व्यवस्था कर सकती है। किसानों को उनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहन, शिक्षा, और आर्थिक सहायता दे सकती है। धन्धों के लिए यातायात के साधनों की उन्नति कर सकती है और माल का बिक्री सुलभ कर सकता है। अगर गाँवों में बिजली भी पहुँच जाय तो कार्य-क्षमता और कार्य-क्षेत्र अधिक बढ़ जाय। सरकार ही यह कार्य सम्पन्न कर सकती है। प्रादेशिक तथा दिल्ली की केन्द्रीय सरकारें ऐसी कोशिश कर रही हैं। घरेलू उद्योगों का उन्नति करना उनका घोषित नीति है। भारत सरकार ने घरेलू धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए एक बोर्ड बनाया है।

हम खेती और घरेलू उद्योग-धन्धों के बारे में काफी जान गए। इनके जरिए बहुत सी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तुएँ उत्पन्न की गई हैं उनको काम में किस प्रकार लिया जाय। अर्थात्, वस्तुओं का किस तरह से उपभोग किया जाय। उपभोग के सम्बन्ध का सारी बातों पर हम अब अर्थशास्त्र के उपभोग विभाग के अन्दर विचार

## अभ्यास के प्रश्न

१—अपने गाँव के किसी किसान से पूछकर लिखिए कि प्रति मास उसे खेती सम्बन्धी कौन-कौन से काम करने पड़ते हैं। किन् महीनों में उसे सबसे अधिक काम रहता है और किन महीनों में उसे सबसे कम ?

२—आपके गाँव के किसान साधारणतः वर्ष भर में कितने महीने बेकार रहते हैं ? इस बेकारी के समय में आप इनको-कौन सा काम करने की सलाह देंगे।

३—आपके गाँव में आजकल प्रतिमास कितना सूत काता जाता है ? यदि गाँव के सब बेकार स्त्री-पुरुष प्रति दिन चार घंटा सूत कातने लगें तो एक मास में कितना सूत तैयार हो सकता है ?

४—आपके गाँव में या आसपास के गाँवों में जुलाहों की कितनी संख्या है ? ये जुलाहे हाथ के कते सूत का कहाँ तक उपयोग करते हैं ?

५—जुलाहों की आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए और उनकी दशा सुधारने का उपाय बतलाइये।

६—आर्थिक दृष्टि से खहर प्रचार की आवश्यकता समझाइए।

७—अपने गाँव के कुम्हार की आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। वह अपनी आमदनी किस प्रकार बढ़ा सकता है ?

८—उत्तर प्रदेश में पीतल के बरतन किन स्थानों में अच्छे और सस्ते मिलते हैं ? मुरादाबाद किस प्रकार के बरतनों के लिए प्रसिद्ध है और उस उद्योग की वर्तमान दशा कैसी है ?

९—आपके जिले में गुड़ किस प्रकार बनाया जाता है। इस प्रदेश में गुड़ कहाँ अच्छा और सस्ता बनता है ?

१०—शहर में दूध का क्या भाव है ? गाँवों में दूध किस दर पर मिलता है ? दोनों दरों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

११—शुद्ध दूध की पहिचान लिखिये। शहर में शुद्ध दूध सस्ते भाव से देने के लिए योजना तैयार कीजिये।

१२—अपने गाँव के मुख्य घरेलू वस्तुओं का वर्णन कीजिए और बतलाइए उसके लिए कच्चा माल किस तरह प्राप्त होता है और उसकी बिक्री किस दर होती है।

१३—आपके गाँव में चमारों की क्या दशा है ? उनकी दशा किस प्रकार सुधारी जा सकती है ?

१४—अपने गाँव के मुख्य घरेलू धन्धों का वर्णन कीजिये । उनमें कौन-कौन सी बुराइयाँ हैं ? उन्हें आप कैसे दूर करिएगा ?

१५—यदि आपको ५००) दे दिया जाय तो आप उसे अपने गाँवों के घरेलू उद्योग-धन्धों को सुधारने के लिए किस प्रकार खर्च करेंगे ।

१६—सरकार योजना बनाकर किस प्रकार घरेलू उद्योग-धन्धों की उन्नति कर सकती है ? उदाहरण देकर समझाइये ।

१७—ग्रामीण उद्योग-धन्धों की आवश्यकता क्यों है ? समझाकर लिखिए कि ग्रामीण धन्धे किस प्रकार के हों ।

## छठा अध्याय

### आवश्यकताएँ ( Wants )

#### आवश्यकता का महत्व

#### ( Importance of Wants, )

किसी वस्तु की उत्पत्ति उसके उपभोग किये जाने के लिये की जाती है । किसान अनाज क्यों पैदा करता है ? उसके आटे की रोटी बनाकर खाने के वास्ते । आदमी कपड़े क्यों बनवाता है ? उन्हें बदन पर पहिनने के लिए । गाँव वाले जाड़े में अलाव क्यों जलाते हैं ? आग ताप कर ठंड मिटाने के लिए । अर्थात् उपयोग करने के कारण ही उत्पत्ति का कार्य किया जाता है । आदमी क्यों खाना खाता है ? काम करने के लिए । और काम क्यों करता है ? उससे पैदा हुए धन से खाना खरीदने के लिए । मनुष्य को तरह-तरह की आवश्यकताएँ रहती हैं । यह भाँति-भाँति के फल, फूल, कपड़े-लत्ते प्राप्त करना चाहता है । इसलिए ससार में तरह-तरह के काम-धन्धे दिखलाई पड़ते हैं । किसान, बढईगिर, लोहारी, चमारी, दर्जी का काम, धी बनाने का धन्धा आदि जितने काम-काज हैं सब की पूर्ति मनुष्य की आवश्यकताओं के हाथ में रहती है । अगर आज हमारी आवश्यकताएँ

कुछ भी न रहे तो शायद बहुत से काम बन्द हो जायें। ऋतु से पेशे वालों का अपना-अपना काम छोड़ना पड़ जाय। अस्तु, कहने का मत यह है कि उत्पत्ति और उपभोग में बहुत गहरा सम्बन्ध है, और हम किमा वस्तु का उपभाग इसलिए करते हैं कि हमें उस वस्तु के उपभोग की आवश्यकता मालूम पड़ती है और हम उस आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं। अतः-एव उपभोग की मूल आवश्यकताएँ हैं; और हमें इनके विषय में कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिये।

### आवश्यकता और इच्छा (Wants and Desire)

आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसको पूरा करने के लिए वह मेहनत करता है। आवश्यकता और इच्छा में फर्क है। आपकी इच्छा कलक्टर, जज और बादशाह बनने के लिए हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि मैं जमींदार बनूँ और जो इस समय जमींदार हूँ वे किसान बनें, और तब अच्छी तरह जमींदार की खबर लेंगे। इच्छा करना और मन के लड्डू खाना बहुत कुछ एक ही बात है। लेकिन जब आप किसी इच्छा को कार्यरूप में कर दिखाने का कोशिश करते हैं तब इच्छा आवश्यकता में पलट जाती है। आप काट पहनने का इच्छा रखते हैं। जब आप कपड़ा मोल लाकर दर्जी से अपना कोट बनवा कर पहनते हैं तो कहा जायगा कि आपको कोट की आवश्यकता थी। इसी तरह बाजार में कई एक वस्तुओं को देख कर उनको खरीदने और उपभोग करने की इच्छा हाता है लेकिन अगर हम उन वस्तुओं का प्राप्त करने का प्रयत्न या उद्योग न करें तो वह केवल कोरा इच्छा हा रह जाती है। किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योग करना निहयत जरूरी है।

### आवश्यकता और उद्योग (Want and Effort)

प्राचीन काल से ही मनुष्यों को अनेक वस्तुओं की आवश्यकता रही है। जिस समय लोग वन में जगली जानवरों के समान रहते थे उस समय भी वे लोगों को अपने प्राण की रक्षा के लिए पाने का पानी और पेट भरने का आवश्यकता थी। जैसे-जैसे आदिमियों का सभ्यता बढ़ती गयी उनकी आवश्यकताएँ भी बढ़ती गईं। जब आग का आविष्कार हुआ मनुष्यों को नाना प्रकार के भोजनों की आवश्यकता हुई। उन्हें यह

मालूम पड़ने लगा कि उधाले चावल खाएँ, दाल पकानी चाहिए या मास को भून कर खाना चाहिये। इसी तरह एक के बाद दूसरी आवश्यकता प्रकट होती गई। जब भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई तो वस्त्रों की आवश्यकता हुई। जब पहनने को कपड़े मिलने लगे तो उनको पेड के नीचे या पेड के ऊपर डालों पर सोना अच्छा नहीं मालूम हुआ और रहने के लिए मकान की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इन सब का तृप्ति के बाद खास-खास तरह के भोजन जैसे रसगुल्ला, कचौड़ी, पकौड, हलुआ आदि की जरूरत हुई। पहनने के लिए अब उत्तम-उत्तम वस्त्र, नेकटाई, कालरदार कमीज, कुरता, पैजामा वगैरह की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह आदिमियों ने अपने को पेड की पत्तियों और फूलों से सजाना छोड़ दिया और सोने-चाँदी के गहने, कड़े, हँसली, जंजीर आदि बनाकर पहनने लगे। इसके बाद रथ या बैलगाड़ी की सवारी, बल्लम, भाला, तलवार आदि हथियारों, सगीन इत्यादि की आवश्यकताये भी प्रकट हुई। कहने का मतलब यह कि जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ती गई और पुरानी आवश्यकताओं की तृप्ति होती गई; त्यों-त्यों नई आवश्यकताये उनके स्थान पर आती गईं यहाँ तक कि अब सख्या गिनती से परे हो गई।

आवश्यकता और उद्योग का गहरा सम्बन्ध है। जैसे-जैसे आदमी की आवश्यकताये बढ़ती जाती हैं, वह उनकी तृप्ति के लिए उद्योग करता रहता है।

मनुष्य एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्योग करता है। वह पूरी होते ही उसे दूसरी आवश्यकता आ घेरती है। इस प्रकार आवश्यकताओं, उद्योग तथा पूर्ति का क्रम बँधा रहता है :—

आवश्यकता—उद्योग—पूर्ति—नई आवश्यकता—उद्योग

मनुष्य बहुत से उद्योग इसलिए भी करता है कि फलस्वरूप नई आवश्यकताये पैदा हो जाएँगी। यथा मिल मालिक नई डिजाइन निकालता है ताकि ग्राहक इसको पसन्द करने लगे। कुछ वर्षों पहले आइसक्रीम बड़े लोगों का पसन्द थी अब उत्पादकों ने उसे गाँवों तक बेचने का बाड़ा उठाया है। इन प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति अधिक लाभ हेतु काम करने वाले करते हैं।

परन्तु बहुत से मनुष्य अपने मनोरंजन या हार्वी स्वरूप विज्ञान, साहित्य



इत्यादि के सम्बन्ध में अध्ययन व खोज करते हैं और नया-नयी बातें ढूँढ निकालते हैं। इन नए आविष्कारों की सहायता से नई-नई वस्तुएँ बनाई जाती हैं और मनुष्य को इन वस्तुओं की भी आवश्यकता मालूम होती है।

### आवश्यकता के लक्षण

आवश्यकताएँ अपरिमित हैं। इनका कोई अन्त नहीं है। आम-तौर पर आदमी का भौति-भौति के भाजन, तरह-तरह के कपड़ों, नई-नई किताबों और दूसरी वस्तुओं की इच्छा बनी रहती है। कहा जाता है कि जिनके पास धन है वे अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। परन्तु जरा सोचा जाय तो मालूम पड़ता है कि कोई भी धनवान् मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसको सब आवश्यकतायें पूरी हो गई हैं, क्योंकि ज्योंही एक आवश्यकता की तृप्ति होती है त्योंही दूसरी उसके स्थान पर आ खड़ी होती है। आवश्यकता की वृद्धि होने से ही सभ्यता की भी उन्नति होती है। मनुष्य को आवश्यकतायें अपरिमित तो हैं ही लेकिन यदि यथेष्ट साधन हों तो मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता किसी एक समय में पूरी की जा सकती है, उदाहरण के लिये एक भूखे आदमी को लीजिये। उसको भोजन की आवश्यकता है लेकिन उसके भोजन की भी एक सीमा है। चार पाँच रोटियों से उसका पेट भर जाता है और उसको उसके बाद फिर रोटियों की जरूरत नहीं रहती। इसी प्रकार किसी एक आवश्यकता को पूरी करने का सब सामान रहने से किसी खास समय में उसकी तृप्ति की जा सकती है। कहा जा सकता है कि कई इच्छाएँ ऐसी हैं जिनकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। जैसे धन की इच्छा, अधिकार की इच्छा, बड़ापन की इच्छा इत्यादि। यह सहसा कहा भी नहीं जा सकता कि कितने धन सामग्री या गहने से कोई आदमी या ओरत मन्तुष्ट होगी। लेकिन इनमें से हर एक इच्छा कई इच्छाओं से मिल कर बनती है। ये एक एक इच्छा नहीं हैं। उदाहरण के लिए धन की इच्छा को ले लीजिये। देखने में तो यह एक इच्छा है पर इसके पीछे उस धन से मिलने वाली अनेक वस्तुओं की इच्छा छिपी है।

मनुष्य सब आवश्यकताओं को एक साथ पूरा कर सकता है और अपनी सब आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक सी जल्दी

रहती हैं। कोई आवश्यकता सबसे अधिक जरूरी है तो कोई कम। साथ ही वही आवश्यकता सबके लिये एक सी जरूरी नहीं होती। रामू के लिए जो आवश्यकता सबसे अधिक जरूरी है, श्याम के लिए वह जरूरी न हो। मान लो रामू पढ़ता है और श्याम नहीं पढ़ता। रामू को तो किताब की जरूरत है लेकिन श्याम को इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई आवश्यकता ऐसी भी हो सकती है जो कि तुम्हारे लिए अभी जरूरी हो, पर मेरे लिए नहीं। हाँ, कुछ देर के बाद वह मेरे लिए भी जरूरी बन सकती है। मान लो, मैं खा चुका हूँ और तुमने अभी खाना नहीं खाया है, इसलिए तुमको अभी खाना खाने के लिए भोजन चाहिए। कुछ पलों के बाद जब तुम्हें फिर से भूख लगेगी तब तुम्हें भी भोजन की जरूरत पड़ेगी। इससे यह भी स्पष्ट है कि कुछ आवश्यकतायें जैसे भूख, प्यास, दस बजे स्कूल जाना आदि: बार-बार आती हैं।

हैं। यों तो हम आवश्यकता के लक्षणों के मुताबिक कह सकते हैं कि कुछ जरूरतों को शीघ्र पूरा करना पड़ता है, कुछ को देर में। जैसे पहनने के लिए कपड़ा चाहे न मिले लेकिन भूख लगने पर खाना अवश्य मिलना चाहिए। कुछ आवश्यकताएँ ऐसी हाताँ हैं कि उनको पूरा करने के लिए बहुत से साधन होते हैं, जैसे प्यास के लिए हम पानी, शरबत, मट्ठा या सोडा लेमन पी सकते हैं। ठीक, लेकिन इस तरह के तो शायद सैकड़ों विभाग बनाए जायें तब भी काम न चलेगा। सबसे अच्छा तरीका वह है जिसमें आवश्यकताओं को तीन हिस्सों में बाँटते हैं; आवश्यक आराम हेतु और विलासिता हेतु। पहले में तो वे आवश्यकताएँ आती हैं जिनको हम आवश्यक (Necessaries) समझते हैं। अधा-अपाहिज कैसा भी मनुष्य क्यों न हो वह अपने शरीर को नाश होने से बचाने की हमेशा कोशिश करता है। पेट भरने के लिए सब को भोजन और पीने का पानी चाहिए। पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है। राम साधारण भोजन करता है, फटा-पुराना कपड़ा पहनता है और टूटी-फूटी स्लीपडी में रहता है। इसके विपरीत श्याम अच्छा अनाज, दूध, फल इत्यादि खाता है। वह साफ-सुथरे कपड़ा पहिनता है और हवादार मकान में रहता है। एक तरह से राम और श्याम दोनों ही जीवन रक्षा के लिए जरूरी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, परन्तु कुछ वर्षों में राम कमजोर और रोगी बन जायगा और श्याम मजबूत बतगड़ा। कहने का मतलब यह है कि आवश्यक वस्तुओं में से कुछ तो केवल मनुष्य को जिन्दा बनाये रखती है और कुछ आदमी की जीवन-रक्षा के अलावा तन्दुरुस्ती भी प्रदान करती है। अतः आवश्यक वस्तुओं के दो वर्ग हो गये—जीवन-रक्षा की वस्तुएँ (Necessaries for existence) और निपुणतादायक वस्तुएँ (Necessaries for efficiency)। इनके अतिरिक्त एक तसरा वर्ग होता है। कृत्रिम आवश्यकता का वस्तुओं का। इनके अन्तर्गत उन चीजों को शुमार करते हैं जो मनुष्य की आदतवश जरूरी हो जाती हैं, जैसे किमान ४ फू पीते हैं और अब शहर में लोग चाय पीते हैं। इनके बिना वे जिन्दा सकते हैं परन्तु पीते-पीते आदत ऐसी हो गई है कि उनके बिना काम नहीं चलता। अतः उन्हें कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुओं में गिनते हैं।

## आराम की वस्तुएँ (Comforts)

जिन चीजों की मनुष्य को आराम करने के लिए जरूरत मालूम पड़ती है उन्हें आराम की वस्तुयें कहते हैं। आराम इस प्रकार की कृत्रिम आवश्यकता को कहते हैं। आराम की वस्तुओं (Comforts) से शरीर को सुख मिलता है और काम करने की ताकत भी बढ़ती है। लेकिन इन पर जितना खर्च किया जाता है उस हिसाब से कार्य-कुशलता नहीं बढ़ती। जैसे किसी गरीब आदमी के लिए धोती, कुर्ता और चप्पल उनकी कार्य-कुशलता बढ़ाते हैं लेकिन अगर वह तिगुना व्यय करके बढ़िया महान धोती, रेशमी कपड़े की कमाज व उम्दा जूता पहने तो उसका कार्य-कुशलता तिगुनी न हो जाएगी। ये तथा गरीब किसान के लिए साइकिल, घड़ी, पक्का मकान इत्यादि आराम की सामग्रियों में शामिल किये जाते हैं।

अन्त में उन आवश्यकताओं की चारी आती है जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य विलासिता की वस्तुओं (Luxuries) का उपभोग करता है। इन चीजों पर जो रकम खर्च की जाती है उससे बहुत कम कार्य-कुशलता मिलती है। कर्म-रुमी तो इन वस्तुओं के उपभोग से कार्य-कुशलता बढ़ने की जगह घटने लगता है। उदाहरणस्वरूप खूब बढ़िया आलौशान महान, बहुत कीमती भड्काली पोशाक व विलासिता हिन्की और अगूरी शराब इत्यादि गिनाई जा सकती हैं। विलासिता की वस्तुओं का सेवन करने से आदमी को आलस्य घेर लेता है और काम करने की नी नहीं चाहता। शराब इत्यादि के सेवन से तो आदमी बिल्कुल बमजोर, नाकाम और गैर-यत्न जाता है।

बिजली के लैम्प इत्यादि आराम की वस्तुयें समझी जावेगी। सायवेरिया में मोटे ऊनी कपड़े आवश्यक हैं परन्तु भारत में आराम देने वाले हैं।

### आवश्यकता की पूर्ति (Satisfaction of Wants)

अब प्रश्न उठता है कि आवश्यकता पूरी किस प्रकार की जाती है। यह तो सब को मालूम है कि हर आदमी पहले अपने खाने-पीने की वस्तुयें खरीदता है। अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार भी यही नर्ताजा निकलता है कि मनुष्य अधिकतर जीवन-रक्षक वस्तुओं का उपभोग करे और आराम व विलासिता की चीजों का उपभोग करने में रुपया-पैसा की फिजूलखर्ची न करे। परन्तु इस बात पर हम बाद में विचार करेंगे। यहाँ पर पहले यह जानना आवश्यक है कि बहुत सी आवश्यकताओं को तो आदमी सीधे-सीधे पूरा कर लेता है। मान लिया आपको पानी पीना है, आप नदी या तालाब पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर आपको जाड़े के दिन में नहाने के लिये पानी गरम करना है तो आप बटलोई में पानी भर कर आग पर चढ़ा देते हैं। जब कोई आवश्यकता सीधे-सीधे पूरी की जाती है तो किसी सम्पत्ति का उपभोग सीधे-सीधे किया जाता है। जैसे यहाँ पर बटलोई से काम लिया गया था। परन्तु अधिकतर आवश्यकता पूर्ति के लिये रुपये-पैसे कमाए जाते हैं और तब उन रुपयों से आवश्यक वस्तुएँ मोल ली जाती हैं। बढई हल, कुर्सी, मेज, आदि चीजे बना कर बेचता है; लोहार फाल, खुर्पा, फावड़ा वगैरह लोहे के सामान बनाता है। वस्तुओं को बेचने से जो पैसा बढई या लोहार को मिलते हैं उनसे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जरूरी वस्तुयें खरीदते हैं। कहने का मतलब यह है कि आवश्यकताओं के पूरा करने के प्रश्न की जगह हमें यह सोचना चाहिये कि कोई मनुष्य अपनी आमदनी के रुपये-पैसों को किस प्रकार खर्च करता है तथा खर्च करने का कौन सा तरीका सबसे उत्तम होगा।

### आय-व्यय (Income and Expenditure)

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है जीवन-रक्षक पदार्थ तो सब लोगों को सेवन करना चाहिये। इन पर किया गया खर्च हमेशा न्याययुक्त कहा जाता है। आराम की वस्तुओं पर किया गया खर्च भी बुरा नहीं है क्योंकि इनसे भी

कार्य-कुशलता बढ़ती है। लेकिन ऐश-आराम और विलासिता की वस्तुओं पर तथा मादक वस्तुओं पर किया गया खर्च अक्सर फिजूलखर्चों में सम्मिलित जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि आमतौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन-सी वस्तु जीवन-रक्षक है, कौन-सी आराम की और कौन सी चीज विलासिता की है। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति, आदत, स्थिति, फैशन व समय के मुताबिक एक वस्तु आवश्यक भी हो सकती है और आराम व विलासिता की सामग्रियाँ भी बन सकती है। अगर कोई किसान एक घड़ा खरीदे तो उसका यह खर्च फिजूलखर्चों में गिना जायगा। लेकिन यदि एक विद्यार्थी घड़ी खरीदता है तो शायद उसकी खरीद न्यायपूर्ण मानी जा सकती है। हमारा गरीब सीतल अगर अपने और बच्चों को भूखा रखकर या कर्ज लेकर घड़ी खरीदता है तो वह जरूर विलासिता की चीज खरीदता है। लेकिन अगर कोई अमीर मनुष्य ऐसा करे तो वह फिजूलखर्चों नहीं कहलायेगी। क्योंकि उसके पास इतना रुपया रहता है कि वह अपनी जरूरी आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरी कर सकता है।

कहा जाता है कि जीवन-रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएँ गिनी गिनाई हैं, और यदि उन्हीं को पूरा करने पर अधिक जोर डाला जायगा तो मनुष्य को अधिक उद्योग नहीं करना पड़ेगा, और मनुष्य जाति असभ्य बन जायगी। अधिक सभ्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम नई बातों का आविष्कार करें और नई नई वस्तुएँ बनावे, जैसे रेडियो, टेलीफोन, हवाई जहाज। ठीक है, लेकिन हमारे गरीब भारत के लिए समय देखकर ही काम करना चाहिये। हमारे किसानों का क्या हालत है? क्या उन्हें जीवन-रक्षा के पदार्थ प्राप्त हैं? अन्दाज लगाया गया है कि जेल के अन्दर कैदियों को जो भोजन मिलता है वह भी बाहर के अधिकांश मनुष्यों को नमक नहीं होता। ऐसी हालत में विलासिता की वस्तुओं पर किया गया खर्च बिल्कुल फिजूल है। इसके अलावा हम बना चुके हैं कि हमारे मजदूर और छोटे शिल्पकार अपनी आमदनी का अधिकांश भाग तम्बाकू, शराब, धूम्रपान आदि मादक वस्तुओं के सेवन में उड़ा देते हैं। ऐसी हालत में हमारे बच्चों को कहीं से धी-बूध मिल सकता है जिससे वे भविष्य में तन्दुरुस्त और कार्य-कुशल बनें। तो फिर धन को किस प्रकार से खर्च करना चाहिये? उत्तर है इस

तरह से जिससे न केवल हमको अधिक से अधिक सुख मिले बल्कि जिससे देश में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा जनसमूह को जीवन-रक्षक वस्तुएँ मिलें। जब तक यह हालत न हो जाय तब तक आराम व विलासिता की वस्तुओं को खरीदना फिजूलखर्ची में गिना जाना चाहिये। इसके बाद जब इन चीजों की भी बारी आवे तब ऐसी वस्तुओं का उपभोग न करना चाहिये जिनसे थोड़ी देर के आनन्द के सिवा और कुछ न मिले, जैसे नाच, खेल, तमाशा, आतिशबाजी। इनमें तो जो सामग्री उसके बनाने में लगाई जाती है वह मिनटों में जलकर खाक हो जाता है। अर्थात् देश का उतना धन नष्ट हो जाता है।

### व्यय के सिद्धांत

तो फिर धन का किस प्रकार व्यय करना चाहिए? उत्तर है, इस तरह कि न केवल हमको अधिक से अधिक सुख मिले बल्कि जिससे देश में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा जन-समूह का जीवन-रक्षक वस्तुएँ मिलें। जब तक ऐसा न हो, आराम और विलासिता की वस्तुओं को खरीदना फिजूलखर्ची है। पान्तु किसी समय भी ऐसा वस्तुओं का उपभोग वाछनीय नहीं है जिनसे क्षणिक आनन्द मिले और देश का धन बर्बाद हो, जैसे आतिशबाजी।

उपयुक्त व्यय के लिए यह आवश्यक है कि अपनी आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान हो तथा उनका तुलनात्मक दृष्टि से पहचानने की भी शक्ति हो। आवश्यकता पूर्ति के कई साधन (वस्तुएँ) होते हैं—कोई टिकाऊ, कोई देखने में भडकाला, कोई दर असल उपयोगी। व्यय करने वाले को वस्तुओं को पहचानने की भी शक्ति होना चाहिये। इसके अतिरिक्त उसे यह मालूम हो कि कौन वस्तु कहाँ अच्छी और सस्ते दाम में मिलता है।

### बचत (Saving)

एक बात और है। क्या मनुष्य को अपनी आमदनी का एक भाग भविष्य के लिए निकाल कर अलग नहीं रख देना चाहिए? कौन जानता है कि जो मनुष्य आज सम्पन्नशाला है वह भविष्य में भा वैसा ही बना रहेगा?

बार-बार अचानक ऐसे कारण आकर उभर आते हैं कि लखपती भी रोटियों को मोहताज हो जाते हैं। इसके अलावा जब आदमी बुढ़ा हो जाता है या चारपाई पकड़ लेता है तब अपनी जिन्दगी को

पुराने ही तरीके से बिताने के लिये उसे पहले से रुपये बचाने पड़ते हैं। इससे अलावा बहुत से सज्जन अपने पुत्रों को पढ़ाकर कमाने योग्य बनाना चाहते हैं और पढ़ाई के लिए उन्हें पैसा संचय करना पड़ता है। बहुत से मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद लड़कों को कुछ धन-दौलत छोड़ जाना चाहते हैं। कुछ आदमी बाद में तीर्थ-यात्रा करना चाहते हैं। कितने तो दान-पुण्य के लिये धन इकट्ठा करना चाहते हैं। इन सब बातों के लिये धन इकट्ठा करना अर्थात् बचाना पड़ता है। बचाई हुई रकम बचत कहलाती है।

बचत कितनी करनी चाहिये और कैसे ? इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य यह बात है कि भविष्य के महत्व के बारे में आदमी-आदमी की राय में फर्क रहता है। कोई भविष्य को मानते ही नहीं। उनका उद्देश्य खा-चाट सब बराबर कर देना रहता है, क्योंकि कौन जानता है कि कब यमदेव का बुलावा आ पहुँचे। ऐसे लोग अपनी आय का अधिकांश भाग थोड़ी देर तक मना देने वाली चीजों पर खर्च करते हैं। लेकिन जो दूरदर्शी होते हैं वे ऐसे खर्च को ताक पर रखकर रुपये को भविष्य के लिये बचा लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम पहले ही बता चुके हैं कि बिना बचत किए पूँजी नहीं बनती। अगर स्वयं या बच्चों को कोई व्यापार या रोजगार कराना है तो बचत करना अनिवार्य है।

परन्तु बचाना कैसे चाहिये ? क्या यह सब से अच्छा होगा कि रुपये को या उन रुपयों से सोना-चाँदी मोल लेकर उनको धरती में गाड़ दें ? हमारे भारत में गहनों के रूप में बहुत सा धन बेकार पड़ा हुआ है। और चूँकि यहाँ पर हर एक आदमी की इतनी भी आमदनी नहीं है कि वह जीवन-रक्षक पदार्थ भी प्राप्त कर सके, इस बात की बड़ी जरूरत है कि बचत की रकम ऐसे काम में लगाई जाय, जिससे देश की पूँजी बढ़े। लेकिन यह तो बहुत दूर की बात है। आप यों ही देखिये। बचत के रुपयों को गहने के रूप में रखने से आपने उस रकम पर कोई सूद तक नहीं मिलता। इस तरह से रकम रखने और गाड़ कर रुपया पैसा रखने में कोई अधिक फर्क नहीं मालूम पड़ता और यह साफ है कि यह तरीका ठीक नहीं। परन्तु अगर गहना बनवाने के नाम पर ही लोग बचत करने को तैयार हों तो यह तरीका अपनाना वाञ्छनीय होगा। परन्तु यह बचत पूँजी का रूप तभी लेगी



जब सरकार सोना-चाँदी सप्लाई करे। अस्तु सब से अच्छा तरीका तो यह होगा कि जैसे-जैसे बचत होती जाय वह डाक-घर या किसी अच्छे बैंक के सेविंग बैंक के हिसाब में जमा कर दी जाय। इससे कुछ सूद मिलने के अलावा रुपया सुरक्षित रहता है। दूसरा तरीका जमीन खरीदना या मकान बनवाना है। इससे भी रकम सुरक्षित रहती है और आमदनी अच्छी होती है। कुछ मनुष्य अपने बुढ़ापे के लिये अथवा अपने सहारे रहने वाले आदमियों को मदद करने के लिये जीवन बीमा करवा लेते हैं। इसके लिये कई-कई साल तक हर साल एक निश्चित रकम बीमा कम्पनी को देनी पड़ती है। अवधि खतम हो जाने पर बीमा की रकम बीमा कराने वाले बुढ़े को या उसकी मृत्यु पर उसके आश्रितों को मिल जाती है।

कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसे अन्न और कपड़े-लत्ते का दुःख नहीं है अपनी आय में से कम से कम दसवाँ हिस्सा हर साल बचाने का दृढ प्रयत्न करना चाहिये। यदि वह ऐसा करने में सफल होगा तो इस बचत की वजह से मुसीबत के बुरे दिनों में कर्जदार होने से बच जायगा और हमेशा सुखी बना रहेगा।

## अभ्यास के प्रश्न

- १—उपभोग की परिभाषा लिखिये और उसका महत्व समझाइये।
- २—आवश्यकताओं की विशेषताएँ लिखिये और उन पर नियन्त्रण की जरूरत समझाइये।
- ३—आवश्यक वस्तुओं के भेद उदाहरण सहित समझाइये। अपने निपुणतादायक आवश्यक पदार्थ और कृत्रिम आवश्यक पदार्थों की सूची दीजिये।
- ४—आराम की वस्तुएँ और विलासिता की वस्तुओं के भेद बतलाइये। किसी किसान की विलासिता की वस्तुओं की सूची तैयार कीजिये।
- ५—मादक वस्तुओं के उपभोग से क्या हानियाँ होती हैं।
- ६—गाँवों में तम्बाकू का उपभोग बहुत होता है। क्या आप इसे समझते हैं?
- ७—कुछ स्थानों में चाय का उपभोग बढ़ रहा है। क्या इसका प्रचार आवश्यक है?

८—सिद्ध कीजिये कि सादा जीवन और उच्च विचार ही आर्थिक दृष्टि से भी सर्वोत्तम ध्येय है ।

९—बिना आमदनी के बढ़ाये संतोष की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है ?

१०—खर्च में बचत की आवश्यकता समझाइये । साधारण परिस्थिति के व्यक्तियों को कम से कम प्रतिमास कितनी बचत करनी चाहिये ?

११—आर्थिक दृष्टि से दानधर्म की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है ? भारत में इस प्रणाली के अनुसार दान कहाँ तक होता है ?

१२—अपनी बचत के धन से सोने-चाँदी के गहना बनवा लेना कहाँ तक उचित है ?

## सातवाँ अध्याय

### भारतीय रहन-सहन का दर्जा

#### रहन-सहन का दर्जा (Standard of Living)

पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएँ अपरिमित होती हैं । फिर भी आदमी अपनी आमदनी अपनी दशा और परिस्थिति के अनुसार कुछ वस्तुओं का उपभोग करने में लगाता है । इन चीजों के उपभोग का जो ढर्रा पड़ जाता है वह बहुत कम बदलता है, और यदि बदलता है तो बहुत धीरे-धीरे । जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्च भी किया जा सकेगा । आमतौर पर एक-सी आमदनी वाले मनुष्य या परिवार करीब-करीब एक ही समान रहते हैं । अर्थात् उनके रहन-सहन का दर्जा एक-सा ही होता है, और जैसे-जैसे आमदनी में कमी-बेशी होगी वैसे ही वैसे रहन-सहन के दर्जों में भिन्नता पाई जाती है । यों तो एक तरह से प्रत्येक मनुष्य अथवा प्रत्येक परिवार एक दूसरे से सभी बातों में कभी भी मिलता-जुलता नहीं है, इसलिये जितने परिवार हैं, उतने ही रहन-सहन के दर्जे हो सकते हैं । लेकिन साधारणतः रहन-सहन के दर्जे चार भागों में बाँटे जाते हैं । पहले दर्जे में वे लोग शामिल रहते हैं जिन्हें जीवन-रक्षक पदार्थ

भी प्राप्त नहीं होते तथा जिन्हें कई-कई दिन तक उपवास करना पड़ता है । इस दर्जे के मनुष्य भीख मांगते हैं और कर्ज भी लेते हैं । इन्हें दरिद्र कहा जाय तो गलत न होगा । हमारे गरीब मजदूर व किसान इसी दर्जे में रखे जा सकते हैं । दूसरा दर्जा उन लोगों का है जिन्हें जीवन-रक्षा सम्बन्धी साधारण पदार्थ ही प्राप्त हो सकते हैं । दोनो वक्त रूखा-सूखा भोजन खाना, फटा-पुराना कपड़ा पहनना व टूटे-फूटे मकान में रहना ही इन लोगों का काम रहता है । तीसरे दर्जे वाले मनुष्यों को जीवन-रक्षक वस्तुओं के अलावा आराम की भी वस्तुएँ मिल जाती हैं । दफ्तर में काम करने वाले हमारे हेडक्लर्क साहब खूब अच्छा खाना खाते हैं, साफ-सुथरा कपड़ा पहनते हैं तथा खुले हुए हवादार मकान में रहते हैं । ये आराम की वस्तुओं का भी सेवन करते हैं । चौथे दर्जे में रईस और अमीर आदमी आते हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं रहती । जो वे चाहे खरीद सकते हैं । उनका जीवन पूरी तरह से विलासिता से पूर्ण होता है, परन्तु यह कोई जरूरी नहीं कि जो लखपती है उसके रहन-सहन का दर्जा सबसे ऊँचा हो । अगर रईस मनुष्य का स्वास्थ्य खराब रहता है और उसे कोई चीज नहीं पचती, तो उनका रहन-सहन सुख देने लायक नहीं होगा । इसी तरह के आदमियों को ऐमा रोग पकड़ लेता है कि उनका असर उनके रहन-सहन पर बहुत पड़ता है । मेवालाल की आँखें खराब हों, हीरा बहरा हो, प्रेम की आँतों में कीड़े पड़ गये हों तो ये लोग उपभोग की चीजों से पूरा-पूरा सतोष और आनन्द नहीं उठा सकते । इसी तरह बहुत से तन्दुरुस्त और तगड़े आदमी शराब, ताड़ी वगैरह पीकर या अनाम-शनाम खाकर या बुरी सोहबत में पड़ जाने के कारण अपने को बरबाद कर देते हैं । फलस्वरूप उनका रहन-सहन का दर्जा गिर जाता है ।

### भारतीय रहन-सहन का दर्जा

ऊपर बताई बातें हमारे भारत पर कुछ लागू होती हैं । यहाँ पर पहले तो आमदनी की कमी है । अदाजा लगाया गया है कि भारत के राजा-ज, सेठ-साहूकार, रईस वगैरह को मिलाकर भी, हर एक भारतीय को आमदनी का औसत चार-पाँच आने ही पड़ता है । इसके अलावा की भी कमी मालूम पड़ता है । सरकार की ओर से यह कहा जाता

है कि भारतवासियों के रहन-सहन का दर्जा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ आराम की जितनी सामग्री आती थी, उनसे कहीं अधिक वस्तुएँ आज-कल आती हैं। देहातों में पक्के मकान बनते जाते हैं। साइकिल का प्रचार बहुत अधिक हो गया है। चाय और सिगरेट की खपत अधिक हो गई है। इत्यादि। परन्तु इस तरह कहने वाले एक बात भूल जाते हैं कि यह मनुष्य को स्वाभाविक आदत है कि वह भोगविलास के पदार्थों का सेवन करना चाहता है और यदि कोई मनुष्य जीवन-रक्षक वस्तुओं को खाने के बजाय शौकीनी करने लग जाय तो क्या इसके यह मतलब होते हैं कि उसका रहन-सहन ऊँचा हो गया। यदि आप ख्याल करिये तो आपको अपने साथियों में ही कितने ऐसे मिल जायेंगे जिनके घर में भूँजी भाँग न होगी पर स्कूल खूब टाट-चाट से आते हैं। आप अपने घर के बूढ़े बाबा से पूछिये तो वे आपको बतलावेंगे कि भारत का पतन हो रहा है। इसका कारण पूछने पर वे शायद आपको यही जवाब देंगे कि जहाँ पहले पौष्टिक पदार्थों का सेवन करते थे और सदैव व्यायाम का ख्याल रखते थे, वहाँ आजकल ऐसी बातों पर अधिक खर्च किया जाता है जिससे शरीर को भी नुकसान पहुँचता है और मानसिक हानि भी होती है।

### रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने का उपाय

अतएव यह बहुत जरूरी है कि भारतवासियों का रहन-सहन, का दर्जा ऊँचा किया जाय, परन्तु हमारा मतलब यह नहीं है कि केवल भोग-विलास की वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि हो, या आराम देने वाले पदार्थों का उपभोग बहुत अधिक बढ़ जाय। दस-बीस फसदी मनुष्यों के रहन-सहन के दर्जे के ऊँचा होने से देश के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता तो इस बात की है कि पहले तो हर एक आदमी को जीवन-रक्षक वस्तुएँ तथा वे पदार्थ मिल जायें जिनसे वह कार्य-कुशल भी बना रहे। देश के सब आदमियों का जीवन सुखमय होना चाहिये। ऐसे मनुष्य बिल्कुल न बचे जो अपने जीवन-रक्षक पदार्थों के लिये ही लालायित हों। हमारे गिरे हुए दर्जे को ऊँचा करने के लिये यह आवश्यक है कि हमें अच्छा तथा स्वास्थ्यप्रद भोजन भर पेट मिले। भोजन अच्छा होने के लिये यह जरूरी है कि खाना साफ बर्तनों में पकाया जाय। भोजन के बाद कपड़े को

बारी आती है। हम जानते हैं कि गरमी, जाड़ा, बरसात इत्यादि का शरीर पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप जाड़े में रुई की मिर्जई न पहनेंगे अथवा कम्बल न ओढ़ेंगे तो आपको ठंड लग जायगी। हर समय गंदे कपड़े पहने रहने से तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी प्रकार रहने के मकान साफ जगह पर बने होने चाहिये। उसके कमरों में रोशनी, सफाई, पानी इत्यादि का इन्तजाम होना चाहिये। एक परिवार के रहने के लिए मकान में, जिसमें पाँच छः आदमी हों, कम से कम चार पाँच कमरे होने चाहिए। तन्दुरुस्ती के लिए कसरत, खेल-कूद, नींद भी बहुत आवश्यक है और थक जाने पर किसी प्रकार के मनोरञ्जन का इन्तजाम रहना चाहिये।

भारतवासियों के रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा करने के लिये यह जरूरी है कि शिक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाय। शिक्षा प्राप्त मनुष्य अधिक कमा सकते हैं। इसके अलावा वे उपयोगी वस्तुओं का उपभोग इस प्रकार से करते हैं कि उनसे अधिक आराम मिलता है। इसके अलावा ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे भारत में सतान वृद्धि कम होवे। इस समय भारत की आबादी उन्तालिस् करोड़ के लगभग है। यदि जनसंख्या घट जाय तो हमको उद्योग के लिये अधिक सामग्रियाँ मिलने लग जायँ। बहुधा देखा गया है कि दूमरों को देख कर आदमी उसी की तरह रहने का प्रयत्न करता है। इससे रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो जाता है। यात्रा करने से हमको बाहर का अनुभव होता है और हम अच्छी वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं। इन सब बातों के अलावा इस बात की कोशिश होनी चाहिये जिससे हमारे किसानों का कर्ज किसी प्रकार कम हो। हमारे किसान भाई कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में पलते हैं और कर्ज को छोड़कर ही मर जाते हैं। परन्तु ये सब काम उस समय तक नहीं हो सकते जब तक कि हमारी सरकार हमारी मदद को न आवे। सरकार की ओर से स्कूल, लाइब्रेरी, दवाखाने, पार्क इत्यादि का प्रबन्ध होना चाहिये। गरीबों को मुफ्त में ही प्रारम्भिक शिक्षा देने का इन्तजाम आवश्यक है। सरकार चाहे तो किसानों का कर्ज। इसके अलावा सरकार उद्योग-धन्धों को मदद दे सकती है। न्या की उन्नति से बेकारी दूर हो सकती है और रहन-सहन का दर्जा है।

## पारिवारिक बजट ( Family Budget )

अब तक जो कुछ कहा गया है उसकी जड़ मनुष्य के रहन-सहन के दर्जे में है। उसको भली भाँति समझने के लिए हमको यह पता लगाना चाहिये कि कौन व्यक्ति कितनी आमदनी करता है तथा वह उस धन को किस प्रकार खर्च करता है। रहन-सहन का दर्जा निश्चय करने के लिए मनुष्यों के आय-व्यय का अध्ययन करना अनिवार्य है। अंग्रेजी में आय-व्यय सम्बन्धी लेखों को बजट कहते हैं। इस शब्द का अब हिन्दी में भी प्रयोग होने लग गया है। किसी मनुष्य या परिवार के बजट के अन्दर यह देखा जाता है कि उस परिवार में कितने मनुष्य हैं, कितनी कमाई करते हैं, वे कैसे मकान में रहते हैं, उनकी उम्र, योग्यता, शिक्षा आदि क्या है ? परिवार की होने वाली आय क्या है ? यह किस प्रकार खर्च की जाती है ? अन्त में कुछ बचत भी होती है अथवा परिवार वालों को कर्ज लेना पड़ता है ? रहन-सहन का दर्जा निश्चय करने के लिए व्यय सम्बन्धी आँकड़ों से बड़ी सहायता मिलती है।

पारिवारिक बजट का महत्व केवल यही नहीं है कि इससे रहन-सहन का दर्जा निश्चित होता है। इसका अन्य महत्व भी है। उनमें से दो-एक का उल्लेख किया जाता है। प्रथम पारिवारिक बजट को ठीक से इकट्ठा करने पर यह मालूम किया जा सकता है कि पारिवारिक व्यय अनावश्यक कामों में तो नहीं हो रहा है। उदाहरणार्थ आजकल के जमाने में यह सम्भव है कि किसी परिवार में अच्छा भोजन न किया जाता हो और बीमार पर अधिक खर्च होता हो। इन बातों का पता लग जाने से सरकार शिक्षा द्वारा जनता की आदत सुधारने का प्रयत्न कर सकती है। द्वितीय, यदि पारिवारिक बजट ऐसा हो कि उससे मालूम पड़ जाय कि पारिवारिक आय किन-किन वस्तुओं की खरीद में खर्च को गई तो सरकार तथा उत्पादक उन वस्तुओं की उत्पत्ति करने का प्रयत्न करेंगे। भारत की आर्थिक उन्नति हो रही है। भाँति-भाँति के उद्योग-धन्धे खोले जा रहे हैं। यह प्रश्न उठता है कि कौन से उद्योग-धन्धे खोले जायें ? किस वस्तु की उत्पत्ति कहाँ तक बढ़ाई जाय ? यदि पारिवारिक बजट के उपयुक्त आँकड़े प्राप्त हों तो इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है।

विविध व्यय सम्बन्धी अकों के अध्ययन करने से यह निश्चय हुआ है कि जिस दर से एक कुटुम्ब की आमदनी बढ़ती है, भोजन का व्यय उसी दर से नहीं बढ़ता। लेकिन वस्त्र, मकान-भाड़े का खर्च उसी दर से बढ़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सामग्री के व्यय की वृद्धि का दर आमदनी की वृद्धि की दर से अधिक बढ़ जाता है। जर्मन निवासी डाक्टर एंजिल हजारों परिवार के बजट को देखकर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कम आमदनी वाले परिवार का अधिकांश भाग जीवन-निर्वाह में खर्च हो जाता है। लेकिन वस्त्र पर प्रत्येक परिवार में प्रतिशत खर्च लगभग बराबर होता है अर्थात् यदि पचास रुपये आमदनी वाले के वस्त्र में करीब आठ रुपये खर्च होते हैं तो सौ रुपये आमदनी वाले का सोलह, और हजार रुपया आमदनी वाले का करीब एक सौ आठ रुपया खर्च होता है। इसी तरह किराये में, रोशनी और ईंधन में भी प्रत्येक परिवार में प्रतिशत खर्च बराबर होता है। लेकिन यह बात जरूर है कि अधिक आमदनी वाले परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा इत्यादि में प्रतिशत खर्च बढ़ जाता है।

### किसान का खर्च

ऊपर कही बातों को और स्पष्ट करने के लिये दो-तीन परिवार के बजट का विवेचन करना आवश्यक मालूम पड़ता है। और चूँकि भारत कृषि-प्रधान देश है इसलिये पहले किसानों की ओर ही दृष्टि डालना उचित जान पड़ता है। यों तो आप को सुखी-किसान भी शायद कहीं-कहीं मिल जायेंगे। हमको उनसे अधिक मतलब नहीं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। अस्तु, भारतीय किसान के रहन-सहन का दर्जा बिल्कुल नीचा है। उसके कुटुम्ब की मासिक आमदनी पन्द्रह रुपये से कम ही रहनी है। यह पता लगाया गया है कि उत्तर-प्रदेश में किसानों की वार्षिक आमदनी सत्तर से नब्बे रुपये के बीच रहती है। इसी से हम इनके रहन-सहन के दर्जे का अनुमान लगा सकते हैं। इन बेचारों को साल भर हमेशा दोनों वक्त सूखा-सूखा भोजन भी नहीं मिलता। पहनने का कपड़ा बहुत ही मामूली, फटा मैला रहता है। अक्सर ये लोग एक साधारण छप्पर में ही गुजर करते हैं। फिर यह पाया गया है कि जो परिवार बहुत गरीब होता है उसमें संख्या बहुत अधिक होती है। इन गरीबों के बच्चे खाली एक कपड़ा

पहिनते या कभी-कभी नगे ही घूमा करते हैं। इन बच्चों को दोनों वक्त दूध, घी या अच्छा खाना तक नहीं मिलता है। उनका पढ़ाई लिखोई का तो कोई परवाह नहीं करता। भारत में शायद ही कोई किसान ऐसा हार्ग जो बर्जशर न हो। किसी का तो यह मत है कि वह कर्ज लेकर पृथ्वी पर आता है, जिन्दगी भर महाजन के यहाँ रुक्या भरता है और अन्त में कर्ज छोड़ कर ही मर जाता है। बिना कर्ज के तो इनका काम ही नहीं चलता। बीज, पशु, औजार या व्याह-शादी का तो छोड़ दोजिये, बेचारा किसान अपने रोज के खर्च के लिये भी कर्ज लेता है। उसको मरकरी लगान भी देना पड़ता है। इसी में उसकी आमदनी का काफी बड़ा हिस्सा निकल जाता है। फिर कर्ज की रकम का बोन बट्टे, वह उसका व्याज तक चुका नहीं पाता।

नीचे एक गरीब और एक मामूली किसान के मन महायुद्ध के पहिले के सालाना पारिवारिक खर्च का ब्योरा दिखाया गया है :—

	मामूली किसान का खर्च (रुपये में)	गरीब किसान का खर्च (रुपये में)
भोजन	६८	४६
कपड़ा	२०	१३
घर	१३	—
रोशनी व लकड़	५	५
बच्चा	१	३
अन्य	४	—
सारा सालाना	१२०	६७



ने केवल लगभग आधी आमदनी भोजन पर खर्च की। दोनों परिवारों की आमदनी का लगभग १६% अर्थात् छठाँ भाग कपड़े पर खर्च हुआ। दान धर्म, यात्रादि पर भी दोनों परिवारों ने अपनी आमदनी का लगभग वही भाग अर्थात् ६% खर्च किया। शिक्षा, दवा आदि की अपेक्षा दान, धर्म आदि पर अधिक खर्च हुआ। इससे भारतीय किसानों की धार्मिक प्रवृत्ति का ज्ञान होता है।

### गाँव के मजदूर और उनका खर्च

अतएव यह तो सिद्ध हो गया कि भारतीय किसान बड़े कष्ट और श्रम से अपना जीवन निर्वाह करता है। किसान का दूमरा भाई है गाँव का मजदूर। कुछ सज्जनों का कहना है कि इनकी हालत तो किसानों से भी खराब है। किसान इन लोगों पर जमींदारी हुकुम चलाते हैं अर्थात् जैसे जमींदार किसानों से बेगार लेते हैं तथा उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं वैसे ही किसान लोग इन मजदूरों के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात तो यह है कि इससे और मजदूर के पारिवारिक व्यय से विशेष सम्बन्ध नहीं है। पर यह जरूर है कि इससे मजदूरों की आय कम हो जाती है। मजदूरों और किसानों के बीच केवल एक फर्क पाया जाता है और वह यह कि किसानों की आय प्रकृति के ऊपर निर्भर रहती है। लेकिन मजदूरों की मजदूरी कुछ न कुछ नियमित होती है। परन्तु सोचने लायक बात तो यह है कि अक्सर मजदूरों का हिस्सा बाँव दिया जाता है। किसान के पास जो अनाज रहता है वह स्वयं उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसी में से उसको मजदूर की मजदूरी देनी पड़ती है। अतएव मजदूर की मजदूरी के रूप में वह कम से कम अनाज देने का प्रयत्न करता है। ऐसी दशा में मजदूर तो सचमुच किसानों से भी गये बीते बन जाते हैं, तब भी हम उन्हें बिना अधिक गलती किए किसानों के रहन-सहन के दर्जे में रख सकते हैं।

### गाँव के कारीगर का व्यय

भारतीय गाँवों में यदि किसी की हालत किसानों और मजदूरों से अच्छी हो जा सकती है तो वह है गाँव के शिल्पी या कारीगर की हालत। उसे न प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है और न मजदूरों की तरह उनकी चुटिया के हाथ दबी रहती है। यदि यह कहा जाय कि गाँव के कारीगर

की मासिक आमदनी पंद्रह रुपये के ऊपर पहुँच जाती है तो कोई गलत बात न होगी। बहुत से परिवारों के बजट को देखने के बाद पता चलता है कि ये लोग भा खाने की चीजों पर आधी से अधिक रकम खर्च कर देते हैं। रोशनी और ईंधन पर इनकी आमदनी का बीसवाँ हिस्सा खर्च होता है और कपड़े-लत्ते पर लगभग दस प्रतिशत। मकान का किराया, रोशनी और ईंधन का खर्च बराबर होता है। आमदनी का बचा हुआ पाँचवाँ भाग अन्य वस्तुओं पर खर्च कर दिया जाता है, हालाँकि घी, दूध तो इन्हें भी नहीं के बराबर ही मिलता है। सफाई और रोशनी का भी इन्तजाम खराब रहता है और किसानों की तरह इनमें भी शराब या ताड़ी पीने की बुरी आदत पाई जाती है। यह बात भी नहीं है कि ये कर्ज न लेते हों और सूद की दर तो हमेशा की तरह पचहत्तर अस्सी प्रतिशत सालाना से कम नहीं होती। शिक्षा और स्वास्थ्य के सन्बन्ध में ये लोग भी बहुत कम खर्च करते हैं।

### अभ्यास के प्रश्न

१—रहन-सहन के दर्जे का अन्दाजा किन-किन बातों से लगाया जाता है ?

२—अपने गाँव के साधारण किसान के रहन-सहन के दर्जे की तुलना उसी गाँव के मजदूर के रहन-सहन के दर्जे से कीजिए।

३—अमीर लोग किन वस्तुओं पर अपना रुपया अधिक खर्च करते हैं ?

४—अपने गाँव में कम से कम एक साधारण किसान, एक अमीर किसान और एक गरीब किसान के आय-व्यय का एक मास का हिसाब लगाइये और यह बतलाइये कि निम्नलिखित मदों पर कितना प्रतिशत खर्च प्रत्येक दर्जे के किसान ने किया :—

(अ) भोजन (ब) कपड़ा (स) मकान भाड़ा (द) शिक्षा (क) मुकदमे-वाजी (ख) मादक वस्तु (ग) दान धर्म (घ) अन्य खर्च।

५—किसी कुटुम्ब के मासिक आय-व्यय का हिसाब देखकर हम यह किस प्रकार बता सकते हैं कि व्यय अच्छे तरीके से किया जा रहा है या नहीं ?

६—रहन-सहन का दर्जा ऊँचा कर देने के क्या तरीके हैं ? उनका उपयोग भारत में कहाँ तक किया जा रहा है ?

७—पारिवारिक आय-व्यय रखने की आवश्यकता समझाइये ।

८—अपने कुटुम्ब के मासिक व्यय की आलोचना कनिये ।

९—यात्रा का रहन-सहन के दर्जे पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

१०—रहन-सहन का दर्जा बढ़ाने में शिक्षा का महत्व समझाइये ।

११—रहन-सहन के दर्जे का अर्थ समझाइये । गाँव में रहन-सहन का दर्जा क्यों नीचा है ? उसे किम प्रकार ऊँचा किया जा सकता है ?

१२—ग्रामीण जनता की दीनता के कारण स्पष्ट कीजिये । उत्तर प्रदेश में उनकी दशा का उन्नत बनाने के लिए कौन से प्रयत्न किये गये हैं ? (१९४६)

१३—आप रहन-सहन के दर्जे से क्या समझते हैं ? गाँवों में यह क्यों बहुत कम है ? इसे किम तरह बढ़ाया जा सकता है ? (१९४४)

## आठवाँ अध्याय

### भोजन कितना और कैसा हो ?

#### भोजन की आवश्यकता

अब तुम जान गए होगे कि हमारे रहन-सहन में भोजन बड़े महत्व का स्थान रखता है । अतएव बहुत जरूरी है कि हम यह जान ले कि हमको कैसा भोजन करना चाहिये । पहले यही बतलाइये कि आप भोजन क्यों करते हैं ? हम जो वस्तुये खाते हैं उनसे क्या मतलब निकलता है ? उत्तर में कहा जा सकता है कि हमें दो बातों की आवश्यकता रहती है । एक तो गर्मी की और दूसरे चर्बी की । आप अभी दिनों-दिन लम्बे-चौड़े होते जा रहे हैं और आपका डीलडौल बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि आप खाना खवें । भोजन करने से करीब पचीस साल का उम्र तक हमारे शरीर और दिमाग की वृद्धि होती है ताकि वे मजबूत बन सकें । दूसरे काम करने से शरीर और दिमाग में जो कमी हाता है उसकी भी आहार से पूर्ति होती है । जो हम खाते हैं उनमें से कोई बदन को गर्म रखता है और किसी से गोश्त है । बदन का चंगा रखने के लिए यह जरूरी है कि हम दोनों तरह

की चीजे खाया करे। हमको जितनी गोश्त बनाने वाली चीजों की जरूरत पड़ती है उससे चार गुना ज्यादा गर्म रखने वाली चीजों की है। अगर हम एक तरह का खाना जरूरत से ज्यादा खाले और दूसरी तरह का जरूरत से कम, तो हमारा पेट भर जायगा लेकिन हमारी तन्दुस्ती को नुकसान पहुँचेगा।

**चर्बी, प्रोटीन (Protein), चीनी और विटामिन (Vitamin)**

ऊपर बताया हुआ बातों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि हमको खास-खास वस्तुएँ खानी चाहिए, परन्तु अब यह कैसे समझा जाय कि कौन-कौन सी चीजे अवश्य खानी चाहिए और कितनी। इसके पहले यह बताना जरूरी है कि प्रत्येक भोजन की वस्तु से हमको तीन पदार्थ मिलते हैं चर्बी, प्रोटीन और चीनी। दही, घी, मक्खन तथा नारियल के तेल आदि में चर्बी की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन एक पदार्थ का अंग्रेजी नाम है। मिर्च, बादाम, मूँगफली, दाल, सूजी, बिना कूटे वा पालिश किये हुये चावल और गोश्त में प्रोटीन काफी होती है। इसी तरह शक्कर, शहद, गन्ना, आटा, चावल, जो व मुरब्बे वगैरह में चीनी बहुत होती है। चर्बी, प्रोटीन और चीनी के अलावा हमको विटामिन नाम के एक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन कई तरह के होते हैं :—जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D इत्यादि। हमको इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। दूध और फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है चर्बी, प्रोटीन व चीनी कम रहती है। लेकिन तब भी उनकी कदर इर्ष्यालिए की जाती है कि उनमें विटामिन होता है। गाय के दूध में ऊपर बताए चारों विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन A सबसे अधिक होता है। यह जरूरी नहीं कि हर एक चीज में ये चारों विटामिन हों जैसे—मिर्च, चाय, कहवा में विटामिन होता ही नहीं। गोभी, टमाटर आदि में पहले तीन विटामिन न्यून होते हैं। फलों में विटामिन C की अधिकता रहती है।

### भोजन के भेद

अस्तु, आजकल के प्रचलित भोजन तीन हिस्सों में बाँटे जा सकते हैं :—  
फल, अन्न और मांस। फल का आहार सबसे धेष्ट समझा जाना है। फलों के ऊपर रहने वाले प्रकृति देवी के पशु-पक्षी कितने सुन्दर, मनमोदक, रंग-  
प्रा० अ० शा०—६

बिरंगे और मधुर कंठ वाले होते हैं। योरुप के विद्वानों ने यह ढूँढ़ निकाला है कि फलों में एक तरह की बिजली होती है जिससे शरीर अच्छी तरह गठ जाता है। फलों के बाद अन्न का नम्बर आता है। रोटी, दाल, भात इन सब की गिनती अन्न में की जाती है। खाना जितना सादा होता है उतना ही अच्छा होता है। हमारे पूर्वजों का उद्देश्य रहता था, "सादा जीवन वृद्धि के विचार"। जो मजा तथा फायदा गेहूँ की बालियों में होता है वह गेहूँ में नहीं होता। गेहूँ से उतर कर रोटी का गुण होता है; उससे उतर कर पूड़ी का और अन्त में पकवानों का। आटा जितना मोटा हो उतना ही अच्छा होता है। आजकल चक्की में पिसने वाले आटे की बहुत सी चीनी गरमी के कारण जल जाती है। चावल के पकाने में उसका पानी अर्थात् माँड़ नहीं फेंकना चाहिये। पके हुए चावल में कुछ नहीं होता, सब गुण तो माँड़ में उतर आते हैं। हम लोगों में कूटे हुये चावल खाने की आदत है। कुटने से चावल का बहुत सा अंश अलग हो जाता है। इसी तरह से दाल को उसके छिलके के साथ खाना चाहिये। मूँग की छिलकेदार दाल में जो गुण होता है वह धुली मूँग की दाल में बिल्कुल नहीं रहता। तरकारियाँ खून व पेट को साफ करती हैं, इसलिये हमारे भोजन में तरकारियों का होना जरूरी है। उनसे पेट का हाजमा कभी बिगड़ने नहीं पाता। इसके अलावा इनमें विटामिन A, B, C, खूब होते हैं। डाक्टर लोग अनाहार में दूध को आवश्यक बताते हैं और थोड़ा सा घी भी। माँस खाने वाले के शरीर में अक्सर एक तरह का विष पैदा हो जाता है तथा माँसाहारी का मन उतना वश में नहीं रहता। योरुप तथा पश्चिम के अन्य देशों में माँसाहारियों का नम्बर घटता जाता है और फलाहार और अनाहार करने वाले मनुष्य संख्या में बढ़ते जा रहे हैं।

### उपयुक्त भोजन की मात्रा

हमारे पुरखे पहले जो खाना खाते थे अथवा उन्होंने रोटी, दाल, भात, तरकारी, घी, दूध का जो सादा खाना ठीक किया था उसमें हमें सब चीजें मिल जाती हैं। रोटी और भात में चीनी की भरमार है, दाल और दूध से मिलता है और अन्य पाचक पदार्थ मिल जाते हैं। आप कहेंगे कि पुराने जमाने की बातें हैं। आपका साथी राम पूछ सकता है कि

क्या रोटी ज्यादा खाई जाय और दूसरी वस्तुएं कम । श्याम कह सकता है कि मैं दूध तो खूब पीऊंगा परन्तु और चीजें केवल नाम करने को खा लूंगा । इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी वस्तु कितनी खानी चाहिये । रोटी या दूध से हमको जितनी गरमी चाहिये उतनी गोश्त बनाने वाली चीजों से नहीं मिल सकती और शक्कर, चावल, घी, मक्खन तो हमको सिर्फ गरम रख सकते हैं । जो लोग गोश्त खाते हैं उनको तो गर्मी पैदा करने वाली और गोश्त बनाने वाली चीजें उसी से मिल जाती हैं । किन्तु बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोश्त नहीं खाते । हिन्दुओं में तो गोश्त खाने का रिवाज कम है । उनको इसके बदले क्या खाना चाहिये ? मूंग, मटर, अरहर और इसी तरह की जितनी दालें हैं उन सब में गरमी पैदा करने वाली और गोश्त बनाने वाली दोनों तरह की चीजें होती हैं । सेर भर मांस में गोश्त बनाने वाली जितनी चीजें होती हैं उससे कहीं ज्यादा सेर भर दाल में होती हैं ।

किसी ने सच कहा है कि हमारे आहार में मास, मछली और अंडे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है । हमें पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन दूध, दही, मट्ठा मिलना चाहिए । इसके अलावा हमारे भोजन में रोज कुछ न कुछ कच्चे ( बिना आँच पर पकाये हुए ) पदार्थों का रहना बहुत जरूरी है । इसके लिए हरा मटर, हरा चना, टमाटर, मूली, गाजर, ताजे फल, वेर, ककड़ी, खरबूजा, खट्टे व मीठे नीबू का रोज सेवन करना चाहिये । इससे स्वास्थ्य बनने के अलावा हमारी आयु भी बढ़ जाती है । हमारे भोजन में गुड़ और शक्कर का रहना बिल्कुल आवश्यक नहीं है । इन्हे यदि थोड़ा सा खाया जाय तो कोई हानि नहीं होती पर ज्यादा खाने से ये नुकसान पहुँचाते हैं । बाजार की मिठाइयाँ तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिये । अस्तु, हिसाब लगाकर निश्चित किया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए एक युवा पुरुष को २४ घंटों में निम्नलिखित भोजन करना चाहिए :—

घर का पिसा आटा ६ छटाँक, दाल १ छटाँक, चावल २ छटाँक, घी आधी छटाँक, तरकारी ६ छटाँक, फल ४ छटाँक, दूध आधा सेर और थोड़ा सा नमक, जो कि खाना पचाने के लिए बहुत जरूरी है ।

भोजन उसी समय करना चाहिये जब खूब भूख लगी हो । यह न होना चाहिए कि बकरी की तरह हर समय मुँह चलता रहे । यह उसी समय हो

सकता है जब कि समय से खाना खाया जाय । खाने के अलावा पानी पीना भी बहुत जरूरी है । लेकिन ध्यान रखना चाहिये कि पानी हमेशा खाना खाने के आधा घंटा बाद पिया जाय । यदि पानी पीने की इच्छा बहुत तेज हो तो खाने के साथ दो चार घूँट पानी पी ले । चौबीस घंटे में दो सेर के लगभग पानी जरूर पीना चाहिए । गर्मों के दिनों में पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए ।

### अभ्यास के प्रश्न

१—एक युवा मनुष्य के लिए प्रतिदिन कितना भोजन स्वस्थ रहने के लिये आवश्यक है ?

२—आपके भोजन में कौन सी बातों का किस परिमाण में होना आवश्यक है ?

३—किसानों और मजदूरों के भोजन में किन बातों की कमी रहती है और यह बिना खर्च बढ़ाये कैसे दूर की जा सकती है ?

४—शहर में रहने वालों और गाँवों में रहने वालों के भोजन में क्या अन्तर रहता है ?

५—जैसे-जैसे आमदनी बढ़ने लगती है भोजन में किस प्रकार का अन्तर होने लगता है ?

६—प्रोटीन, चर्बी और विटामिन किन पदार्थों में अधिक होते हैं ?

७—भोजन में दूध, फल और हरी तरकारी का महत्व समझाइये ।

८—सात्विक भोजन के लिए किन वस्तुओं का उपभोग कितने परिमाण में करना चाहिए ?

९—तामसिक भोजन के पदार्थों की सूची दीजिये ।

१०—मानसिक परिश्रम करनेवाले व्यक्तियों को अपने भोजन में किन वस्तुओं का अधिक परिमाण में उपभोग करना चाहिये ?

११—भारत में भोजन की वर्तमान कमी के कारण क्या हैं ? इसे दूर करने के क्या उपाय हैं ? (१६४८)

१२—संतुलित भोजन किसे कहते हैं ? इसके मुख्य अंश क्या हैं ? (६४७)

## नवाँ अध्याय

### विनिमय (Exchange)

#### वस्तुओं की बदला-बदली (Barter)

लकड़ी का काम करने वाले बढई को बिना मोल लिये खाने को अनाज नहीं मिल सकता। वह कुर्सी, मेज, खिड़की, हल, गाड़ी, आदि बनाकर बेचता है। बेचने से जो दाम आता है उससे मंडी में जाकर वह अनाज खरीदता है। परन्तु क्या यह जरूरी है कि बढई माल को रुपये-पैसे के बदले बेचे ? हमारे गाँव में अधिकतर यह होता है कि किसान अनाज देकर अपने मतलब की वस्तु दूसरे से ले लेते हैं। अगर रामू को एक जोड़ा धोती लेना होता है तो वह पन्द्रह-बीस सेर अनाज देकर बजाज से उस धोती को ले लेता है। लोहार को जब अनाज की जरूरत पड़ती है तो वह किसी किसान को जिसे फावड़े आदि की जरूरत होती है, औजार देकर अनाज ले लेता है। पुराने समय में रुपया पैसा तो चलता नहीं था उस समय इसी तरह की बदला-बदली होती थी। हमारे गाँवों की तरह ही अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि देशों के असभ्य जंगली अब भी हाथी दाँत, गोंद, मोम, शुतुर्मुख के पर वगैरह देकर उनके बदले में हथियार, औजार और खाने-पीने की चीजें लेते हैं।

बदले के लिए कम से कम दो चीज की आवश्यकता होती है। जब हम यह कहते हैं कि किसी का बदला हो सकता है, तो हमारा मतलब यह रहता है कि उस चीज का बदला किसी और चीज से हो सकता है। लेकिन एक बात है। मान लो किसी बढई ने एक हल तैयार किया और वह उसके बदले अनाज लेना चाहता है। पर अनाज पैदा करने वाले किसान को उस समय हल की दरकार नहीं है। या अगर उसे हल की जरूरत है तो हो सकता है कि उसके पास बदले में देने के लिए काफी अनाज न हो। यह भी हो सकता है कि किसान हल को जगह अनाज को ज्यादा काम की वस्तु समझता हो और इसलिये हल की जगह अनाज न देना चाहता हो। ऐसी हालत में बेचारे बढई को किसी ऐसे किसान को ढूँढना पड़ेगा जिसे हल की जरूरत हो, जिसके पास अनाज भी काफी मात्रा में हो और जो हल को अनाज से



अधिक उपयोगी समझता हो । अदला-बदली हो जाने से दोनों को लाभ होता है । किसान को अनाज की अपेक्षा अधिक काम की चीज मिल जाती है, इसी तरह बढई को भी हल के बदले अनाज मिल जाने से लाभ होता है । अगर बढई को ऐसा कोई किसान नहीं मिलेगा तो वह भूखों मरने लगेगा । और फिर खाली अनाज से बढई का काम नहीं चलता । उसे नमक, मिर्च, तेल, खटाई आदि भी चाहिए । मान लो उसे हल के बदले अनाज मिल भी गया तो उसे ऐसे आदमियों की तलाश करनी पड़ेगी जो नमक, मिर्च, मसाला आदि देकर अनाज ले लें । इसी तरह दूसरे पेशे वालों को भी तङ्ग होना पड़ेगा क्योंकि सब को चीजे बदलने की जरूरत होती है । लेकिन अगर इसी तरह सब लोग अपनी चीजे लेने वालों का पता लगाने लगे तो बहुत बखेडा पैदा हो जाय । इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए रुपये-पैसे चलाए गए और आजकल हमें जब किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो हम बाजार जाकर उसे मोल ले लेते हैं । अर्थात् जिस मनुष्य के पास वह वस्तु रहती है उसे कुछ पैसे या रुपये देकर बदले में उस वस्तु को ले लेते हैं । किसी वस्तु की बिक्री से खरीदने और बेचने वालों को लाभ ही होता है, नुकसान नहीं । खरीदार रुपये की जगह उस वस्तु को ज्यादा काम की समझता है और बेचने वाले को रुपये की जरूरत रहती है ।

### माल की खरीद और बिक्री (Sale and Purchase)

हम जिस मनुष्य के पास से चीज मोल लेते हैं, वह सौदागर या व्यापारी कहलाता है, लेकिन सौदागर और व्यापारी में एक फर्क रहता है । व्यापारी थोक माल खरीदता है और जरूरत के मुताबिक बेचता है । सौदागर व्यापारियों से माल खरीदकर खाने या उपभोग करने वालों के हाथ बेचता है । व्यापारी एक फसल को एक जगह इकट्ठा करता है, फिर उसको साफ कराकर फुटकर बेचने वालों के हाथ बेच देता है । व्यापारी कम से कम दोनों के अनाज को मोल लेकर अधिक दाम पर बेचता है । किसान फसल तैयार होते ही बेच देते हैं । उस समय अनाज का भाव सस्ता रहता है । किसानों को अविचार नहीं होता कि अगर अनाज रक्खा रहेगा तो आगे चलकर काफी लाभ होगा । लेकिन दरअसल बात तो यह है कि हमारे की हालत ऐसी बुरी है और वे इतने कर्जदार रहते हैं कि वे अनाज

को घर में रख नहीं सकते। व्यापारी सस्ते अनाज को मोल ले लेकर बड़े भर लेता है और जब भाव खूब तेज होता है तब उसे बेचता है।

फसल तैयार होने के समय तो किसान प्रायः सब अनाज बेच देते हैं पर थोड़े दिन बाद उनकी रसद चुक जाती है। तब वे बनिये की शरण जाते हैं। बनिया उस समय अनाज किसानों को बाँटता है। और उनसे वादा करा लेता है कि फसल पर वे उसका सवाया देंगे। इसी तरह बोनी के समय वह किसानों को तेज भाव पर अनाज देता है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि बनिये को क्या लाभ होता है। मान लो फसल पर वह एक रुपये का चार सेर गेहूँ खरीदता है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर वह तीन सेर का अनाज बेचता है और वादा करा लेता है कि दूसरी फसल पर व्याज सहित इन रुपये का अनाज लेगा। फसल पर छै-सात महीने में व्याज सहित रुपये का फिर चार सेर के भाव से गेहूँ ले लेता है। इस तरह एक ही साल में दो गुना फायदा उठाता है। फसल की बिक्री में लाभ-हानि, देर-सवेर, तेजी-मन्दी का ध्यान रखने से यही लाभ होता है।

इस खरीद और बिक्री से बनिये व्यापारी को ही फायदा होता है। बेचारा किसान को तो नुकसान ही रहता है। अगर उपज कम होती है तो किसानों को अधिक दाम तो मिलते नहीं। हाँ, बनिया राम जरूरी माल को अधिक ऊँचे भाव पर बेचकर खरीदारों से ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये, उन्हें इन बनियों के हथकंडे से बचाने तथा उनकी हालत को अच्छी बनाने के लिये गाँवों में माल बेचने तथा किसानों के लिये उनके जरूरत की वस्तु खरीदने वाली कमेटियाँ (समितियाँ) बन गई हैं। इन कमेटियों को क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ कहते हैं। उन समितियों का काम यह होता है कि वे अपने सदस्यों की उपज अच्छे से अच्छे दामों पर बेचने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा समिति किसानों के लिये अच्छे-अच्छे एक तरह के बीज इकट्ठा करती हैं, अच्छी खाद का इन्तजाम करती हैं इत्यादि। आगे के किसी अध्याय में हमें इन समितियों के बारे में खुलकर हाल बतलाया जायगा।

### वाजार (Market)

अब प्रश्न उठता है कि माल कहाँ बेचा और खरीदा जाता है? तुम

जवाब दोगे, “बाजार में”। लेकिन बाजार से क्या समझा जाता है? ग्रामतौर पर जहाँ पर तरकारी-भाजी मोल लेते हैं अथवा जहाँ अपनी जरूरत की वस्तु या वस्तुएँ खरीदते हैं उस जगह को बाजार या मन्डी कहते हैं। गाँव में जानते हैं कि दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते बाजार लगता है। जगह-जगह म्यूनिस्पैल्टी पक्की इमारत या घेरा बनवा देती है जिसमें तरह तरह के सामान बेचने के लिये दूकानें लगाई जाती हैं। पर साधारण तौर पर हम बाजार या मन्डी से जिस स्थान को समझते हैं यह अर्थशास्त्र के अदर बाजार नहीं कहलाता। अर्थशास्त्र में किसी पदार्थ के बाजार से उस सारे क्षेत्र से हमारा मतलब होता है जिसमें बेचने और खरीदने वाले आपस में इस तरह से सम्बन्ध रखते हैं कि उस बाजार में वस्तु का अनकरीब एक सा दाम रहता है। यदि गेहूँ का व्यापार दुनियाँ के भिन्न-भिन्न देशों में आसानी से और कम खर्च से होता है तो तमाम दुनिया गेहूँ का बाजार कही जायगी। यह जरूरी नहीं है कि बेचने और खरीदने वाले एक ही स्थान में इकट्ठे हों वे दूर दूर रह सकते हैं।

उदाहरण के लिये उस बाजार को ले लीजिये जिसमें कम्पनियों के हिस्से बिकते हैं। आप जानते हैं कि अक्सर बड़ी कम्पनियों और बैंकों में केवल एक ही व्यक्ति का रुपया तो लगा नहीं रहता। बल्कि कम्पनी में पाँच-पाँच, दस-दस या सौ-सौ रुपयों के हिस्से होते हैं। शुरू में हर हिस्से के खरीदार को हिस्से के दाम देने पड़ते हैं। जब कम्पनी चल निकलती है और कम्पनी को खूब मुनाफा होने लगता है तो हर हिस्से पर प्राप्त होने वाले मुनाफे की रकम बढ़ जाती है। इससे हिस्सों का दाम बढ़ जाता है अर्थात् यदि कोई अपने एक सौ के हिस्से को बेचे तो लोग उसे सौ से अधिक दाम पर खरीद लेंगे। चूँकि आदमी घर बैठे इन हिस्सों की खरीद-फरोख्त कर सकता है अतएव हिस्से का बाजार बहुत विस्तृत होता है।

हमने ऊपर कहा है कि बाजार में वस्तु की कीमत अनकरीब एक सी रहती है। आप पूछ सकते हैं क्यों? उत्तर है लाग-डाट के कारण। एक छोटा-सा घर अपने अनाज की मंडी का ले लीजिये। उसमें बहुत से चावल, गेहूँ बेचने वाले बैठते हैं मान लो गेहूँ का भाव चार सेर फी रुपये अब अगर मेवालाल एक रुपये में तीन ही सेर गेहूँ देना चाहेगा

तो खरीदने वाले उसे छोड़कर औरों से गेहूँ मोल लेंगे। इसी तरह अगर रामचन्द्र सवा चार-सेर का गेहूँ बेचने लगे तो खरीदने वाले और दूसरे बनिए जल्दी उसका सारा गेहूँ मोल ले लेंगे और भाव फिर चार सेर का हो जायगा। इस तरह गेहूँ का भाव चार सेर का ही बना रहेगा। जिन पदार्थों का बाजार फैला हुआ होता है उनके साथ भी यही होता है। अगर बाजार के किसी कोने में भाव मँहगा है तो दूसरी जगह वाले माल बेचने के लिए वहाँ पहुँच जायेंगे। और जहाँ पर माल सस्ता होता है वहाँ का माल दूसरी जगह वाले जल्दी से खरीद लेते हैं और वहाँ भी फिर भाव बढ़ जाता है।

### बाजार का क्षेत्र (Extent of the market)

किसी वस्तु की कीमत जितने क्षेत्र में समान हो उतना ही अच्छा होता है। डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि की सहायता से वस्तुओं के मूल्य में घट-बढ़ का समाचार आसानी से किसी स्थान में तुरन्त भेजा जा सकता है, और रेल, नहर, सड़कें, मोटर आदि से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचाया जाता है। इससे समय और धन दोनों में किरफायत होती है और बाजार का क्षेत्र बढ़ता है। यों तो बाजार बढ़ाने के लिए पाँच बातों का होना जरूरी है। पहले तो वस्तु ऐसी होनी चाहिये जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। मकान आदि की तरह बड़ी व स्थिर न होनी चाहिये। छोटी होने के अलावा वस्तु जल्दी न बिगड़ती हो अर्थात् टिकाऊ हो। फल और मछली की कीमत एक सी नहीं रह सकती। लेकिन सोना, चाँदी वगैरह की कीमत बाजार में एक सी रहती है। दूसरी बात यह है कि पदार्थ को ले जाने में समय कम लगे। साथ ही खर्च भी कम पड़ना चाहिये अर्थात् मूल्य की तुलना में वह अधिक भारी न हो जैसे पत्थर, लकड़ी इत्यादि। फल वगैरह ऐसी चीजें हैं कि जब तक उन्हें सावधानी से न रक्खा जाय तब तक ये दूर नहीं भेजे जा सकते। पत्थर की नक्काशी की चीजों के टूट-फूट जाने का बड़ा डर रहता है और उन्हें दूर भेजने के लिए बड़ी होशियारी से उनका पैकल बनाना पड़ता है। इसका व्यय तथा मार्ग में उनके टूट जाने का डर, उनकी कीमत और खर्च बढ़ा देता है। तीसरी बात यह है कि वस्तु की माँग काफी और चारों ओर होनी चाहिये।

पदार्थ ऐसे होने चाहिये कि लोगों को उनके बारे में सारा हाल अच्छी तरह बताया जा सके तथा दूर-दूर रहने वाले खरीदार अच्छी तरह यह जान सकें कि वे किस तरह का माल मंगा रहे हैं। खेती करने से जो अनाज आदि चीजें पैदा की जाती हैं वे कई प्रकार की होती हैं। गेहूँ भी कई प्रकार का होता है। इनका दूर-दूर रहने वाले आदमियों को ठीक-ठीक परिचय देना बड़ा कठिन होता है। इससे कीमत के विचार से गेहूँ, चना आदि चीजें सोना चाँदी की बनिस्बत बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं। इसी कारण गेहूँ, चना आदि का बाजार बहुत विस्तृत नहीं होता। इस तरह जमीन का बाजार बहुत कम विस्तृत होता है क्योंकि वह बिल्कुल स्थिर होती है। मकानों और अपने-अपने मन के पसन्द की चीजों की भी यही हालत है।

**वस्तु की कीमत किस प्रकार निश्चित होती है**

किसी वस्तु के बाजार के सम्बन्ध में बताते समय हमने कहा है कि बाजार में कीमत एक सी रहती है। सवाल उठता है कि बाजार में कौन सी कीमत निश्चित की जाती है? विनिमय के सम्बन्ध में हमने कहा था कि किसी वस्तु की बिक्री उसी समय हो सकती है जब कि वह आसानी से प्राप्त हो तथा खरीदार को उसकी आवश्यकता हो। जब किसी वस्तु के उपरोक्त दोनों गुण होते हैं तब उसकी माँग तथा पूर्ति के अनुसार कीमत निश्चित होती है। माँग से हमारा मतलब वस्तु की उस मात्रा या वजन से है जिसे कुल खरीदार मोल लेने को तैयार रहते हैं; और पूर्ति वस्तु की उस मात्रा के बराबर है जिसे व्यापारी बेचने को तैयार रहता है। यदि माँग अधिक है तो खरीदार आपस में चढ़ा-चढ़ी करते हैं और बेचने वाले को अधिक दाम मिलता है। यदि पूर्ति ज्यादा है व खरीद कम, तो कम दाम पर ही चीजें बिकेगी। परन्तु यदि किसी वस्तु के सब व्यापारी आपस में किसी तरह का समझौता करके यह निश्चित कर लें कि हम अमुक कीमत से कम पर माल नहीं बेचेंगे तो खरीदार को शायद उतनी ही कीमत देनी पड़े। खरीदार क्यों उस निश्चित कीमत को देगा? क्योंकि उसे उस चीज की आवश्यकता

और जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे ही वह उस वस्तु की जरूरत को और महसूस करता जायगा। यह तो सब कोई जानता है कि गरज होती है। अगर अपनी गरज (स्वार्थ या आवश्यकता) है तो हम

उतने हो दाम देकर उस चीज को खरीदेंगे । मान लो घर में आटा नहीं है और बाजार में पिसा हुआ आटा नहीं मिल सकता तब तुमको मन्डी जाकर अनाज मोल लेना पड़ेगा । उस समय यदि मन्डी वाले चार सेर की जगह तीन सेर फी रुपये की दर से ही गेहूँ आदि देने का निश्चय कर लें तो तुम क्या करोगे । बिना अनाज लिए तुम्हारा पेट का काम चल नहीं सकता । अगर तुम इतना दाम न देना चाहोगे, तो जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे-वैसे तुम्हे अनाज की जरूरत ज्यादा महसूस होती जायगी और तुम अधिक दाम देने को तैयार होते जाओगे, यहाँ तक कि अन्त में तुम व्यापारी को मुँह-माँगा दाम देकर उस पदार्थ को खरीद लोगे ।

यदि सोचकर देखा जाय तो मालूम होगा कि ऊपर दिये हुए उदाहरण में पूर्ति तो कम थी और खरीददार की माँग बहुत अधिक । माँग और पूर्ति का किसी वस्तु की कीमत पर क्या असर पड़ता है इसका एक और उदाहरण लीजिये । मान लीजिये आपको अनार लेना है । फल की मन्डी में जाने पर आपने कई फलवालों के पास अनार देखा, मगर भाव पूछने पर सब ने एक रुपया सेर बताया । अगर आपको अनार लेना बहुत ही जरूरी है तो आप फल वालों के इर्द-गिर्द इस प्रकार चक्कर लगायेंगे, जैसे दूध के चारों ओर बिल्ली । फलवाले इससे आपकी आवश्यकता की याह पा लेंगे और फिर तो आप उनसे कभी भी रुपये सेर से कम पर अनार न ले सकेंगे । मान लीजिये आपके ले चुकने पर एक सज्जन और आ पहुँचे । उन्हें अनार का भाव मालूम पड़ा तो वे बोले कि तेरह आने सेर दोने ? अनार वाला बोला कि देखिये बाबू साहब खडे हैं, पूछ लीजिए । उन मशौदय की अनार की आवश्यकता है इसलिये उन्होंने चौदह आने सेर पर अनार माँगा । भाव कुछ बढ़ते देखकर अनार वाले टेढ़े पड़ने लगे । उन पर खरीददार जाने लगा । इस पर अनारवाला सोचता है कि शायद हमसे ज्यादा दाम नहीं देना चाहते । साथ ही वह इस बात पर भी ध्यान देता है कि रुपये में उल्टे चार आने का फायदा होना है ।

आपने, दूसरे सज्जन की माँग इतनी अधिक नहीं थी कि वे रुपये सेर का दाम देने को तैयार हो जाने। उन्होंने देखा कि इन अनार वालों का गुट अधिक दाम माँग रहा है तो वे जाने लगे। अनार के रहते माँग कम हो गई और इसीलिये गुट में से एक को कम दाम पर अनार बेचना पड़ा। यदि दूसरे सज्जन के सामने और लोग भी आने लगते तो अनार का भाव पन्द्रह आने पर ही बना रहता है।

यदि माँग बिल्कुल ही कम हो तो कीमत और भी गिर जाती है। अनार जल्दी बिगड़ने वाला फल है। मान लो रात हो गई और बाजार में सन्नाटा छाने लगा अर्थात् ग्राहकों का आना कम हो गया। उसी समय एक मनचला जवान आ पहुँचा। भाव पूछ कर बोला कि चौदह आने सेर दो तो दो सेर दे दो। अनार वाला मन में सोचता है कि क्या पता दो सेर अनार बेचने के लिये मुझे कल कब तक ठहरना पड़े। फिर रात को कुछ अनार बिगड़ने लगेंगे। इसके अलावा तुरन्त नफे के चार आने मिल जायेंगे, यह सोचकर वह चौदह आने सेर पर ही अनार बेच देता है।

किसी चीज के भाव के निश्चित होने पर उस चीज की मात्रा या वजन का असर जरूर पड़ता है। तीसरे सौदे में अनार वाले ने इसका खयाल किया था। यही क्या, आप कहीं भी थोक में अधिक माल लीजिये तो आपको कम कीमत देनी पड़ेगी। बाजार में आप आम खरीदने जाइये, अगर वैसे में एक आम मिलता है तो शायद दस में एक दर्जन और अठारह आने में सौ आम मिल जायेंगे। इसके अलावा अनार वाले ने भविष्य का भी खयाल किया था।

यदि अनाज वालों को यह पता चल जाय कि वर्षा की कमी के कारण अबकी बार खेती खराब हो रही है तो वे अभी से भाव तेज कर देंगे। वे जानते हैं कि यदि आज कोई तेज भाव पर अनाज नहीं खरीदेंगे तो कल आवश्यकता बढ़ जाने पर लोग अवश्य ही अनाज खरीदेंगे व्यापार में भविष्य कितना खेल खेलता है इसका अंदाजा लगाना कठिन है। कितने सेठ करो ने इसी की बदौलत कोठियाँ खड़ी कर लीं और इसी कारण से अपनी पैदा कर रहे हैं। समय के साथ भी कीमत घटती-बढ़ती है। यदि गेहूँ चार सेर का बिकता है तो हो सकता है कल सवा चार सेर का

विकने लगे । क्यों ? मान लीजिए कल सुबह गाँव से गेहूँ की बीस गाड़ियाँ आ गईं । इससे गेहूँ की पूर्ति के विचार से माँग के कम पड़ जाने से भाव गिर गया और गेहूँ सवा चार सेर का विकने लगा । खयाल कीजिये कि किसी वर्ष खेत में खूब अनाज पैदा हुआ । परन्तु इसी समय योरुप में लड़ाई छिड़ जाने से वहाँ अनाज की माँग बहुत बढ़ गई । किसानों और व्यापारियों ने अच्छे दाम पर अनाज बाहर भेजना प्रारम्भ कर दिया । इस समय देश में अच्छी फसल होने पर भी अनाज का कीमत बढ़ जायगी ।

यदि हम अनार वाला उदाहरण फिर से ले लें तो क्या अनार बेचने वाला बारह आने सेर का दाम ले लेगा ? कदापि नहीं । बारह आने तो उसका लागत खर्च है । मुनाफा व मेहनत के दाम कहाँ गये ? बारह आने छोड़ वह तेरह आने पर भी अनार बेचने को तैयार नहीं होगा । लेकिन वस्तु की हालत खराब हो जाने पर कीमत अवश्य गिर जाती है । मान लो, कोई जलेबी वाला है । रात हो जाने पर जलेबी सूख कर बासी हो जाती है । वह जानता है कि दूसरे दिन ताजो जलेबियाँ बनेगी उस समय बासी जलेबियों को कोई नहीं पूछेगा । इसलिये रात को भाव और कम कर देगा या अंत में जलेबियों को स्वयं खा लेगा ।

किसी वस्तु की उत्पत्ति में जो खर्च बैठता है उस वस्तु की कीमत उस खर्च के आस-पास ही रहती है । यदि आशा, निराशा, रुपये की तंगी इत्यादि का विचार न किया जाय तो उस वस्तु की कीमत हमेशा चीज को उत्पन्न करने के व्यय से थोड़ी सी अधिक ही रहती है । इस अधिकता में बेचने वाले का मुनाफा शामिल रहता है । एक किसान को उपज करने में खेतों को जोतना, बोना व सीचना पड़ता है । इसके अलावा अनाज की कटाई, मँड़ाई करके बाजार में लाने में खर्च होता है । यह सब खर्च तथा उसकी मजदूरी-मुनाफा और खेत का लगान, उत्पादन व्यय में शामिल रहता है । तुमको मालूम है कि कई मिले एक ही तरह का माल तैयार करती हैं । परन्तु सब का लागत-खर्च भिन्न होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा । ऐसी हालत में क्या तुम बता सकते हो कि बाजार में उस वस्तु का मूल्य सबसे कम लागत के हिसाब से निश्चित होगा या सबसे अधिक लागत के अनुसार । इन दशाओं में हमेशा किसी चीज की कीमत सबसे अधिक लागत



का ध्यान रखकर निश्चित होती है। हाँ, यदि लागू हो तो सबसे कम लागत वाली मिल कम कीमत पर माल बेचेगी। परन्तु यदि ऐसा हुआ तो दूसरी मिलें बन्द हो जाएँगी।

कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि उनकी मात्रा कभी बढ़ाई नहीं जा सकती जैसे पुराने चित्र, सिक्के इत्यादि। इनकी कीमत माँग और पूर्ति के हिसाब से ही तैयार की जाती है। उत्पादन व्यय का उस पर कोई असर नहीं पड़ता।

### खेती से उत्पादन पदार्थों की कीमत

ऊपर कीमत निश्चित होने के सम्बन्ध में जो बातें बतलाई गई हैं वे हमारे गाँव में विकने वाली वस्तु के ऊपर नहीं लागू होतीं। इसका एक विशेष कारण है। हमारे किसान कर्जदार रहते हैं। गाँव के महाजन किसानों को खाने के लिए अनाज उधार देते हैं। परन्तु ये खाते में अनाज का वजन लिखकर बाजार-भाव से सेर आधा-सेर कम अनाज का दाम लगाकर खाते में लिख लेते हैं। फसल पर ये लोग रुपये के बदले में अनाज लेते हैं। परन्तु किस भाव ? इस बार अनाज बाजार से सेर आधा-सेर अधिक भाव पर लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि चार सेर का भाव है तो उधार देने के समय अनाज का भाव पौने चार सेर का लगाया जाता है और फसल पर लेते समय पाँच सेर का भाव लगाया जाता है। बेचारे किसानों को इससे काफी घाटा सहना पड़ता है।

इसके अलावा बहुत सी उपज को किसान व्यापारी के हाथ बेचता है। व्यापारी फसल के समय तो सस्ते दामों में अनाज खरीदता है, फिर कुछ दिनों बाद उसी अनाज को किसानों के हाथ महँगे दामों में बेचता है। आप कह सकते हैं कि किसान अपने लिए अनाज बचाकर क्यों नहीं रख लेता। ठीक है, परन्तु हमारे किसान की ऐसी हालत है कि वह फसल को अपने पास रख तो सकता ही नहीं। किसान जितना अनाज पैदा करता है उसका एक बड़ा भाग तो नाई, धोबी, लोहार वगैरह के पास चला जाता है। कर्ज पटाने व लगान देने के लिए रुपये की जरूरत पड़ती है। इसलिए बाकी भाग भी फौरन बेचना पड़ता है। किसान जब मंडी में अनाज बेचने जाता है तो उसके और व्यापारी के बीच में दलाल आ पड़ता है। फिर उसे अनाज वाले को, तौलने वाले को, रसोइया को, भिंती और मेहतर को

कुछ न कुछ देना पड़ता है। इसके अलावा मंडी के कुएँ के लिये गंगाजली के नाम पर व धर्मखाते के नाम अनाज वसूल किया जाता है। फिर जिस बाट से तौल कर व्यापारी अनाज लेता है वे गड़बड़ होते हैं। इन सब बातों से किसान जिस भाव से अनाज बेचता है वह और सस्ता हो जाता है। बल्कि यह कहा जाय कि हमारे किसान की हालत ऐसी गिरी हुई है कि माल बेचते समय किसान लूटा जाता है। किसानों की बिगड़ी हुई हालत के अलावा अनाज को बेचने के लिए उसे अच्छे तरीके नहीं प्राप्त हैं। हमारे किसानों की पहुँच अच्छे बाजारों तक नहीं होती। खेती से उत्पन्न पदार्थों को बाजार में बेचने के प्रश्न के ऊपर हम अगले किसी अध्याय में अच्छी तरह विचार करेंगे।

### अभ्यास के प्रश्न

- १—अदला-बदली की सुविधाएँ उदाहरणों सहित समझाइए।
- २—किसी वस्तु को बिक्री में बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को लाभ होता है। उदाहरणों सहित समझाइए।
- ३—अदला-बदली क्या है ? क्या यह आपके गाँव में पाई जाती है ? क्रय-विक्रय ने इसका स्थान क्यों ले लिया है ?
- ४—फसल बेचते समय भारतीय किसानों को किस प्रकार हानि उठानी पड़ती है ?
- ५—अपने गाँव के किसी किसान के साथ मंडी जाकर यह पता लगाइये कि अपना अनाज बेचते समय तौलने वाले को, नौकरों को तथा धर्म के नाम पर कितना अनाज देना पड़ा।
- ६—यदि किसी वर्ष वर्षा कम हो जाय तो उसका असर अनाज की कीमतों और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर कैसा पड़ेगा ?
- ७—यदि किसी वर्ष वर्षा बहुत अच्छी हो और फसल अच्छी आवे परन्तु विदेश से अनाज की माँग बढ़ जाय तो अनाज की कीमत पर तथा अन्य वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
- ८—स्वदेशी आन्दोलन का गाँधी टोपी की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा ? इसका प्रभाव विदेशी टोपियों की कीमत पर क्या हुआ ?
- ९—वस्तु की कीमत का उसके लागत खर्च से क्या सम्बन्ध रहता है ?

१०—लागत खर्च में जो खर्च शामिल किये जाते हैं उनकी सूची किसी एक वस्तु का उदाहरण लेकर तैयार कीजिए ।

११—सूती कपड़ा भारत में सैकड़ों मिलों में तैयार किया जाता है और प्रत्येक का औसत लागत खर्च भिन्न-भिन्न है । ऐसी दशा में सूती कपड़े का मूल्य किस मिल के लागत खर्च के बराबर होगा ?

१२—लागत खर्च से कम कीमत पर वस्तु किन दशाओं में बेची जाती है ?

१३—आप 'बाजार के क्षेत्र' से क्या समझते हैं ? किसी वस्तु के बाजार का क्षेत्र किन बातों पर निर्भर रहता है ? विस्तृत बाजार वाली कम से कम दस वस्तुओं की सूची तैयार कीजिये ?

१४—निम्नलिखित वस्तुओं का बाजार किन दशाओं में विस्तृत हो सकता है ?

कलमी आम, लकड़ी, कम्पनी का हिस्सा ( शेयर ), पुस्तक, नयी मशीन ।

१५—किसी वस्तु की कारखाने की कीमत और फुटकर बिक्री की कीमत के पारस्परिक सम्बन्ध उदाहरणों सहित समझाइये ।

१६—सफल दूकानदार में किन गुणों की आवश्यकता है ?

## दसवाँ अध्याय

### ग्रामीण फसल की बिक्री

#### प्राक्कथन

पिछले अध्याय में हमने फसल की बिक्री के बारे में थोड़ा सा हाल चताया था । हम यह बातें चुके हैं कि किसानों को ज्यादातर अपना माल उन महाजनों के हाथ बेचना पड़ता है जिससे वे रुपया उधार लिए रहते हैं । यह कहने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती कि वे माल लेते समय बाजार से बहुत सस्ता दाम लगाते हैं । परन्तु कुछ किसान ऐसे भी हैं जो स्वयं मंडी में अनाज बेचते हैं । आप पूछ सकते हैं कि किसान किस मंडी में अपना अनाज बेचता है और किस प्रकार बेचता है ।

इसके पहले कि हम मंडी और बिक्री के ढंग के बारे में कुछ बताएँ, यह कहना गलत न होगा कि किसान और खरीददार के बीच में व्यापारी का होना जरूरी है। सब खरीददार फसल तैयार होते ही साल भर के लिए अनाज या अन्य उपज यों खरीद नहीं सकते। उन्हें जब जरूरत होती है तथा जब जेब में पैसे होते हैं तब अनाज खरीद लेते हैं। परन्तु हमारे किसान के लिए यह बहुत जरूरी है कि फसल तैयार होने के बाद जितनी जल्दी हो, उसे वह बिक जाय। वह साल छः महीने तक अनाज को लिए बैठा नहीं रह सकता। पहले तो उसके पास इतनी जगह ही नहीं होती कि वह उपज को रखे। आप जानते ही हैं कि फसल काट कर वह खलिहान में रखता है। दूसरी बात यह है कि किसान को लगान, सूद, मजदूरी आदि देनी पड़ती है। सरकार लगान अधिकतर रुपये में माँगती है। कुछ मजदूरी भी पैसे में देनी पड़ती है। अतएव यह जरूरी हो जाता है कि किसान फसल रख नहीं सकते, इसलिए इन दोनों के बीच व्यापारी का होना जरूरी है। इन व्यापारियों से बड़ा काम निकलता है। यह एक फसल को एक स्थान में इकट्ठा करते हैं। फिर इन्हे साफ कराकर तथा उनकी किस्मों को अलग अलग करके बाजारों में भेज देते हैं। वहाँ छोटे दूकानदार अनाज को खरीद कर फुटकर खरीददारों के हाथ बेच देते हैं।

### बिक्री की बातें

अस्तु, उपज को मुनाफे के साथ बेचने के लिए यह अत्यन्त जरूरी है कि बेचने वाले को बाजार भाव व बाजार की दशा का पूरा ज्ञान हो। कौन चीज कहाँ मस्ती बिकती है, कहाँ ले जाने से महँगी बिकेगी, किस रास्ते तथा किस तरह ले जाने से भाड़ा कम पड़ेगा, इन सब बातों का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि उपज को किस समय अथवा कितने दिनों के अन्दर बेच देना चाहिए। परन्तु हमारे किसान तो अशिक्षित और निर्धन हैं। वे भाव-भाव के बारे में कुछ नहीं जानते। प्रायः उन्हें बाहर की मंडियों का भाव मालूम नहीं रहता, और न उन्हें बाहर जाकर बेचने का सुभीता ही रहता है। इसलिए उन्हें गाँव में या पास की किसी मंडी में जो दाम मिलता है उसी में सतोष करना पड़ता है।

## मंडी में फसल की बिक्री

प्रथम तो किसान को यही नहीं मालूम पड़ता कि उसका माल उचित भाव से बिक रहा है या नहीं, और उसे ठीक-ठीक दाम मिल रहे हैं या नहीं। फिर म्युनिस्पल टैक्स (चुंगी) के अलावा किसान को मंडी में गाड़ी ठहराने का शुल्क, दलाल की दलाली देनी पड़ती है। फिर अनाज उतारने वाले पल्लेदार को, माल तौलने वाले को, भूसा निकालने वाले को तथा गौशाला, मन्दिर, प्याऊ आदि न जाने उससे किस-किस के लिए दान लिया जाता है। तम्बाकू खरीदने वाला तौलाई की गिनती के लिए मन पीछे तम्बाकू का एक पूड़ा लेता है, गंगा जी के नाम पर दूसरा पूड़ा लिया जाता है। तौलने वाला अपने काम के लिए एक पूड़ा लेता है। फिर तौलाई और दलाली अलग लगती है। इस तरह से बेचने वाले की खासी रकम निकल जाती है। इसके अलावा अनाज जिस बाट से तौला जाता है वह अक्सर बनावटी होता है। व्यापारी सरकारी पन्सेरी की जगह पत्थर के बाट काम में लाते हैं। बेचारे किसान इस बाबत भी कुछ नहीं कह सकते। यही नहीं, कभी तौलने वाला डंडी मारता है, तराजू में पसंगा रखता है इत्यादि।

## गाँव में बनी वस्तुओं की बिक्री

इसी प्रकार की हालत हमारे गाँवों के शिल्पी और कारीगरों की भी है। गाँव में अधिकतर जुलाहे, बढई, रस्सी-बटने वाले, तेली, मोची आदि कारीगर और दस्तकार रहते हैं। इनको भी बाजार भाव का ज्ञान नहीं होता। जुलाहा बुनकर कपड़ा तैयार करता है। बढई बिना माँग के हल को बना लेता है। रामू किसान फुरसत के वक्त सन को बटकर रस्सी तैयार करता है। बालादीन टोकरी बना डालता है। शङ्कर तेली अलसी और सरसों का तेल तैयार करता है। इनको बेचने के लिए वे पहले गाँव में ही खरीददार ढूँढ़ते हैं। अपने तैयार माल को गाँव के महाजन या साहूकार के पास ले जाते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या उसे कपड़े, रस्सी आदि की जरूरत है। परन्तु एक बात है। इन महाजनों और साहूकारों के हाथ माल बेचने से उन बेचारों को पूरा दाम कभी नहीं मिलता। गाँव के ये कारीगर अपने माल को के हाट में ही बेचते हैं। यदि गाँव के पास कहीं मेला होता है तो बेचने से माल को वहाँ ले जाते हैं।

### ग्रामीण सड़क

माल को बेचने की प्रथा में जो बुराईयाँ हैं उनको दूर करने के लिए देश की सरकार कोशिश करती रहती है। माल को अच्छी मंडी में पहुँचाने के लिए पहले तो इस बात की आवश्यकता है कि गाँवों का मंडियों से सम्बन्ध हो। अर्थात् मंडियों को मिलाने के लिए अच्छी उम्दा सड़कें हों। आप यदि गाँवों की ओर जाने का कष्ट करें तो आपको मालूम होगा कि प्रथम तो गाँव में जाने के लिए रास्ता ही नहीं होता, यदि होता भी है तो कच्चा, धूल और गड्ढों से भरा हुआ, जिसमें से बैलगाड़ी को निकाल ले जाना कठिन जान पड़ता है। फिर बैलगाड़ी, ऊँट तथा घोड़े गदहे होते ही कितने किसानों के पास हैं। गाँव में मुश्किल से दो तीन बैलगाड़ियाँ निकल सकती हैं। ऐसी हालत में यह बड़ा जरूरी है कि गाँव में पक्की सड़कें बनाई जावें। बीसवीं शताब्दी के नये जमाने में बैलगाड़ी का काम नहीं। यदि मोटर लारी का इन्तजाम हो सके तो बड़ा ही अच्छा हो जिससे किसान अपने माल को अच्छी मंडी में कम खर्चा से पहुँचा सकें। द्वितीय महायुद्ध खतम हो जाने के कारण फौज की मोटर लारियों से पदार्थों की ढुलाई का काम लिया जा सकता है।

यह सन्तोष की बात है कि भारत सरकार और प्रादेशिक सरकार यातायात की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं और इस हेतु योजनाएँ बना ली हैं। इन योजनाओं में लारी रेल को लागू गड्डाट बिल्कुल घट जायेगी।

### सहकारी संस्थायें और बिक्री

#### ( Cooperative Marketing Societies )

लेकिन किसानों की तो अवस्था ऐसी है कि माल को मंडी में पहुँचाने का इन्तजाम हो जाने से भी उनकी हालत अधिक नहीं सुधर सकती। हर एक किसान के पास शायद इतनी अधिक फसल नहीं होती कि वह उसे मोटर पर लाद कर मंडी ले जाय। इससे भी अधिक मार्के की बात तो यह है कि किसान यह नहीं जानता कि फसल को किस मंडी में ले जायें। फिर भाव-ताव और मंडी में लिए जाने वाली तरह-तरह की उगाही का सवाल तो बाकी रह जाता है। यह देखा गया है कि सहकारी संस्थाएँ किसानों को इस दुःख से उबार सकती हैं। सहकारी संस्था वह संस्था है जो सरकार

के सहकारी विभाग की ओर से खोली जाती है। इसमें गाँव वाले सदस्य बनाए जाते हैं। सस्था का मैनेजर, जिसकी नियुक्ति सरकार की ओर से होती है, किसानों की उपज को खरीद कर उसे महेँगी से महेँगी मंडा में बेचता है। इस प्रकार से सस्था को जो लाभ होता है उससे मैनेजर वगैरह को तनख्वाह काटने के बाद जो बचता है वह तो मेम्बरों को ही बाँट दिया जाता है। यही नहीं, बाजार सम्बन्धी अन्य बातों की जानकारी प्राप्त करने के बाद सहकारी समिति माल को अंतिम खरीददार के हाथ भी बेच सकती है। ऐसा करने से बीच के कई दलालों की दलाली तथा नाना प्रकार के शुल्क आदि से सहज ही छुटकारा मिल जाता है और किसानों को भी अधिक से अधिक दाम मिल जाता है।

विदेशों में तो इन सस्थाओं को काफी सफलता मिली है। इंग्लैंड, अमरीका आदि देशों में हजारों ऐसी समितियाँ काम कर रही हैं। हमारे देश में भी ऐसी समितियाँ खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है। जब प्रदेशों का इतजाम कांग्रेस के हाथ में आया तब ये समितियाँ खूब जोर-शोर से खोली गईं। प्रादेशिक सरकारों ने अब इन समितियों की अधिक संख्या में व्यवस्था और उन्नति करने की योजना बनाई है। इन समितियों को माल रखने की और सुविधा देने के लिए सरकारी व्यय से छोटी बड़ी सीमेंट की खत्तियाँ ( जमीन के अन्दर गोदाम ) बनाई जायेगी। परन्तु भारत में एक और विशेष बात यह है। हमारे किसान बहुत ऋणी हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। पहले तो इस कर्ज के मारे किसानों को अपना माल महाजन के हाथों में ही बेचना पड़ता है दूसरे कर्ज अधिक होने से महाजन किसी प्रकार किसान से अपना रुपया निकालना चाहता है। महाजन भी समिति के मेम्बर बन तो सकते ही हैं। बस वे उस समिति से किसान को रुपया कर्ज दिला देते हैं। यह रुपया वे किसानों से खुद दिए हुए कर्ज की अदाएँगी में वसूल कर लेते हैं। और फिर महाजन साहब समिति की मेम्बरी छोड़ देते हैं। बाद में किसान के रुपया चुका न सकने के कारण समिति का काम रुक जाता है और फिर सब हो जाता है। परन्तु समिति के इन गुण-दोषों के बारे में बताने की यह नहीं है। आगे चलकर साख के सम्बन्ध में बताते समय इन सस्थाओं में और खुल कर बतायेगे।

हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि हमको अपने अपद और मूर्ख किसान समूह को पढ़ा-लिखाकर एक ऐसे व्यापारी मंडल में बदल देना है कि वे आजकल के व्यापारी मंडल का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि किसानों की पुश्तैनी आलस्य और असमर्थता को उनसे भगा दिया जाय। व्यापारियों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह घुसा देने की जरूरत है कि वे उचित लाभ लेते हुए किसानों से मिलकर काम करें। अब तो व्यापारियों को कन्ट्रोल में लाने के लिये तथा बड़ी मंडियों में सुप्रबन्ध के लिये कमेटियाँ बनाई जाएँगी। ये कमेटियाँ उन सब वेईमानी और दिक्कतों को दूर करने तथा किसान को ठहरने की सुविधा देंगी।

### ग्रामीण बाजार

प्रतिदिन के काम के लिये गाँव में कुछ दूकानें तो रहती ही हैं जैसे तेली की दूकान, मोची की दूकान, बढई की दूकान, भुँजवा की दूकान इत्यादि। परन्तु बात यह है कि गाँव का बढई, चमार, तेली वगैरह हर समय लकड़ी, चमड़े और तेल का ही काम नहीं करते। अधिकतर इनके पास खेत होते हैं और ये अपना अधिक समय खेती करने में लगाते हैं। बिहारी चमार के पास चमड़े की कटाई, सिलाई आदि करने के औजार रहते हैं, परन्तु वह उनको तभी निकालता है जब गाँव का कोई मनुष्य उसे अपना जूता मरम्मत करने को दे जाता है। या जब कुएँ से पानी निकालने वाले चमड़े का डोल फट जाता है और उसका मालिक उस डोल को ठीक कराने के लिए बिहारी के पास लाता है। बिहारी बाजार के महादेव चमार की तरह दूकान खोलकर दिन भर नहीं बैठा रहता। इसी प्रकार बाजार में दूकान कर शीतल बढई लकड़ी का कोई न कोई काम करता ही रहता है, उसका मुख्य पेशा लकड़ी का काम करना है। जब उसके पास मरम्मत के लिए कोई काम नहीं रहता तब वह अपने मन से कुर्सी, मेज, खाट आदि चीजे बनाया करता है। जब कहीं पर चमार, बढई, तेली, कुम्हार आदि दूकान खोल कर काम करते हैं, तब हम कहते हैं कि उस जगह पर बाजार है। अधिकतर गाँवों में बाजार नहीं होता। गाँव में कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो खेती करने के अलावा बढई, चमार, कुम्हार आदि का काम



भी जानते हैं। अतएव जब रामू को चारपाई की जरूरत पड़ती है तो गोपाल बढई फुरसत के समय में लकड़ी को काट-छील कर रामू के लिये एक चारपाई बना देता है। इसी तरह जूता फट जाने पर हामिद चमार अपने कामों से फुरसत पाकर जब बैठता है तो औजार निकाल कर जूते को सी देता है। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक गाँव में एक बाजार हो। शहरों में तो बाजारों का होना अनिवार्य है क्योंकि वहाँ तो हर समय कोई न कोई व्यक्ति माल खरीदने अथवा कोई वस्तु बनवाने के लिये तैयार रहता है। बढई, चमार, लोहार वगैरह को सुबह से शाम तक करने के लिये काफी काम रहता है। लेकिन गाँवों में इतना काम कहाँ से आये? अतएव कुछ बड़े-बड़े गाँवों में ही बजार रहते हैं बाकी में नहीं। और जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं बाजारों की जरूरत भी वहाँ नहीं रहती है।

### हाट

यदि गाँवों में बाजार हो तब भी गाँव वालों को हर एक आवश्यक चीज वहाँ नहीं मिल सकती। मान लीजिये कोई वस्तु गाँव में नहीं बनती और रामू किसान को उसकी बड़ी जरूरत है। एक दूसरे गाँव में वह वस्तु बनाई जाती है। परन्तु उस वस्तु के बनाने वाले को क्या गरज पड़ी है कि वह रोज रामू के गाँव में उस वस्तु को बेचने आया करे। इसलिये हफ्ते में कहीं एक बार कहीं दो बार बाजार लगता है। इसे हाट कहते हैं। ग्राम समूह के बीच के किसी एक गाँव को हाट के लिये चुन लिया जाता है। हाट के दिन उस गाँव के चारों ओर स्थित गाँवों से लोग अपने अपने वस्तुओं को लेकर आते हैं। कोई तरकारी-भाजी बेचने लाता है, कोई टोकरी, कोई रस्सी, कोई कपड़ा। इसी तरह से जो जिसके पास होता है वह उसे बेचने के लिये लाता है। तेली तेल लाता है, लोहार फावड़ा कुदाली लाता है, और चमार जूता, चमड़े का डोल आदि चीजें लाता है। बेचने वालों के अलावा गाँवों से माल खरीदने वाले भी आते हैं। जो जिसकी जरूरत होती है वह उस वस्तु को खरीद लेता है। अधिकतर हाट दोपहर के बाद लगता है और रात होते-उठ जाता है।

### गाँव का मेला

१.- के अलावा त्योहारों पर मेला लगता है। चूँकि त्योहार साल भर

मे एक बार आते हैं इसलिए मेला साल में लगता है। मेला किसी कसबे या बड़े गाँव में लगता है। उसमें बड़ी भीड़ होती है। मेले में दूर-दूर के गाँवों के लोग आते हैं। जब मेला लगता है तो गाँव में सब लोगों के घर पर मेहमान आते हैं। मुँड के मुँड लोग देखने आते हैं। मेले में जो भीड़ होती है उसमें यदि कोई छूट जाय तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए मेले में सब लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई भटक न जाय। ऊपर बताई बात से यह मालूम पड़ जाता है कि मेले में सैकड़ों आदमी इकट्ठे होते हैं। मेले में तरह तरह की दूकानें आती हैं। कहीं खिलौने विकते हैं, कोई कागज के फूल, चिड़ियाँ और बाँसुरी बेच रहा है। कहीं फल विकते हैं, कहीं मिठाई और कहीं बरतनों के ढेर लगे रहते हैं। मेले में खेल भी बहुत होते हैं। मेले में हिंडोले भी गड़ते हैं। लड़के और बड़े लोग उन पर झूलते हैं। कहीं कहीं बड़े मेले लगते हैं। जो चीजे गाँव के हाट व बाजारों में विकने नहीं आती वे मेलों में विकने आती हैं। बड़े बड़े मेलों में गाय, बैल, घोड़े आदि भी विकने आते हैं।

### हाट और मेले का महत्व

गाँव और गाँव के रहने वालों का ख्याल रखते हुए यदि हाट और मेलों के बारे में सोचा जाय तो वे काफी महत्व रखते हैं। हाटों में अधिकतर अनाज आदि की बिक्री अधिक होती है। इसके विपरीत मेलों में खेल-खिलौने और मिठाई के अलावा दस्तकारी की वस्तुओं और जानवरों की खरीद-फरोख्त होती है। अतएव हाट तो किसानों के लिए उपयोगी होते हैं और मेले कारीगरों और दस्तकारों के लिए। इसके अलावा यदि गाँव भर का ख्याल किया जाय तो हाट मेलों से बढ़कर स्थान रखते हैं। क्योंकि हाट में अनाज, तरकारी व हाथ की बनी हुई चीजे विकने आती हैं। व्यापारी लोग अकसर हाटों से अनाज खरीद ले जाते हैं।

### हाट और मेले का संगठन

परन्तु कुछ गाँव से हाट व मेले का स्थान पास नहीं पड़ता। यह बहुत जरूरी है कि हाट लगाने के स्थान इस प्रकार चुने जाएँ कि आस-पास के गाँव के निवासियों को उसमें पहुँचने का मौका मिले। इसके अलावा किसान के ठगे जाने से बचाने के लिए उन्हें बाजार-भाव का शान कराना

बड़ा आवश्यक है और आजकल न तो हाट ही व्यवस्थित रूप में लगते हैं और न मेले ही। हालाँकि इनके जरिए किसान व गाँव के कारीगर अपना बहुत कुछ माल बेच सकते हैं—परन्तु देखा जाता है कि इनमें और खास कर मेले में मजा उड़ाने, तमाशा देखने आदि की गरज से लोग ज्यादा आते हैं। इलवाइयों, खिलौने बेचने वालों, चटपटे बेचने वालों और भूना फुलाने वालों को तो काफी आमदनी होती है। परन्तु, औरों को बिक्री बहुत कम होती है। इस बात की बड़ी जरूरत है कि इनका इस प्रकार से संगठन किया जाय कि हाट और मेलों में बड़ी तादाद में बेचने और खरीदने वाले आवें और खूब खरीद-फरोख्त होवे, लेकिन इस तरह से कि किसानों को धोखा न खाना पड़े।

### अभ्यास के प्रश्न

१—उन व्यापारियों की सूची तैयार कीजिये जो आपके गाँव से अनाज खरीदकर मंडी में ले जाते हैं। यह भी पता लगाइए कि किस व्यापारी ने अनाज आपके गाँव में किस भाव में खरीदा और उस समय पाँस की मंडी में उसका क्या भाव था ?

२—तैयार होते ही किसानों को फसल क्यों बेच देनी पड़ती है ? इससे उनको क्या हानियाँ होती हैं ? ये हानियाँ कैसे रोकी जा सकती हैं ?

३—आपके जिले में खेती की उपज की बिक्री का क्या ढग है ? किसान को अपने माल की उचित कीमत क्यों नहीं मिलती ?

४—क्या आपके गाँव के पास से पक्की सड़क गई है ? यदि नहीं, तो उसके न होने से आपके ग्रामवासियों को क्या असुविधाएँ होती हैं ?

५—यदि आपको अपने जिले में नई सड़कों के बनवाने का कार्य सौंपा जाय तो आप किस प्रकार की सड़कें कौन से स्थान से कहाँ तक बनवावेगे ?

६—बनिए से किसानों को क्या लाभ है ? क्या यह जरूरी है कि उनको हटाने के लिए सहकारी बिक्री समितियाँ बनाई जायँ ?

७—सहकारी बिक्री समिति का संगठन समझाइये और उसके द्वारा होने वाले लाभों का दिग्दर्शन कीजिये ?

—आपके गाँव के आस-पास किन-किन स्थानों में किस-किस दिन लगते हैं ? इन हाटों में कौन-कौन सी वस्तुएँ बिकने को आती हैं ?

इन हाटों से किसानों को क्या लाभ होते हैं ? इन हाटों की व्यवस्था में किन सुधारों की आवश्यकता है ?

६—आपके गाँव के आस-पास किस स्थान में कब 'मेला' लगता है ? इस मेले में अधिकतर कौन सी वस्तुएँ विकने को आती हैं और इस मेले से किसानों को क्या लाभ होते हैं ?

१०—साप्ताहिक हाट और मेलों का ग्रामीणों के लिए क्या महत्व है ? गाँव का बनियाँ कौन सी आर्थिक सेवा करता है ? (१६४३)

११—गाँव के कारीगरों को अपनी बनी हुई वस्तुएँ बेचने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे किस प्रकार दूर की जा सकती हैं ?

१२—आपके गाँव में ग्वालों की संख्या कितनी है ? प्रतिदिन उनके यहाँ कितना दूध होता है और इसके बेचने का क्या प्रबन्ध है ? दूध के विकने पर शेष दूध का क्या उपयोग किया जाता है ?

१३—यदि आपको अपने गाँव में सहकारी बिक्री समिति स्थापित करने को कहा जाय तो आप अपना कार्य किस प्रकार आरम्भ करेंगे ?

१४—आपकी प्रादेशिक सरकार किस प्रकार किसानों की बिक्री सम्बन्धी दिक्कतें दूर करने की कोशिश कर रही है ?

१५—आपके जिले में कृषि पदार्थों की बिक्री कैसी होती है ? किसानों को अपने माल का उचित दाम क्यों नहीं मिलता ?

१६—किसान को अपने माल की बिक्री में क्या कठिनाइयाँ होती हैं ?

१७—वर्तमान भारत में वस्तुओं के भाव क्यों अधिक हैं ? उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा अत्यधिक मुनाफा का लेना कहाँ तक इसका कारण है ? (१६४७)

## ग्यारहवाँ अध्याय

### वितरण (Distribution)

#### वितरण क्या है ?

अभी तक हमने केवल इस बात पर विचार किया है कि धन किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है । परन्तु यह हमने अब तक नहीं बताया है कि

उत्पत्ति के कार्य में हाथ बटाने वालों को उत्पन्न किये धन का हिस्सा किस प्रकार मिलता है। इसके पहले कि यह बताया जाय कि प्रत्येक का किस प्रकार हिस्सा लगाया जाता है, यह याद दिलाना जरूरी मालूम पड़ता है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति के साधन क्या क्या हैं ? तुम जानते ही हो कि भूमि का होना अनिवार्य है। जमीन के अलावा मेहनत करना भी जरूरी है। इसके अलावा धन भी लगाना पड़ता है और साथ ही साथ इन्तजाम की भी जरूरत पड़ती है। जो इन्तजाम करता है अधिकतर वही साहसी भी होता है। किसी काम के लिए जोखिम उठाने वाला भी होता है। मिलों में इन्तजाम करने वाले को मैनेजर कहते हैं और जोखिम उठाने वाले को साहसी कहते हैं।

अतः प्रत्येक तैयार या पैदा की वस्तु में पाँच अंश होते हैं। प्रथम, प्रकृति-दत्त भूमि जिसमें वह सब वस्तुयें शामिल हैं जो तैयार वस्तु में निहित हैं। द्वितीय, मजदूर का श्रम। तृतीय, पूँजीपति की पूँजी का उपयोग। चतुर्थ, मैनेजर की व्यवस्था और पंचम, साहसी का साहस। अतः वस्तु की प्राप्त कीमत में से भूमि के अंश को छोड़ कर शेष में से भूमि के मालिक श्रमिक पूँजीपति, मैनेजर और साहसी का अपना अपना अंश दे देना चाहिये। यही होता है और इसी को वितरण कहते हैं।

**वितरण कैसा होता है।**

जमीन जिसकी होती है वह कुछ रुपये लेकर अपनी जमीन दूसरों को लगान पर दे देता है। किसान जमींदारों से लगान पर खेत ले लेते हैं। मेहनत करने वाले मजदूर को अपने श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है। रुपया कर्ज देने वाला महाजन कर्जदार से सूद वसूल करता है। इन्तजाम करने वाले को वेतन मिलता है। वितरण के अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न साधनों को क्या हिस्सा मिले और कैसे। और इन सब के बाद जो कुछ बचा रहता है वह साहस करने वाले का मुनाफा कहलाता है। इस प्रकार उत्पन्न किये धन में से पाँच हिस्से किये जाते हैं जिनको लगान, मजदूरी, सूद, वेतन और मुनाफा कहते हैं।

**खेती में वितरण**

२ देश के बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास निज की जमीन नहीं है न पूँजी या रकम ही होती है। जमीन तो ये जमींदार से लेते हैं

और पूँजी महाजन से। वे तो केवल मेहनत ही करते हैं। फिर मेहनत करने के लिये भी तो किसान कभी-कभी मजदूरों को लगा लेता है। अक्सर खेत सींचने, काटने इत्यादि के लिए मजदूर नौकर रखे जाते हैं। फसल काटने पर जब उपज तैयार होती है तब पहले तो उन्हें जमींदार का लगान चुकाना पड़ता है। इसके बाद जिस महाजन से किसान कर्ज लेकर बीज आदि मोल लाता है और अनाज पैदा होने तक खाता-पीता है, उसे सूद व कर्ज का रुपया अदा करना पड़ता है। यह कोई जरूरी नहीं कि वह कर्ज का सारा रुपया लौटा दे। महाजन तो सूद चाहता है। जब तक उसे सूद का रुपया मिलता जाता है वह कुछ नहीं कहता। इसके सिवा मजदूरों की मजदूरी भी तो किसान ही देते हैं। ज्यादातर फसल तैयार होने के पहले ही वह दे दी जाती है, जहाँ नहीं दी जाती वहाँ फसल में से हिस्सा दिया जाता है। बाकी जो कुछ रह जाता है वह किसान के हाथ लगता है। कहीं-कहीं लगान, सूद और मजदूरी एक ही मनुष्य को मिलती है और कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न आदमियों को। जिसकी जमीन है वही यदि पूँजी भी लगाये और मेहनत भी करे तो सब हिस्से उसे ही मिल जायेंगे। लेकिन भारत में ऐसा हाल बहुत कम है। यहाँ की जमीन की मालिक सरकार ही समझी जाती है। अतएव यदि कोई आदमी अपनी ओर से पूँजी व मेहनत दोनों ही लगावे तब भी उसे सरकार को लगान या मालगुजारी देना पड़ता है। और जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, यहाँ के किसानों की पूँजी भी महाजन से उधार लेनी पड़ती है। इससे उन्हें जमीन से पैदा होने वाली सम्पत्ति का केवल मजदूरी और मुनाफे वाला अंश मिलता है। चूँकि उन्हें मजदूरी भी लोगों से करानी पड़ती है, इसलिए उन्हें मजदूरी में से भी कुछ हिस्सा औरों को बाँट देना पड़ता है।

यह सब करने के बाद शायद ही कुछ बचता हो। फिर मुनाफे की कौन कहे। सरकार लगान और मालगुजारी का बन्दोबस्त हरवार बीस तोस साल में करती है। लगान इतना बढ़ गया है कि हरसाल हजारों किसानों को लोटा-थाली बेचकर भीख माँगने की नौबत आती है। जब लगान चुकाने में तो बेचारे किसानों की यह हालत होती है तो कैसे कहा जा सकता है कि आजकल किसानों को खेती में मुनाफा मिलता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि

से मुनाफा होना अवश्य चाहिए, लेकिन जिस दशा में हमारे किसान खेती करते हैं उसमें यदि मुनाफा और पूरी मजदूरी न मिले तो कोई ताज्जुब नहीं है।

### लगान (Rent)

अस्तु, तुम पूछ सकते हो कि लगान शुरू कब से हुआ और वह किस सिद्धान्त के अनुसार लगाया जाता है। जमीन, खेत, जङ्गल, खान आदि को व्यवहार में लाने के लिये उससे स्वामी को दी जाने वाली रकम को लगान कहते हैं। जमीन पर कब और किसका अधिकार हुआ और कैसे? शुरू में आदिमियों की संख्या कम थी और, उनको देखते हुए जमीन बहुत अधिक थी। अतएव जो जहाँ चाहते खेती करते थे। जितनी जमीन जोतना चाहते थे, जितनी लकड़ी काटना चाहते थे, जितनी धातु खान से खोदना चाहते थे, सब स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते थे। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। उस समय 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाला मामला सब जगह चलता था। इसके बाद जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ती गई वैसे ही वैसे भूमि की माँग भी बढ़ती गई। भूमि का क्षेत्र परिमित होने के कारण जिसके अधिकार में जो जमीन आ गई वही उसका मालिक बनने लगा। अब अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा जमीन होती तो उसने उसके उपयोग करने का अधिकार दूसरे को देकर उसके बदले में उत्पत्ति का कुछ हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस हिस्से का नाम ही लगान है।

प्राचीन काल में जमीन का मालिक राजा नहीं होता था लेकिन राजा खेती करने वालों से उपज का छठा हिस्सा लिया करता था। बस राजा का सिर्फ इतना ही हक था। यह एक तरह का 'टैक्स' (कर) कहा जा सकता है।

लगान दो तरह से निश्चित होते हैं:—एक तो रिवाज के अनुसार, दूसरा चढा ऊपरी से। भारत में कहीं-कहीं रीति-रिवाज के मुताबिक पैदावार का आधा, तिहाई, चौथाई या पाँचवाँ भाग के बराबर लगान लिया जाता है। भारत में चढा-ऊपरी वाली रीति भी प्रचलित है अर्थात् जो सब से अधिक लगान देता है वही जमान पाता है। इसके अलावा लगान दो तरह के होते हैं एक तो कुल लगान होता है जिसे बोल-चाल में लगान ही कहते हैं। आर्थिक लगान होता है। आर्थिक लगान का हिसाब इस प्रकार

लगाया जाता है कि खेत की पूरी उपज के मूल्य में से उसकी खेती का सब प्रकार का लागत खर्च निकाल दिया जाता है। बची हुई सारी रकम आर्थिक लगान कहलाती है। कुल लगान में आर्थिक लगान के अलावा जमीन में लगे हुये धन का सूद और जमीन के मालिक का मुनाफा भी शामिल रहता है। अब तक भारत में लगान दो प्रकार से वसूल की जाती थी। कुछ प्रदेशों में किसान से सरकार सीधे लगान वसूल करती थी। इस प्रथा को रैयतवारी कहते थे। अन्य जगहों में जमींदारी प्रथा चालू थी। अब कुछ प्रदेशों में जैसे, उत्तर प्रदेश, बिहार, में जमींदारी प्रथा का कानून द्वारा अन्त कर दिया गया है। जमींदारी प्रथा में सरकार की ओर से जमीन का इंतजाम जमींदारों के हाथ में रहता है। निश्चित दर के लगान पर किसानों को खेत जोतने का अधिकार दे देते हैं। ऐसी हालत में किसान जमींदार को आर्थिक लगान नहीं देता। उसके बजाय वह किस दर से लगान देता है, वह सरकार पहले से ही निश्चित कर देती है। जमींदार भी किसान से वसूल होने वाली सारी रकम सरकारी खजाने में नहीं जमा करता। उसे जो रकम सरकार को देनी पड़ती है वह मालगुजारी कहलाती है और वह भी सरकार द्वारा पहले से निश्चित कर दी जाती है। यह रकम प्रायः किसानों से मिलने वाले लगान का ४०% या ५०% होता है।

यह जरूरी नहीं कि दो बराबर क्षेत्र वाले जमीन के टुकड़ों का लगान बराबर हो। उन टुकड़ों के गुण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, अतएव उनके लगान में भी फर्क होगा। जब आबादी के बढ़ने के अथवा पास से रेल निकल जाने के कारण जमीन की माँग बढ़ जाती है तो लगान भी बढ़ जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है भारत में पहले रीत-रिवाज के मुताबिक ही लगान लिया जाता था। जब तक किसान नियम के मुताबिक लगान देता रहता था तब तक उसे वेदखल नहीं कराया जा सकता था। लेकिन फिर आबादी की वृद्धि और उपज के बाजार का क्षेत्र बढ़ने के कारण भूमि की माँग बढ़ गई। इससे लगान सम्यन्धी नियम टूट गया और अब अधिकांश किसानों का लगान बन्दोबस्त के समय सरकार निश्चित करती है।

### मजदूरी (Wages)

भारतीय किसान साधारणतया यदि अपनी ओर से कोई चीज लगाता है तो वह उसका मालिक है। इसके बदले में उसे मजदूरी मिलनी चाहिये।



लेकिन उसे मजदूरी देने वाला तो कोई होता नहीं, वह स्वयं जो उपज पैदा करता है उसी में उसकी मजदूरी शामिल रहती है। बढई, लोहार आदि जो अपने औजारों से अपनी ही भूमि पर काम करते हैं उन्हें जो मजदूरी मिलती है उसमें उनकी मजदूरी ही नहीं बल्कि जमीन का लगान और औजार में लगे धन का सूद भी मिला रहता है।

अस्तु, आजकल वस्तु बनाने वाले मजदूरों को उनकी बनाई वस्तु नहीं दी जाती। यदि दी जाय तो बड़ी मुश्किल आ पड़े। यदि मेहनत के बदले मजदूरी के रूप में खान के मजदूर को कोयला, बिजलीघर के श्रमिक को बिजली, मोटर के हिस्से बनाने वाले को मोटर के हिस्से, जिल्द बाँधने वाले को किताबें ही दी जायें, तो उस वस्तु का वह क्या करे? मजदूर को तो अपना पेट पालने के लिये आटा-दाल और पहनने को कपड़ा-लत्ता चाहिए। मजदूरी के बदले कोयला मिलने से उसे हर वक्त और हर जगह पर कोयले के बदले उसकी आवश्यकता की ये वस्तुएँ तो मिल नहीं सकती हैं। इसलिये आजकल मजदूरों की मजदूरी रुपये पैसों में चुकाई जाती है। इस प्रकार की मजदूरी को नकद मजदूरी कहते हैं।

असली मजदूरी और नकद मजदूरी में बहुत अन्तर होता है। मजदूर अपनी मजदूरी के पैसों से खाने-पीने की वस्तुएँ कपड़ा आदि मोल लेता है। यदि मजदूरी के पैसों से वह इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद सकता है तब तो असली मजदूरी अधिक कही जायगी। परन्तु यदि वह अब कम सामान खरीद सकता है तब हम कहेंगे कि उसकी असली मजदूरी घट गई। अतः यह कोई जरूरी नहीं है कि नकद मजदूरी बढ़ने से असली मजदूरी भी बढ़ जाय। आजकल मध्यम श्रेणी की आय ड्योढ़ी दुगुनी हो गई है परन्तु वस्तुओं के भाव चौगुने हैं। अतः उनकी असली मजदूरी घट गई है।

मजदूरों को नकद मजदूरी तो अधिकतर कारखानों में ही मिलती है और यह जोर डाला जाता है कि मजदूरी की रकम इतनी हो कि मजदूर अपना भरण-पोषण कर सकें। भारत में दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती ही जाती है। इसलिये मजदूरों की तादाद बढ़ती जाती है। फलतः आपस में काम पाने के लिए लाग-डॉट चलती है। कारखाने वाले इसका फायदा उठाकर मजदूरी देते हैं। मजदूरी की पूर्ति के सम्बन्ध में जानने योग्य बात यह है कि

यह जल्दी घटती बढ़ती नहीं । नए कारखानों के खुलने पर ज्यादातर मजदूरी और जगह की अपेक्षा चढ़ी हुई ही रहती है । एक बात और है । कारखानों या किसी व्यापारी के दफ्तर में काम करने के लिए मजदूर का पढ़ा-लिखा होशियार और विश्वास-पात्र होना बहुत जरूरी है । हमारे मजदूर अधिकतर पढ़े-लिखे नहीं होते । अतएव वे नहीं जानते कि कहाँ अधिक मजदूरी मिलती है । मजदूरी बाँटने वाले तथा अन्य लोग उन्हें खूब धोखा देते हैं । खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, जो कि अधिकतर जिन्स में मजदूरी पाते हैं, बहुत कम मजदूरी मिलती है । फसल काटने के समय उन्हें कुछ ज्यादा मजदूरी मिलती है और उसमें भी उनका पेट नहीं भर सकता, फिर और दिनों की तो बात ही क्या है । अधिकतर बीमारी तथा विवाह के लिए मजदूर उधार लेता है और जब तक ऋण अदा न हो जाय तब तक वह ऋणदाता के यहाँ मुफ्त में या चवैनी पर काम करता है । पुश्त-दर पुश्त गुजर जाते हैं । परन्तु ऋण अदा नहीं होता और ऋणी मजदूर नहीं, गुलाम बना रहता है । इसे दूर करना चाहिये । अस्तु, जैसा कि योरप वगैरह में होता है वैसे ही भारत में भी यह बड़ा जरूरी है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी मिले जिनमें उन्हें जीवन की आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो सकें । भारत सरकार ने एक नया राज-नियम बना दिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक मजदूर की निम्नतम मजदूरी निश्चित की जायगी ।

### सूद (Interest)

पूँजी का व्यवहार करने के बदले पूँजीपति को जो कुछ दिया जाता है उसे सूद या व्याज कहते हैं । सूद के कारण धन बढ़ता है ।

सूद के दो भेद हैं—कुल सूद और वास्तविक सूद । साधारण भाषा में जिसे सूद कहते हैं उसी को अर्थशास्त्र में कुल सूद कहते हैं । अगर श्याम ने बारह रुपए सैकड़े सालाना पर एक सौ रुपया उधार लिया तो वर्ष भर का “कुल सूद” बारह रुपया हुआ । इस रुपए को उधार देने में ऋण-दाता का कुछ हिसाब-किताब रखने का व्यय होगा, कुछ रुपया वापिस न मिलने का जोखिम है । अगर इन दोनों बातों का अंश निकाल दिया जाय तो वास्तविक सूद बच जाएगा । हम यह सकते हैं कि वास्तविक सूद केवल पूँजी के व्यवहार का प्रतिफल है ।

सूद की दर का निश्चय—पूँजी की माँग और पूर्ति से होता है। अगर पूँजी की माँग अधिक है तो सूद की दर अधिक होगी। अगर पूँजी की माँग कम है और पूर्ति अधिक है तो सूद की दर कम होगी। लेकिन अधिकतर उधार देने वालों की कमी रहती है या यो कह लें कि किसान मजदूर आदि केवल दो एक महाजनों को जानते हैं। अतः उनकी अज्ञानता के कारण उन्हें सूद की दर अधिक देनी पड़ती है। गाँव का महाजन और मिल के पास रहने वाला बनिया महाजन तो अधिकतर सूद की दर दो पैसे से लेकर एक आने की रुपया प्रति मास तक आसानी से ले लेते हैं। परन्तु जब काबुली उधार देते हैं तो वे दो आने की रुपया तक सूद लेते हैं क्योंकि वे ज्यादातर अधिक गरीब और गरजमन्द को बिना अधिक पूछ-ताछ के रुपया देते हैं और रुपया न मिलने पर अदालत में जाने की जगह अपने डंडे का भरोसा रखते हैं। सहकारी साख समितियाँ १२-१८ प्रतिशत वार्षिक पर उधार देती हैं क्योंकि उन्हें सस्ती दर पर रुपया मिलता है। इस सम्बन्ध में हम विशेष हाल आगे बताएँगे। प्रादेशिक सरकार भी रुपया उधार देती है और उसकी दर समिति से भी कम होती है। व्यापारी बैंक जैसे इम्पीरियल बैंक ६ प्रतिशत सालाना सूद पर दे देती हैं। उन्हें सहकारी समिति से भी सस्ते पर रुपया प्राप्त होता है। दूसरे व्यापारी बैंक ज्यादातर रुपए वाले व्यापारी को तथा मिल वालों को पूँजी उधार देते हैं। अतः उनके रुपए वापस न मिलने का जोखिम कम रहता है। यह भी बात है कि शहरों में उधार देने वाले बैंकों की कमी नहीं रहती। पूँजी की पूर्ति काफ़ी होने से सूद की दर घट जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सूद की दर माँग और पूर्ति पर निर्भर रहती है।

हमारे किसानों की हालत इतनी खराब रहती है कि उन्हें अपने श्रम का पूरी तौर से बदला भी नहीं मिलता। फसल तैयार होने नहीं पाती कि जमींदार का कारिन्दा, मजदूर, महाजन सब उसे लूटने आ पहुँचते हैं। महाजन उसे बीज, खरीदने, बैल मोल लेने आदि कार्यों को रुपया उधार देता है। हमारे महाजन गाँव के अपढ़ किसानों को खूब लूटते हैं। तीस चालीस रुपये देकर पचास के रुक्के पर अँगूठा लगवा लेना तो आसान काम है। सूद १ दर पैसे दो पैसे रुपये से लेकर आना दो आना रुपया माहवार तक होती

है। छोटे किसानों का रुपया उधार लिए बगैर काम नहीं चल सकता।

शहरों में सेठ-साहूकार जायदाद रेहन करके या गहना गिरवी रखकर रुपया कर्ज देते हैं। परन्तु यह जरूरी नहीं कि रुपया उधार देने के लिए कोई वस्तु गिरवी रखी जाय। अक्सर महाजन विश्वासपात्र सज्जनों को हाथ का रुक्का लिखा कर ही रुपया उधार दे देते हैं। कभी-कभी रुक्के में फेर पड़ने से या उसके खो जाने पर महाजन को असल से भी हाथ धोना पड़ता है। आजकल यदि देखा जाय तो रुपया के लेन-देन के बगैर कुछ काम ही नहीं चल सकता। विदेशों से करोड़ों रुपये का माल आता है और वहाँ जाता है। व्यापार में उन्नति करने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि उसमें रकम लगाई जाय। व्यापारी के पास पर्याप्त रकम तो होती नहीं। उसे बैंकों से रुपया उधार लेकर लगाना पड़ता है। कहाँ तक बताएँ, सरकार को भी कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज में कोई बुराई नहीं समझी जाती। लेकिन यह बात उसी वक्त तक लागू होती है जब कर्ज से होने वाली उन्नति से सूद से अधिक फायदा होता रहता है। लेकिन भारतीय किसान और मजदूर तो फिजूल खर्ची और अनुत्पादक कार्य के लिए भी कर्ज लेते हैं। विवाह-शादी या जन्म-मरण सम्बन्धी रिवाज में बहुत खर्च कर दिया जाता है। फिर अपने रोजाना खर्च के लिए भी किसान रुपया उधार लेते हैं। यह अनुत्पादक होता है। उनसे सूद का मिलना तो अलग रहा अमल का भी खातमा हो जाता है। इसके अलावा किसानों की साख और हैसियत कम होने से उनसे अधिक दर से सूद लिया जाता है। अधिक सूद की दर का यह भी कारण है कि कृषि अनिश्चित है। अतः यह निश्चय नहीं है कि रबी या खरीफ की फसल के बाद रुपया अवश्य वापस मिल जायगा। गिरी अवस्था के कारण हमारा किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में मर जाता है।

### वेतन

व्यवस्था कार्य के लिए मैनेजर को वेतन मिलना है। आज कल व्यवस्था कार्य करना विशेषज्ञ का काम हो गया है। फलतः अगर मदी और मस्ती आने पर कारखानों का काम बंद प्राय होता है तब भी मैनेजर मोटी मोटी तनख्वाह उकारते रहते हैं। अमेरिका में ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब मजदूर निकाले जाते हैं और उनकी मजदूरी कम की जाती है तब भी

मैनेजर अच्छूता बचा रहता है। जहाँ तक गाँवों का प्रश्न है, किसान के खाने का व्यय ही नहीं चलता, उसके वेतन और मुनाफे की तो बात ही नहीं उठती।

### मुनाफा या लाभ (Profit)

साहस का प्रतिफल मुनाफा या लाभ है। बिना लाभ कोई काम नहीं होता। हमारा किसान ही इससे परे है। कारण वह दूसरा धन्धा नहीं ढूँढ़ता। वह कृषि को व्यापार नहीं बरन् अपना जीवन-क्रम समझता है। तथा वह बाप दादों की भूमि और पेशे को छोड़ उनकी आत्मा दुखी नहीं करना चाहता। अन्यथा हर व्यापार, उत्पादन कार्य आदि के लिए लाभ अनिवार्य है।

मुनाफे के दो भेद हैं—कुल मुनाफा और वास्तविक मुनाफा। एक व्यापारी सौ रुपए की वस्तु ११० रु० में बेचता है। हम कहेंगे कि उसे १०% का कुल मुनाफा हुआ। परन्तु इस दस रुपए में उसकी पूँजी का सूद, जमीन किराया, बीमे की रकम तथा अप्रत्याशित वृद्धि शामिल है। अप्रत्याशित वृद्धि से हमारा मतलब उस वृद्धि से है जिसका व्यापारी को वित्कुल ध्यान नहीं था तथा जिसकी उसको पहले से कोई आशा नहीं थी। कुल मुनाफे में उपर्युक्त अंश निकाल देने पर वास्तविक मुनाफा बच रहता है।

मुनाफा भी साहस की माँग और पूर्ति पर निर्भर है और उन्हीं के द्वारा निश्चित होता है। अगर चीनी के उद्योग खोलने के लिए साहसियों की कमी न हो तो बहुत से चीनी के कारखाने खुल जाँएंगे और प्रत्येक साहसी को कम मुनाफा होगा। जहाँ केवल एक दो साहसी होंगे वहाँ वे अधिक लाभ कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय लोहे के उद्योग में अधिक लाभ है। यह वास्तविक मुनाफे की बात हुई। अगर हम कुल मुनाफे की दृष्टि से विचार करें तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन व्यय कम होने तथा अधिक दाम वसूल करने से लाभ बढ़ता है। अतः मिल-मालिक उसी मजदूरी में अधिक काम कराना चाहता है और मजदूरी भी कम करना चाहता है। माल जितनी जल्दी बिकता है उतनी ही बिक्री अधिक होती है और मुनाफा भी बढ़ जाता है। अगर बाजार में प्रतियोगिता कीमत और लाभ घट जायगा। अधिक जमीन तथा मशीन के पास

होने से भी मुनाफा अधिक होता है। बुद्धिमानों और दूरदेशी से प्रवृत्त करने पर भी मुनाफा बढ़ जाता है।

कुल मुनाफे की दृष्टि से ही हम यह भी कह सकते हैं कि प्रदेश और नगर में कुछ ऐसे बड़े सौदागर होते हैं जो देश के अन्दर और बाहर के भाव का हर वक्त पता लगाये रखते हैं और वे एक ओर से माल खरीदकर दूसरी ओर बेच लेते हैं। बीच का मुनाफा वे खुद खा जाते हैं। कुछ सौदागर जिन्हें आदतियाँ कहते हैं बनियों या किसानों से माल खरीद कर बड़ी-बड़ी मंडियों में या बन्दरगाहों में भेज देते हैं। ये लोग अपने काम में बड़े चतुर होते हैं और किसानों तथा बनियों की अज्ञानता से खूब लाभ उठाते हैं। दूकानदारी में मुनाफे का एक विचित्र ही ढंग रहता है। वहाँ पर तो दूकानदार हर एक ग्राहक से मोल करता है, दाम बँधे तो होते नहीं। एक वस्तु का दाम किसी से चार आना, किसी से साढ़े चार आना या पाँच आना लिया जाता है। ग्राहक जितना ही अवोध होता है उतना ही दूकानदार को अधिक मुनाफा होता है।

आजकल अधिक मुनाफा लेना व्यापार-कुशलता का चिन्ह माना जाता है। जिस मनुष्य को सबसे अधिक मुनाफा होता है लोग उसकी ही नकल करने की कोशिश करते हैं। मुनाफा बढ़ाने के लिये कंपनियाँ अपने नौकरों से कह देती हैं कि यदि किसी निश्चित सीमा से अधिक लाभ हुआ तो इस अधिक लाभ का एक हिस्सा तुमको भी दिया जायगा। इससे मजदूर और दिल लगाकर काम करते हैं, परन्तु याद रखना चाहिए कि अधिक मुनाफा करने से कुछ थोड़े से ही मनुष्यों के पास द्रव्य और रुपया इकट्ठा हो जाता है। इसके विपरीत हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम सब की आवश्यकताओं को पूरा करें। मनुष्य का उद्देश्य सुख-शान्ति प्राप्त करना रहता है। केवल रुपया पैसा से ही आदमी को सुख-शान्ति नहीं मिल सकती। अलग किसी अध्याय में हम जमींदारी प्रथा, किसान का जमींदार से क्या सम्बन्ध रहता है इत्यादि के बारे में तुम्हें कुछ हाल बताएँगे।

### अभ्यास के प्रश्न

१—वितरण का अर्थ उदाहरण सहित समझादिये।

२—लगान का सिद्धान्त समझादिये। अत्यधिक लगान किन दशाओं में लिया जा सकता है?

३—उत्तर प्रदेश में लगान और मालगुजारी का क्या सम्बन्ध है ?

४—जमीन कितने प्रकार की होती है ? उनके गुणों का लगान से क्या सम्बन्ध है ? जमीन की स्थिति का लगान से क्या सम्बन्ध है ?

५—नई सड़कों के बनने, नई रेल की लाइन खुलने, मनुष्य की संख्या वृद्धि इत्यादि का लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

६—अनाज की मूल्य वृद्धि का लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

७—मजदूरी किस सिद्धांत के अनुसार निश्चित होती है ? भारत में मजदूरी कम होने के प्रधान कारण क्या हैं ?

८—असली मजदूरी और नकद मजदूरी के भेद उदाहरणों सहित समझाइये ।

९—उत्तर प्रदेश में मजदूरों को कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिये ?

१०—सूद की दर किस प्रकार निर्धारित होती है ? गाँवों में सूद की दर अधिक होने के प्रधान कारण क्या हैं ?

११—किस कर्ज के लिए सूद की दर अधिक होती है—उत्पादक कर्ज के लिए अथवा अनुत्पादक कर्ज के लिये ?

१२—अपने गाँव के पाँच किसानों के आय व्यय का कम से कम एक फसल का पूरा हिसाब रखिए और यह पता लगाइये कि प्रत्येक को कितना मुनाफा हुआ । यदि किसी किसान को कुछ भी मुनाफा न हुआ तो उसके न होने के कारणों का पता भी लगाइए ।

१३—लगान खर्च में कौन कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं ?

१४—किन उद्योग-धंधों में अधिक मुनाफा होना है और क्यों ?

१५—बहुत लोगो की यह धारणा हो गई है कि इस प्रदेश में अधिकांश किसानों को खेती से कुछ भी मुनाफा नहीं होता । यह कहाँ तक सत्य है ? यदि यह सत्य है तो किसान फिर खेती क्यों नहीं छोड़ देते ?

१६—भारतीय गाँवों में सूद की दर अधिक क्यों है ? उसे घटाने के लिये क्या उपाय करिएगा । (१९४३)

१७—गाँव के विभिन्न काम करने वालों को किस प्रकार मजदूरी मिलती है ? मजदूरी के इस ढंग का उनकी कार्य-क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (१६४४)

१८—लगान का अर्थ समझाइये । गाँव में लगान किस प्रकार निश्चित होता है ? हाल में किसान को अत्यधिक लगान से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? (१६४५)

१९—(अ) सूद क्यों दिया जाता है ?

(ब) (i) काबुली ३६% सूद पर रुपया उधार देता है ।

(ii) सहकारी समिति १२% सूद लेती है ।

(iii) बैंक व्यापारियों को ६% सूद पर देती है ।

सन्तुष्ट में समझाइए कि उपर्युक्त सूद की दरों में अंतर क्यों है ? (१६४६)

२०—‘मजदूरी’ की व्याख्या कीजिए । गाँव का मजदूर कानपुर जाकर अठाई रुपये रोज पर काम नहीं करता और अपने ही गाँव में बारह आने रोज पर मजदूरी करना पसंद करता है । इसका क्या कारण है ? (१६४६)

२१—(अ) विभिन्न कृषि-मजदूर को भिन्न मजदूरी क्यों मिलती है ?

(ब) यदि कृषि-मजदूर प्रत्येक कृषि कार्य के लिए एक समान योग्य हो, क्या तब भी मजदूरी भिन्न होगी ? (१६४८)

## बारहवाँ अध्याय

### औद्योगिक मजदूर

#### गन्दी वस्तियाँ

कारखानों और मिलों में काम करने वाले तीस चालीस लाख मजदूरों की जिन्दगी मनुष्य की जिन्दगी नहीं कही जा सकती । मजदूर को अपनी आय का चौथाई से छठवाँ भाग किराये पर व्यय करना पड़ता है । तब भी उसे एक गद्दी सी कोठरी मिलती है । इस निवास स्थान में हवा की गुजर नहीं होती । यहाँ पाखाने और स्नान का कोई प्रबन्ध नहीं होता । गन्दा



पानी निकलने और बहने के लिए उपयुक्त नालियाँ नहीं होतीं। यहाँ सफाई नहीं की जाती। जो मजदूर अपनी गृहस्थियों के साथ रहते हैं उन्हें उसी कमरे में रहना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पकाना आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रति छोटी कोठरी में पाँच छः प्राणी रहते हैं। वेपर्दगी के कारण मजदूर अधिकतर अकेले रहते हैं। अतः वे जुए, शराब, वेश्यावृत्ति के शिकार बन जाते हैं। रहने वाले साँस के, मूत्र के तथा तपेदिक के रोगों के शरीर बन जाते हैं। बालमृत्यु और मृत्यु संख्या अधिक होती है। इन सब बातों का मजदूर की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। उत्पादन कम होता है। वे जल्दी-जल्दी देहात भागते हैं ताकि अपने बाल बच्चों के साथ रह आएँ और स्वास्थ्य भी सुधार ले।

औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बम्बई में जो जाँच हुई है उससे प्रतीत होता है कि वहाँ-६७ प्रतिशत मजदूर एक कोठरी में रहते हैं और प्रत्येक कोठरी में ६ से ६ तक प्राणी रहते हैं। अहमदाबाद में ७५ प्रतिशत मजदूर एक कोठरी में रहते हैं। लगभग यही दशा कानपुर, मदरास तथा कलकत्ता की है। रहने के स्थान की इस कमी का मजदूरों के स्वास्थ्य पर भयंकर प्रभाव पड़ता है। सच तो यह है कि यह केन्द्र बीमारियों के स्थायी अड्डे बन गए हैं और मजदूरों को उनमें नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वास्तव में जिस प्रकार के मकानों में भारतीय मजदूर रहता है वे मनुष्य के लिए क्या पशुओं के लिए भी उपयुक्त नहीं है। हम नीचे कुछ विशेष किस्म के निवास स्थानों का हाल बताते हैं।

### बम्बई

बम्बई में अधिकांश मजदूर “चालों” में रहते हैं। चाल कोठरियों की एक लम्बी पक्ति को कहते हैं जिसके सामने एक पतला बरामदा होता है। यह कई मजिल की होती है और एक दूसरे से सटी होती है। दो चालों के बीच में एक गज से अधिक जगह नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि नीचे की मजिल तथा ऊपर की मजिलों के बीच की कोठरियों में हवा और रोशनी नहीं पहुँचती। इन चालों में शौचगृह नहीं होते। दो चालों के बीच जो पतली सी गली होती है वही शौचगृह का काम देती है। इसका यह होता है कि चालों में तेज दुर्गन्ध सदैव बनी रहती है। कोठरियों

की खिड़कियाँ उस गली की ओर ही खुलती हैं जिन्हे दुर्गन्ध के कारण मजदूर बन्द रखते हैं इस कारण कोठरियों में हवा का प्रवेश नहीं हो पाता । इन चालों का कूड़ा भी इसी गली में फेंक दिया जाता है । मलमूत्र और कचरे की सड़ोद भयंकर दुर्गन्ध उत्पन्न करती है और सारे वायुमण्डल को दूषित कर देती है ।

### कलकत्ता

कलकत्ते के समीप मजदूर “बस्तियों” में रहते हैं । कलकत्ते की ये बस्तियाँ इतनी गन्दी होती हैं कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । वे गन्दे रोग ग्रस्त बिल हैं जहाँ मानवता सड़ती है । ये बस्तियाँ भोपड़ों की होती हैं । बस्ती का मालिक मजदूर को जमीन दे देता है और बाँस और फूस दे देता है तथा मजदूर स्वयं भोपड़ा खड़ा कर लेता है । इन भोपड़ों में हवा और रोशनी के लिए खिड़की या रोशनदान नहीं होते तथा धुआँ निकलने के लिये कोई मार्ग नहीं होता । बस्तियों के आस पास अनेक पोखरे और तालाब होते हैं जिनमें वर्षा का जल सड़ता है और वे रोगों के कीटाणुओं के जन्म स्थान बन जाते हैं । इन बस्तियों में स्वच्छ जल की कमी रहती है । दो बस्तियों के बीच में ३ फीट चौड़ी गली होती है और उसमें ही बस्ती की गन्दी नाली बहती है । और इन्हीं गन्दी बस्तियों में मजदूर नारकीय जीवन व्यतीत करता है ।

### मदरास

मदरास में अधिकांश मजदूर “चैरियो” में रहते हैं । मजदूर खाली स्थान पर स्वयं अस्थायी भोपड़े या कच्ची पक्की कोठरिया बना लेते हैं और इन्हीं को चैरी कहते हैं । जमीन के मालिक उनसे बहुत अधिक किराया लेते हैं । इनमें नालियाँ नहीं होती और पानी तथा रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं होता । शहर के अत्यन्त गन्दे भाग में होती हैं । ये कोठरियाँ या भोपड़े छोटे होते हैं । उनकी दीवारें कच्ची होती हैं और तेल के पाँपे की दीन से छाँदे जाती हैं । यह अत्यधिक गन्दी होती हैं । शौचगृहों का कोई प्रबन्ध नहीं होना इस कारण गन्दगी और भयंकर रोग धारण कर लेती हैं ।

### कानपुर

कानपुर में अधिकांश मजदूर “अहातो” में रहते हैं। इन अहातों में एक कोठरी और उसके सामने एक बराड़े वाले बहुत से मकान होते हैं। प्रत्येक कोठरी में एक दरवाजा होता है कोई खिड़की नहीं होती। इनमें हवा और रोशनी का भी समुचित प्रबन्ध नहीं होता तथा गन्दगी तो हद दर्जे की होती है।

### अहमदाबाद

अहमदाबाद में भी मजदूर मानो नरक में रहता है। अधिकांश मजदूर एक कोठरी में रहते हैं जिनमें हवा और रोशनी का गुजर नहीं होता। गन्दे तो यह इतने होते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। पानी और शौचगृहों की व्यवस्था बहुत खराब होती है।

### कोयले के खानों के केन्द्र

रानीगज, झरिया तथा अन्य कोयले की खानों के केन्द्रों में मजदूर “घोरो” में रहते हैं। इन कोठरियों में ही मजदूर रहते हैं और उन्हीं में वे खाना पकाते हैं। इनकी छूते वर्षा में चूनी है। इनमें खिड़की या रोशनदान नहीं होते और न वहाँ सफाई रहती है। अधिकांश मजदूर गन्दे तालों के पानी को काम में लाते हैं।

ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि भारतीय कारखानों के मजदूरों को कैसी गन्दी वस्तियों में रहना पड़ता है। कुछ स्थानों पर कुछ मिल मालिकों ने सुधरी हुई वस्तियाँ बनाई हैं किन्तु वे बहुत कम हैं। हर्ष की बात है कि सरकार का इस ओर ध्यान गया है और मजदूरों के लिये अच्छे मकानों को बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

हमारे कारखाने के मजदूरों की बढ़ती हुई बीमारियों के इलाज का भी तो कोई प्रबन्ध नहीं है। न कोई यह शिक्षा देता है कि उन्हें किस प्रकार का भोजन करना चाहिये, न उसके खेलकूद का प्रबन्ध है, न मनोरंजन या क्लब की व्यवस्था है। परन्तु अब मजदूरों के दिन पलट रहे हैं। इन गन्दी वस्तियों का शीघ्र ही रूप बदल जाएगा।

### औद्योगिक सुख-सुविधा

एक जमाना था जब मिलों और कारखानों में काम करने वालों की दशा परवाह नहीं की जाती थी। न काम करने के घटे का नियंत्रण था,

न वेतन का । मुसीबत के दिनों में पैसों का कोई सिलसिला नहीं रह जाता था । उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की किसी को चिन्ता नहीं थी । वह कहाँ काम करते हैं, किस प्रकार के वातावरण में काम करते हैं, किस प्रकार का काम करते और कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, इन सब बातों का किसी को ध्यान नहीं था ।

### सरकारी प्रयत्न

परन्तु अब भारत सरकार कारखानों के मजदूरों के लिए उचित सुविधाएँ और वेतनादि प्राप्त करने के लिये वचनबद्ध है । भारत सरकार ने सामाजिक बीमा का कानून बनाया है । मिल मालिक और एक रुपये प्रति दिन से अधिक वेतन पाने वाले मजदूरों से चन्दा लेकर एक कोष स्थापित किया जायगा । जब कोई मजदूर बीमार पड़ेगा तो उसे इस कोष से डाक्टरों सहायता पहुँचाई जावेगी । उसे ५६ दिन तक अपनी मजदूरी भी दी जायगी और अशक्त होने पर सहायता भी की जायगी । नौकरी पर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को पेन्शन दी जाएगी । बच्चों को मातृत्व-काल में १२ सप्ताह की छुट्टी मिलेगी और उस काल में इसी कोष से बारह आने प्रतिदिन सहायता मिलेगी ?

इसी प्रकार कारखाना-कानून में संशोधन किया गया है । अब मजदूरों को अधिक स्वास्थ्यप्रद, साफ सुथरी और अधिक सुरक्षित परिस्थिति में काम करने को मिलेगा । उन्हें सवेतन छुट्टी भी मिलेगी । अब तक मिलों में मजदूरों को ठेकेदारों के द्वारा नौकरी मिलती थी । यह ठेकेदार उन्हें लूटता था । अब सरकार नौकरी दिलाऊ केन्द्रों को स्थापित कर रही है । ये केन्द्र बिना किसी से फीस लिये मजदूरों को नौकरी दिलाते हैं । मजदूरों के लिये प्रावुडेट फंड की व्यवस्था की जा रही है ।

मजदूरों के लिये उपयुक्त मकानों की व्यवस्था करने के लिये भी सरकार कानून बना रही है । इस समय भारत सरकार दस लाख मजदूरों को बसाने की एक योजना चला रही है । कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों के लिये पचास हजार मकान बनाना आरम्भ हो गया है ।

भारत सरकार मजदूरों के वेतन के सम्बन्ध में भी एक न्यूनतम वेतन कानून बनाया है। इसके अन्तर्गत सरकार यह निश्चय कर देगी कि किस काम के लिए कम से कम कितनी मजदूरी दी जाय। इसी कानून में खेती में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी निश्चित करने की भी व्यवस्था है।

### मिल मालिकों के प्रयत्न

अब मिल मालिक भी मजदूरों की सुख-सुविधा का कुछ ध्यान रखने लगे हैं। कुछ मिलें मजदूरों के लिये मकान बनवाती हैं जिससे मजदूर अपने बाल-बच्चों के साथ रहता भी है और गैर हाजिर भी कम रहता है। कहीं-कहीं बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध है और मजदूरों के लिये रात्रि-पाठ-शालाएँ, मनोरञ्जन और व्यायाम के लिए अखाड़े, व्यायाम-शालाएँ आदि का इतजाम करते हैं। कुछ मिलों में दवा भी मुफ्त बाँटी जाती है।

### अन्य संस्थाओं के प्रयत्न

अन्य संस्थाओं में मजदूर सघ मुख्य हैं। हम उनके बारे में नीचे बता-येंगे। इन्हें छोड़ कर कुछ स्थानों में समाज सेवा सघ, सरवेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, बाल-सुख-संघ आदि शिक्षा, औषधि, जच्चा-बच्चा की सेवा का प्रबन्ध करती हैं। वे प्रचार द्वारा शराब खोरी, जुआ आदि बुराइयों को दूर करने के लिये भी प्रयत्न करते हैं। कहीं-कहीं वनियों और महाजनों से बचाने के लिए सस्ते अन्न, चाय आदि की दुकानें भी खोली गई हैं।

### ट्रेड यूनियन

भारतीय ट्रेड यूनियन कानून के द्वारा मजदूरों का यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने सघ (ट्रेड यूनियन) बनाएँ। ये इन संघों के द्वारा कारखानेदारों से सामूहिक ढंग पर सौदा कर सकते हैं।

भारत में अभी तक ट्रेड यूनियनों की संख्या कम है। लगभग तीन चौथाई ट्रेड यूनियन छोटी-छोटी हैं। रेल, कपड़े की मिलों और मल्लाही सम्बन्धी काम करने वाले मजदूरों की ट्रेड यूनियन सबसे अधिक हैं। ट्रेड-यूनियनों के लगभग दो तिहाई सदस्य इन्हीं तीन क्षेत्रों में काम करते हैं। उद्योग धन्धों में मजदूरों के जो सघ बनते थे उन्हें अधिकतर मिलमालिक मानते थे। सरकार भी इस ओर चुन रहती थी। परन्तु जैसा ऊपर

चताया जा चुका है, अब सरकार ने इन संघों को कानूनी रूप देने का निश्चय कर लिया है।

परन्तु हमारी ट्रेड यूनियनों में अक्षमता भरी पड़ी है। हमारे मजदूरों की शिक्षा-दीक्षा तो नहीं के बराबर रहती है। अतः ट्रेड यूनियन की नेतागिरी कुछ पढ़े लिखे लोगों के हाथ में होती है। मजदूर उन्हीं के इशारे पर नाचते हैं। शीघ्र प्रसिद्धि प्राप्ति के लालच में ये नेतागण मजदूरों को तरह तरह के लाल दे देते हैं, और फिर उसकी पूर्ति के लिए वे उन्हें हड़ताल करने के लिए उकसाते हैं, हड़तालों के कारण उत्पादन घट जाता है और वस्तुओं की उत्पत्ति कम होती है। आजकल हमारे आजाद देश में मिल के तैयार माल की जो कमी है उसका एक महत्वपूर्ण कारण हमारी ट्रेड यूनियने कही जा सकती हैं। उनके कारण ही मजदूरों में अधिक वेतन माँगने और धीरे-धीरे काम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस समय तो यह जरूरी है कि मजदूर नेता मजदूरों को समझा कर हड़ताले रोकें और उन्हें अधिक उत्पत्ति के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें।

ट्रेड यूनियने मजदूरों को नकारात्मक ढंग से तो सहायता करने का प्रयत्न करती हैं परन्तु रचनात्मक ढंग से कोई काम नहीं करती। उदाहरणार्थ मजदूरी की कमाई ऋण चुकाने और बर्निंग को दाम देने में उड़ जाती है। ट्रेड यूनियनों का कर्त्तव्य है कि वे मजदूरों की अपनी दूकानें खोलें ताकि वे बर्नियों के चंगुल से बच सकें। मजदूरों को वर्तमान व्यय में अधिक सामान दिलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। इसी प्रकार मजदूरों की ओर से ट्रेड यूनियनों को मकान मालिकों से मोर्चा लेना चाहिए जो अधिक किराया ले कर तंग और गन्दी बस्तियों में रहने पर बाध्य करते हैं। परन्तु ट्रेड यूनियने ऐसे काम नहीं करती। कहा जाता है कि यदि उनके नेता इस प्रकार मजदूरों की कठिनाइयाँ हल कर दें तो उनकी पूछ कम होगी। उनकी नामवरा नहीं होगी। उनके नाम और उनके वक्तव्य समाचार पत्रों में स्थान नहीं पायेंगे। यदि ऐसा है, तो उनका ख्याल गलत है। देश में सच्चे चुपचाप कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम धीरे-धीरे फैल जाता है। सब उनको जानने लगते हैं। यह प्रसिद्धि अधिक टिकाऊ होती है। कम से कम देश को इसी प्रकार के काम करने वालों की आवश्यकता है।

हमारी ट्रेड यूनियनों में धन की भी कमी रहती है । आय-व्यय का कोई हिसाब नहीं रखा जाता । मेम्बरों की कोई पूरी सूची नहीं रहती । अतः हड़ताल के दिनों में मजदूरों को अधिक सहायता नहीं पहुँचाई जा सकती और अधिकतर हड़तालें असफल साबित होती हैं ।

### भारतीय ट्रेड यूनियनों की निर्बलता के कारण

मजदूर आन्दोलन की निर्बलता के मुख्य कारण नीचे लिखे हैं :—

१—मजदूरों का अशिक्षित होना, वे मजदूर संगठन से होने वाले लाभ को नहीं समझते ।

२—औद्योगिक केन्द्रों में मजदूर एक भाषा नहीं बोलते । उनकी भाषा भिन्न होती है क्योंकि वे भिन्न-भिन्न प्रदेशों से आते हैं । इस कारण उनका संगठन अच्छा नहीं हो पाता ।

३—मजदूर अत्यन्त निर्धन होते हैं वे चन्दा इत्यादि देने में रुचि नहीं दिखाते ।

४—भारत में औद्योगिक केन्द्र बिखरे हुये हैं वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं इस कारण उनको संगठित करने की उतनी सुविधा नहीं है ।

५—भारतीय मजदूर स्थायी रूप से औद्योगिक केन्द्रों में काम नहीं करते । वे कुछ समय काम करके फिर अपने गाँवों को लौट जाते हैं इस कारण वे मजदूर आन्दोलन में अधिक दिलचस्पी नहीं लेते ।

६—मजदूर आन्दोलन का योग्य हाथों में न होना ।

आज भारतीय मजदूर आन्दोलन राजनैतिक नेताओं के हाथ में है । कुछ मजदूर यूनियनों कम्युनिस्टों के हाथ में हैं । कुछ सामाजवादियों के हाथ में और कुछ कांग्रेस के हाथ में हैं । ये मजदूर नेता अपने दल के स्वार्थ से मजदूरों में कार्य करते हैं उनके हितों का इतना ध्यान नहीं रखते ।

### अभ्यास के प्रश्न

१—भारतीय मजदूर किस दशा में रहता है, उसका सन्क्षिप्त विवरण दीजिए ।

२—भारत के किन्हीं दो औद्योगिक केन्द्रों में मजदूर के रहने के स्थानों का वर्णन कीजिए और बतलाइए कि उसका उनके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है ।

- ३—भारतीय मजदूर के लिए सरकार ने कानून बनाकर कौन सी सुविधाये प्रदान की हैं ।
- ४—भारतीय ट्रेड यूनियनों ( मजदूर सभाओं ) का सन्निहित विवरण दीजिए ।
- ५—भारतीय ट्रेड यूनियनने सुसंगठित क्यों नहीं हैं ? उनकी निर्बलता के क्या कारण हैं, लिखिए ?
- 

## तेरहवाँ अध्याय

### बटाई प्रथा

पिछले अध्याय में तुमको धन के वितरण के बारे में बताया गया था । लगान का जिक्र करते समय जमींदार प्रथा, स्थाई बन्दोबस्त आदि का थोड़ा सा हाल लिखा गया था । लगान के इन विभिन्न बन्दोबस्तों तथा जमींदार और किसान के सम्बन्ध के बारे में हम अगले अध्याय में खुल कर हाल लिखेंगे । सरकार जमीन जमींदार के सुपुर्द कर देती है । इसके बदले में जमींदार सरकार को मालगुजारी देने के लिए बाध्य हो जाते हैं । सरकार को अधिकतर मालगुजारी से ही मतलब रहता है । जमींदार को इस बात की स्वतन्त्रता रहती है कि वह जिस प्रकार चाहे उस प्रकार उन खेतों को काम में लावे । चाहे वह स्वयं मजदूर लगा करके जमीन जोते बोवे और फसल पैदा करे चाहे वह लगान के ऊपर उस जमीन को किसान को उठा दे । जमीन को लगान पर देने से जमींदार को किसान से एक निश्चित दर से रुपया मिलता है । यह दर खेत के क्षेत्र के हिसाब से होता है जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया था । सरकार द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि जमींदार किसी खेत से किसी निश्चित रकम से ( जो भी ठीक हो जाय ) अधिक लगान नहीं ले सकता । किसान जमींदार को यही लगान देकर रह जाता है । लगान पर दी गई जमीन के जोतने-बोने का सारा खर्च किसान के ऊपर रहता है । जमींदार को उससे कोई मतलब नहीं रहता । किसान अपना हल-बैल लावे, अपनी ओर से मेहनत, धन



तथा बीज आदि लगावे । चूँकि जमींदार को केवल लगान से मतलब रहता है, अतएव उसको इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि किसान के खेत में कितना अनाज पैदा होता है ।

### बटाई प्रथा क्या है ?

ऊपर बताई गई प्रथा के अलावा एक और रीति है । जमींदार या मौरूमी किसान अक्सर अपनी जमीन किसान को इस शर्त पर जोतने देने के लिए दे देते हैं कि वे उनसे नकद लगान लेंगे नहीं परन्तु पैदा होने वाली उपज का एक हिस्सा ले लेंगे । इसकी बटाई-प्रथा कहते हैं । अधिकतर जमींदार कुछ जमीन तो स्वयं जोतते-बोते हैं, कुछ बटाई पर किसानों को दे देते हैं । लेकिन आमतौर पर जमींदार जमीन को बटाई पर देना पसन्द नहीं करते । इसका कारण हम आगे चलकर बतायेंगे । बटाई पर जमीन देने से पहले जमींदार और किसान आपस में तय कर लेते हैं कि हल, बैल, बीज आदि कौन देगा ? यदि ये सब चूँजे किसान लगाता है तो जहाँ तक होता है आधा-आधा हिस्सा तय होता है अर्थात् यदि दो सौ मन अनाज पैदा होगा तो सौ मन अनाज जमींदार ले लेगा । कहीं-कहीं जमींदार किसान को बीज दे देता है । कभी हल-बैल भी मिल जाते हैं । ऐसी हालत में जमींदार पैदावार का दो तिहाई हिस्सा ले सकता है ।

### बटाई की दर

वैसे तो बटाई-प्रथा के अन्तर्गत किसान को मालगुजारी नहीं देनी पड़ती । लेकिन कुछ जगहों में ऐसी भी शर्त रखी जाती है कि मालगुजारी कौन देगा । यदि किसान मालगुजारी भी देता है तो जमींदार का हिस्सा केवल चौथाई भी रह सकता है । बटाई प्रथा में उत्तर प्रदेश में अधिकतर आधा हिस्सा कर लिया जाता था । लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है यह जरूरी नहीं है कि आधा हिस्सा ही लिया जाय । जमीन की हालत के ऊपर भी हिस्सा निर्भर रहता है । उदाहरण के लिए जमींदार के पड़ी हुई बेकार जमीन को ले लीजिए । कुछ जमीन परती पड़ी रहती कुछ ऊसर होती है । किसी जमीन के साथ उससे लगा हुआ ताल

तलैया भी दे दिया जाता है । इसके अलावा जिस जमीन में खेती होती है उसके किनारे कुछ बेकार जमीन पड़ी रहती है । जमींदार अक्सर ऐसी जमीन बहुत कम बटाई पर किसानों को देते हैं । जब ऊसर या बेकार पड़ी जमीन किसान को दे दी जाती है तब लगान लिया जाता है । वह जमीन उसे मुफ्त में जोतने-बोने को मिल जाती है । किसान मेहनत-मजदूरी लगा कर उस जमीन में खेती करता है और जो कुछ पैदा होता है उसे अपने काम में लाता है । लेकिन साल दो साल के बाद जमींदार अपना हक जाहिर करता है । जमीन तो अब उपजाऊ बन गई और दूसरे लोग उपज का कुछ हिस्सा देकर उस जमीन को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं । अतएव जिस किसान ने उस जमीन में पहले-पहल खेती की है वह जमींदार को उपज का एक हिस्सा देने पर मजबूर हो जाता है, हालाँकि यह बात जरूर है कि आरम्भ में यह भाग बहुत छोटा रहता है । किसान जमींदार को चौथाई या तिहाई भाग देने लगता है ।

यों तो मामूली जमीन और बेकार जमीन ही अधिकतर बटाई पर दी जाती है । परन्तु कभी-कभी उपजाऊ भूमि भी बटाई पर उठाई जाती है । आमतौर पर अच्छी व उपजाऊ जमीन लगान तय हो जाने पर बटाई के ऊपर उठाई जाती है ।

हिस्से पर मामला तय करे। परन्तु जैसा कि हम पहले बता आये हैं मामले तय होने में माँग और पूर्ति का हाथ रहेगा। यदि शंकर को खेती करने की गरज है तो वह रामू को शायद दो तिहाई तक दे देवे। परन्तु इसके विपरीत यदि फसल के बीच किसी कारण रामू अपना खेत किसी दूसरे को देना चाहता है तो शायद रामू को आधा हिस्सा भी मिलना मुश्किल हो जाय।

### बटाई प्रथा के गुण-दोष

जैसे और बातों में गुण-दोष होते हैं वैसे ही बटाई प्रथा में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। यदि किसान की दृष्टि से देखा जाय तो बटाई-प्रथा लगान प्रथा से कहीं बेहतर है। लगान पर लो हुई जमीन में उपज हो या न हो किसान को लगान तो देना ही पड़ता है। किसान यदि बहुत रोया-गाया तो कुछ माफी मिल जाती है। परन्तु बटाई पर दी हुई जमीन में तो किसान और जमींदार दोनों ही आपस में पहले से तय किये हिस्से में उपज बाँटते हैं। यदि अनावृष्टि या अन्य किसी कारण से किसी साल फसल मारी जाती है तो किसान जमींदार को बाकी फसल का हिस्सा देता है। इसी तरह यदि फसल बहुत अच्छी है तो किसान के साथ जमींदार को अधिक मात्रा में फसल मिल जाती है। परन्तु इसके अलावा कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें किसान उठा सकता है। जैसे यदि किसान के पास हल बीज न हों तो वे जमींदार से मिल सकते हैं। इस प्रथा में जमींदार को अलग नुकसान ही नुकसान दिखलाई पड़ता है। फसल खराब होने पर उसे किसान से ज्यादा दाम तो मिलता नहीं है। अतएव उस समय उसे अपनी गाँठ से मालगुजारी देनी पड़ती है।

इसके अलावा बटाई प्रथा के अन्तर्गत जमींदार को रुपये तो मिलते नहीं। उसे अनाज मिलता है। यहाँ पर भी किसान को फायदा ही रहता है। मान लो खेत में सौ मन अनाज पैदा हुआ। मान लो किसान अपने खाने-पीने के लिए दस मन अनाज रख कर नब्बे मन बेच देता है और फिर जमींदार को लगान के रुपये दे देता है। परन्तु यदि किसान ने खेत प्राप्ति हिस्से की बटाई पर लिया होता तो किसान को पचास मन अनाज मिलता। इस पचास में से उसे अब केवल चालीस मन अनाज बेचने की

सकलीफ उठानो पड़ेगी और जमींदार को पचास मन अनाज वेचना पड़ेगा । ऐसी दशा में एक बात और होती है । यदि कहीं फसल के बाद अनाज का बाजार भाव गिर जाय अर्थात् सस्ता विकने लग जाय तो जमींदार को और घाटा होता है क्योंकि चढ़े हुए भाव से वेचने पर उसे जो रुपये मिलते हैं उतने रुपये अब नहीं मिल सकते । इसके अलावा किसान कुछ नाजायज फायदे उठा सकता है । जैसे कुछ बेईमान किसान रात में या जमींदार की गैरहाजिरी में अनाज काट लेते हैं या काटा अनाज खलिहान से अपने घर उठा लेते हैं । इसके अलावा यह तो मामूली बात है कि बेटवारा होते समय यदि जमींदार या उसका आदर्मा नहीं पहुँचता तो किसान अपने घर अधिक माल उठवा देता है ।

बटाई प्रथा विधवाओं, नाबालिगों व उन व्यक्तियों की दृष्टि से भी अच्छी है जो विशेष कारणवश स्वयं खेती नहीं कर सकते और जो अधिकतर मजदूर रखकर खेती नहीं करा सकते ।

परन्तु बटाई-प्रथा के तीन मुख्य दोष हैं । प्रथम बटाई वाले किसानों को अधिकतर खेत में कोई हक नहीं प्राप्त होता । यह जरूर है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लगभग प्रत्येक खेतिहर को कम से कम लगातार पाँच साल तक खेती करने का हक मिल गया है वैसे ही हक दूसरी जगह भी दिये जायें । सन् १९४० के बंगाल कर्मशान ने बङ्गाल प्रान्त के बटाई पर खेती करने वाले बरगादार किसानों के लिये ऐसी ही सिफारिश की थी ।

द्वितीय, बटाई प्रथा में किसान अपनी मेहनत द्वारा उपज में जो वृद्धि करता है उसका केवल एक भाग उसे मिलता है । किसान को उपज बढ़ाने में उत्साहित करने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी वृद्धि में जमींदार का हिस्सा न हो ।

तृतीय, कहीं-कहीं लगान पर खेती करने वाले किसानों की अपेक्षा बटाई पर खेती करने वाले किसानों की हालत अच्छी नहीं है । उदाहरण के लिये बंगाल में बटाई की दर आधी उपज है । यदि यह बढ़ाकर एक तिहाई भी कर दी जाय तब भी उन्हें इस प्रकार जितना लगान पड़ेगा वह खेतों के मालिक की देन का साढ़े पाँच गुना होगा । अतः यह आवश्यक है कि बटाई की दर घटा कर उपज का चौथाई या पाँचवाँ हिस्सा कर दिया जाय ।

अतः इस समय बटाई प्रथा के कारण देश की उर्वरता नहीं बढ़ पाती । इसलिए अनुपयुक्त रूप में होने के कारण बटाई प्रथा देश के हित में रुकावट पैदा करती है ।

### मजदूरी सम्बन्धी बटाई

अब तक हमने जिस बटाई का हाल बताया है उसके अलावा गाँव में एक और बटाई होती है । यह बड़ा जरूरी है कि इस दूसरी बटाई को भी स्पष्ट कर दिया जाय । यह दूसरी बटाई भी खलिहान में ही होती है; परन्तु इसके हिस्सेदार बनिये, ब्राह्मण, नाई, चमार, धोबी, बढई, लोहार आदि गाँव के काम करने वाले होते हैं । भारतीय गाँवों में यह रिवाज है कि ये लोग साल भर किसानों को जिस वस्तु की जरूरत होती है देते रहते हैं । तेल की जरूरत पड़ने पर तेली को तेल देना पड़ता है । मतई का जूता फट जाने पर हामिद उसके लिये दूसरा जूता बना देता है । धोबी सब घर वालों के कपड़े धोता है । वह हर एक बड़े आदमी या औरत के पीछे चार-पाँच पसेरी अनाज लेता है । उसे छोटे बच्चों का कुछ नहीं मिलता । इसी प्रकार लोहार, बढई आदि कारीगर भी गाँव भर की सेवा करते हैं और फसल तैयार हो जाने पर हर एक के खलिहान से अपने-अपने हिस्से का अनाज ले आते हैं । इन लोगों के साथ हमे खेती में काम करने वाले मजदूरों को नहीं भूल जाना चाहिये । इन्हें अधिकांश मजदूरी काम करने के साथ ही साथ रोजाना मिलती जाती है क्योंकि इनको तो रोज ही खाने के लिये अन्न चाहिये । परन्तु फिर भी फसल के समय कुछ मजदूर फसल तैयार हो जाने पर नाज मिलने की शर्त पर लगाए जाते हैं । कुछ मजदूर पैसों पर काम करते हैं । परन्तु उन्हें भी फसल में से कुछ मिल जाता है । फसल कट जाने पर किसान ऐसा खुश रहता है कि उस समय उसके पास जो पहुँच जाये उसे ही कुछ न कुछ मिल जाता है ।

अस्तु, अब समझ में आ गया होगा कि इस बटाई और पहले बताई हुई बटाई में क्या फर्क है । पहली बटाई तो लगान का एक रूप-मात्र है । फर्क यही है कि लगान में आमतौर पर कमी नहीं की जाती और फसल में होने वाली घट-बढ़ का किसान ही जिम्मेदार होता है, परन्तु बटाई में किसान य जमींदार भी कुछ अंश में उसके सुख-दुख का साथी बनता है ।

दूसरी किस्म की बटाई में किसान उन सब कारीगरों और काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी चुकाता है, जो बिना कुछ लिए साल भर किसान की सेवा करते हैं तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पहली भाँति की बटाई का अन्न लगान है, तो दूसरी में दी हुई उपज मजदूरी और 'कीमन' स्वरूप है।

### बटाई और रीति-रिवाज

ऊपर बताई बटाई-प्रथाओं की दर में दस्तूर और रीति-रिवाज का बहुत कुछ असर पड़ता है। यदि यह दस्तूर चला आ रहा है कि सोहनसिंह कुँए के पास वाले खेत को उठाने में किसान से दो-तिहाई हिस्सा लेता है तो चाहे इस साल रामू खेत को ले चाहे पारसाल श्याम उस खेत को ले, सोहनसिंह का उस खेत में दो-तिहाई का हिस्सा रहेगा। इसी प्रकार यदि किसी खेत के साथ सोहनसिंह बीज भी देता है तो उसे दस्तूर के मुताबिक उस खेत को लेने वाले को बीज देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार धोबी, चमार, मेहतर आदि के हिस्सों के बारे में भी दस्तूर और रीति-रिवाज का बोलबाला रहता है। वंश परम्परा से धोबी का छोटे बच्चों और विधवाओं के पीछे कुछ भी अन्न नहीं मिलता। इसी प्रकार आदमी पीछे गाँव के धोबी को चार पंसेरी अनाज मिलता है, उस दर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि रीति-रिवाज के इस प्रभाव के कारण गाँवों के आदमियों के हिस्सों की दर बहुत पीढ़ियों तक स्थायी बनी रहती है। इससे महेँगी और सस्ती के समय गाँव वालों की आर्थिक दशा पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। महेँगी के समय में गरीब किसानों की हालत गिर जाती है। परन्तु लोहार, चमार आदि के जीवन में कुछ दिनों तक कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। भिन्न-भिन्न काम करने वालों की क्षमता में कुछ न कुछ अन्तर होता ही है। यदि उनकी कार्य-क्षमता एक सी हो, तब भी मजदूरी में अंतर रहेगा; क्योंकि उनको मजदूरी अधिकतर रीति-रिवाज पर निर्भर है।

अन्तु, जैसा हम आरम्भ में कह चुके हैं अगले अध्याय में हम सरकार और किसानों के सम्बन्ध में कुछ बातें बतायेंगे। सरकार किस प्रकार किसानों से लगान की दर निश्चिन करती है? क्या सरकार हमेशा जमींदार के

जरिये किसान से मालगुजारी वसूल करती है या कहीं पर किसान से सांघे वसूल करती है ? जमींदार सरकार को लगान का कौन सा भाग देते हैं ? जमींदार और किनानों के बीच आजकल कैसा सम्बन्ध है ? इन प्रश्नों में उत्तरों के अलावा खेती सम्बन्धी कागजातों के बारे में भी कुछ बातें बताई जावेगी।

### अभ्यास के प्रश्न

१—बटाई प्रथा आप के गाँव में कहाँ तक प्रचलित है ? आप पटवारी द्वारा यह पता लगाइये कि गत वर्ष कितने खेत बटाई पर किसानों को दिये गये थे।

२—आप के गाँव में बटाई की दर साधारणतया क्या है ? इससे अधिक दर किन दशाओं में लां जाती है ? रीति-रिवाज का इस दर पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

३—बटाई पर जोते जाने वाले खेतों की फसल की तुलना उन खेतों की फसल से कीजिये, जिनमें खेतों के मालिक ने स्वयं खेती की है। किन खेतों में फसल अधिक अच्छी होने की आशा की जाय और क्यों ?

४—अपने गाँव में जाकर यह पता लगाइये कि फसल तैयार हो जाने पर किसानों को हल पंछे नाई, धोवी, बढई, पुरोहित, चमार, कुम्हार इत्यादि को कितना अनाज प्रतिवर्ष देना पड़ता है।

५—बटाई प्रथा के गुण-दोष समझाइये और यह बतलाइये कि उसके दोष किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं ?

६—‘बटाई प्रथा में बेईमानी की बहुत गुञ्जाइश है’ यह कथन कहाँ तक सत्य है ?

७—‘बटाई प्रथा किसानों के लिए लाभदायक, परन्तु देश के लिए हानिकारक है,’ इस कथन की आलोचना कीजिए।

८—इस प्रदेश के गाँवों में रीति-रिवाज का लगान, मजदूरी और सूद की दर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

९—विभिन्न कृषि-मजदूर को भिन्न मजदूरी क्यों मिलती है ? यदि प्रत्येक कृषि-मजदूर प्रत्येक कृषि-कार्य के लिए एक समान योग्य हो, क्या तब मजदूरी भिन्न होगी ?

## चौदहवाँ अध्याय

### जमींदार और किसान

लगान के सम्बन्ध में लिखते समय देश में प्रचलित बन्दोवस्तों का जिक्र आया था। अब हम इन बन्दोवस्तों, जमींदारों तथा किसानों के आपस के सम्बन्ध व खेती के कागजात के बारे में विस्तारपूर्वक विचार करते हैं।

#### स्थायी बन्दोवस्त

सन् १८६० के लगभग बंगाल के गवर्नर लार्ड कार्नवालिस ने सरकार की ओर से भारत के कुछ भागों में मालगुजारी की रकम हमेशा के लिए निश्चित कर दी। यह रकम किसानों से वसूल किये जाने वाले लगान की नब्बे फी सैकड़ा थी। इस बन्दोवस्त से सरकार को बँधी हुई रकम मिलने लगी और फिर हर साल भुक्त से छुट्टी हो गई। इसके अलावा सोचा गया कि हमेशा के लिए बन्दोवस्त हो जाने पर जमींदार किसान की पढ़ाई-लिखाई, तन्दुरुस्ती, सफाई आदि का इन्तजाम करेंगे। लेकिन स्थायी बन्दोवस्त हो जाने की वजह से खेती में उन्नति होने पर सरकार की आमदनी नहीं बढ़ सकती थी। सन् १८०० से जमीन की पैदावार बहुत बढ़ गई है तथा जमींदार लगान के रूप में किसानों से उस समय की बनिस्वत अब कई गुना रुपया वसूल कर रहे हैं। लेकिन सरकार को एक पाई ज्यादा नहीं मिल सकती, यद्यपि आजकल देश की उन्नति तथा भलाई करने के लिये रुपये की बड़ी जरूरत है। दूसरे कुछ जमींदार दयालु और परोपकारी अवश्य हैं, लेकिन जो आशा की गई थी कि ऊपर बनाए बन्दोवस्त के बाद वे लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उन्नति करेंगे वह विलकुल पूरी नहीं हुई। अन्तु, स्थायी बन्दोवस्त बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन में चालू है।

#### बंगाल का फ्लाऊड कमीशन

१९४० में बंगाल सरकार ने श्री फ्लाऊड नुशान्स की अध्यक्षता में वहाँ की जमीन के बन्दोवस्त के सम्बन्ध में एक जाँच कमिशन भिजाया था। इस कमिशन की राय यह है कि बंगाल में स्थायी बन्दोवस्त ने भूमि के प्राप्ति और खेती में कोई सुधार नहीं हुआ। जमींदारों ने, जैसी



जाती थी कि वे अपनी जमीदारियों की उन्नति की ओर ध्यान देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया और उस प्रथा से किसानों की बहुत हानि हुई। वे भी भूमि तथा खेती की उन्नति नहीं कर पाते, साथ ही प्रादेशिक सरकार को एक बहुत बड़ी हानि यह हुई कि उसकी मालगुजारी (Land Revenue) से होने वाली आमदनी सदैव के लिए निश्चित हो गई। वह कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती। कमीशन का अनुमान था कि अगर आज के हिसाब से बंगाल में मालगुजारी लगाई जावे तो बंगाल सरकार को कई करोड़ रुपये का लाभ हो। अतएव कमीशन की राय थी कि बंगाल में जमींदारी प्रथा नष्ट कर दी जाये और स्थायी बन्दोबस्त तोड़ दिया जावे। सरकार जमींदारों को बदले में रकम देकर उनसे जमींदारी ले ले।

### अस्थायी बन्दोबस्त

भारत की अन्य जगहों में अस्थायी बन्दोबस्त है, अर्थात् वहाँ पचीस या तीस साल के लिए मालगुजारी निश्चित की जाती है। इसके बाद फिर से जमीन की देख-भाल की जाती है तथा उपज की जाँच करके मालगुजारी ठीक की जाती है। ज्यादातर यह देख गया है कि हर नए बन्दोबस्त के साथ मालगुजारी का भार बढ़ता ही रहता है। ये अस्थायी बन्दोबस्त कई तरह के हैं। बम्बई, मद्रास आदि प्रदेशों में रैयतवारी रिवाज चालू है। इसमें सरकार सीधे किसान से लगान वसूल करती है। किसान और सरकार के बीच में कोई जमींदार नहीं होता। बम्बई या मद्रास में तास साल में बन्दोबस्त होता है। रैयतवारी के अलावा महालवारी प्रथा होती है। यह मध्य प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित है। रैयतवारी और महालवारी प्रथा में केवल यही फर्क है कि महालवारी के अन्तर्गत गाँव का मालगुजार मालगुजारी चुकाने का जिम्मेदार रहता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में जमींदारी प्रथा चालू है। इसमें जमींदार या ताल्लुकदार अपने हिस्से की मालगुजारी देने के जिम्मेदार रहते हैं। जमीन के लगान की रकम सरकार की ओर से तय कर दी जाती है। जमींदार उस लगान की दर से किसानों को खेती करने के लिये जमीन देते हैं। इस तरह जमीन से जो लगान आ सकता है उसका निश्चित हिस्सा सरकार लेती है। मान लो जमींदार सौ रुपया लगान के रूप में वसूल कर सकता है।

पहले सरकार इसमें से सत्तर अस्सी रुपये मालगुजारी के रूप में ले लेती थी। लेकिन अब तो घटते-घटते यह रकम चालीस-पचास फी सैकड़ा के करीब रह गई है।

सरकारी मालगुजारी नगद रूपयों में ली जाती है, अनाज वगैरह में नहीं। जिस साल पानी कम बरसता है या ओला पाला पड़ता अथवा टिड्डी आदि लग जाती है, उस साल फसल खराब हो जाती है। मालगुजारी का कुछ हिस्सा माफ कर दिया जाता है। लोगों की शिकायत है कि छूट नुकसान के हिसाब से कम होती है। मालगुजारी के साथ लगान में भी कमी करनी पड़ती है। लगान मालगुजारी से भिन्न होता है। लगान तो किसान देता है और मालगुजारी जमींदार देता है। लगान जमींदार को मिलता है पर मालगुजारी सरकारी खजाने में जमा की जाती है। जहाँ जमींदार नहीं हैं, जैसे उन प्रदेशों में जहाँ रैयतवारी प्रथा चालू है, वहाँ किसानों का सरकार से सीधा सम्बन्ध रहता है। वहाँ सरकार किसानों से मालगुजारी वसूल करती है। सरकार लगान की दर व मालगुजारी दोनों को निश्चित करती है। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी उस लगान के आधार पर निश्चित होती है जो किसान पिछले बन्दोवस्त के समय जमींदार को देते थे। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर जमीन के गुणों और स्थिति की जाँच करते हैं और उसी हिसाब से लगान निश्चित किया जाता है। अगर किसी जमीन की मिट्टी अच्छी है तथा वह बाजार से बहुत पास है, तो उसका लगान ज्यादा रक्खा जाता है। लेकिन लगान (जमींदार के न रहने पर यह मालगुजारी भी कहा जा सकता है) की दर निश्चित करने की जो रीति बम्बई में चालू है वह सबसे अच्छी कही जाती है। वहाँ पर यह जानने की कोशिश की जाती है कि पिछले बन्दोवस्त के समय जो उपज हुई थी उसकी कीमत क्या थी और उस उपज को पैदा करने के लिए क्या खर्च बैठा था। उपज की कीमत से यह खर्च निकाल कर जो बचता है उसका लगभग आधा भाग आगामी बन्दोवस्त तक के लिए मालगुजारी निश्चित की जाती है। यों तो लगान निश्चित करने का यह तरीका हमारे प्रदेश के तरीके से कहीं अच्छा है। लेकिन किसानों को यह शिकायत रहती है कि उपज की कीमत बढ़ाकर और लागत खर्च घटाकर हिसाब लगाया जाता है। कहा जाता है कि इससे

किसानों को पूरी मजदूरी भी नहीं मिल पाती। किसानों के कई महीने भूखे रहने का कारण यह भी है।

### जमींदार और किसान

भारत में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास के उत्तरी जिलों में जमींदार प्रथा है तथा मध्य भारत, राजस्थान और विन्ध्यप्रदेश में जागीरदारी प्रथा है। जमींदार किसानों से लगान वसूल करके आधी से कम रकम मालगुजारी के रूप सरकारी खजाने में जमा कर देते हैं और शेष उनकी आय होती है। जमींदारों ने कभी अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। वे किसानों से अधिक से अधिक से लगान वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जो मौरूसी काश्तकार नहीं थे, शिकमी काश्तकार थे उनकी स्थिति तो दयनीय थी। उनको आये दिन वेदखल किया जाता था और अधिक लगान और नजराना लेकर दूसरों को जमीन उठा दी जाती थी। किसान को यह भरोसा नहीं रहता था कि उसके पास भूमि रहेगी या नहीं। केवल यही नहीं, जमींदार तथा जागीरदार किसानों से बेगार लेते थे किसान को बिना कुछ दिए ये लोग अपने खेतों पर तथा मकान पर काम करवाते थे। जमींदार तथा जागीरदार के पशुओं को चारा, लकड़ी, दूध इत्यादि मुफ्त देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त जमींदार और जागीरदार अनेक प्रकार की लगाते (कर) किसानों से जबरदस्ती वसूल करते थे। इस प्रकार जमींदार किसानों का शोषण करता था। केवल बात यहाँ तक ही नहीं रहती थी। जमींदार गाँव में मनोरंजन तथा विलासिता के साधन न होने के कारण गाँव छोड़कर शहरों में रहते थे। गाँव का धन उनके द्वारा खिचकर शहरों को जाता था और गाँव निर्धन हो रहे थे। गाँव में जमींदारों के कारिन्दे या कामदार काम करते थे जो किसानों का और भी अधिक शोषण करते थे। इस सबका परिणाम यह हो रहा था कि गाँवों की स्थिति दयनीय होती जा रही थी और ऐसी स्थिति में खेती की उन्नति नहीं हो सकती थी। खेती की उन्नति के लिए यह आवश्यक था कि जमींदारी और जागीरदारी को समाप्त कर दिया जावे और किसान को भूमि का स्वामी बना दिया जावे। यही कारण है पूर्वी पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मध्य भारत २ राजस्थान में जमींदार उन्मूलन कानून बना दिए गए और जमींदारों

और जागीरदारों को साधारण हर्जाना देकर समाप्त किया जा रहा है। वह दिन अब दूर नहीं है जबकि जमींदार और जागीरदार इस देश में नहीं रहेगे और किसान भूमि का स्वामी हो जावेगा।

### उत्तर-प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून

उत्तर-प्रदेश में पहली जुलाई १९५२ से जमींदारी उन्मूलन और भूमि-सुधार कानून (१९५१) लागू हो गया है। इसके अनुसार कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थलों को सभी भूमि पर से जमींदारों के अधिकारों का अंत हो गया है। प्रत्येक जमींदार को उसके वास्तविक मुनाफे पर उभयुक्त मुआविजा दिया जावेगा। किसानों की दो श्रेणियाँ होंगी—( १ ) भूमिधर ( २ ) सीरदार। वर्तमान जमींदार को सीर और खुदाशत भूमि में भूमिधर के अधिकार मिलेंगे। जो किसान अपनी लगान का दस गुना एक साथ दे देगा वह भी उस भूमि का भूमिधर कहलावेगा। भूमिधर किसानों को भूमि बेचने या बंधक रखने का पूर्ण अधिकार रहेगा। उन्हें भूमि पर मौरूसी हक रहेगा। सीरदार किसानों को भी मौरूसी हक रहेगा। परन्तु वह भूमि को न बेच सकेगा और न गिरवी रख सकेगा। इस प्रकार जो रुपया इकट्ठा होगा उसमें से जमींदारों को मुआविजा दिया जावेगा। जो छोटे जमींदार हैं उन्हें मुआविजे के अतिरिक्त काम धन्धा करने के लिये कुछ पूँजी सहायता के रूप में दी जावेगी। छोटे जमींदारों में पुनर्स्थापन सहायता उन्हीं को दी जावेगी जिनका वास्तविक मुनाफा दस हजार रुपया वार्षिक से कम होगा और यह सहायता उनके वास्तविक मुनाफे के एक गुने में २० गुने तक होगी। जिनकी आय कम होगी, उनको अधिक और जिनकी आय अधिक होगी, उनको कम सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए जिनकी वार्षिक आय २५ रुपया है उन्हें २० गुनी और जिनकी ५ हजार से दस हजार तक है उन्हें एक गुनी ग्रांट दी जावेगी। जो दस साल का लगान पेशगी देकर भूमिधर का अधिकार प्राप्त करेंगे उनका लगान जो आज वे देने हैं उसका आधा कर दिया जावेगा। भविष्य में केवल नायालिंग, विधवा, अपंग अथवा शारीरिक दृष्टि से अशक्त व्यक्ति और सेना में नौकरी करने वाले या विद्यार्थी अपनी भूमि को लगान पर उठा सकेंगे। भविष्य में किसी एक व्यक्ति के पास ३० एकड़ भूमि से अधिक भूमि नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त कानून में

भूमि को ६१/४ एकड़ से छोटे टुकड़ों में न बँटने देने तथा सहकारी खेती की भी व्यवस्था की गई है। अन्य प्रदेशों में भी जमींदारी प्रथा का अन्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमींदारों को उनकी क्षतिपूर्ति की रकम के सरकारी बौंड दिये हैं जिन पर २ 1/2 प्रतिशत सूद दिया जावेगा और ४० वर्षों में सारी रकम चुका दी जावेगी।

### जमींदारी प्रथा के विनाश का प्रभाव

उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के विनाश का परिणाम यह होगा कि किसान स्वयं भूमि का मालिक हो जावेगा। वह यदि अपनी भूमि से सुधार करके, कुआँ खोदकर तथा अन्य प्रकार से परिश्रम करके भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ावेगा तो उसको लाभ होगा। वह भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके वंशजों के अधिकार में रहेगी। अतएव किसान भूमि का सुधार करने, उसमें पूँजी और श्रम लगाने में सकोच नहीं करेगा। इसका परिणाम यह होगा कि खेती की उन्नति होगी, आज जितनी पैदावार होती है उससे अधिक पैदावार होगी और किसान समृद्धिशाली बनेगा। आज तो किसान को जमींदार भूमि से बेदखल करके दूसरे को भूमि दे सकता है। ऐसी दशा में किसान भूमि का सुधार करने तथा पैदावार को बढ़ाने का प्रयत्न क्यों करे? गैर मौरूसी काश्तकार को जमींदार जब चाहे इस भूमि पर से हटा सकता है और उसकी लगान बढ़ा सकता है। ऐसी दशा में जब तक कि जमींदारी प्रथा विद्यमान है तब तक किसान को आर्थिक दशा ठीक नहीं हो सकती और न खेती की ही उन्नति हो सकती है।

### पटवारी के कागजात

अस्तु, अब यह बताना बड़ा जरूरी है कि किसान और जमींदार के बीच जो बात ठहरती है तथा लगान वगैरह के बारे में जो फेर-फार होते रहते हैं उनका हिसाब कौन रखता है? तुम सबने पटवारी का नाम जरूर सुना होगा। बस, यही पटवारी खेतों से सम्बन्ध रखने वाले सब कागजात रखते हैं। और उत्तर प्रदेश में यही अब किसानों से लगान वसूलेंगे। इन कागजों को लैन्ड-रेकर्ड्स या जमीन के कागजात कहते हैं। के वगैर क्या काश्तकार क्या जमींदार, यहाँ तक कि सरकार का भी

काम नहीं चल सकता। सब के लाभ के लिए यह निहायत जरूरी है कि उन कागजों में जो कुछ दर्ज हो, वह ठीक हो। यदि उसमें जरा सी भी गलती हो गई तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर होगी। इसलिये यह आवश्यक है कि कागजों में सारी बातें अच्छी व पूरी तरह भरी जायें। यह ठीक मालूम पड़ता है कि हम तुम्हें पटवारी के सभी कागजातों के बारे में थोड़ा हाल बता दें।

पटवारी के पास जो कागजात रहते हैं वे सब छपे हुये फार्मों पर लिखे हुये होते हैं। पटवारी उन्हें एक सरकारी अफसर से जिसको रजिस्ट्रार-कानूनगो कहते हैं, प्राप्त करते हैं। रजिस्ट्रार-कानूनगो को सरकार की तरफ से ये कागजात छपे छपाये मिलते हैं। वे ही उन्हें रखते हैं और जिस पटवारी को जरूरत पड़ती है, उसे दे देते हैं। उन कागजों के नाम ये हैं—

शजरा मिलान, खसरा, स्याहा, खतौनी, जमाबन्दी, बहीखाता जिन्सवार और खेवट।

### शजरा मिलान

शजरा मिलान गाँव के खेतों और मकानों का नकशा होता है। यह मोमजामे के कपड़े या मजबूत कागज का बनाया जाता है। इसमें हर तरह की आराजी का नकशा दिया जाता है। जिस खेत का नकशा रहता है उसी में उसका नम्बर भी दिया रहता है। यह तुम्हें मालूम ही है कि आराजी या रकबा की हालत बदलती है, क्योंकि किसान खेत बेचते, खरीदते और दखल बेदखल होते रहते हैं। अतएव निश्चित समय के बाद इस नकशे में भी फेरफार होता रहता है। इसके लिए पटवारी हर एक खेत की जाँच करता है। साल भर के अन्दर उसमें जो रद्दोबदल होते हैं उनका ठीक ठीक हाल यह लिख लेता है। इस काम के लिए खेत को नापना पड़ता है। यदि नाप में जरा सी भी गलती हो गई तो बड़ी गड़बड़ी पड़ जाती है। इसलिए यह जरूरी होता है कि जिसका कुछ भी हक जमीन में हो, यह पटवारी के साथ साथ जाकर यह देखे कि सब लिखा-पढ़ी ठीक-ठीक हो रही है या नहीं। शजरा मिलान में तालाब, बाग और कुआँ वगैरह भी दिखाये जाते हैं। यह निहायत जरूरी होता है कि काश्तकार और जमींदार पटवारी की मदद करके ठीक-ठीक बातें पटवारी को लिखा दें। अस्तु,

१	खेत का नम्बर			
२	क्षेत्रफल एकड़ में या बन्दोबस्तो बीघे में			
३	मुहाल का नाम और पट्टा का नाम			
४	खेवट का नम्बर			
५	खतौनी का नम्बर			
६	किमान का नाम व जात			
७	नाचे का किसान और जात			
८	लगान			
९	सिंचाई का तराका			
१०	कुएँ			
११	सींचा हुआ	उपज	खरीफ	जोता हुआ क्षेत्रफल
१२	बिना सींचा हुआ	क्षेत्रफल		
१३			रबी	क्षेत्रफल
१४	सींचा हुआ	उपज		
१५	बिना सींचा हुआ	क्षेत्रफल	जाइद	क्षेत्रफल
१६		उपज		
१७	सींचा हुआ	क्षेत्रफल		
१८	बिना सींचा हुआ			
१९				
२०	सींचा हुआ	दो फमलो क्षेत्रफल		
२१	बिना सींचा हुआ			
२२	जमीन की क्रिम	बिना जोती हुई भूमि		
	क्षेत्रफल			
४	कैफियत			

१	सिलसिलेवार नम्बर		
२	किसान का नाम, वल्लिदयत और जात		
३	खेती का समय		
४	खसरा नम्बर		
५	गाँव के बाँधों में	क्षेत्रफल	
६	एकड़ या बन्दोबस्ती बाँधों में		
७	बिना जोना गया क्षेत्रफल		
८	कानूनी माँग		
९	ज्यादा माँग	नकद लगान	लगान
१०	अनाज की नकद कीमत	अनाज लगान	
११	अन्य सम्बन्धी खेतों का लगान		
१२	किस्त और साल	कुल माग वकाया सहित	
१३	प्रत्येक किस्त का माँग		
१४	रकम	वसूल यायी	
१५	मिचारे के नम्बर की तारीख		
१६	प्रत्येक किस्त का वकाया भाग		
१७	कोषायत		



१	थोक और पत्ती का नम्बर और नम्बरदार का नाम	
२	हिस्से (खाता) का सिलसिलेवार नम्बर	
३	हिस्से की तादाद, लगान और कर	
४	हिस्सेदार का नाम, वल्लिदयत वगैरह	फमली के लिये
५	तबादला करने वालों के नाम वगैरह	
६	जिसका तबादला हो उसका नाम मय रजिस्ट्रार-कानूनगो के दस्तखत, वगैरह	
७	तबादला होने वाले व्यक्तियों के नाम, वल्लिदयत वगैरह	
८	( जैसा स्तम्भ ५ में है )	फमली के लिए
९	( स्तम्भ ६ की तरह )	
१०	( स्तम्भ ७ की तरह )	
११	( स्तम्भ ५ की तरह )	फमली के लिये
१२	( स्तम्भ ६ की तरह )	
१३	( स्तम्भ ७ की तरह )	
१४	( स्तम्भ ५ की तरह )	फमली के लिये
१५	( स्तम्भ ६ की तरह )	
१६	( स्तम्भ ७ की तरह )	
१७		कैफियत

शजरा मिलान में गाँव की जितनी जमीन होती है, उसका इसमें खेतवार हिसाब रहता है। इस नक्शे को देखकर कोई भी किसान अपना खेत जान सकता है।

## खसरा

शजरा मिलान में तो खेतों का नक्शा ही रहता है लेकिन खसरे में जर्मन का पूरा हाल रहता है। नक्शे में जितने खेत रहते हैं उसमें उनके नम्बर दिये रहते हैं। वही नम्बर सिलसिलेवार खसरे में दर्ज रहते हैं। उन्हीं नम्बरों के साथ उन खेतों का क्षेत्रफल, लगान, जमीन किस तरह की है, जमींदार का नाम, किसान का नाम और फसल की किस्म आदि सब लिखे रहते हैं। जैसा साथ में छपे खसरे के फार्म से स्पष्ट है। खसरे का ठक-ठीक लिखा जाना बहुत जरूरी है। खेतों की गलत नापजोख का असर शजरा मिलान में तो नहीं के बराबर रहता है, लेकिन खसरे में अगर कुछ भी गलत लिखा जाता है तो बाद में लड़ाई-झगड़े चल जाते हैं और किसान वगैरह मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिये यह परमावश्यक है कि जमींदार और काश्तकार दोनों पटवारी के साथ रहकर अपने खेत की सब बातें खसरे में लिखवा दें। जो जो फेर-फार हुए हैं; वे जरूर ही पटवारी के कागजों में दर्ज हो जाने चाहिये। प्रत्येक गाँव का खसरा हर वर्ष ३० अप्रैल तक तैयार हो जाना चाहिए और दूसरे वर्ष अगस्त तक रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा हो जाता है।

## स्याहा

स्याहा वह कागज होता है जिसमें पटवारी जमींदार के कागजात देखकर लगान की वसूलयाची को खानापूरी करता है

## बहीखाता जिन्सवार

बहीखाता जिन्सवार में लगान का हिमाय लिखा जाता है। इसके साथ ही लगान का तरीका भी दिया रहता है। चाहे वह बटाई से लिया जाय चाहे और किसी तरीके से।

## खतौनी

खतौनी जमावन्दी खसरे के मुताबिक बनाई जाती है। इसमें कब्जे के मुताबिक किसानों के नाम दिये जाते हैं। किसानों और जमींदार के सब खेत एक जगह दर्ज रहते हैं। उसी में साथ ही लगान और बकाया लगान भी लिखा रहता है। खतौनी में भी सब जरूरी तबदीलियाँ लिखी रहती हैं। खतौनी का एक फार्म पृष्ठ १४५ पर छपा है।

## खेवट

ऊपर पटवारी के कागजातों में खेवट का नाम भी आया है। यह मुहाल-वार तैयार किया जाता है। हर एक मुहाल में सभी दखलकारों का एक रजिस्टर होता है। उसमें रकबे के सब मालिकों का हर एक अधिकार लिखा रहता है और यह भी लिखा रहता है कि वह अधिकार कितना और किस किस्म का है। पृष्ठ १४६ पर छपे खेवट के फार्म से यह बात स्पष्ट है। खेवट में जो तबदीली होती है, वह रजिस्ट्रार कानूनगों का आज्ञा लेकर होती है। उसके हुक्म के बिना कोई फेर-फार नहीं हो सकता। जो भी घटा-बढ़ी होती है उस पर उसके दस्तखत होते हैं, जिससे कि उनके लिए वही जिम्मेदार रहे।

## पटवारी के अन्य कार्य

- ऊपर बताये छै कागजातों को तो पटवारी पूरा ही करता है। उसके अलावा जब कोई किसान या जमींदार मर जाता है, जब कोई जमीन बेची जाता है, गाँवों की जब सरहद बदली जाती है, तब इन सब का हाल पटवारी को लिखकर देना पड़ता है। इसके अलावा जिस साल वर्षा कम होने के कारण, बाढ़ के कारण उज्र मारी जाती है, तब भी पटवारी को रिपोर्ट लिखनी पड़ती है।

पटवारी गाँव के बहुत काम का होता है। लेकिन वह किसानों पर होने वाले अत्याचार नहीं रोक सकता। ये अत्याचार तो तबो रोक सकते हैं जब जमींदारों की आँखें खुलें या किसान मिलकर कुछ काम करें। अब तो गाँव में लोग मिलकर समिति बना लेते हैं। इसे सहकारी समिति कहते हैं। सहकारी समितियाँ किसानों की हालत बहुत कुछ सुधार सकती हैं। हम इनका विचार सहकारिता के अन्तर्गत करेंगे।

## अभ्यास के प्रश्न

१—अपने गाँव के किसानों से पूछ कर यह ठीक ठीक पता लगाइये कि उनको गत वर्ष में अपने जमींदार को किस प्रकार की कितनी बेगार देनी पड़ी ।

२—यदि आप किसी गाँव के जमींदार बना दिये जायें तो उस गाँव के किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे ?

३—गैर मौरूसी काश्तकार की तुलना में मौरूसी काश्तकार की खेती अच्छी होने के प्रधान कारण क्या हैं ?

४—‘किसान गरीब होने से अंत में जमींदार भी गरीब हो जाता है’ इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए ।

५—जिन प्रदेशों में जमींदार नहीं हैं, क्या उनमें किसानों की दशा अच्छी है ? यदि नहीं तो उसके प्रधान कारण क्या हैं ?

६—स्थायी बन्दोबस्त के गुण-दोष लिखिये ?

७—उत्तर प्रदेश और बम्बई प्रदेश की मालगुजारी निश्चित करने की प्रणालियों की तुलना कीजिए । अर्थशास्त्र की दृष्टि से कौन-सी प्रणाली उत्तम है ?

८—उत्तर प्रदेश में नये कानून द्वारा किसानों को कौन-सी सुविधाएँ हुई हैं ? सन्क्षेप में लिखिए ।

९—गाँव में पटवारी का क्या महत्व है ? इसके द्वारा किसानों का क्या लाभ हो सकता है ?

१०—पटवारी के मुख्य कागजातों का वर्णन कीजिए । ये कागजात ठीक किस प्रकार रखाये जा सकते हैं ?

११—अपने गाँव के पटवारी से ‘खसरा’ लेकर उसका एक पृष्ठ नकल कर लाइये और यह जाँच कीजिये कि उसमें लिखी हुई बातें कहाँ तक ठीक हैं ।

## पन्द्रहवाँ अध्याय

### ग्रामों की समस्याओं का दिग्दर्शन

(Village Problems)

इस पुस्तक का विषय ग्राम्य अर्थशास्त्र (Rural Economics) है। पहिले अध्यायों में अर्थशास्त्र के मुख्य सिद्धान्तों पर विचार किया जा चुका है। अगले अध्यायों से हम ग्रामों की समस्याओं पर विचार करेंगे। इस अध्याय में इन समस्याओं का दिग्दर्शन कराते हैं।

भारत कृषि-प्रधान देश है। लगभग ३६ करोड़ जनसंख्या वाले इस महादेश में लगभग ७५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। जिस देश में लगभग तीन चौथाई जनसंख्या खेती करके गुजारा करता हो, वहाँ गाँवों का बहुतायत से होना अनिवार्यभावी है। यही कारण है कि भारत गाँवों का देश है। सारे देश में लगभग ५३ लाख गाँव हैं, जिनमें देश की ८२ प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ऐसी दशा में यदि भारत को गाँवों का देश कहा जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। महात्मा गाँधी ने ठीक ही कहा था कि वास्तविक भारत की जानकारी कलकत्ता और बम्बई जैसे विशाल नगरों को देखने से नहीं हो सकती, यदि किसी को भारत का सच्चा स्वरूप देखना है तो उसे गाँवों की ओर जाना चाहिये।

ऊपर दिए हुये विवरण से यह तो ज्ञात हो गया कि भारत में गाँवों का बहुत अधिक महत्व है। गाँव कोई नई संस्था नहीं है, वह हजारों वर्ष पुरानी है, और आज भी जब कि उसकी सब ओर से उपेक्षा हो रही है, वह जीवित है। परन्तु गाँवों की दशा अत्यन्त गिरी हुई है। गाँवों में रहने वाले अधिकांश ग्रामीण पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। दरिद्रता, गन्दगी, लड़ाई झगड़े, ऋण और अशिक्षा का गाँवों में एकछत्र राज्य है। सच बात तो यह है कि गाँवों की दशा अत्यन्त दयनीय है। न वहाँ स्कूल, अस्पताल और सड़कें ही होती हैं और न सभ्यता के कोई दूसरे ही साधन वहाँ मिलते हैं।

सैकड़ों वर्षों से नगरों द्वारा गाँवों का शोषण होता रहा है। गाँवों का केवल आर्थिक शोषण ही हुआ हो, यही बात नहीं है। प्रादेशिक सरकार अपनी आय का अधिकांश भाग गाँवों से वसूल करके अधिकतर नगरों पर व्यय करने लगी। इसका फल यह हुआ कि गाँव निर्धन हो गये। जमींदारों के नगर में जाकर बसने से एक हानि यह हुई कि जो भी गाँवों में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे गाँव में नहीं रहे। क्रमशः गाँवों में बुद्धि और धन का अकाल हो गया। इसका फल यह हुआ कि गाँवों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई। उनका सब तरह से पतन हो गया।

हर्ष का विषय है कि सैकड़ों वर्षों के उपरान्त अब सरकार, देश के नेताओं, तथा शिक्षित व्यक्तियों का ध्यान गाँवों की गिरी हुई अवस्था की ओर आकर्षित हुआ और ग्राम-सुधार आन्दोलन ( Rural uplift movement ) देश में उठ खड़ा हुआ है। इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं कि यदि हम चाहते हैं कि अधिकांश जनसंख्या आज जैसी नीची श्रेणी का जीवन व्यतीत न करके अच्छा जीवन व्यतीत करे तो हमें गाँवों का सुधार करना चाहिये।

इसमें पहले कि हम गाँवों को सुधारने की बात सोचें, हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भारत के गाँवों में कौन कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं, जिनके हल किये बिना गाँवों का सुधार नहीं हो सकता।

### गाँवों की समस्याएँ (Village Problems)

विद्वानों ने बहुत खोज करने के बाद यह नतीजा निकाला है कि जो

कुटुम्ब गाँवों में रहते हैं उनका जीवन और शक्ति शहरों में रहने वाले कुटुम्बों की अपेक्षा अधिक होती है। यदि किन्हीं सौ ग्रामीण कुटुम्बों को ले लिया जाय जो वरावर गाँव में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हों और उन्हीं की स्थिति के सौ शहराती कुटुम्बों को ले लिया जाय तो मालूम होगा कि गाँव में रहने वाले कुटुम्बों की आयु शहरों में रहने वाले कुटुम्बों से अधिक होगी। कहने का तात्पर्य यह कि जो कुटुम्ब सदैव गाँवों में रहते हैं वे बहुत अधिक पीढ़ियों तक चलते रहते हैं और शहरों में रहने वाले कुटुम्ब कुछ पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाते हैं। सच तो यह है कि गाँव, मनुष्य जन-संख्या की नर्सरी है जहाँ से मनुष्य रूपी पौधा शहरों में लगाया जाता है। जिस प्रकार कोई पौधा अपनी प्राकृतिक अवस्था में खूब पनपता है और अप्राकृतिक वातावरण में उसकी बाढ़ रुक जाती है, ठीक उसी तरह से मनुष्य की जीवन-शक्ति शहरों में पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाती है।

यदि गाँवों से शहरों में नया खून न पहुँचे तो शहरों में बहुत घटिया लोग दिखलाई दे। लेकिन गाँव से कुछ न कुछ कुटुम्ब सदैव शहरों में जाकर बसते रहते हैं और वहाँ जाकर धीरे-धीरे निस्तेज हो जाते हैं। इस लिये ग्रामीण जन-संख्या ही किसी देश की शक्ति का आधार है। यदि ग्रामीण जनसंख्या गिरी हुई दशा में रही तो देश की अवनति हुए बिना नहीं रह सकती। इसके लिए यह जरूरी है कि स्वस्थ, बुद्धिमान और पुरुषार्थी स्त्री-पुरुष गाँव में रहे।

आज भारतीय गाँवों की दशा यह है कि जो भी गाँव का लडका पढ़ जाता है, जो चार पैसे वाला हो जाता है, वह सदैव के लिए गाँव छोड़ कर शहरों में जाकर बस जाता है। जमींदार शहरों के आकर्षण के कारण अपनी जमींदारियाँ छोड़कर शहरों में जाकर बस गए हैं। ये जमींदार किसानों से प्राप्त धन को गाँवों में व्यय न करके शहरों में व्यय करते हैं। इस कारण गाँव निर्धन होते जा रहे हैं। भारत के गाँव का मस्तिष्क और पूँजी बाहर चली जा रही है। गाँव दिवालिया हो रहे हैं। जो भी व्यक्ति बुद्धिमान, साहसी और महत्वाकांक्षी होता है, वही गाँव छोड़कर शहर में जा बसता है। क्रमशः गाँवों में मनुष्यों का छाँटन रह गया है और प्रथम श्रेणी के

लोग शहरों में जाकर निस्तेज और क्षीण होते जा रहे हैं । इसका देश पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और हमारा सब तरह से पतन हो रहा है ।

कुछ हद तक गाँवों से शहरों की ओर प्रवास होना अनिवार्य है । हमारा कहना यह है कि गाँवों में भी शिक्षित, बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति रहना पसन्द करें जिससे कि जाति का हास न हो ।

अब हमें देखना चाहिए कि लोग गाँवों से भागते क्यों हैं ? गाँवों में आय के साधन कम हैं । ऊँचे दर्जे का सामाजिक जीवन, शिक्षा, मनोरंजन, सड़क, डाक, रेल, तार इत्यादि का अभाव है । यही कारण है कि कुशाग्र-बुद्धि और महत्वाकांक्षी युवक शहरों की ओर भागते हैं ।

अस्तु, जब तक हम गाँवों में यथेष्ट आय के साधन, शिक्षा, मनोरंजन, सड़क, डाक इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध नहीं कर देंगे तब तक यह प्रवास नहीं रुक सकता । वास्तव में हमारे ग्राम-सुधार आन्दोलन का यही लक्ष्य होना चाहिए ।

मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि गाँवों की नीचे लिखी मुख्य समस्याएँ हैं :—

१—ग्रामवासियों का पूर्ण निराशावादी दृष्टिकोण । गाँव वाला इस बात का विश्वास ही नहीं करता कि उसकी दशा सुधर सकती है, अस्तु वह अपनी दशा सुधारने का प्रयत्न भी नहीं करता ।

२—गाँवों में सफाई का अभाव । रोगों की बहुलता तथा चिकित्सा के साधनों का अभाव ।

३—गाँवों में शिक्षा की कमी ।

४—गाँवों में मनोरंजन तथा खेल-कूद के साधनों का अभाव तथा घरों को अधिक आकर्षक बनाने की समस्या ।

५—स्वास्थ्य रक्षा तथा उसके सिद्धान्तों की जानकारी न होना ।

६—पशुओं की समस्या तथा उनकी उन्नति के उपाय ।

७—खेती-बारी की उन्नति ।

८—गाँव में लड़ाई-भगड़े और मुकदमेवाजी की समस्या ।

९—ग्रामीण ऋण की समस्या ।

१०—गाँवों में धंधों की कमी और आय के साधनों का न होना ।



११—गाँवों में गमनागमन के साधनों का अभाव ।

१२—गाँवों में प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ तथा अंधविश्वास ।

अब हम प्रत्येक समस्या को लेकर उसकी विस्तृत आलोचना अगले अध्यायों में करेंगे ।

## अभ्यास के प्रश्न

१—भारत में गाँवों का महत्व बतलाइये और लिखिए कि गाँव वर्तमान समय में इतने महत्वपूर्ण क्यों हो रहे हैं ?

२—भारत के गाँवों की वर्तमान गिरी हुई दशा के मुख्य कारण क्या हैं ? विस्तारपूर्वक लिखिए ।

३—“ग्राम-सुधार” कार्य से आप क्या समझते हैं ? आजकल यह विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है ?

४—गाँवों की मुख्य समस्याएँ क्या हैं ? संक्षेप में लिखिये ।

५—यदि गाँवों में पुरुषार्थी, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति न रहे तो क्या हानि होगी ?

६—अपने प्रदेश के गाँवों की मुख्य समस्याएँ बतलाइए । ग्राम-सुधार तथा कृषि विभाग ने उनका कहाँ तक सुधार किया है । (१९४४ तथा १९४६) ।

## सोलहवाँ अध्याय

### किसानों का निराशावादी दृष्टिकोण

वास्तविक बात तो यह है कि ग्रामवासी इतने अधिक निराशावादी बन गये हैं कि उनको, चाहे कितना कहा जाय, यह विश्वास ही नहीं होता कि उनकी दशा में सुधार हो सकता है । यही कारण है कि जब उनसे किसी नवीन सुधार को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, तो वे इच्छापूर्वक उसे कभी स्वीकार नहीं करते । यदि ग्रामीण चेचक का टीका लगवाता है तो इस कारण नहीं कि उसका विश्वास है कि वह लाभदायक है, परन्तु सरकारी कर्मचारियों के भय से अथवा सरकार को प्रसन्न करने के लिए वह ऐसा करता है । सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाती

है, परन्तु वह कानूनों का बहुत कम उपयोग करता है। आज-कल ग्राम-मुधार आन्दोलन ( Rural uplift movement ) का जोर है। किसी किसी गाँव में यह दिखलाई पड़ता है कि मानो किसानों ने सफाई, घरों में हवा और रोशनी तथा अन्य आवश्यक सुधारों को अपना लिया है, किन्तु वास्तविक बात तो यह है कि यह सब सरकारी अफसरों के भय से अथवा उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि सरकारी कर्मचारी अथवा जिलाधीश उस गाँव की ओर से अपना ध्यान हटा लेते हैं तो थोड़े ही दिनों में गाँव पुरानी दशा को पहुँच जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्राम-वासियों के हृदय में अपनी तथा अपने गाँव की दशा सुधारने की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होती। जो कुछ भी वे करते हैं बाहरी दबाव के कारण करते हैं।

प्रश्न यह है कि ग्रामवासी इतने अधिक निराशावादी क्यों हैं ? क्यों वह अपने सुख, स्वास्थ्य और उन्नति के प्रति इतना उदासीन है ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें ग्रामवासियों की वास्तविक स्थिति को समझना होगा। वे शताब्दियों से दुर्भिक्ष और रोगों के शिकार होते चले आ रहे हैं। प्रकृति ऐसी चंचल और अस्थिर है कि खेती का धंधा बिल्कुल अनिश्चित बन गया है। किसान चाहे जितनी मेहनत करे, चाहे जितनी सावधानी से खेती को जोते बोवे, परन्तु वर्षा के कम होने से, अथवा अत्यधिक वर्षा होने से, टिड्डियों तथा अन्य फसलों के रोगों से, ओलों और तुषार से, तथा अन्य प्राकृतिक परिवर्तनों से, उसकी खेती नष्ट हो सकती है। किसान इस प्राकृतिक आक्रमण से अपनी फसल की रक्षा करने में असमर्थ रहता है। यही नहीं, शताब्दियों से वह और उसके पशु भयंकर रोगों के शिकार होते आ रहे हैं। जहाँ पशुओं की बीमारी फैली कि लाखों की संख्या में पशु मरने लगते हैं और यही दशा मनुष्यों की होती है।

यही नहीं, किसान भयंकर कर्ज के बोझ से इतना दबा रहता है कि वह अपने खेत में जो कुछ पैदा करता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा महाजन के पास चला जाता है। बेचारे गरीब किसान के पास तो सिर्फ ६ या १० महीने के खाने का अनाज भर रह जाता है। इन परिस्थितियों के कारण ग्रामवासी नितान्त निराशावादी तथा भाग्यवादी बन गया है।

यही कारण है कि' ग्रामवासियों के जीवन का सिद्धान्त यह बन गया है 'वर्तमान को देखो, भविष्य की चिन्ता न करो। क्योंकि भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता।' एक कारण और भी है जो किसान को अपने धंधे की उन्नति करने से रोकता है। वह है उसका ऋणी होना। भारतीय किसान इस बुरी तरह ऋण के बोझ से दबा हुआ है कि यदि वह वैज्ञानिक ढंग से खेती करके अपनी भूमि की पैदावार बढ़ाता है तो उसे कुछ लाभ नहीं होता। जितनी अधिक पैदावार होती है वह महाजन के पास जाती है। किसान को तो वर्ष में केवल आठ महीने का भोजन मिलता है। ऐसी दशा में वह खेती के आवश्यक सुधारों को क्यों अपनावे। जमींदारी प्रथा भी किसान को निराशावादी बनाती है। हर्ष की बात है कि अब जमींदारी प्रथा शीघ्र ही नष्ट होने जा रही है।

ग्रामवासियों को भाग्यवादी से पुरुषार्थवादी, और निराशावादी से आशावादी कैसे बनाया जावे। इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि जब तक ग्रामवासी यह विश्वास नहीं करने लगते कि उनकी गिरी हुई दशा में सुधार होना संभव है और अपनी दशा सुधारने के लिए उनमें उत्कट लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब तक गाँवों का सुधार होना असंभव है। गाँवों का सुधार स्वयं ग्राम-वासियों के द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। यदि सरकार अथवा और कोई संस्था किसी गाँव में नालियाँ, सड़कें तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कर दे तो थोड़े दिनों में उनका निशान भी नहीं रहेगा। नालियों और सड़कों की देख-भाल, सफाई और मरम्मत कौन करेगा। गाँव वाले तो उन्हें चाहते नहीं थे, वे तो उन्हें दान-स्वरूप मिली है। जिस वस्तु के लिए हम परिश्रम करते हैं अथवा धन व्यय करते हैं, उसका ठीक उपयोग भी करते हैं, और उसकी देख-भाल भी करते हैं। अतएव सरकार तथा ग्राम सुधार कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं का कार्य केवल इतना ही होना चाहिये कि वे अनुसंधान करें, ग्राम समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, इसका अध्ययन करें, और उसके अनुसार योजना बना कर गाँव वालों को बतावे।

यह तो हुआ काम करने का ढंग, परन्तु किसानों के भाग्यवादी दृष्टि-कोण को कैसे बदला जावे? इसके लिए लगातार प्रचार तथा शिक्षा की

आवश्यकता होगी। शिक्षा तथा प्रचार के द्वारा ही उनका दृष्टिकोण बदला जा सकता है। जब ग्रामवासियों का दृष्टिकोण बदल जावेगा, तभी उनमें अपनी वर्तमान दयनीय दशा के विरुद्ध असंतोष तथा घृणा उत्पन्न होगी। जिस दिन ग्रामवासियों में अपनी गिरी हुई दशा के विरुद्ध असंतोष तथा घृणा उत्पन्न हो जावेगी और वे भाग्यवादी नहीं रहेगे, उसी दिन से ग्रामों की दशा स्वयं सुधरने लगेगी।

आज तो भारतीय किसान घोर भाग्यवादी बन गया है। यदि खेत की फसल नष्ट हो जाती है, बैल मर जाता है, कर्जों में जमीन जायदाद बिक जाती है या बीमारी में उसके परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वह “भाग्य का दोष” कह कर चुप हो जाता है। उस विपत्ति को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं करता। बाप-दादों से चले आने वाले पैतृक कर्जा, जमींदार, पुलिस, महाजन, अदालतों और तहसीलों के कर्मचारियों का अत्याचार और शोषण, निर्धनता, बीमारी, अशिक्षा, और गरीबी ने उसे इतना निराशावादी बना दिया है कि वह यह स्वप्न में भी नहीं सोचता कि उसकी दयनीय स्थिति में सुधार हो सकता है। जब ग्राम-सुधार कार्यकर्त्ता उससे कहता है कि यदि कार्यकर्त्ता की बातों पर ध्यान दे तो उसकी दशा सुधर सकती है तो ग्रामीण सुन तो लेता है किन्तु विश्वास नहीं करता। और जब तक ग्रामीण का निराशावादी दृष्टिकोण बना हुआ है तब तक कोई स्थायी सुधार नहीं हो सकता।

अस्तु, जरूरत इस बात की है कि उसके दिल में अपनी इस दयनीय अवस्था के विरुद्ध घृणा और घोर असंतोष उत्पन्न किया जावे। वह सोचने लगे कि मैं इस बुरी दशा में नहीं रहूँगा, तब फिर उसे बतलाया जावे कि वह अपनी दशा किस प्रकार सुधार सकता है। तभी ग्रामीण नई बातों को स्वीकार करेगा।

अतएव जब तक किसान के हृदय में अपनी दयनीय दशा के विरुद्ध तीव्र असंतोष उत्पन्न नहीं हो सकता, तब तक न तो उसका निराशावादी दृष्टिकोण ही दूर होगा और न वह अपनी दशा को सुधारने की चेष्टा ही करेगा।

आज तो वह “मृत्यु का संतोष” लिये हुए जी रहा है। जो लोग भी

गाँवों की दशा को सुधारना चाहते हैं उन्हें इसके विरुद्ध ग्रामीणों में “असतोष” की भावना भरनी चाहिये ।

### अभ्यास के प्रश्न

१—किसान को जब उसके स्वास्थ्य और खेती की उन्नति के लिये कोई भलाई की बात बतलाई जाती है तो वह उसको अपनी इच्छा से कभी नहीं मानता । इसका कारण क्या है ?

२—किसान इतना अधिक निराशावादी क्यों बन गया ? इसके कारण बतलाइये ।

३—गाँव वालों की दशा को सुधारने में उनका निराशावादी और भाग्यवादी होना क्यों बाधक है ?

४—गाँव वालों की दशा में सुधार करने के लिए उनमें अपनी वर्तमान गिरी हुई दशा के प्रति असतोष उत्पन्न करने, और उन्हें पुरुषार्थवादी बनाने की जरूरत क्यों है ?

५—खेती की सफलता भाग्य पर निर्भर है । इस कथन की आलोचना कीजिए ।

## सत्रहवाँ अध्याय

### गाँव की सफाई (Sanitation of Village)

साधारणतः हम लोगों की यह धारणा बन गई है कि हमारे गाँवों में मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है । गाँवों में रोग और महामारी बहुत कम होती है । क्योंकि मनुष्यों को खुली हुई हवा और सूर्य का प्रकाश खूब मिलता है । किन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है । प्लेग, हैजा, हुकवर्म, कालाजार, चेचक तथा क्षय रोग गाँवों में घर बनाये हुए हैं । इन भयंकर रोगों के अलावा वर्षा के बाद गाँवों में सर्वत्र जूड़ी बुखार का भयंकर प्रकोप होता है, बङ्गाल और आसाम में तो मलेरिया का भीषण प्रकोप होता है । धान की फसल खड़ी रहती है किन्तु काटने वाले नहीं मिलते । इसका कारण है, गाँवों की गंदगी ।

गाँवों में सर्वत्र गंदगी का साम्राज्य होता है। गाँवों के समीप जाइये; दुर्गन्ध, मक्खियों, धूल और कूड़े की बहुतायत पाइयेगा। गाँव के समीप ही छोटे-छोटे ताल और पोखरे होते हैं जिनमें गंदा पानी सड़ा करता है। अनेक रोगों के कीटाणु यहीं जन्म लेते हैं। घरों में नालियाँ या नाबदान नहीं होते, जिनके कारण घरों का पानी गलियों में बहता रहता है। गाँव की गलियाँ कच्ची होती हैं, वे कभी साफ नहीं होती, उन पर धूल और कूड़ा जमा रहता है। बरसात में ये गलियाँ दलदल बन जाती हैं। किसानों की स्त्रियाँ घरों को साफ रखती हैं, किन्तु गली में कोई सफाई नहीं करता। अधिकतर गाँवों के घरों में शौचस्थान नहीं होते, स्त्री-पुरुष बाहर खेतों और मैदानों में शौच को जाते हैं। गाँवों की आबादी के चारों ओर मैदान, खेत, जङ्गल तथा तालाब ही गाँव वालों के शौचस्थान होते हैं। इससे गाँव में गंदगी फैलती है तथा वायु अशुद्ध होती है। गाँव के अन्दर ही खाद के ढेर लगे रहते हैं जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। घरों में काफी हवा और रोशनी आने का कोई प्रबन्ध नहीं होता और जिन कोठों में मनुष्य रहते हैं उनमें ही पशुओं को रक्खा जाता है। इस कारण घर भी गंदे रहते हैं। इन सब कारणों से गाँव में बहुत गंदगी रहती है और उसी के कारण पशु और मनुष्यों की बीमारियाँ फैलती हैं। अब हम प्रत्येक गंदगी के कारण पर विचार करते हैं।

### ताल या पोखरे (Village Pond)

ग्रामवासी अपने मकान कच्ची मिट्टी के बनाते हैं। प्रतिवर्ष वर्षात वीत जाने पर उन्हें अपने मकानों की मरम्मत करनी पड़ती है। अतएव उन्हें मिट्टी की बहुत आवश्यकता होती है। दूर न जाकर गाँव के लोंग आबादी के पान ही भूमि को गंदकर मिट्टी निकालने हैं जिनमें उन्हें मिट्टी टोला न पड़े। कड़ी-कड़ी धीरे-धीरे वह स्थान तालाब या पोखरा का रूप धारण कर लेता है। गाँव जितना ही पुराना होता जाता है, उनमें ही अधिक ताल और पोखरे बनने जाते हैं, क्योंकि गाँव वालों को मिट्टी की हर साल आवश्यकता पड़ती है।

ताल व पोखरों में प्रस्थान का पानी भर जाता है। वर्षा के दिनों में गाँव की गंदगी को नाप लेकर पानी इस ताल या पोखरे में आता है

प्रकार कच्ची खाद से कोई लाभ नहीं होता, वरन् उससे दीमक उत्पन्न होती है। खाद को गड़हों में सड़ाकर ही खेतों में डालना चाहिये। प्रयत्न तो यह करना चाहिये कि प्रत्येक घर में एक शौच-स्थान हो और कुछ सार्वजनिक शौचगृह हों, जिनका उपयोग अजनबी तथा गाँव में बाहर से आने वाले व्यक्ति कर सके। परन्तु अभी यह असम्भव नहीं है। भारत में तीन प्रकार के शौचस्थान गाँवों के लिए उपयोगी बतलाये गये हैं। एक तो खाद के गड़हे को ही शौचस्थान की भाँति काम में लाया जावे किन्तु किसान मैला के खाद को छूना नहीं चाहता, इस कारण इन गड़हों का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरे प्रकार का शौचस्थान बोर लैट्रिन (Bore Latrine) (भूमि में सूराख करके शौचस्थान बनाना) है। किन्तु स्वास्थ्य-विभाग का कहना है कि इससे पानी दूषित हो सकता है। तीसरे प्रकार का शौचस्थान साधारण गड़हे के रूप में बनाया जाता है, किन्तु उसमें एक प्रकार की हरी मक्खी उत्पन्न हो जाती है। इन गड़हों के चारों तरफ अरहर की एक बाड़ खड़ी करके दो तरफ़ें उस पर रखने से एक अच्छा खासा शौचस्थान तैयार हो सकता है। यदि शौचस्थान तैयार करने में कुछ कठिनाइयाँ हों तो इस बात का खूब प्रचार करना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति मैदान में शौच जाते समय अपने साथ खुर्पी अवश्य ले जावे और एक फुट का छोटा सा गड़हा करके उसमें शौच करके मल को मिट्टी से दबा दे। इससे गाँवों में हुकवर्म रोग नहीं होगा और गाँव गन्दगी से बच जावेगा।

### नावदान तथा नालियों की समस्या (Drainage)

गाँव की यह समस्या भी महत्वपूर्ण है। घरों में रसोई घर, बर्तन मॉजने तथा नहाने-धोने में जो पानी काम में लाया जाता है वह घरों में अथवा गलियों में गन्दगी फैलाता है। जहाँ देखिये वहाँ घरों के बाहर गलियों में काली काली कीचड़ दिखलाई देती है। इसका फल यह होता है कि उससे मच्छर उत्पन्न होते हैं और गन्दगी बढ़ती है। कुओं के पास भी पानी बहुत गिरता है, किन्तु उसके निकास का कोई प्रबन्ध नहीं होता। फल यह होता है कि कुएँ के पास दलदल तथा कीचड़ हो जाता है और वहाँ से पानी बह कर गलियों में जाता है।

होना तो यह चाहिये कि कुओं के पास ही औरतों के नहाने तथा कपड़े

धोने के लिये एक पर्दे की जगह बना दी जावे। पुरुषों के लिए खुली जगह भी उपयुक्त हो सकती है। इससे लाभ यह होगा कि घरों में बहुत कम पानी जावेगा और वहाँ गन्दगी कम होगी। अतएव वहाँ नाली बनाने की आवश्यकता ही न होगी। कुये की मन ( जगत ) को ऊँचा बनाया जाना चाहिये। अच्छा तो यह हो कि वह पटा हो, जिससे पत्ती और कूड़ा कुये में न जा सके। कुये के चारों ओर ढलवाँ सीमेंट की नाली बनवा दी जावे जिससे कि जो पानी गिरे वह कुएँ के पान ही न भरे। कुये के पास ही पानी गिरने से कुये का पानी दूषित हो जाता है। कुये की नाली और स्नान तथा कपड़े धोने के स्थानों की नालियाँ एक बड़ी नाली में मिला दी जावें। यह नाली भी कंकरीट की बनाई जावे या कुये का पानी नाली द्वारा गाँव के बाहर ले जाया जावे या दूसरा उपाय यह हो सकता है कि कुये के पास ही एक बगीची लगाई जावे और उसके पेड़ों और पौधों की सिचाई के लिये कुये के पानी का उपयोग कर लिया जावे। इन वाटिकाओं में फल और फूलों के पेड़ लगाये जावे। इनसे यह लाभ होगा कि गाँव का सौंदर्य बढ़ेगा और गन्दगी भी नहीं होगी। जिन घरों में बहुत जल काम में लाया जाता हो, वहाँ भी गृह-वाटिका में, अथवा तरकारी की बगारी में उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में इस समस्या को हल करने के लिये सोकेज पिट ( Soakage Pit ) बनाये गए हैं, किन्तु जब तक सोकेज पिट गहरे और बहुत बड़े तथा अच्छी तरह बनवाये न जावें, उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। लेकिन और कुछ प्रयत्न न होने से वे ही अच्छे हैं। वाटिकाओं द्वारा इस समस्या को अधिक सकलतापूर्वक हल किया जा सकता है।



तथा रोशनी का काफी प्रबन्ध नहीं करता। उनके मकान में खिड़की अथवा रोशनदार होते ही नहीं। ग्रामीण खिड़की अथवा रोशनदान चोरों के भय से नहीं लगाते। परन्तु हवा और रोशनी जीवन और स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है, अतएव रोशनदान अवश्य निकलने चाहिये। यदि छत के समीप ऊँचे पर रोशनदान लगाया जावे और उसमें लोहे की छड़ें हों तो चोरों का भी इतना भय नहीं रहेगा। यदि मकान एक दूसरे से भिड़े हों तो छत में रोशनदान तथा हवादान लगाना चाहिये। भविष्य में एक दूसरे मकान से सटा कर मकान न बनाने के लिये गाँव वालों को कहना चाहिये।

बहुत से ग्रामीण घरों में स्त्रियाँ सोने के कोठे में ही एक किनारे भोजन बनाती हैं, जिसमें धुआँ घुटता है और सोने का कमरा गन्दा हो जाता है। अतएव उन्हें यह बतलाया जाना चाहिए कि रसोई आँगन के एक किनारे पर सोने के कोठे से दूर होनी चाहिए और रसोई घर में धुआँ निकलने का मार्ग होना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। धुये से रसोई घर काला नहीं होगा, और घर की स्त्रियों की आँखें खराब होने से बच जावेंगी।

बहुत से किसान मकान में रहने के स्थान पर ही पशुओं को बाँध देते हैं। इससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और गन्दगी बढ़ती है। मकान के साथ एक छोटी सी पशुशाला होनी चाहिए जहाँ बैल बाँधे जावे। यदि पृथक् पशुशाला का प्रबन्ध न हो सके तो भी मकान में पशुओं को रहने के स्थान से दूर बाँधना चाहिए।

### गाँव की सड़के ( Village Roads )

गाँव की सड़के कच्ची होती हैं। दोनों ओर के खेतों के मालिक धीरे धीरे सड़क को खोद कर खेतों में मिलाने का प्रयत्न करते हैं, इससे सड़क पतली और टेढ़ी हो जाती है। यही नहीं, किसान अपने खेत की मेंड को बनाने के लिए सड़क में से मिट्टी खोद लेते हैं, जिससे सड़क में गड़हे बन जाते हैं। नहरें तथा कुये का पानी जब सड़क के पार ले जाया जाता है तो वह सड़क पर ही बहता रहता है। अधिकतर ये कच्ची सड़कें आस-पास के खेतों से नीची होती हैं। इस कारण बरसात में इनमें पानी भर जाता है।

सच तो यह है कि बरसात के दिनों में बैलगाड़ी का इन सड़कों पर चल सकना अमम्भव हो जाता है। सड़क खेतों से ऊँची होनी चाहिए जिससे वर्षा का पानी खेतों में चला जावे। गाँव की पचासत गाँव वालों को सड़क में से मिट्टी खोदने के लिए मनाही कर दे, और प्रतिवर्ष वर्षा के उपरान्त गाँव वाले मिल कर स्वयं सड़क की मरम्मत कर ले तो गाँव वालों को अपना पैदावार मंडियों में ले जाने, तथा आने-जाने में बहुत सुविधा हो जावे। सरकार और जिलाबोर्ड यह नियम बना दे कि जो गाँव सड़क बनाने के लिये मजदूरी मुफ्त देगा, उसको क़रुड अथवा अन्य सामान पक्की सड़क बनाने के लिये मुफ्त दिया जावेगा। इस प्रकार बहुत थोड़े व्यय से और गाँव वालों के परिश्रम से गाँवों में पक्की सड़कें बन सकती हैं। हाँ, वहाँ वालों को उन सड़कों की प्रतिवर्ष मरम्मत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। किन्तु यह काम तभी हो सकेगा जब गाँव वालों में अपने गाँव की दशा सुधारने की उत्कट लालसा उत्पन्न हो जावेगी।

### गाँव में कुशल दाइयों की समस्या

गाँवों में जो दाइयाँ हैं वे न तो गर्भवता स्त्रियों को ठीक से देखभाल ही करना जानती हैं और न बच्चा जनाने का काम ही ठीक तरह से कर सकती हैं। ग़दी तो वे इतनी होती हैं कि उनके छूने से ही माँ और बच्चे को रोग हो जाते हैं। सच तो यह है कि गाँवों में बहुत बड़ी सख्या में जो गर्भवती मातायें और बच्चे मरते हैं उनका कारण एक मात्र कुशल और साफ दाइयों का न होना है।

जब तक हर एक गाँव में या दो चार गाँवों के बीच एक शिक्षित कुशल और ट्रेनिंग दाई नहीं होगी, तब तक, बच्चों और माताओं की मृत्यु रोक नहीं जा सकती। ये दाइयाँ माताओं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करती हैं। अतएव सरकार, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा अन्य सभा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि यह किसी प्रकार रोक जावे।

प्रादेशिक सरकारों का प्रत्येक जिले में दाइयों के ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को तथा अन्य संस्थाओं को गाँवों की दाइयों को वर्जिफा देकर वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए।

तथा रोशनी का काफी प्रबन्ध नहीं करता। उनके मकान में खिड़की अथवा रोशनदार होते ही नहीं। ग्रामीण खिड़की अथवा रोशनदान चोरों के भय से नहीं लगाते। परन्तु हवा और रोशनी जीवन और स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है, अतएव रोशनदान अवश्य निकलने चाहिये। यदि छत के समीप ऊँचे पर रोशनदान लगाया जावे और उसमें लोहे की छड़े हों तो चोरों का भी इतना भय नहीं रहेगा। यदि मकान एक दूसरे से भिड़े हों तो छत में रोशनदान तथा हवादान लगाना चाहिये। भविष्य में एक दूसरे मकान से सटा कर मकान न बनाने के लिये गाँव वालों को कहना चाहिये।

बहुत से ग्रामीण घरों में स्त्रियाँ सोने के कोठे में ही एक किनारे भोजन बनाती हैं, जिसमें धुआँ घुटता है और सोने का कमरा गन्दा हो जाता है। अतएव उन्हें यह बतलाया जाना चाहिए कि रसोई आँगन के एक किनारे पर सोने के कोठे से दूर होनी चाहिए और रसोई घर में धुआँ निकलने का मार्ग होना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। धुये से रसोई घर काला नहीं होगा, और घर की स्त्रियों की आँखे खराब होने से बच जावेंगी।

बहुत से किसान मकान में रहने के स्थान पर ही पशुओं को बाँध देते हैं। इससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और गन्दगी बढ़ती है। मकान के साथ एक छोटी सी पशुशाला होनी चाहिए जहाँ बैल बाँधे जावें। यदि पृथक् पशुशाला का प्रबन्ध न हो सके तो भी मकान में पशुओं को रहने के स्थान से दूर बाँधना चाहिए।

### गाँव की सड़के ( Village Roads )

गाँव की सड़कें कच्ची होती हैं। दोनों ओर के खेतों के मालिक धीरे धीरे सड़क को खोद कर खेतों में मिलाने का प्रयत्न करते हैं, इससे सड़क पतली और टेढ़ी हो जाती है। यही नहीं, किसान अपने खेत की मेंड़ को बनाने के लिए सड़क में से मिट्टी खोद लेते हैं, जिससे सड़क में गड़हे बन जाते हैं। नहरें तथा कुये का पानी जब सड़क के पार ले जाया जाता है तो वह सड़क पर ही बहता रहता है। अधिकतर ये कच्ची सड़कें आस-पास के खेतों से नीची होती हैं। इस कारण बरसात में इनमें पानी भर जाता है।

सच तो यह है कि बरसात के दिनों में बैलगाड़ी का इन सड़कों पर चल सकना अमम्भव हो जाता है। सड़क खेतों से ऊँची होनी चाहिए जिससे वर्षा का पानी खेतों में चला जावे। गाँव की पचायत गाँव वालों को सड़क में से मिट्टी खोदने के लिए मनाही कर दे, और प्रतिवर्ष वर्षा के उपरान्त गाँव वाले मिल कर स्वयं सड़क की मरम्मत कर लें तो गाँव वालों को अपनी पैदावार मंडियों में ले जाने, तथा आने-जाने में बहुत सुविधा हो जावे। सरकार और जिलाबोर्ड यह नियम बना दे कि जो गाँव सड़क बनाने के लिये मजदूरी मुफ्त देगा, उसको कंकड़ अथवा अन्य सामान पक्की सड़क बनाने के लिये मुफ्त दिया जावेगा। इस प्रकार बहुत थोड़े व्यय से और गाँव वालों के परिश्रम से गाँवों में पक्की सड़कें बन सकती हैं। हाँ, वहाँ वालों को उन सड़कों की प्रतिवर्ष मरम्मत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। किन्तु यह काम तभी हो सकेगा जब गाँव वालों में अपने गाँव की दशा सुधारने की उत्कट लालसा उत्पन्न हो जावेगी।

### गाँव में कुशल दाइयों की समस्या

गाँवों में जो दाइयाँ हैं वे न तो गर्भवता स्त्रियों को ठीक से देखभाल ही करना जानती हैं और न बच्चा जनाने का काम ही ठीक तरह से कर सकती हैं। गदी तो वे इतनी होती हैं कि उनके छूने से ही माँ और बच्चे को रोग हो जाते हैं। सच तो यह है कि गाँवों में बहुत बड़ी सख्या में जो गर्भवती मातायें और बच्चे मरते हैं उनका कारण एक मात्र कुशल और साफ दाइयों का न होना है।

जब तक हर एक गाँव में या दो चार गाँवों के बीच एक शिक्षित कुशल और ट्रेन्ड दाई नहीं होगी, तब तक, बच्चों और माताओं की मृत्यु रोक नहीं जा सकती। ये दाइयाँ माताओं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करती हैं। अतएव सरकार, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा अन्य सभा संस्थाओं का यह कर्त्तव्य है कि यह किसी प्रकार रोक जावे।

प्रादेशिक सरकारों को प्रत्येक जिले में दाइयों के ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को तथा अन्य संस्थाओं को गाँवों की दाइयों को वर्जीफा देकर वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए।

जब काफी शिक्षित दाइयाँ तैयार हो जावे तब सरकार को एक कानून बना देना चाहिये कि बिना लाइसेंस लिए कोई भी दाई का काम नहीं कर सकती और लाइसेंस केवल उन्ही को दिया जावे जो कि ट्रेड हैं और इस कार्य में कुशल हैं।

जब तक ऐसा नहीं किया जावेगा तब तक बच्चों और माताओं के जीवन की रक्षा नहीं की जा सकती।

केवल बच्चा जनाने के लिए कुशल दाइयों का प्रबन्ध कर देने से हो काम नहीं चलेगा। गाँव की स्त्रियों को बच्चों के ठीक प्रकार से लालन-पालन करने की शिक्षा भी देना आवश्यक है। माताओं की भूल से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए इन दाइयों का कर्त्तव्य भी होगा कि वे बच्चों के लालन-पालन की शिक्षा स्वयं प्राप्त करे और माताओं को दे।

प्रतिवर्ष गाँव में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रदर्शन (Baby Show) किये जावे और स्वस्थ बच्चों की माँ को पारितोषिक दिया जावे। इसके साथ ही बच्चों का लालन-पालन कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी कराई जावे। यह प्रदर्शन कई दिन तक होना चाहिए।

### गाँव में सफाई और स्वास्थ्य की योजना

भारत में रोके जा सकने वाले रोगों के कारण जो भयकर हानि हो रही है वह सहकारी स्वास्थ्य समितियाँ स्थापित करके रोकੀ जा सकती है। हर एक गाँव में स्वास्थ्य रक्षक समिति की स्थापना की जावे। जहाँ तक हो सके हर एक गाँव वाले को उसके लाभ समझा कर उसका सदस्य बना लिया जाय।

सब सदस्यों की एक साधारण सभा हो। प्रतिवर्ष सभा वार्षिक प्रोग्राम निश्चित करे और दो मंत्री तथा पंच निर्वाचित कर दे। एक मन्त्री गाँव को सफाई की देख-भाल करे और दूसरा मन्त्री गाँव में चिकित्सा और दवा का प्रबन्ध करे।

गाँव के पास के सब गडहों को पाट दिया जाय, नालों तथा खेतों के बहाव को ठीक कर दिया जाय। वर्षा समाप्त हो जाने पर जहाँ पानी रुक जाय वहाँ मिट्टी का तेल छिड़काया जाय। इससे मलेरिया बुखार गाँव में

नहीं फैल सकता क्योंकि मलेरिया ज्वर का कीड़ा रुके हुए पानी में ही उत्पन्न होता है ।

पास के चार-पाँच गाँवों की स्वास्थ्य रक्षक समितियाँ मिलकर एक बड़ी समिति बनाले । हर एक ग्राम-समिति के प्रतिनिधि बड़ी समिति के सदस्य रहेंगे । बड़ी समिति एक चिकित्सक तथा योग्य नर्स को नौकर रखे । इनको निजी प्रैक्टिस करने की आज्ञा न होनी चाहिए । नर्स का काम यह होगा कि वह बड़ी समिति से सम्बन्धित गाँवों में बच्चा जुनाने का काम करे । बड़ी समिति का चिकित्सक बीच के गाँव में रहे और प्रतिदिन दो गाँवों में जाकर वहाँ जो भी बीमार हो, उन्हें दवा दे ।

चिकित्सक का मुख्य कार्य केवल चिकित्सा करना ही न होगा, बरन् रोगों से बचने का उपाय बताना भी उसका कर्त्तव्य होगा । मास में एक दिन प्रत्येक गाँव में चिकित्सक व्याख्यान देकर बतावे कि रोग क्यों उत्पन्न होते हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हैं । इसी प्रकार समिति की नर्स गर्भवती स्त्रियों का निरीक्षण करे और उनको बच्चों के लालन-पालन करने तथा गर्भवती स्त्रियों को किस प्रकार रहना चाहिये, इसकी शिक्षा दे ।

प्रत्येक सदस्य समिति को मासिक चन्दा देगा । जो सदस्य चन्दा देने में असमर्थ हो उससे समिति चन्दा न लेकर शारीरिक परिश्रम करवा ले । इस प्रकार सब ग्रामवासी यदि चाहे तो स्वास्थ्य रक्षक समिति के सदस्य बन सकते हैं । समिति अपने सदस्यों के लिये औपधियाँ भी रखे ।

ये बड़ी समितियाँ मिलकर जिला स्वास्थ्य रक्षक समिति का सङ्गठन करें । जिला समिति का कार्य केवल ग्राम समितियों की देखभाल करना, स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी प्रचार करना, जिले के किसी स्वास्थ्य-विभाग के कर्मचारियों से लिखा-पढ़ी करके जब कभी उस जिले के किसी भाग में बीमारों फैल जावे, उनको रोकवाने का प्रयत्न करना होगा ।

प्रादेशिक सरकार, जिला बोर्ड इन समितियों को आर्थिक सहायता देकर इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं । इस प्रकार यदि संगठन हो तो ग्रामीण अपने प्रयत्न के द्वारा ही गाँव में सफाई और स्वास्थ्य रक्षा की समस्या को हल कर सकते हैं ।

## अभ्यास के प्रश्न

१—गाँव इतने गंदे क्यों होते हैं ? कारण बतलाइये ।

२—गाँव के समीप के ताल और पोखरों का गाँव वालों के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है ? विस्तारपूर्वक लिखिये ।

३—गाँव के तालों और पोखरों से गाँव वालों के स्वास्थ्य पर जो बहुत बुरा असर पड़ता है, उससे बचने का रास्ता क्या है ?

४—किसान आजकल जो गाँव के किनारे ढेर लगाकर खाद बनाते हैं, उसको तुम कैसा समझते हो ? उसके हानि लाभ लिखिए ।

५—खाद को तैयार करने का अच्छा और स्वास्थ्य बढ़ाने वाला ढंग कौन सा है ?

६—गाँवों में रहने वाले खुले मैदानों, खेतों और तालाबों के किनारे शौच जाते हैं, इससे क्या हानियाँ होती हैं ?

७—गाँवों के लिए किस प्रकार के शौचस्थान उपयुक्त होंगे ? इन शौचस्थानों से गाँव के रहने वालों को क्या लाभ होगा ? सक्षेप में लिखिए ।

८—कुओं की मन (जगत) न होने से क्या हानि होती है ? कुओं के पास वाटिका अथवा सोकेज पिट बनाने से क्या लाभ होगा ?

९—घरों के फिजूल पानी के बहाने से जो गंदगी उत्पन्न होती है, उसको दूर करने का क्या उपाय है ?

१०—घरों में रोशनदान और धुआँ निकलने का मार्ग क्यों जरूरी है ? उससे क्या लाभ होगा ?

११—गाँव में कच्ची सड़कों की जो दशा है, उसको लिखिए और बतलाइये कि इन सड़कों का सुधार कैसे हो सकता है ?

१२—गाँव में चिकित्सा का कैसा प्रबन्ध है सक्षेप में बतलाइये और चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध किस प्रकार हो सकता है इस पर अपना मत दीजिए ?

---

## अठारहवाँ अध्याय

### ग्रामीण शिक्षा ( Rural Education )

भारत में शिक्षा का अभाव है, फिर गाँवों का तो पूछना ही क्या ? वहाँ तो निरक्षरता का साम्राज्य है। बड़े-बड़े नगरों तथा कस्बों में शिक्षा की कुछ सुविधाएँ हैं, परन्तु गाँवों में बहुत कम पाठशालाएँ देखने को मिलेंगी। इसका फल यह हुआ कि गाँव के लड़के निरक्षर रह कर जीवन व्यतीत करते हैं। समस्त स्वतन्त्र भारत में दो लाख के लगभग प्राइमरी पाठशालाएँ हैं। इन पाठशालाओं में बहुत अधिक संख्या शहरी पाठशालाओं की है। अतएव समस्त स्वतन्त्र भारत के ग्रामों में एक लाख से अधिक पाठशालाएँ नहीं हैं। अब प्रादेशिक सरकारें ग्राम-शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दे रही हैं और हजारों पाठशालाएँ स्थापित की जा रही हैं।

गाँवों में पाठशालाओं की बहुत कमी तो है ही परन्तु जो भी पाठशालाएँ गाँव में हैं वहाँ की शिक्षा बिल्कुल शहरातू है। जो शिक्षाक्रम शहरों में है, वही गाँवों में चलाया जा रहा है। शहर के शिक्षक ही गाँवों में भेजे जाते हैं। वे ही पाठ्य-पुस्तकें, वे ही विषय, वही पद्धति अर्थात् सब कुछ वही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गाँव वालों की कोई विशेष आवश्यकताएँ ही नहीं हैं, और न गाँवों में कोई ऐसी बात है, जिसको अपनाया जावे। इस शहरातू शिक्षा का फल यह हुआ कि ग्रामीण सभ्यता क्रमशः घृणा की वस्तु बनती जाती है। शहर के शिक्षित व्यक्ति तो गाँव की सभ्यता, गाँव की वेश-भूषा और गाँव के रहन-सहन को घृणा की दृष्टि से देखते हो हैं, गाँव के पढ़े-लिखे लड़के भी गाँव की प्रत्येक वस्तु से घृणा करने लगते हैं। यहाँ तक कि “गँवार” शब्द असभ्य, मूर्ख तथा अशिक्षित का पर्यायवाची बन गया है। इन सबका फल यह हुआ कि गाँव का शिक्षित लड़का और उसका अनुसरण करने के कारण गाँव के समस्त लड़के सभ्यता, वेशभूषा तथा रहन-सहन के विषय में शहरों को आदर्श मानते और उसकी नकल करते हैं। आज गाँव के लड़कों को आकांक्षा यह नहीं है कि गाँव में रहे और उसका उन्नति करें, वरन् उनकी आकांक्षा शहरी जीवन व्यतीत करने, अथवा कम से कम उसकी नकल करने की होती है। यह सब किस कारण हो रहा



है ? प्राइमरी पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक में ग्रामीण जीवन, गाँवों की आवश्यकताओं, और ग्रामीण समस्याओं की पूर्ण उपेक्षा की गई है। जो देश ग्राम-प्रधान है, वहाँ ग्रामों की इस प्रकार उपेक्षा हो, क्या यह लज्जा की बात नहीं है ?

अतएव केवल इसी बात की आवश्यकता नहीं है कि गाँवों में अधिक स्कूल की स्थापना की जावे, वरन् इस बात की भी आवश्यकता है कि ग्राम पाठशालाओं का पाठ्य-क्रम गाँवों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जावे। केवल ग्राम पाठशालाओं के पाठ्यक्रम को ही गाँव की परिस्थिति के अनुसार बनाने से काम नहीं चलेगा। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में भी ग्राम सम्बन्धी विषयों का समावेश होना चाहिये, जिससे कि शिक्षित व्यक्तियों में ग्रामों के प्रति घृणा की भावना न रहे और वे उनकी ओर आकर्षित हों। उच्च शिक्षा में ग्राम सम्बन्धी विषय रखने से एक लाभ यह भी होगा कि शिक्षित व्यक्ति ग्रामीण समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेगा, और उसके कारण उनकी सहानुभूति गाँवों के प्रति बढ़ जावेगी।

### ग्राम्य पाठशाला का पाठ्यक्रम

साधारण लिखाई-पढ़ाई तथा अन्य विषयों के अतिरिक्त, ग्राम्य पाठशालाओं में कृषि सम्बन्धी आवश्यक बातों, सहकारी समितियों के सम्बन्ध में साधारण जानकारी, शारीरिक तथा गाँव की सफाई, तथा अन्य आवश्यक बातों की जानकारी भी कराई जानी चाहिये। पाठशाला का एक छोटा सा फार्म होना चाहिये जिस पर अच्छे ढंग से खेती पाठशाला के लड़के स्वयं करे, और उन पर नई बातों का अनुभव प्राप्त करे जिनको कृषि विभाग खेती के सुधार के लिये आवश्यक समझता है। पाठशाला की सफाई के लिए एक आदर्श होना चाहिये। प्रतिदिन विद्यार्थियों की शारीरिक स्वच्छता का निरीक्षण होना चाहिये। साफ कैसे रहना चाहिये, इस सम्बन्ध में उन्हें सब बातें जाननी चाहिये। पाठशाला में वे सब बातें बतानी चाहिये जो गाँव की सफाई के लिये आवश्यक समझी जावें। ग्राम पाठशालाओं में किसी कौशल की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिये।

प्रत्येक पाठशाला में एक वालचर ट्रूप ( Scout troop ) होना

चाहिए जिससे बालक अच्छी आदतें सीखे और उनमें सेवा की भावना जागृत हो। किन्तु बालचर द्रूप केवल दिखाने के लिए न हो। पाठशाला के विद्यार्थियों को वे खेल, जिनको कि गाँव में प्रचार करना अभीष्ट है, नियम के साथ सिखाये जावें।

यदि महात्मा गांधी की वर्धा योजना के अनुसार पाठशालाओं में उद्योग-धन्धों के आधार पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जावे तो ग्राम पाठशालाओं को भी उस योजना में सम्मिलित करना चाहिये। यदि वर्धा योजना स्वीकृत न भी हो तो भी ग्राम पाठशाला में ग्रामीण उद्योग-धन्धों की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। ग्राम पाठशाला की पढाई का उद्देश्य गाँव के लड़के को केवल साक्षर बना देना ही नहीं होना चाहिए, वरन् उसका उद्देश्य उनको साक्षर बनाने के अतिरिक्त अच्छा ग्रामीण और सफल कृषक बनाना होना चाहिए।

### स्त्री शिक्षा

किन्तु एक बात ध्यान में रखने की है। बिना लड़कियों को शिक्षित बनाये, गाँवों में भी शिक्षा का विस्तार नहीं हो सकता और न गाँवों का सुधार ही हो सकता है। आजकल ग्राम-सुधार की बहुत चर्चा है; परन्तु ग्राम-सुधार कार्य में लगे हुए लोग यह भूल जाते हैं कि जो परिवर्तन वे गाँव तथा गाँव वालों के घरों में लाना चाहते हैं, वे बिना गाँव की स्त्रियों की इच्छा के लाये ही नहीं जा सकते। जब तक गाँव की स्त्रियाँ उन परिवर्तनों को नहीं अपनाती, तब तक उनकी उपयोगिता को समझते हुए भी गाँव के पुरुष उनको स्वीकार ही नहीं कर सकते। इस कारण गाँव की लड़कियों की शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है।

गाँव में लड़कों की ही शिक्षा की ओर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो लड़कियों की शिक्षा के विषय में पूछना ही क्या है? उसकी तो नितान्त अवहेलना की गई है। अब समय आ गया है कि लड़कियों की शिक्षा का महत्व समझा जावे और उस पर ध्यान दिया जावे।

लड़कियों की शिक्षा किस प्रकार की हो, इस पर जहाँ तक गाँवों का सम्बन्ध है, दो मत नहीं हो सकते। लड़कियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त उन्हें कुशल गृहिणी बनाने के लिये जिन बातों की आवश्यकता है, वे सभी

वातें उन्हें सिखलाई जानी चाहिये । खाना बनाना, भिन्न-भिन्न खाद्य पदार्थों के गुण तथा उनका मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा इसका ज्ञान, सिलाई, घर के अन्य सब कार्य, हिसाब रखना, साधारण बीमारियों तथा छूत के रोगों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी चूहों, मच्छरों तथा मक्खियों से क्या हानि पहुँचती है, इसका ज्ञान, कुछ उपयोगी और सदैव काम में आने वाली औपधियों का उपयोग, बच्चों का लालन-पालन तथा घरों को सुन्दर बनाना, ये कुछ ऐसे विषय हैं, जिन्हें बड़ी लड़कियों को सिखाने की आवश्यकता है ।

परन्तु भारत में केवल लड़के और लड़कियों की शिक्षा के प्रबन्ध करने से गाँवों का शीघ्र ही सुधार न हो सकेगा । यदि हम चाहते हैं कि गाँवों में नवीन जीवन का प्रादुर्भाव शीघ्र ही हो तो हमें प्रौढ़ों ( adults ) को भी शिक्षित बनाने का प्रबन्ध करना होगा । आजकल यदि गाँवों में कोई लड़का कुछ पढ़ता भी है तो प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त, वह सब भूल जाता है और पहले की ही भाँति निरक्षर बन जाता है । माता और पिता अशिक्षित होते हैं, इस कारण वे लड़के और लड़कियों के लिये ऐसा कुछ प्रबन्ध नहीं करते कि वे पढ़ा-लिखा न भूल जावे । शिक्षित माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ पढ़ना-लिखना भूल ही नहीं सकते । प्रौढ़ों की शिक्षा ग्राम सुधार कार्य को शीघ्र सफल बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । प्रौढ़ की शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाओं की योजना करनी होगी । स्त्री और पुरुषों की शिक्षा का अलग अलग प्रबन्ध करना होगा । यह कार्य गैरसरकारी कार्यकर्त्ताओं को, जिनमें सेवा भाव हो, सौमना चाहिये । गाँव की पंचायत से उन्हें इस कार्य में सहायता मिल सकेगी । सहकारी शिक्षा समितियाँ ( co-operative education societies ) स्थापित करके यह कार्य और भी अच्छी तरह से चलाया जा सकता है, जैसा कि पंजाब में हुआ है । स्त्री और पुरुषों के लिये अलग-अलग समितियाँ स्थापित होनी चाहिए । गाँव के सेवा भाव वाले और पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषों को इस कार्य में अपना थोड़ा सा समय देने पर राजा किया जावे, तब ही काम में सफलता मिल सकती है । शिक्षा के सम्बन्ध में जो भी रात्रि पाठशाला का काम हो = समिति, चन्दे के रूप में इकट्ठा करे, चन्दा पैदावार के रूप में भी जमा

किया जा सकता है। यदि सरकार उस प्रकार की समितियों को सहायता दे, तो उनके द्वारा केवल प्रौढ़ों (adults) को ही शिक्षा का प्रबन्ध नहीं वरन् गाँव के लड़के-लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सकता है। किताबी शिक्षा के साथ-साथ, गाँव वालों में अखबार तथा अन्य पुस्तकों को पढ़ने की आदत भी डालनी चाहिये। उसके लिए समिति पुस्तकालय और वाचनालय खोल सकती है।

ग्राम्य पाठशाला में शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त गाँव का लड़का यदि मिडिल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने चला जाता है, तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा यह भय रहता है कि कहीं पढ़ना लिखना भूल न जावे। इस भय को दूर करने, गाँव के लड़कों की साक्षरता को स्थायी बनाने और उनके ज्ञान की वृद्धि करने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना उतनी ही आवश्यक है जितनी पाठशालाओं की स्थापित करने की। शिक्षा-प्रचार के साथ साथ ग्राम्य पुस्तकालयों की नितान्त आवश्यकता है। पुस्तकालय घूमने-फिरने वाले भी हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक यह होगा कि गाँवों के लिए साप्ताहिक समाचार-पत्र निकाले जावे और ग्राम्य पुस्तकालयों के लिए ग्रामोपयोगी सरल पुस्तकें लिखाई जावे। कुछ पुस्तकें तो स्थायी रूप से प्रत्येक गाँव में रहे और अन्य पुस्तकों के पच्चीस-पच्चीस पुस्तकों के सेट बनवा दिये जावे, जो एक गाँव से दूसरे गाँव में घूमते रहे।

रेडियों के द्वारा भी गाँव में ससार तथा देश की हलचलों के विषय में जानकारी कराई जा सकती है और मनोरंजन के साथ-साथ उनका ज्ञान-वर्धन भी किया जा सकता है। यदि देखा जावे तो रेडियो का प्रचार कार्य गाँव में बहुत उपयोगी हो सकता है। जहाँ जलविद्युत् है, वहाँ रेडियो सेट अवश्य लगवाना चाहिये। रेडियो प्रोग्राम भी गाँव के लिए उपयोगी हो, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये।

### ग्राम्य शिक्षक

जहाँ ग्राम शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वहाँ वह एक अत्यन्त कठिन समस्या भी है। गाँव में शिक्षा प्रचार के लिए देश को ऐसे ग्राम शिक्षकों की आवश्यकता होगी कि जो गाँवों से सहानुभूति रखते हों और गाँव में जाकर सेवा-कार्य करने को तैयार हों। लड़कियों की शिक्षा की समस्या अभी हल

हो सकती है जब ग्राम शिक्षकों की पत्नियों को ग्राम-ग्रन्थापिका बनने के लिए उत्साहित किया जावे और उनको आवश्यक शिक्षा दी जावे। इस कार्य के लिए बहुत धन और शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। परन्तु बिना इस कार्य को किये निस्तार भी नहीं है।

ग्राम्य शिक्षक के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें एक बात न भूलनी चाहिये। गाँवों की पाठशाला के शिक्षक में नीचे लिखे गुण हों :—

(१) गाँवों से जिन्हें प्रेम हो जो गाँवों से घृणा न करते हों वरन् गाँवों की सेवा करने में जिन्हें आनन्द मिलता हो। शहरी वातावरण में पले हुए व्यापक गाँवों से घृणा करते हैं परन्तु नौकरी न मिलने पर गाँवों की पाठशालाओं में पढ़ाने लगते हैं। ऐसे व्यापकों से गाँव का हित न होगा।

(२) ग्राम्य व्यापक को फैशन से दूर सादा होना आवश्यक है नहीं तो वह ग्रामवासियों में भी फैशन का प्रचार करेगा और अपनी बुरी आदतों को फैलावेगा।

(३) ग्राम्य व्यापक ऐसा होना चाहिये जो शारीरिक परिश्रम के महत्व को समझता हो, स्वयं परिश्रम करे और विद्यार्थियों में शारीरिक परिश्रम के प्रति आदर उत्पन्न करे।

सक्षेप में हम कह सकते हैं कि ग्राम्य शिक्षक एक सेवक हो। वह सदा परिश्रमी, और गाँव के जीवन को पसन्द करने वाला हो। नहीं तो उसके सम्पर्क में आकर गाँव के बालकों में ग्राम के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होगी और शारीरिक परिश्रम के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जावेगी।

शिक्षा-योजना की सफलता के लिये यह भी जरूरी है कि हर एक गाँव में सरकार कानून बनाकर प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दे। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य तो होना ही चाहिये, वह निःशुल्क (बिना फीस) भी होनी चाहिए, तभी भारत में अशिक्षा का रोग मिट सकता है। यह देश के लिए अत्यन्त लज्जा की बात है कि यहाँ की केवल १२ प्रतिशत जनसंख्या लिख पढ़ सकती है। सच तो यह है कि जब तक देश में अशिक्षा का रोग दूर नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती।

हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार, इस प्रकार का नियम बनाने जा रही है कि जो युवक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे,

वे गाँवों में शिक्षक का कार्य करें। उससे ग्राम शिक्षा की समस्या को हल करने में सुविधा होगी।

सारे देश में कोई भी सुधार-कार्य पूरी तरह से सफल नहीं होता, इसका मुख्य कारण जनता का अशिक्षित होना ही है। अतएव गाँवों की उन्नति के लिये भी शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है।

### सार्जेन्ट रिपोर्ट

युद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा की उन्नति किस प्रकार की जावे, इस सम्बन्ध में जाँच करने के लिये भारत सरकार ने एक बोर्ड स्थापित किया था, जिसके मन्त्री श्री सार्जेन्ट महोदय थे, जो भारत सरकार के शिक्षा विषयक मामलों के सलाहकार थे। बोर्ड ने युद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा किस प्रकार फैले, इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ग्रामों में शिक्षा (प्रारम्भिक) किस प्रकार हो, इस सम्बन्ध में नीचे लिखा मिफारिश की गई है।

( १ ) हमारी राय में भारत में अनिवार्य और निःशुल्क ( बिना फीस ) प्रारम्भिक शिक्षा ६ से १४ वर्षों तक के लड़के-लड़कियों के लिए सर्वत्र शीघ्र ही प्रचलित कर देना चाहिये। ऐसा करने के लिये लगभग १८ लाख अध्यापकों की जरूरत होगी और २०० करोड़ रुपया व्यय होगा। इनलिए यह योजना लगभग ४० वर्षों में पूरी होगी।

( २ ) शिक्षा किसी दस्तकार के द्वारा दी जावे, जिस वेतन शिक्षा-पद्धति कहते हैं।

( ३ ) इस योजना को सफल बनाने के लिए अध्यापकों की आज्ञा जो गिराई हुई दशा है, उसे दूर करना होगा। उन्हें उचित वेतन देना होगा और योग्य व्यक्तियों को अध्यापक बनने के लिए उत्साहित करना होगा।

यदि यह योजना काम में लगी गई, तो आशा है, गाँवों में आज जो अशिक्षा का अव्यवहार है, वह दूर हो सके और गाँव वाले शिक्षित हो सकें।

निर्माण महात्मा गाँधी के नेतृत्व में तालीमी सच ने किया था, और वह वर्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है। तालीमी सच ने जो बेसिक (Basic) शिक्षा पद्धति निकाली है, उसका उद्देश्य तो यह है कि बालक किसी धन्धे के आधार पर और उसके द्वारा सभी आवश्यक विषयों की शिक्षा-प्राप्त कर सके, जिससे उसका पूर्ण विकास हो सके। महात्मा गाँधी का तो यह मत था कि भारत जैसे निर्धन देश में करोड़ों व्यक्तियों का शिक्षा-व्यय इतना अधिक होगा कि राष्ट्रीय सरकार भी उतना व्यय करने में असमर्थ होगी। अस्तु, शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि उसका खर्चा भी निकल सके। इसलिये उन्होंने धन्धे के द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि विद्यार्थी जो वस्तुएँ पढ़ते समय तैयार करेंगे, उनको बेचकर बहुत कुछ शिक्षा का व्यय पूरा किया जा सकता है। अभी तक महात्मा गाँधी का इस योजना को, देश के शिक्षा-शास्त्रियों ने स्वीकार नहीं किया है। वर्वा योजना में केवल ७ वर्ष से १४ वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है।

पढ़ना-लिखना सीखना जरूरी है ही, परन्तु हमको गाँवों में उस प्रकार की शिक्षा का प्रचार करना है कि जो गाँव वालों की मनोवृत्ति को बदल सके। आज गाँवों में जिस प्रकार की सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ फैली हैं, वे दूर हो सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि उनका सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण उदार बने, उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की भावना पैदा हो, उनमें देश के प्रति प्रेम पैदा हो और श्रम के महत्व (Dignity of Labour) को समझ सके।

अशिक्षा के कारण जो आज बहुत से कुसस्कार गाँव वालों में पाये जाते हैं, उनमें आपस में जो द्वेष और लड़ाई झगडा देखने को मिलता है और आपस के सहयोग की भावना का आज जो नितान्त अभाव है, हम उसका अन्त करना चाहते हैं और गाँववालों के जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाना चाहते हैं। हमारी शिक्षा का ध्येय होगा, गाँववालों को एक अच्छा नागरिक (Citizen) बनाना और जीविकोपार्जन के लिये उन्हें पूर्ण तरह से योग्य और उपयुक्त बनाना। दूसरे शब्दों में उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि वे अपने शिक्षाकाल में कोई न कोई ऐसा उपयोगी कार्य

सीखे जिसके द्वारा वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा वही हो सकती है, जो एक लक्ष्य को सामने रख कर दी जावे।

### प्रौढ शिक्षा ( Adult Education )

केवल लड़के-लड़कियों को शिक्षित बना देने से ही हमारे गाँवों की समस्या हल नहीं होगी। हमें प्रौढ़ों को भी शिक्षित करना होगा। जब तक घर में बड़े पुरुष और स्त्रियाँ भी शिक्षित नहीं होंगी ग्राम-सुधार का कार्य सफल नहीं हो सकता। जब तक हम गाँव के प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों को शिक्षित नहीं बनाते, तब तक गाँवों से गंदगी, रोगों तथा रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को दूर नहीं किया जा सकता, और न गाँवों में खेती में सुधार और उद्योग-धन्धों की उन्नति ही सम्भव है। प्रौढ़ों को शिक्षित करके ही हम उनके दृष्टि-कोण को बदल सकते हैं, उनमें स्वाभिमान और आत्म-विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं और गाँव से कलह और द्वेष को दूर कर सकते हैं। सच तो यह है कि ग्राम-वासियों की कार्य-क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमें विशेष प्रयत्न करना होगा। रात्रि पाठशालाओं का आयोजन करना होगा, मैजिक लैन्टर्न, फिल्मों तथा रेडियो, तथा हेलमेल दिवस मनाकर उन्हें शिक्षित बनाना होगा। प्रौढ़ों को केवल अच्छे ज्ञान कराने से ही काम नहीं चलेगा वरन् उनको साक्षर बनाने के अतिरिक्त आधुनिक समस्याओं की भरपूर जानकारी करानी होगी। उनको अवविश्वास, रूढ़िवादिता और भाग्यवाद के अधिकार से निकाल कर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना होगा।

आज भारत स्वतन्त्र हो गया है और हमने जनतन्त्र को स्वीकार किया है। प्रत्येक बालिग स्त्री-पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया है। ऐसी दशा में यदि हमने प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा प्रौढ़ ग्रामीणों को शिक्षित नहीं बनाया तो वे अपना मत ( वोट ) ऐसे व्यक्तियों को न देकर जो याग्य देश-भक्त और ईमानदार हो ऐसे चतुर व्यक्तियों को दे सकते हैं जो योग्य, सच्चे और ईमानदार न हों। ऐसी दशा में देश का बहुत अहित होगा। अतएव देश के हित को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है।



## अभ्यास के प्रश्न

१—गाँव वाले जो यह कहते सुने जाते हैं कि “लड़कों को पढ़ाने से वे खेती के काम के नहीं रहते” इसका कारण क्या है ?

२—शहरो जैसी शिक्षा गाँवों के लड़कों को देने का क्या परिणाम हुआ है ?

३—गाँव की पाठशालाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिये ?

४—बालचर किसे कहते हैं ? बालचर द्रूप की व्यवस्था गाँव की पाठशाला में करने से क्या लाभ होगा ?

५—गाँव की पाठशालाओं में, खेती और गाँव के उद्योग-धन्वों के सम्बन्ध में क्यों शिक्षा देनी चाहिये ।

६—गाँव की उन्नति के लिए लड़कियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है ?

७—गाँव की लड़कियों की शिक्षा किम प्रकार की होनी चाहिये ?

८—गाँव वालों को शिक्षित बनाने के लिए, ग्राम वाचनालय और पुस्तकालय क्यों जरूरी हैं ? गाँवों में किस तरह के पुस्तकालय खोले जाने चाहिए ?

९—गाँव की पाठशाला किस प्रकार गाँव का सुधार करने में सहायक हो सकती है ?

१०—गाँव के लिये कैसे शिक्षक चाहिए ?

११—प्रौढ़ शिक्षा से तुम क्या समझते हो ?

१२—तालीमी सघ क्या कार्य करता है ?

## उन्नीसवाँ अध्याय

### मनोरंजन के साधन

मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, उसकी कार्य-क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए मनोरंजन अत्यन्त आवश्यक है। दिन भर काम करने के उपरान्त मनुष्य का शरीर तथा मस्तिष्क थक जाता है। उस समय थोड़ा सा मनोरंजन उसमें नवीन स्फूर्ति

उत्पन्न कर देता है। यदि मनुष्य सर्वदा कार्य करता रहे, विश्राम करने के अतिरिक्त उसके पास मनोरंजन का कोई साधन न हो, तो उसका जीवन नीरस हो जावेगा और उसकी कार्य-क्षमता घट जावेगी। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य प्रतिदिन एक ही प्रकार का जीवन व्यतीत करते करते ऊब जाता है। उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति मस्तिष्क का ही कार्य करता है और अधिकतर बैठा ही रहता है तो उसको कभी-कभी पैदल चलने की इच्छा होती है और खेल तथा संगीत से उसे सुख मिलता है। जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन हर एक को सुखद प्रतीत होता है। इसी कारण मनुष्य समाज ने भिन्न-भिन्न प्रकार के मनोरंजन ढूँढ निकाले हैं, जिनसे दैनिक कार्य की नीरसता नष्ट होती है और जीवन अधिक सुखमय और सरस बनता है। मनोरंजन की आवश्यकता बृद्ध, प्रौढ़, और बालकों, सभी को होती है। हाँ, बालकों को खेलकूद को अधिक रुचि होता है और वह स्वाभाविक भी है।

आज भारत के ग्रामों की ऐसी शोचनीय दशा हो रही है कि गाँव वालों को मनोरंजन के साधन भा उपलब्ध नहीं हैं। गाँववालों का जीवन अत्यन्त नीरस बना हुआ है। यही कारण है कि जो युवक थोड़ा सी भी शिक्षा पा जाता है, वह गाँव में रहना नहीं चाहता। गाँव में खेल तथा मनोरंजन के साधनों का इतना अधिक अभाव है कि यदि दो बैल या कुत्ते आपस में लड़ते हैं, तो उस लड़ाई को देखने के लिये ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है। गाँव बहुत ही सुनसान और निर्जन स्थान होता है। यही कारण है कि किसान उदास मनोवृत्ति वाला होता है और उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता, क्योंकि उसको कोई बात देखने-सुनने तथा उस पर विचार करने के लिये नहीं मिलती।

ग्राम-जनों की बुद्धि का विकास तथा उनकी निराश मनोवृत्ति का नाश तभी हो सकता है जब कि वे कभी-कभी खेल खेलें, तमाशे, प्रदर्शनियाँ तथा मेले देखें और उन्हें सार में क्या हो रहा है इसके समाचार प्रतिदिन मिलते रहे। यही नहीं सायंकाल को जब वे काम से थककर घर पर आवे तो उनके लिये थोड़े से मनोरंजन की भी आवश्यकता है जिससे उनका मस्तिष्क और शरीर ताजा हो जावे। प्रौढ़ों के अतिरिक्त गाँव के लड़कों

के लिये तो खेल की और भी अधिक आवश्यकता है जिससे उनमें अनुशासन (Discipline), साहस, फुर्ती तथा सामूहिक भावना का उदय हो।

### गाँवों के खेल

आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक गाँव में खेल के लिये एक मैदान तैयार किया जावे और ऐसे खेलों का प्रचार किया जावे जो कम खर्चीले हों, जिनमें अधिक लोग भाग ले सकें और जिनके द्वारा खेलने वालों में सामूहिक सगठन तथा अनुशासन का भाव उदय हो। इस दृष्टि से फुटबाल और कबड्डी उपयोगी है। अन्य भारतीय खेल जो भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित हैं उनका भी गाँवों में प्रचार किया जावे।

### भारतीय खेल

हमारे देश में भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बहुत तरह के खेल प्रचलित हैं, जैसे नमक-चोर, रामडडा इत्यादि। इन सब खेलों को इकट्ठा करके उनके नियम इत्यादि बनाकर पुस्तकें प्रकाशित कराई जावे और उन उन खेलों का गाँवों में प्रचार किया जावे। साथ ही नये खेल प्रचलित किये जावे, जैसे वालीबाल बासकेटबाल इत्यादि।

जरूरत इस बात की है कि एक 'ग्रामीण खेल बोर्ड' स्थापित किया जावे जिस प्रकार से अखिल भारतीय फुटबाल, क्रिकेट तथा हाकी और टेनिस के लिये बोर्ड स्थापित हैं। 'ग्रामीण खेल बोर्ड' भारतीय खेलों का प्रचार गाँवों में करने और उनकी देखभाल इत्यादि का काम करे। खेल ऐसे हों जो अधिक खर्चीले न हों, जिन्हें अधिक व्यक्ति खेल सकें और जिनसे सगठन, सामूहिक भावना, शारीरिक विकास, स्फूर्ति, साहस, तथा अनुशासन का उदय हो।

### गाँव का स्काउट द्रुप

गाँवों में बालचर आन्दोलन का प्रवेश अवश्य होना चाहिये। इससे गाँवों को बहुत लाभ होगा, गाँव के युवकों में सगठन उत्पन्न होगा, मिलजुल कर कार्य करने की आदत पड़ेगी। गाँव में जो बहुत सा बुराईयाँ हैं उनके दूर करने में इन शिक्षित बालचरों से बहुत सहायता मिल सकती है। गाँव में भ्रातृभाव भी इस आन्दोलन के द्वारा उत्पन्न हो सकता है।

गाँव की सफाई, सड़कों को ठीक रखना, फसल के कीड़ों को नष्ट करना, तथा गाँव में मनोरंजन का साधन उपलब्ध करने में बालचर बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। गाँव को तो लाभ होगा ही, बालचरों को इसी आन्दोलन के द्वारा स्वयं एक मनोरंजन का साधन प्राप्त हो जावेगा और उनका शारीरिक, मानसिक तथा चरित्र विषयक विकास होगा।

### भजन तथा भजन मंडलियाँ

गाँव के लोग भजन बहुत पसन्द करते हैं। यदि प्रत्येक प्रदेश में ऐसे भजनों का संग्रह किया जावे जो ग्रामीण जीवन का दिग्दर्शन कराते हैं, अथवा जिनमें गाँवों की प्रचलित कुरीतियों का विवरण है और जो सरल भाषा में लिखे गए हों, तो बहुत अच्छा हो। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे भजन योग्य व्यक्तियों से लिखवाये जावे और उनको प्रकाशित कराकर उनका गाँवों में प्रचार कराया जावे। गाँव की पाठशाला के विद्यार्थियों, बालचरों, स्त्रियों और प्रौढ़ों की भजन-मंडलियाँ बनाई जावें जो उन्हीं भजनों को उत्सव, त्योहार तथा अन्य अधिवेशनों के समय पर गाया करें। भजनों के प्रचार से दो लाभ होंगे, एक तो प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध वातावरण बनेगा दूसरे मनोरंजन भी होगा। हमारे गाँवों में अत्यन्त प्राचीन कला पूर्ण नृत्य होते हैं उन्हें भी फिर से जीवित करना चाहिये।

### नाटक तथा प्रहसन

ग्राम सुधार का कार्य करने वाले गाँव की पाठशाला के अध्यापक की सहायता से प्रत्येक गाँव में यदि मनोरंजन तथा खेलकूद का प्रबन्ध करने वाली सभा बनावे, जिनमें गाँव के प्रमुख लोग भाग लें तो इस दिशा में बहुत कुछ हो सकता है। योग्य लेखकों से प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में गाँव की प्रति दिन की समस्याओं से सम्बन्ध रखने वाले नाटक और प्रहसन लिखवाये जावे और गाँव के युवकों की सहायता से होंली, दिवाली, राम-लीला, ईद, बड़ा दिन इत्यादि त्योहारों तथा अन्य उत्सवों पर वर्ष भर में तीन चार बार चौदनी रात्रि में, स्कूल अथवा किमी चौमल पर दिखलाये जावे तो गाँवों में सुरुचिपूर्ण मनोरंजन का एक अच्छा साधन उपलब्ध हो सकता है।

## रेडियो

रेडियो, ससार को विज्ञान की अत्यन्त उपयोगी देन है। मनोरजन, और शिक्षा-प्रचार के लिये रेडियो से अच्छा और कोई दूसरा साधन नहीं है। यदि प्रत्येक गाँव में अथवा सम्पत्तियों दो तीन गाँवों में एक रेडियो सेट लगा दिया जावे और प्रत्येक प्रदेश में प्रदेशीय ब्राडकास्टिंग स्टेशन स्थापित कर दिये जावे तो ग्रामीणों के लिये प्रत्येक दिन प्रोग्राम रक्खा जा सकता है। सायकल गाँव के लोग इकट्ठे होकर बीमारियों को दूर करने, पशुओं के पालन, गल्ले का भाव, खेती के नवीन तरीकों और गाँव की समस्याओं पर विशेषज्ञों द्वारा बताई हुई बातों से अपना मन बहला सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि रेडियो का ठीक-ठीक उपयोग किया जावे तो अशिक्षित ग्राम्य को ससार में क्या हो रहा है, उनके देश में क्या हो रहा है, गाँव की समस्याओं को कैसे हल किया जा सकेगा इत्यादि विषयों का पूरा ज्ञान कराया जा सकता है। प्रादेशिक सरकार रेडियो सेट दे और गाँव के लोग उसके रखने का व्यय सहन करें तो यह योजना सफल हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी इसमें सहायता दे सकते हैं।

## मैजिक लैन्टर्न तथा सिनेमा-शो

प्रत्येक सरकारी विभाग, जिसका सम्बन्ध गाँव से है अपने विभाग से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं के चित्र बनवाये और लैन्टर्न के द्वारा उनका समय-समय पर प्रदर्शन कराया जावे। उदाहरण के लिये स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग तथा पशु-चिकित्सा विभाग अपने-अपने विषय के चित्र तैयार करावे और उनका प्रदर्शन हो। मेलों और उत्सवों के अवसर पर इनका प्रदर्शन विशेष रूप से किया जावे।

ऐसी सिनेमा फिल्म तैयार करना इस समय कठिन दिखलाई देता है जो गाँव वालों के लिये उपयोगी हो, क्योंकि बोलती हुई फिल्म बहुत खर्चीली होती है। साथ ही ग्राम्य जीवन को भली प्रकार चित्रित कर सकने वाले लेखक और उसका प्रदर्शन करने वाले एक्टर्स भी कम हैं। परन्तु प्रत्येक प्रदेश में वहाँ की बोलचाल की भाषा में ग्राम्य उपयोगी फिल्म बनवाने

का प्रदेशीय सरकार को अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। फिल्म के साथ अच्छे हल, बैल, बीज, बीमारियों, इत्यादि के सम्बन्ध के चित्र भी रहे। घूमने वाला सिनेमा, इन फिल्मों को प्रदेश के गाँवों में दिखावे और उसके साथ ही प्रचार कार्य भी करे तो गाँवों में मनोरंजन का एक अत्यन्त उत्तम साधन उपलब्ध हो सकता है। परन्तु फिल्म तैयार करवाने में बड़ी सावधानी करनी होगी। नहीं तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। यह कार्य व्यावसायिक कम्पनियों पर न छोड़ कर सरकार को स्वयं करना चाहिये।

इस प्रकार जब गाँवों में सुरुचिपूर्ण मनोरंजन के साधन उपलब्ध किये जावेंगे तथा खेल का प्रबन्ध किया जावेगा तभी ग्रामीण जनता का जीवन सरस बन सकेगा और गाँवों में आकर्षण उत्पन्न हो सकेगा।

### ग्राम-सेवादल

खेलों के सिवाय लड़कों और युवकों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, उनमें सेवा की भावना उत्पन्न करने के लिए ग्राम-सेवादल की बड़ी आवश्यकता है। हर एक गाँव में एक ग्राम-सेवादल बनाया जावे। ग्राम-सेवादल में गाँव के बड़े लड़के तथा युवक भर्ती किए जावे। उन्हें सेवा का महत्व समझाया जावे जिससे गाँव का हर एक युवक ग्राम सेवा को करने लिए गौरव समझे। ग्राम-सेवादल नीचे लिखे काम करे:—होली, दिवाली, दशहरा इत्यादि त्योहारों पर गाँव की सफाई करने में सहायता देना, टिड्डी तथा अन्य फसलों के शत्रुओं (काँड़ों) को मारने में गाँव वालों की सहायता करना, विशेष अवसरों पर नाटक, प्रहसन, तथा अन्य खेल-तमाशों का आयोजन करके गाँव-गाँव में लोगों का मनोरंजन करना, गाँव के गल्लों को ठीक करना और गाँव में फलों के वृक्ष लगाना। गाँव में जहाँ से वृक्ष तो हर एक आदमी को लगाना चाहिये। इससे दो लाभ होंगे। एक तो गाँव की सुन्दरता बढ़ेगी दूसरे फल खाने को मिलेंगे। गाँव के गल्ले ठीक करने और मन के गहरी को भरने में भी ग्राम-सेवादल गाँव वालों की सहायता कर सकता है।

## घरों को अधिक आकर्षक बनाना

जिस प्रकार हमारे गाँवों में कोई आकर्षण नहीं है, उसी तरह गाँवों के रहने वालों के घरों में भी कोई आकर्षण नहीं रह गया है। जब कभी थका हुआ किसान खेतों पर से आता है तो घर में उसके लिए ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता कि उसका मन बहले। खाली समय में वह चिलम लेकर किसी चौपाल पर गप्प उड़ाता है। एक दूमरे की बुराई करना, दूमरों के घरों को आलोचना करना, यही ग्रामीणों का काम रह गया है। इसका फल यह होता है कि एक दूमरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और जलन के भाव उत्पन्न होते हैं। पटवारी, मुखिया तथा अन्य व्यक्ति जिनका मुकदमेबाजी तथा लडाई-मुगडे से लाभ होता है, इसका लाभ उठाते हैं। यह तभी बन्द हो सकता है जब घरों को आकर्षक बनाया जावे।

घरों को आकर्षक बनाने के लिए वाटिका आन्दोलन अत्यन्त आवश्यक है। फूलों की ब्यारियों में उत्पन्न होने वाले फूल और तरकारी उसके लिए एक आकर्षण की वस्तु होगी। फूलों से घरों को आकर्षक बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ उसके लिए हमें पुष्पवाटिका आन्दोलन चलाना होगा वहाँ गृह-स्वामिनी को भी घरों को अधिक सुन्दर बनाने की शिक्षा देनी होगी। अभी तक ग्राम-सुधार कार्य-कर्त्ताओं ने गृह स्वामिनी की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। जब तक गाँवों की स्त्रियाँ ग्रामीण जीवन को मधुर और घरों को अधिक आकर्षक बनाने का काम अपने हाथ में नहीं ले लेतीं, तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी।

यह तो स्वास्थ्य और सफाई के परिच्छेद में ही लिखा जा चुका है कि गृह-वाटिका से दो लाभ होंगे, एक तो उससे फूल और तरकारी मिलेगी, दूसरे, घर के काम में लाया हुआ पानी जो नाली न होने के कारण सड़ता रहता है और गदगी उत्पन्न करता है, उसका उपयोग हो सकेगा। घर के काम में आने वाले पानी की समस्या को तो पानी सोखने वाले गड्ढों के द्वारा भी हल किया जा सकता है। सड़ने वाले पानी की समस्या यदि इन गड्ढों (सोकेज पिट) से भी हल किया जावे तो भी गृह-वाटिका तो हर एक घर में होनी ही चाहिए। प्रकृति ने फूल जैसी सुन्दर चीज उत्पन्न

की है, गाँवों में वह आसानी से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हम उसके आनन्द से वंचित हैं।

इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य है। गाँवों के कुओं के पास इतना अधिक पानी गिरता है कि दलदल बन जाता है। इस गन्दगी को दूर करने का सहज उपाय यह है कि वहाँ एक छोटी सी वाटिका लगा दी जावे, उससे गंदगी तो दूर होगी ही गाँव भी आकर्षक बन जावेगा।

### पर्व और त्योहार

पर्व और त्योहार भी मनुष्य जीवन को सरस और सुखी बनाते हैं तथा समाज को जीवन प्रदान करते हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पर्व और त्योहारों को अधिक सजीव बनावे। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, भारत के स्वतंत्र होने का दिन तथा यदि गाँवों में मुसलमान और इसाई हों तो ईद और बड़ा दिन सगठित रूप से धूम-धाम से मनाना चाहिये। होली, दिवाली पर गाँव भर की सफाई का प्रोग्राम रखा जा सकता है तथा सुरुचिपूर्ण नाटक, प्रहसन खेलकूद का आयोजन किया जा सकता है। रक्षा-बंधन को गाँव वालों को एक स्नेह-सूत्र में बाँधने का साधन बनाया जा सकता है। दशहरे पर खेल-कूद, व्यायाम, दंगल का आयोजन किया जाना चाहिये। ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा गाँव में सामूहिक रूप से पर्व और त्योहार मनाने का प्रबन्ध करे तो गाँव के त्योहार और पर्व अधिक सजीव और गाँव के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के दिन को हमें राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप मनाना चाहिये। उससे गाँव वालों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी और देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। उसकी जानकारी होगी। गाँवों के मेलों की भी हमें उन्नति करनी चाहिये।

### अभ्यास के प्रश्न

- १—हमें मनोरजन और खेल-कूद की आवश्यकता क्यों होती है ?
- २—मनोरजन और खेल-कूद से मनुष्य के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है ?
- ३—गाँवों के लिए कैसे खेल-कूद उपयुक्त होंगे ?
- ४—रेडियो के द्वारा गाँवों में मनोरजन और शिक्षा के कार्य में कहाँ तक सहायता मिल सकती है ?



५—मनोरंजन के साधनों का उपयोग ग्राम-सुधार सम्बन्धी प्रचार कार्य में किस प्रकार किया जा सकता है ?

## बीसवाँ अध्याय

### स्वास्थ्य-रक्षा के सिद्धान्तों का प्रचार

सर्वसाधारण का यह विचार है कि गाँव स्वास्थ्यप्रद स्थान होते हैं और वहाँ रोग इत्यादि का प्रकोप कम होता है । किन्तु यह धारणा भ्रान्तिमूलक है । भारतीय ग्रामों में रोगों ने स्थायी रूप से अङ्कुर जमा रक्खा है । प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में ग्रामीण इन रोगों के शिकार होते हैं । वर्तमान काल में भारतवासियों की औसत आयु लगभग तेईस वर्ष है जब कि अन्य देशों में चालीस वर्ष या उससे अधिक है । इसी प्रकार वहाँ फी-हजार आदमियों में से कोई तीस आदमी प्रतिवर्ष मर जाते हैं, जब कि समार के कितने ही देशों में हजार पीछे केवल दस या ग्यारह ही मरते हैं । इससे स्पष्ट है कि वहाँ स्वास्थ्य सुधार की ओर यथेष्ट ध्यान देने की कितनी आवश्यकता है ।

इस सम्बन्ध में आल इंडिया-मेडिकल-रिसर्च-वर्क्स कान्फ्रेंस ने जो प्रस्ताव पास किया है वह ध्यान देने योग्य है । उस प्रस्ताव का आशय निम्न लिखित है—“इस सम्मेलन का विश्वास है कि रोके जा सकने वाले रोगों से भारत में प्रतिवर्ष पचास या साठ लाख मृत्युएं होती हैं और भारत का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे रोगों से जिनको रोका जा सकता है, वर्ष में दो सप्ताह से लेकर तीन सप्ताह तक काम करने से बेकार हा जाता है । यही नहीं, सम्मेलन का यह भी विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति की कार्य-क्षमता इन रोगों से बीस फी सदी घट जाती है । सम्मेलन का अनुमान है कि यदि इन रोगों के द्वारा होने वाली आर्थिक हानि का हिसाब लगाया जावे तो वह श्रमों रुपये प्रतिवर्ष होगी ।”

स्वास्थ्य रक्षा के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता है:—

(१) सफाई, हवा और रोशनी, (२) शुद्ध और पौष्टिक भोजन, (३) परिश्रम अथवा व्यायाम, (४) विध्राम, (५) रोगों से बचने के उपायों की जानकारी, (६) चिकित्सा का उचित प्रबन्ध । अब हमें यह देखना है

कि भारतीय ग्रामों में ऊपर लिखे स्वास्थ्य-रक्षा के साधन कहाँ तक उलब्ध हैं ।

### सफाई, हवा और रोशनी

सफाई, स्वास्थ्य के लिये नितान्त आवश्यक है । यही नहीं, सफाई मनुष्य को आत्मसम्मान, संयम, अनुशासन और मिलजुल कर रहना सिखाती है । सफाई से शारीरिक उन्नति तो होती ही है, मानसिक विकास भी होता है । अतएव ग्राम-सुधार में सफाई का सर्वोच्च स्थान है । केवल शारीरिक सफाई ही यथेष्ट नहीं समझी जानी चाहिये । कपड़ों, घर, पीने का पानी, गली-गाँव और खेतों, सभी की सफाई आवश्यक है । गाँवों में सफाई और रोशनी का अभाव है । यह हम 'गाँवों की सफाई' नामक परिच्छेद में लिख चुके हैं । परन्तु गाँव वालों को अपने शरीर की सफाई के सम्बन्ध में अधिक मतर्क रहने के लिए; उन्हें इसकी शिक्षा देनी होगी । नियमित रूप से शुद्ध कुएँ अथवा नदी के जल में प्रतिदिन स्नान करने, कभी-कभी अपने पहिनने के कपड़ों को साफ करने, दाँतों को प्रतिदिन साफ करने, आँखों को शुद्ध जल से धोने का महत्व उन्हें समझना होगा और ऊपर लिखी स्वास्थ्य प्रदान करने वाली आदतें डलवानी होगी । अभी साधारण किसान इस ओर बहुत ही उदासीन है और इनका महत्व ही नहीं समझता ।

इस शारीरिक सफाई की ओर ध्यान न देने के कारण गाँवों में बच्चे, लियों और पुरुष अनेक रोगों से पीड़ित रहते हैं । फोडे-फुन्सी, आँख और दाँत के रोगों का तो सीधा कारण सफाई न करना है । इनमें आँखों का रोग तो गाँव में सर्व-प्रचलित है । गाँव के बच्चों की आँखें देखिये, वे अधिकतर मैली मिलेगी । आँखों के इन रोगों के कारण बच्चों की आँख खराब हो जाती है । भारत में प्रति हजार बच्चों और खराब आँखों वाले स्त्री-पुरुष की संख्या बहुत अधिक है । अधिकांश में बचपन में ही आँखें खराब हो जाती हैं और आँखें खराब होने का ६० फी सदी कारण गाँव में गन्दगी या असावधानी होती है ।

गन्दगी और सड़ी हुई वस्तुओं के विपैले कण हवा से उड़कर गाँव वालों को आँखों में पड़ते हैं । बच्चे गन्दगी के ढेरों के पास खेलते हैं । गन्दे गाँवों में मक्खियाँ बहुत होती हैं और बच्चों की आँखों पर बैठकर उन्हें गन्दा

कर देती हैं। विशेष कर बीमार आँख या गन्दी आँख पर मक्खियाँ और भी अधिक बैठती हैं। जब किसी बच्चे, स्त्री अथवा पुरुष की आँख रोगी होती है तो वे गन्दे हाथों से उसे छूते या मलते हैं। इसका फल यह होता है कि आँख स्थायी रूप से खराब हो जाती है। आँख की बीमारी घर में तथा क्रमशः गाँव में फैलती है। यदि ध्यान से देखा जावे तो प्रत्येक गाँव में ऐसे लोग यथेष्ट संख्या में मिलेंगे जिनकी आँखें स्थायी रूप से खराब हो गई हैं।

इसका केवल एक ही उपाय है, सफाई। गाँव की सफाई, चेहरे और आँखों की सफाई, कपड़ों की सफाई और शरीर की सफाई ही इस रोग को दूर कर सकती है। जितनी बार भी हो सके, दिन में उतनी बार आँख साफ की जानी चाहिये, तभी वे रोग मुक्त हो सकती हैं।

### शुद्ध और पौष्टिक भोजन

स्वास्थ्य-रक्षा के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन भी अत्यन्त आवश्यक है किन्तु अधिकांश गाँव वालों को पौष्टिक भोजन तो दूर रहा, भर पेट भोजन भी नहीं मिलता। जब तक किसान को पूरे पेट भोजन नहीं मिलता, तब तक उसके स्वास्थ्य की उन्नति की आशा करना स्वप्न के तुल्य है। किसान के पास भर पेट अन्न तभी बच सकेगा जब लगान कुछ कम किया जावे, उसके ऋण के बोझ को हल्का किया जावे और किसान वैज्ञानिक ढङ्ग से खेती करके भूमि से अधिक पैदावार उत्पन्न करे। पौष्टिक भोजन की प्राप्ति के लिये किसानों को अपने घरों और खेतों पर अधिक फल और तरकारी उत्पन्न करना, गाय और भैंस पालना चाहिये। शहद की मक्खियों को पालतू बना कर उनसे नियमित रूप से शहद तैयार करवाना और जिन्हे धार्मिक अडबचन न हो, उनको मुर्गी पालना चाहिये ? किन्तु केवल इतना करने से ही पौष्टिक भोजन की समस्या हल नहीं हो जावेगी। किसानों की स्त्रियों को पाक-शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। यह तभी होसकता है जब गाँव की लड़कियों को शिक्षा दी जावे। किसान की स्त्री अपने घर, रसोई और बरतनों को बहुत साफ रखती है, यदि वे यह और जान जावे कि मक्खियाँ चूहे तथा अन्य कोड़े-मकोड़े मनुष्य को क्या हानि पहुँचाते हैं और जल किस प्रकार दूषित

होता है और उसके पीने से कैसे-कैसे भयंकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं तो गाँव बहुत से रोगों से बच जावे।

### परिश्रम अथवा व्यायाम

गाँव वालों को व्यायाम कराने की विशेष आवश्यकता नहीं है, खेतों में हो उन्हें यथेष्ट परिश्रम करना पड़ता है। हाँ अवकाश के समय खेलने से स्वास्थ्य भी बनता है और मनोरंजन भी होता है।

### विश्राम

स्वास्थ्य के लिए विश्राम और मनोरंजन की भी आवश्यकता है। यदि किसान अपनी दिनचर्या को ठीक बना ले तो उसे विश्राम भी मिल सकता है।

### रोग और उनसे बचने के उपाय की जानकारी

ज्वर, प्लेग, हैजा, चेचक, मोतीभरा, मलेरिया, कालाजार तथा हुकबर्म गाँवों के भयंकर रोग हैं। इनके कारण प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में मृत्यु होती है। इन रोगों का मुख्य कारण गाँव का गन्दा होना और गाँव वालों की लापरवाही है।

गाँव की सब प्रकार से, जैसा सफाई के अध्याय में लिखा है, सफाई रखना चाहिए। इतना करने पर इन रोगों का डर कम हो जावेगा। प्रति छः साल बाद चेचक का टीका लगवाने से (यदि चेचक का प्रकोप हो तो उस समय भी टीका लगवाने से) और, रोशनी तथा सफाई का प्रबन्ध रखने से चेचक का भय जाता रहेगा। प्लेग वस्तुतः चूहों का रोग है, अतएव उससे बचने का मुख्य उपाय चूहों को दूर करना है। चूहे रोशनी से घृणा करते हैं, अतएव घरों में रोशनी का पूरा प्रबन्ध करना चाहिए। नाथ ही उनके बिलों को बन्द करके, बिल्ली, चूहेदानी तथा जहर का उपयोग करके उनको नष्ट किया जा सकता है। सन्दूक तथा अनाज भरने की चीजों को तनिका ऊँचे पर रखना चाहिए जिससे चूहे उनके नीचे अपने रहने का स्थान न बना लें। जब प्लेग का प्रकोप हो तो हर एक को प्लेग का टीका लगवाना और गाँव को छोड़ देना आवश्यक है। हैजा पानी के रसाव हो जाने से तथा खराब पानी पीने से होता है। अतएव पीने के पानी को शुद्ध रखना, कुओं की समय-समय पर सफाई करवाना, और उनमें

लाल दवा डालना, भोजन को शुद्ध रखना तथा सफाई रखना ही, उसको रोकने के मुख्य उपाय हैं।

हुकवर्म रोग गाँव वालों के मैदान में शौच जाने से उत्पन्न होता है, अतएव शौचस्थान का प्रबन्ध उसका मुख्य उपाय है। यदि शौचस्थान का प्रबन्ध न हो सके तो गाँव वालों में पुरानी पद्धति अर्थात् मल को एक कुट गडहे में दवा देने का प्रचार करना चाहिए। गिनीवर्म नामक रोग दूषित जल पीने से होता है, अतएव शुद्ध जल पीने से इसका भय दूर हो सकता है।

गाँव में मलेरिया का बहुत प्रकोप होता है और प्रतिवर्ष, वर्षा के उपरान्त गाँव वाले ज्वर से एक सप्ताह से लेकर दो सप्ताह तक पीड़ित हो जाते हैं। खेती काटने के लिए आदमी नहीं मिलते। उत्तर-प्रदेश में भी मलेरिया के कारण खेती को बहुत हानि पहुँचती है। मलेरिया की समस्या तनिक कठिन है। मलेरिया एक प्रकार के मच्छरो द्वारा उत्पन्न होती है, अतएव गाँव के आध मील चारों ओर जितने गडहे, खड्ड तथा नाले इत्यादि हों, उन्हें गाँव की पंचायत पटवा दे। जो पाटे नहीं जा सकते उनमें वर्षा के उपरान्त समय-समय पर मिट्टी का तेल छुडवा दिया जावे। यदि कोई तालाब तथा पोखरा ऐसा हो कि जिसका पानी पशुओं के पीने के काम आता हो और उसमें मिट्टी का तेल छुडवाना उचित न समझा जावे, तो उसके चारों ओर बहुत सफाई रखी जावे। तालाब के किनारे-किनारे घास, पौधे, कूड़ा-ककट जो भी हो उसको साफ कर दिया जावे। भविष्य में गाँव वालों को तालाब के समीप शौच जाने तथा उसमें कूड़ा डालने की मनाही कर दी जावे। इतना करने पर मच्छरों का उत्पन्न होना बन्द हो जावेगा और मलेरिया का प्रकोप बहुत कम हो जावेगा। कुनीन और ऐसी आयुर्वेदिक दवा-इयों का जो मलेरिया को रोक सके, गाँव में खूब प्रचार करना चाहिए। दवाइयों सरकार लागत मूल्य पर किसानों को बेचे और जो बहुत निर्धन हैं उन्हें सुप्त दे।

इन बीमारियों के अतिरिक्त गाँवों में गन्दी अशिक्षित दाइयों और बच्चा उत्पन्न होने के समय व्यवहार में लाई जाने वाली गन्दी और हानिकर रस्मों के कारण असंख्य बच्चों तथा माताओं का जीवन नष्ट हो जाता है। अधिकतर

कोई नीच जाति की गदी, वृद्धा स्त्री, जिसको ठीक-ठीक दिखलाई भी नहीं पडता और, जिसके बसो तथा नाखून में गन्दगी का विष भरा हुआ है, वह बच्चा उत्पन्न कराने का काम करती है। फिर माता को सबसे गन्दी, अँधेरी कोठरी, जिसमें हवा की गुञ्जाईश ही नहीं हो सकती, बच्चाखाने के लिये दी जाती है। यही नहीं, घर के सबसे अधिक गंदे कपड़े और खाट उसको मिलती है। ऐसी दशा में यदि प्रसव काल में बहुत सी मातायें अथवा नवजात बच्चे मर जाते हैं अथवा उसके शरीर में कोई स्थाई खराबी आ जाती है, तो आश्चर्य की बात ही क्या है ?

इस समस्या को हल करने का यही एक उपाय है कि गाँव की ऐसी दाइयों को जो 'ठीक' समझी जावें दाई का काम सिखाया जावे और केवल ट्रेड दाइयों को ही प्रसव करने के लिए लाइसेंस दिया जावे। दाइयों के अतिरिक्त यदि गाँव को अन्य स्त्रियाँ ट्रेनिङ लेना चाहें तो उन्हें भी शिक्षा दी जावे। इनके साथ-साथ प्रचलित गद्दी रस्मों के विरुद्ध प्रचार किया जावे और गाँव वालों को समझाया जावे कि उनसे उनकी कितनी हानि होती है। ट्रेड दाइयों को पचायत, जिला बोर्ड की सहायता से नौकर रख सकती है। ये ट्रेड दाइयाँ ग्रामीण माताओं को बच्चों के लालन-पालन के सम्बन्ध में भी उचित परामर्श देगी।

### क्षयरोग या तपेदिक (Tuberculosis)

दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से भारत में क्षयरोग तेजी से फैल रहा है और अब यह रोग गाँव में भी पहुँच गया है। यह अत्यन्त भयङ्कर छूत का रोग है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि भारत में केवल इस रोग से ही प्रति वर्ष १५ लाख मनुष्य मर जाते हैं।

खूनी खाँसी आना, सध्याकाल ज्वर सा हो जाना, काम करने में जल्दी थक जाना, नौद न आना, किसी भी काम में जी न लगना, पेट भारी रहना, इसके प्रारम्भिक लक्षण हैं। धीरे-धीरे जब रोग बढ़ने लगता है, तब खाँसी बढ़ती है, शक्ति घटने के साथ शरीर का वजन भी घटने लगता है। सायंकाल ज्वर आ जाता है, कफ के साथ खून भी गिरने लगता है। अन्त में आदमी बिलकुल निरङ्ग होकर मर जाता है।

यह बीमारी परम्परागत होती है। यदि बाप को हुई है तो लड़के को भी

हो सकती है। इसके कीड़े बहुत छोटे होते हैं। एक इंच में २५०० कीड़े स्थान पा सकते हैं। यह बीमारी एक के बाद दूसरे को लगती भी बहुत जल्दी है, यहाँ तक कि इस मर्ज के रोगी के थूक से भी हजारों कीड़े फैल जाते हैं। कुटुम्बियों के साथ यह बीमारी प्रेम रखती है। जिस घर में यह एक बार पहुँच जाती है, फिर उस घर से उसका निकलना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। यदि यह बीमारी किसी स्त्री को हो गई तो उसके पति और बच्चों का इससे बचना बहुत कठिन होता है।

यह बीमारी उन लोगों को अधिकतर हो जाती है जो गंदे घरों में रहते हैं, जहाँ धूप और हवा नहीं पहुँचती। अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने, अत्यन्त चिन्ताग्रस्त रहने से भी यह शरीर में बैठ जाती है, और चुनचाप अपना काम करती रहती है। दुर्व्यसन अर्थात् नशा इत्यादि करने, घर की कलह, कर्जदारी के कारण चिन्तित रहने से भी यह बीमारी हो जाती है।

भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह रोग बहुत पाया जाता है। स्त्रियों को हवा और रोशनी पूरी तरह से नहीं मिलती। उनको पौष्टिक भोजन भी कम खाने को मिलता है। पर्दे की प्रथा तथा छोटी उमर में विवाह भी इस रोग के मुख्य कारण हैं।

इस रोग से बचने के नीचे लिखे उपाय हैं—

- (१) भूख से अधिक कभी न खाओ।
- (२) भोजन नियत समय पर करो। यदि भूख न लगी हो तो भोजन न करो। जितना पचा सको उतना खाओ।
- (३) अपनी पाचन शक्ति को ठीक रखो।
- (४) चवा-चवा कर खाओ।
- (५) बीच-बीच में उपवास करके पाचन शक्ति को तेज करो।
- (६) कुछ पौष्टिक पदार्थ अवश्य लो, जैसे मक्खन, घी, फल इत्यादि।
- (७) थूक में क्षय के कीटाणु होते हैं इसलिये घर में फर्श पर, दीवार पर कभी न थूको। कागज, तमाल या कपड़े पर थूक कर उसे जला डालना अच्छा है।
- (८) यदि पीकदान में थूको तो उसे गरम जल से साफ रखो।
- (९) क्षयरोगी को अलग रखो, उसके कपड़े बर्तन इत्यादि को खीलते पानी में गरम करो और उसे किसी भी काम में न लाओ।

(१०) क्षयरोगी को खुली हवा में रखना चाहिये ।

(११) क्षयरोगी को खूब आराम करना चाहिये ।

(१२) प्रतिदिन नहाना चाहिये ।

(१३) क्षयरोगी को खूब हवादार और खुले मकान में जहाँ धूप आ सके रहना चाहिये ।

(१४) क्षयरोगी के साथ किसी को रहना या खाना न खाना चाहिये ।

सरकार ने ऐन्टी ट्यूबरकुलोसिस लीग ( Anti Tuberculosis League ) की स्थापना की है, जो इन बातों का प्रचार करती है । किन्तु होना यह चाहिये कि इस रोग को रोकने का पूरा प्रयत्न किया जावे और उसकी चिकित्सा का प्रबन्ध होना चाहिये । इस रोग से देश को भयंकर हानि पहुँच रही है । अब भारत सरकार इस रोग को रोकने के लिए बी० सी० जी० के टीके लगवा रही है ।

### चिकित्सा का प्रबन्ध

खेद है कि भारतीय ग्रामों में चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है । ग्रामीण तो राम भरोसे पड़े रहते हैं । जिला बोर्ड, जिला केन्द्र, तहसीलों और बड़े-बड़े कस्बों में अस्पताल चलता है । किन्तु गाँवों में चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं होता । गाँव वाले तहसील तथा जिलों के शफाखानों से बहुत कम लाभ उठा पाते हैं । क्योंकि एक तो वे दूर होते हैं, दूसरे वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती । अतएव आवश्यकता इस बात की है कि गाँव में चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध किया जावे । किन्तु प्रत्येक गाँव में चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध करना अत्यन्त कठिन है । अतएव जिला बोर्ड पाँच-पाँच या उससे अधिक गाँवों के समूह के बीच एक चिकित्सक रखे । प्रादेशिक सरकार इसके लिए जिला बोर्ड को सहायता दे । यदि वैद्य और हकीमों को गाँव में नियुक्त किया जावे तो अधिक अच्छा हो, क्योंकि एक तो वे कम वेतन पर गाँव में रहना स्वीकार करेंगे, दूसरे देशी दवाइयों का मूल्य बहुत कम होता है । इन कारण ग्राम-वासी उन दवाइयों को खरीद सकेंगे । इन ग्रामीण चिकित्सकों को प्रावेट प्रैक्टिस करने की आज्ञा न होनी चाहिये । प्रत्येक गाँव में एक स्वास्थ्य-रक्षक समिति बनाई जावे । प्रत्येक गाँव वाले को उसका सदस्य बनाया जावे । सदस्यों ने कुछ फीस ली जावे ( दो आना प्रति मास ) ।



चिकित्सक बीच के गाँव में रहे और एक दिन में प्रातःकाल ७ से १० तक एक गाँव में, और सायंकाल को दूसरे गाँव में निश्चित स्थान पर गाँव के मरीजों को देखे। इस प्रकार चिकित्सक एक सप्ताह में दो बार प्रत्येक गाँव में चिकित्सा के लिए जावेगा और महीने में एक बार वह स्वास्थ्य-रक्षा के सिद्धान्तों का प्रत्येक गाँव में प्रचार करेगा। दवाइयों का मूल्य प्रत्येक गाँव की स्वास्थ्य समिति घर पीछे लगाई हुई फीस से देगी। दवाइयों का मूल्य गाँव वाले ही दें और चिकित्सक का वेतन सरकार तथा जिला बोर्ड दे तो प्रत्येक गाँव में चिकित्सा का प्रबन्ध अवश्य होगा।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाँवों में लगभग दो हजार चिकित्सालय खोलने का प्रबन्ध किया था। यह अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य है। अन्य प्रादेशिक सरकारों का ध्यान भी अब गाँवों को ओर आकर्षित हुआ है। आशा है कि भविष्य में ग्रामों में चिकित्सा का कुछ प्रबन्ध अवश्य होगा।

### अभ्यास के प्रश्न

१—भारत में साधारण मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और मृत्यु-संख्या भी यहाँ अन्य देशों से अधिक है, इसका क्या कारण है?

२—स्वास्थ्य रक्षा के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, उनका उल्लेख कीजिये ?

३—सफाई का स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है ? यह भी बतलाइये कि गाँव में सफाई कैसी होती है ?

४—शारीरिक सफाई का मनुष्य के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है ? गाँव के रहने वाले शारीरिक सफाई का कितना ध्यान रखते हैं ?

५—साधारण गाँव के रहने वालों का दैनिक भोजन क्या होता है ? क्या वह भोजन उसके स्वास्थ्य को ठाक रखने के लिए काफी है ?

६—उन रोगों का उल्लेख कीजिये, जिनसे गाँवों में लोग अधिक संख्या में मरते हैं ?

७—चेचक, हैजा, प्लेग और मलेरिया क्यों और कैसे होते हैं ? इन रोगों से बचने के उपाय क्या हैं ?

८—गन्दी और अशिक्षित दाइयों से बच्चे पैदा करवाने से क्या हानि होती है ?

६—गाँवों में यदि कोई बीमार हो जाता है तो वह अपनी दवा किससे करवाता है ? गाँव में चिकित्सा का क्या प्रबन्ध है ?

१०—गाँव में कम खर्च से चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किस प्रकार किया जा सकता है ?

११—क्षयरोग से बचने के लिए क्या करना चाहिये ?

## इक्कीसवाँ अध्याय

### पशु-पालन

#### गाँव में गाय और बैल का महत्व

इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय किसान खेती के कार्य के लिए बैल पर निर्भर है। यदि किसान के बैल अच्छे हैं कमजोर नहीं हैं तभी वह अच्छी फसल पैदा कर सकता है। कमजोर बैलों से अच्छी फसल पैदा हो ही नहीं सकती। भूमि की जुताई से लेकर फसल को बाजार में बेचने जाने तक जितनी भी खेती में क्रियाएँ हैं, उन सब में बैल की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। गाय किसान को तथा उसके बच्चों को शुद्ध दूध देती है। अतएव अच्छी गाय और बैलों का किसान के पास होना किसान की आर्थिक स्थिति तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। भारत में खेती बिलकुल गो-वंश पर निर्भर है। इसी कारण हिन्दुओं में गाय की इतनी प्रतिष्ठा है। किसान की सबसे मूल्यवान पूँजी, उसके बैलों की जोड़ी होती है, बिना बैलों के वह कुछ कर ही नहीं सकता।

आज भारत में ससार के एक चौथाई गाय-बैल निवास करते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले धन का मूल्य खेती की पैदावार का मूल्य के लगभग आधा होता है। अस्तु, खेती के उपरान्त देश में यही धधा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी से गाय और बैलों का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

#### गो-वंश की अत्यन्त हीन दशा

भारत के लिये खेती सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धन्धा है जिस पर देश की तीन चौथाई जनसंख्या निर्भर है। उस धन्धे का आधार गो-वंश

हीन दशा में हो, यह आश्चर्य की बात है। ज़िन्तु बात सच्ची है। गो-वंश की दशा आज अत्यन्त शोचनीय है, यदि जमुना पार के मथुरा इत्यादि जिले, पंजाब के हिसार, हरियाणा तथा काठियावाड़ की गाँवों को छोड़ दिया जावे तो अन्य प्रदेशों की गायों की नत्ल इतनी गिर गई है कि वह दूध देने वाला जानवर ही नहीं रह गया। उसके स्थान को भैंस ने ले लिया। साधारणतः ये गायें सेर या डेढ़ सेर दूध देती हैं। जब कि यूरोप तथा अन्य देशों में यदि कोई गाय पन्द्रह या सोलह सेर से कम दूध देती है तो वह पालने योग्य नहीं समझी जाती, माँस बनाने के कारखाने को भेज दी जाती है।

यही दशा बैलों की भी है। खेतों पर काम करते हुये बैलों को देखिए। अधिकतर निर्बल, नाटे, और दुबले-पतले बैल दिखाई देगे। भला इन निर्बल बैलों से अच्छी खेती कैसे सम्भव हो सकती है। किसान को अच्छा हल या रात्रा पेरने का कोल्हू दोजिये तो वह उसकी उपयोगिता को समझते हुए भी उसे इस कारण नहीं लेता क्योंकि उसके निर्बल बैल उसे चला न सकेंगे। बैलों की नत्ल विगड़ गई है; फिर भी भारत के कुछ भागों में अच्छी नत्ल के बैल पाये जाते हैं। जिनकी नत्ल अभी नहीं विगड़ी है। उनमें 'शाहिवाल' और 'हरियाणा' पंजाब के, 'काकरेज' गुजरात का, 'गिर' काठियावाड़ का, 'औन्गल' मद्रास का, 'पँवार' उत्तर प्रदेश का, 'गोर्ला' मध्य प्रदेश का, और 'मालवी' मध्य भारत का मुख्य है।

### गो-वंश की हीन दशा के कारण

गो-वंश की इस शोचनीय दशा के तीन मुख्य कारण हैं। ( १ ) अच्छे चारे का अकाल ( २ ) पशु रोगों और बीमारियों से बहुसंख्या गाय और बैलों का नाश ( ३ ) गाय-बैलों की नत्ल को अच्छा बनाने के उचित प्रबन्ध का न होना।

### आवश्यकता से अधिक बैल

चारे के सम्बन्ध में लिखने से पूर्व एक बात समझ लेने की है। एक निर्बल और अशक्त बैल जो एक अच्छे बैल की तुलना में एक तिहाई काम करता है, अच्छे बैल से कुछ ही कम खाता है। अतएव यदि अच्छे

गाय या बैल रक्खे जावें तो सब काम कम गाय बैलों से चल जावेगा और कम चारे की आवश्यकता होगी। परन्तु यदि खराब गाय-बैल रक्खे जावेंगे तो सख्या मे अधिक रखने पड़ेगे और चारा अधिक खिलाना पड़ेगा। अच्छे बैल को रखने का खर्चा एक रद्दी बैल के रखने से कुछ ही अधिक पड़ता है। परन्तु काम को देखते हुये अच्छा बैल सस्ता बैठता है। सन् १९२६ में भारतीय शाही कृषि कमीशन की सम्मति मे भारत मे प्रति एकड़ और दूसरे देशों से कहीं अधिक बैल हैं। उसका मत है कि यदि ये बैल अच्छे होते तो इतने अधिक बैलों को न रखना पड़ता। भारत मे एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। किसी भी प्रदेश मे गाय और बैलों की सख्या खेती के योग्य बैलों पर निर्भर है। बैलों को पालने के लिए जितनी खराब दशा किसी प्रदेश की होगी, उतने ही अधिक गाय और बैल उस प्रदेश मे इस आशा से पाले जावेंगे कि इनमे से खेती योग्य यथेष्ट बैल मिल जावेंगे। इसका फल यह होता है कि चारे की उस प्रदेश में और भी कमी हो जाती है; गायें कम बच्चे देने लगती हैं। और उनसे बछड़े छोटे होने लगते हैं, जिनसे किसान का काम नहीं चलता। किसान उपयोगी और अच्छे बैलों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक बछड़ों को उत्पन्न कराता और पालता है। जैसे-जैसे सख्या बढ़ती जाती है, बैलों की साइज छोटी होती जाती है, वैसे ही वैसे चारे की कमी बढ़ती जाती है।

इनमें से अधिकांश निर्बल बैल खेती के लिए उपयुक्त ही नहीं होते। गो-वंश की नस्ल इस समय इतनी खराब हो गई है कि देश के सामने यह एक बड़ी समस्या के रूप मे खड़ी हो गई है। अब हम इन तीनों कारणों की विस्तृत आलोचना करेगे, जिनके कारण गो-वंश की दशा इतनी शोचनीय हो गई है, और यह भी बतलावेंगे कि गाय और बैलों की नस्ल को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है।

### चारे की कमी (Fodder)

भारत मे जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे-वैसे खेती के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती गई। कारण यह था कि खेती के अतिरिक्त और कोई धंधा ही नहीं था, जिसमें बढ़ी हुई जनसंख्या लग सकती। इसका फल यह हुआ कि चरागाहों को खेतों में परिणत कर दिया

गया । गोचर-भूमि के कम हो जाने से चारे की कमी हो गई । चरागाह तो कम हो गए किन्तु किसान ने गाय और बैलों के पालने का ढंग वही पुराना रक्खा । भारतीय किसान का अपने पशु को पालने का ढंग यह है कि गाय जब दूध देती है तब तो उसको घर पर सानी (भूसा-करवी, तथा घास इत्यादि ) यथेष्ट दी जाती है परन्तु जब वह सूख जाती है तब उसको बहुत कम खाने को मिलता है । केवल वह मैदानों पर चर कर पेट भरती हैं । किन्तु चरागाह की कमी के कारण तथा मार्च, अप्रैल, मई, जून में घास के जल जाने के कारण गायें प्रायः भूखी रहती हैं । क्रमशः वह दुर्बल होती जाती है । बैलों को जब कि काम करते हैं, उन दिनों उन्हें किसान घर पर अधिक सानी देता है, किन्तु जिन दिनों खेतों पर काम कम होता है, उन्हें भी मैदानों पर चरने को छोड़ दिया जाता है ।

अस्तु, चारे की समस्या को हल करने के दो ही ढंग हैं, या तो चरागाहों को बढ़ाया जावे अथवा इसी भूमि पर अधिक से अधिक चारा उत्पन्न किया जावे । कृषि कमीशन की राय में तथा अन्य कृषि-शास्त्रियों की राय में अब गोचर-भूमि बढ़ाई नहीं जा सकती । अतएव इसी भूमि पर तथा खेतों पर अधिक से अधिक चारा उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए । अधिक चारा उत्पन्न करने के लिये निम्नलिखित उपाय करने होंगे । गाँव के चारों ओर मैदानों और खेतों में जो भी गड़हे तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि हो, उसको चौरस कर दिया जावे जिससे कि वर्षा का पानी गिरते ही तुरन्त न बह जावे परन्तु धीरे-धीरे बहे और भूमि उसको सोखे । इससे केवल अधिक घास ही नहीं उत्पन्न होगी वरन् खेती भी अच्छी होगी । चरागाह में गाय और बैलों के चरने पर गाँव की पचायत का नियन्त्रण होना चाहिये । यदि चरागाह का एक हिस्सा एक वर्ष पशुओं के चरने के लिए रक्खा जावे तो दूसरे हिस्से पर घास खूब बढ़ने दी जावे और उसको काट कर साइलो (Silo)\* में भर कर साइलेज (Silage) बना ली जावे या काट-काट कर खिलाई जावे ।†

\*साइलो ( Silo )—घास अथवा चारे को अच्छी दशा में सुरक्षित रखने वाला गड़हा ।

†साइलेज (Silage)—साइलो में रक्खी हुई घास अथवा अन्य चारा साइलेज कहलाती है । साइलेज बनाने में चारे के सारे पौष्टिक अंश सुरक्षित रहते हैं ।

चरागाह पर पशुओं को चराने से घास नष्ट हो जाती है, बढ़ती ही नहीं है। अतएव घास काट कर खिलाने से चरागाहों से अधिक चारा मिल सकता है। घास का ठीक उपयोग करने के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा तथा अन्य प्रकार की करबी की भी साइलेज बनाने से चारा स्वास्थ्यवर्धक तथा अच्छा बना रहता है। सुखा देने से बहुत सा चारा नष्ट हो जाता है और उसके गुण जाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ सिचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो, वहाँ किसानों को चारे की फसल उत्पन्न करने को उत्साहित करना चाहिये। यदि क्लोवर (Clover) नाम की एक प्रकार की घास तथा अन्य चारे की फसल जो बहुत जल्दी तैयार हो सकती है और जिन्हे किसान बिना अपनी मुख्य फसलों का त्याग किए काट सकता है, उत्पन्न की जावे तो किसान के पास यथेष्ट चारा हो सकता है। कृषि-विभाग को चाहिये कि वह अन्य चारे की फसलों की खोज करे जो कि शीघ्र तैयार हो सकें।

भारत में जङ्गलों में बहुत अधिक घास बेकार सूख जाती है। यदि वह घास काट कर चारे के रूप में परिणत की जा सके और रेल घास को बहुत सस्ते किराये पर देश में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचा सके तो जो यह अनन्त राशि में चारा नष्ट होता है और पशु भूखे मरते हैं यह अवस्था दूर हो सकती है।

प्रत्येक गाँव में जो ऊसर अथवा बजर भूमि है उसका उपयोग भी जंगल उत्पन्न करने में करना चाहिये। जङ्गल विभाग शीघ्र उत्पन्न होने वाले वृक्षों का जङ्गल उस भूमि पर गाँव वालों की सहायता से लगवावे और उस जङ्गल से गाँव के लोग चारा और ईंधन अपनी आवश्यकतानुसार ले लिया करें। उस जङ्गल की देख भाल गाँव की पंचायत करे।

### साइलेज (Silage) बनाने के उपाय

सूखे चारे को सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम साधन साइलेज बनाना है। किसान एक गड़हा जो ऊपर आठ फुट चौड़ा हो और तले पर सात फुट चौड़ा हो, और जिसकी गहराई आठ से दस फुट तक हो, खोदे। ज्वार, बाजरा, मक्का तथा अन्य प्रकार की करबी के टुकड़े करके घास,

पेड़ों की पत्तियों तथा अन्य पौधों, सबों को काटने के उपरान्त तुरन्त ही ठूँस-ठूँस कर और जहाँ तक हो सके, दाब-दाब कर भर दे। ऊपर से पत्थर ईंटे तथा भारी चीजे रख दे। बहुत अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक चारा तैयार हो जावेगा।

### पशुओं के रोग (Cattle diseases)

भारत में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पशु रिन्डरपैस्ट ( Rinderpest ) जानवरों के प्लेग, सैप्टीसीमिया ( Septicemia ) तथा मुँह और पैर की बीमारियों से मरते हैं। इनमें रिन्डरपैस्ट अत्यन्त भयङ्कर रोग है जिससे प्रतिवर्ष असंख्य गाय, बैल तथा अन्य पशु मर जाते हैं। यह छूत का रोग है। जब फैलता है तो अग्नि की तरह फैलता है और बेचारा किसान अपने बैलों से हाथ धो बैठता है। पशु-चिकित्सा-विभाग सिरम ( Serum ) का टीका लगाकर पशुओं की रक्षा करता है। किन्तु पशु-चिकित्सालय अधिकतर जिलों और तहसीलों में ही होते हैं। किसान अपने बीमार बैलों को भला वहाँ कैसे ले जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि पशु-चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जावे और वे गश्त करते रहे। सरकार का तो यह कर्तव्य है ही कि वह अधिक से अधिक पशु-चिकित्सा की सुविधाएँ प्रदान करे। किन्तु किसानों का भी यह कर्तव्य है कि वे जब मेलों तथा पैठों से बैल मोल लावे तो उसे एक सप्ताह तक अलग बाँध कर खिलावे। जानवरों में न मिलने दें। जब कभी कोई पशु बीमार हो जावे तो उसे अन्य जानवरों से अलाहदा कर दें। और अपने जानवरों को ताल तथा पोखरों का सड़ा हुआ गदा पानी न पिलावे। तभी किसानों के जानवर बीमारी से बच सकते हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि जब तक बैलों की बीमारियों से रक्षा न की जा सकेगी तब तक किसान बढ़िया बैल नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको उसकी बीमारी से मर जाने का बराबर भय रहेगा। ऐसी दशा में वह सस्ता से सस्ता बैल खरीदना ही पसन्द करेगा।

रिन्डरपैस्ट ( पशुओं का प्लेग ) भयङ्कर छूत का रोग है। जब यह रोग फैलता है तो गाँव के गाँव साफ हो जाते हैं। प्रतिवर्ष भारत में लाखों की संख्या में पशु इस रोग से मर जाते हैं।

जब पशु बीमार होता है तो खाना छोड़ देता है और सुस्त रहने

लगता है फिर उसको तेज बुखार चढ़ता है तथा तीन-चार दिन में मर जाता है। यदि एक पशु को यह बीमारी लग गई तो यह गाँव भर में फैल जाती है।

पशु-चिकित्सा विभाग ने इसकी दवा तो निकाल ली है। जब बीमारी फैली हो और पशु को दवा (सिरम) का टीका लगवा दिया जाय तो पशु पर बीमारी का असर नहीं होता, किन्तु देश के लगभग पाँच लाख गाँवों में सिरम का टीका लगाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। पशुओं के डाक्टर बड़े कस्बे या शहरों में रहते हैं। गाँव के लोग उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकते।

आवश्यकता इस बात की है कि बहुत ज्यादा "सिरम" तैयार कराया जावे और गाँव के मुखिया, पटवारी, गाँव की पाठशाला के अध्यापक, तथा अन्य कर्मचारियों को टीका लगाना सिखा कर दवा उन्हें दे दी जावे। इस प्रकार पशुओं की इस रोग से रक्षा हो सकती है।

### गाय-बैलों की नस्ल सुधारना (Cattle-breeding)

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि गाय और बैलों की नस्ल बिगड़ गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि गाँव तथा कस्बों में अच्छे साँड़ों की कमी है। हिन्दुओं में प्राचीनकाल से यह प्रथा थी कि किसी वृद्ध के मरने पर उसके वंशज एक अच्छी नस्ल के अच्छे बछड़े को साँड़ बनाते थे। साँड़ बनाने के लिए बहुत अच्छा बछड़ा छाँटा जाता था। किन्तु अब लोग पुण्य तो कमाना चाहते हैं और इस कारण किसी रद्द बछड़े को साँड़ बना देते हैं। इसका फल यह हो रहा है कि वे धार्मिक-साँड़ (जो कि खराब नस्ल के हैं) हजारों लाखों की संख्या में छूटे फिरते हैं और गाय-बैलों की नस्ल को खराब करते हैं। यही नहीं, बूढ़े और अशक्त साँड़ भी वशोत्पत्ति करते रहते हैं। जब कि बछड़े पैदा करने का प्रबन्ध इतना खराब है, फिर नस्ल कैसे अच्छी बन सकती है।

अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि इन रद्दी साँड़ों को दूर किया जावे। कुछ विशेषज्ञों का तो यह कहना है कि इन साँड़ों को मरवा दिया जावे। किन्तु हिन्दू इसको सहन न कर सकेंगे, अतएव इन रद्दी साँड़ों को नपुंसक करवा दिया जावे, जिससे वे सन्तानोत्पत्ति के योग्य



न रहे। भविष्य में इस प्रकार साँड़ बनाकर छोड़ने के विरुद्ध नियम बना दिया जावे। केवल अच्छी नस्ल के बछड़ों को ही साँड़ बनाया जावे। भारत के प्रत्येक देश में कुछ सरकारी साँड़ फार्म हैं जहाँ अच्छी जाति के साँड़ तैयार किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी दो ऐसे सरकारी फार्म हैं जहाँ अच्छी नस्ल के साँड़ तैयार किये जाते हैं। किन्तु इनमें इतने साँड़ प्रति वर्ष नहीं दिये जा सकते जितनी गाँवों को आवश्यकता है। साधारणतः सौ गाँवों के लिए एक अच्छे साँड़ की आवश्यकता है।

गाय और बैल की नस्ल तभी सुधर सकती है कि जब गाँव-गाँव में अच्छे साँड़ पहुँचा दिये जावे। इसके लिये केवल सरकार पर अवलम्बित रहना ठीक नहीं है। सरकार कभी भी ध्येष्ट सख्या में साँड़ बाँट न सकेगी। इसके लिये डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड, गाँव वालों की पंचायतों, जमींदारों, कोर्ट्स-आव-वाड्स, गऊशालाओं और पिंजरापोलों, गाँव की सहकारी समितियों तथा अन्य गाँव के धनी व्यक्तियों को साँड़ों को पालना चाहिए और नस्ल को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

### भारत का विभाजन और पशुधन

१९४५ की पशु गणना के अनुसार अविभाजित भारत में ढोरो की सख्या २० करोड़ ६० लाख थी। विभाजन के उपरान्त भारत में १७ करोड़ ६० लाख ढोर रह गये। इनमें १३ करोड़ ६० लाख गाय, बैल हैं और ४ करोड़ भैंस हैं। आज भी संसार के लगभग २५ प्रतिशत ढोर भारत में हैं।

परन्तु विभाजन के फलस्वरूप जहाँ तक अच्छी नस्ल का प्रश्न है भारत को बहुत हानि हुई, शाईवाल, मांटगोमरी, सिंधी, थार पारकर जैसी दुधारू नस्लें तथा थारी, भगनारी, और धन्नी जाति की नस्लें जो खेती के लिए उत्तम बैल उत्पन्न करती थीं वे सभी पाकिस्तान में रह गईं।

ढोरो की उत्तम नस्लें पाकिस्तान में रह जाने के कारण भारत सरकार उन नस्लों को भारत में उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही है। नस्ल की उन्नति करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश को प्रतिवर्ष दो लाख उत्तम जाति के साँड़ चाहिए जबकि सरकारी बुलफार्मों से प्रतिवर्ष केवल ७५० उत्तम जाति के साँड़ ही तैयार होते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के

लिए सरकार ने “की-विलेज-स्कीम” को अपनाया है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ गाँवों को उत्तम जाति के साँड़ दिये जावेंगे और उनसे जो भी बछड़े उत्पन्न होंगे वे सरकारी बुलफार्मों पर पाले जाकर उत्तम साँड़ बनाये जावेंगे। और फिर वे गाँवों को दे दिए जावेंगे। भारत सरकार ने १६०० नस्ल-सुधार-केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है पशु विभाग कृत्रिम रूप से गायों से सन्तानोत्पत्ति कराने का प्रयोग कर रहा है जिसमें सफलता प्राप्त हुई है।

इस योजना से भविष्य में भारत में गोवंश की उन्नति होने की आशा है।

### जिला-बोर्ड ( डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड ) द्वारा सहायता

प्रत्येक जिला ( डिस्ट्रिक्ट ) बोर्ड को अपने जिले की गाय और बैलों की जाँच करना चाहिये और उसके उपरान्त यह निश्चय करना चाहिए कि कौन सी नस्ल का साँड़ उस जिले के लिए उपयुक्त रहेगा। जहाँ-जहाँ पशु-चिकित्सालय हों वहाँ-वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड साँड़ रखे। ये समीपवर्ती गाँवों के उपयोग के लिए हों। जो भी पंचायत, गऊशाला अथवा अन्य संस्था नस्ल अच्छी करने के लिए साँड़ मोल ले, उसे बोर्ड आर्थिक सहायता प्रदान करे। गाय और बैलों की नुमाइश कराई जावे। मेलों, नुमाइशों तथा पैठों में प्रचारकों को भेजकर इस बात का प्रचार कराया जाय कि अच्छी नस्ल किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है। साथ ही अच्छे साँड़ तथा उनसे उत्पन्न गाय और बैलों का प्रदर्शन कराया जावे। जो किसान अच्छे गाय और बैल उत्पन्न करें, उनको इनाम दिया जावे।

सरकार पंचायतों तथा सहकारी समितियों को उत्साहित करे कि वे साँड़ खरीदें और अपने क्षेत्रों में गाय और बैलों की नस्ल को सुधारने के लिये अपना-अपना प्रयत्न करे। यदि गाँव के लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर साँड़ रखें तो गाय को गामिन कराने की थोड़ी सी फीस ली जा सकती है, जिनसे साँड़ का पालन हो सकता है।

### सहकारी नस्ल-सुधारक समितियाँ

#### ( Co-operative Cattle-breeding Societies )

गाँव वालों को भी अपने गाय-बैलों की नस्ल सुधारने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। इसके लिए उन्हें एक सहकारी समिति गाय-बैलों की

नस्ल सुधारने के लिए स्थापित करना चाहिये। पूर्वी पंजाब तथा अन्य प्रदेशों में ये सहकारी नस्ल-सुधार समितियाँ स्थापित की गई हैं। ये समितियाँ अच्छे साँड रखती हैं। रद्दी और खराब नस्ल के साँडों को गाँव से हटा देती हैं। गाँव की गायों का रजिस्टर रखती हैं। गायों के गाभिन होने तथा उनके ब्याने का लेखा रखती हैं। गाय तथा उनसे उत्पन्न सन्तान पर निशान डालती हैं। ( यह निशान मिटते नहीं। इनसे यह ज्ञात होता है कि नस्ल में कितनी उन्नति हुई। ) अच्छी नस्ल के साँड और गाँव की छुटी हुई गायों के ससर्ग से जो गायें उत्पन्न हों, उनके दूध का लेखा रखती हैं, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वे कितना दूध देती हैं। गाँव के गाय और बैलों की बीमारी से रक्षा करने के लिए उनको टीका लगवाती हैं। नस्ल-सुधार समिति अपना खर्च चलाने के लिए सदस्यों से प्रवेश-फीस लेती है। सदस्यों से गायों की गाभिन कराई की जो फीस ली जावे, गैर सदस्यों की गाय बच्चा पैदा करे तब नाम-मात्र की फीस ली जावे, तथा सदस्यों द्वारा गाय अथवा बैल बेचे जाने पर भी थोड़ी सी फीस ली जावे।

### ग्राम-सुधार विभाग

ग्राम-सुधार विभाग को भी इस कार्य में सहयोग देना चाहिये। जो गाँव कैटिल-ब्रीडिंग सोसायटी स्थापित करे और अच्छी नस्ल का साँड मोल ले उन्हें ग्राम सुधार विभाग, साँड का २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत मूल्य दे। इसके अतिरिक्त वह इस सम्बन्ध में प्रचार कार्य करे।

### गऊशाला

गऊशालाएँ भी गाय और बैल की नस्ल अच्छा बनाने में बहुत कुछ कार्य कर सकती हैं। इस समय तो भारत भर में हजारों गऊशालाओं पर हिन्दू करोड़ों रुपये व्यय करते हैं, किन्तु वह बूढ़े तथा रोगी गाय और बैलों को रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। यदि इन गऊशालाओं को गाय-बैलों की नस्ल के सुधारने का केन्द्र बना दिया जावे तो बहुत कुछ काम हो सकता है।

पशुओं और विशेष कर गाय और बैलों की नस्ल तभी सुधर सकती है जब कि जनता, सार्वजनिक संस्थाएँ, तथा सरकार सभी इस ओर प्रयत्न-शील हों।

हिन्दू गाय को अत्यन्त पवित्र मान कर उसकी पूजा करते हैं किन्तु गऊशालाये जिन पर हिन्दुओं का करोड़ों रुपये व्यय होता है गाय की उन्नति के लिए कुछ नहीं करतीं। हमें यह न भूल जाना चाहिये कि जब तक हम गाय की नस्ल की उन्नति करके उसको लाभदायक पशु नहीं बना देते तब तक उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती।

होना यह चाहिये कि प्रत्येक गऊशाला एक या अधिक अच्छी जाति का साँड़ रखे, जिससे कि उस इलाके में नस्ल अच्छी बने। जहाँ गऊशाला बहुत धनवान हो वहाँ अच्छे साँड़ तैयार किये जावे और दूसरी गऊशालाओं को दिये जावे। गायों के पालन, चारे की व्यवस्था, साइलेज बनाने, पशुओं के रोगों की जानकारी कराने, पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध करने का गऊशाला-केन्द्र होना चाहिए।

वर्ष में एक बार समीपवर्ती प्रदेश की गायों पर पारितोषिक दिया जावे, अच्छे बछड़े और गायों पर पारितोषिक दिया जावे। इस प्रकार देश की गऊशालाये गो-वंश की उन्नति का प्रधान साधन बन सकती हैं, आज तो वे बूढ़े पशुओं को रखने का स्थान मात्र हैं।

## गो-सेवा संघ

कई वर्ष हुए महात्मा गाँधी के नेतृत्व में गो-सेवा संघ की स्थापना हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य गाय की नस्ल की उन्नति करना और इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। इस संघ का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो इस बात का व्रत ले अर्थात् प्रतिज्ञा करे कि वह आजीवन गाय का ही दूध, और उसके ही दूध से बने हुए घी, दही, मक्खन इत्यादि का उपयोग करेगा।

गो-सेवा-संघ ने वर्धा में गौपुरी नामक स्थान बनाया है, जहाँ गाय की नस्ल का सुधार करने, दूध को बढ़ाने, चारे इत्यादि की व्यवस्था करने और पशुओं के रोगों को रोकने तथा अन्य सभी आवश्यक समस्याओं पर अनुसंधान हो रहा है।

पालने और दूध तथा घी के लिए भैंस पालने की परिपाटी चल पड़ी है, यह हानिकारक है। इसमें हमें एक पशु के स्थान पर दो पशुओं को रखना पड़ता है और चारे की समस्या और भी विकट रूप धारण कर लेती है। अतएव गो-सेवा-सघ का कहना यह है कि हमें गाय की ऐसी नस्ल उत्पन्न करनी चाहिये जो कि खेती के लिए उत्तम बैल भी दे और दूध भी खूब दे जिससे कि भैंस रखने की आवश्यकता न रहे। यही कारण है कि सघ जनता से गाय के दूध घी इत्यादि को काम में लाने का आग्रह करता है।

आज तो स्थिति यह है कि गाय बैल उत्पन्न करने के लिए पाली जाती है, दूध तो वह नाम-मात्र को ही देती है। भैंसा खेती के काम नहीं देता इसलिए गाय पालना जरूरी है। लेकिन गाय के दूध न देने के कारण भैंस पालनी पड़ती है। इससे बहुत हानि होती है। इसलिए अगर ऐसी गाय की नस्ल तैयार की जावे जो दूध भी खूब दे और खेती के लिए उत्तम बैल भी पैदा करे तो हानि बच सकती है। गो-सेवा-सघ इसी प्रकार की दोहरे काम वाली गाय की नस्ल को उत्पन्न करने पर जोर देता है।

भारत का विभाजन हो जाने से जहाँ तक गोधन का प्रश्न है भारत की स्थिति पहले से बहुत खराब हो गई है। अविभाजित भारत में २० करोड़ ६० लाख गोवश भारत में रहा और ३ करोड़ पाकिस्तान में चला गया। जहाँ तक संख्या का प्रश्न है भारत में संख्या यथेष्ट है परन्तु अधिकांश गोवंश की अच्छी नस्लें पाकिस्तान में रह गईं जो अच्छे बैल उत्पन्न करती हैं और दूध अधिक मात्रा में देती हैं। शाईवाल, माटोगोमरी, सिधी, थार पारकर, इत्यादि अच्छी नस्लें पाकिस्तान में रह गईं। भारत में इतनी अच्छी नस्लें नहीं हैं।

यही कारण है कि भारत में केन्द्रीय सरकार गोवश की नस्ल को सुधारने की ओर अधिक प्रयत्नशील है। अतएव सरकार ने एक योजना बनाई है। देश भर में उत्तम जाति के सॉड उत्पन्न करने के लिए ५४० बुलफार्म स्थापित किए जावेंगे जिनसे प्रतिवर्ष दस हजार उत्तम जाति के सॉड तैयार होंगे जो कि गोवश की नस्ल को उन्नत करेंगे।

## अभ्यास के प्रश्न

- १—गाय किसान के लिए कयो उपयोगी जानवर है ?
  - २—खेती में बैलों का किन-किन कार्यों में उपयोग होता है ?
  - ३—भारत में किन प्रदेशों की गायें अधिक दूध देती हैं और बैलों की कौन सी अच्छी नस्लें मिलती हैं ।
  - ४—भारत में गाय और बैलों की नस्लें खराब हो गईं हैं, इसका क्या कारण है ?
  - ५—क्या भारत में बैल जरूरत से ज्यादा हैं ? यदि हैं, तो इसका कारण बतलाइये ।
  - ६—गाँवों में चारे की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय काम में लाना चाहिये ?
  - ७—साइलेज किसे कहते हैं, वह कैसे तैयार होती है और उससे क्या लाभ होता है ?
  - ८—पशुओं की कौन-कौन सी भयंकर बीमारियाँ गाँव में फैलती हैं ? उनसे पशुओं की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है ?
  - ९—गाय और बैलों की नस्ल को सुधारने के लिए कौन से उपाय काम में लाना चाहिए ?
  - १०—जिला बोर्ड (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) तथा कैटिल-ब्रीडिंग सोसाइटी गाय-बैलों की नस्ल को सुधारने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं ।
  - ११—गो-सेवा-सघ गो-वश की उन्नति के लिए क्या कर रहा है ?
-

## बाईसवाँ अध्याय

### खेती की उन्नति के उपाय

(Agriculture Improvement)

#### कृषि की गिरी हुई दशा

भारत कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग तीन-चौथाई जन-संख्या खेती पर ही निर्भर है। खेती का देश के आर्थिक संगठन में सर्वोच्च स्थान होने पर भी खेती की दशा अत्यन्त गिरी हुई है, यह आश्चर्य की बात है। देश की निर्धनता को दूर करने के लिए जहाँ देश की औद्योगिक उन्नति करने की आवश्यकता है वहाँ उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि भूमि की उपज बढ़ाई जावे। जैसा कि हम किसी पिछले अध्याय में बतला आए हैं, अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रति एकड़ उपज सब से कम है। भारत में प्रति एकड़ कपास की पैदावार पच्चीस पौंड है जब कि मिश्र की ४०० पौंड तथा संयुक्तराज्य-अमरीका की २५० पौंड है। भारत में एक एकड़ में जितना गन्ना उत्पन्न होता है उससे चौगुना जावा और छः गुना क्यूबा में उत्पन्न होता है। भारत में प्रति एकड़ इंगलैंड का एक चौथाई गेहूँ उत्पन्न होता है। यद्यपि इन देशों और भारत की खेती वारी के ढङ्ग में बहुत अन्तर है। वहाँ खाद, यन्त्र और शक्ति के द्वारा बड़े-बड़े खेतों पर आधुनिक वैज्ञानिक ढङ्ग से खेती होती है। अतएव यह कहना कि भारत भी प्रति एकड़ इतनी ही पैदावार उत्पन्न कर सकता है, ठीक न होगा। परन्तु फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि यदि खेती-वारी अधिक सावधानी से की जावे तथा आवश्यक सम्भव सुधार कर दिये जावे तो उपज बहुत कुछ बढ़ाई जा सकती है।

अब हम उन साधनों का वर्णन करते हैं कि जिनकी कृषि में आवश्यकता होती है और साथ ही यह बतलाने का भी प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

#### कृषि के आवश्यक साधन

उत्पादन कार्य में चार साधन आवश्यक हैं:—१. भूमि (Land)

२. पूँजी ( Capital ), ३. श्रम ( Labour ), ४. संगठन ( Organisation ) और साहस ( Enterprise ) ।

### भूमि

भूमि के अंतर्गत हमें निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन करना है :—  
छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतों की समस्या । खाद की समस्या ।

### पूँजी

पूँजी के अंतर्गत पशुधन, खेती के यन्त्र, बीज, सिचाई, साख की समस्याएँ आती हैं ।

### श्रम तथा संगठन

श्रम तथा संगठन के अंतर्गत किसानों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, फसलों के शत्रु तथा पैदावार को बेचने की समस्याओं का अध्ययन करना होगा ।

### छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतों की समस्या

यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि भारतीय किसानों के पास भी थोड़ी सी भूमि होती है । वह भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी होती है । यह सर्वमान्य बात है कि जब तक किसान छोटे-छोटे अनेक खेतों पर खेती करने का प्रयत्न करता है, जो एक दूसरे से बहुत दूरी पर बिखरे हुए हैं, तब तक खेती की उन्नति होना सम्भव नहीं है । खेती की उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खेत एक चक्र में हों ।

किसी-किसी प्रदेश में तो खेतों के ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं और इतनी दूरी पर बिखरे हैं कि उन पर खेती करने से कोई लाभ हो ही नहीं सकता । भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होने का खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है । औसत किसान अपनी शक्ति और साधन का उचित उपयोग नहीं कर सकता । एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक उसे जाने में बहुत समय नष्ट करना पड़ता है । इन बिखरे हुए टुकड़ों की ठीक तरह से देख-भाल भी नहीं हो सकती, बहुत सी जमीन मेड़ बनाने में व्यर्थ चली जाती है । किसानों के खेत एक जगह न होकर बिखरे होने के कारण उसे दूसरों के खेतों में से होकर जाना पड़ता है जिससे झगड़ा होता है और



मुकदमेवाजी की नौबत आती है। सिचाई के मामले में भी अड़चन होती है। किसान अपने सब ढुकड़ों पर तो कुआँ बना ही नहीं सकता। और एक कुएँ से दूर-दूर के खेतों को पानी ले जाने में दूसरों के खेतों में से पानी ले जाना पड़ता है। बिखरे हुये खेतों के कारण अच्छे यन्त्र और औजार काम में लाये नहीं जा सकते, क्योंकि वे भारी होते हैं और किसान उन्हें अपने कंधों पर रख कर एक ढुकड़े से दूसरे ढुकड़े पर नहीं ले जा सकता। न खेत पर वह और कोई सुधार ही कर सकता है। छोटे-छोटे खेतों में बाड़ लगाने का खर्च भी बहुत पड़ता है इसलिए बिना बाड़ की खेती करनी होती है। किसान के पास सारी भूमि एक चक्र में न होने के कारण वह अन्य देशों के किसानों की तरह अपने खेत पर मकान बना कर नहीं रहता वरन् खेतों से दूर बस्ती में रहता है। वैज्ञानिक ढग की खेती करने के लिए किसान को खेत पर ही रहना चाहिये, क्योंकि उस दशा में वह हर एक वक्त खेतों की देख-भाल कर सकेगा उसको स्त्री तथा बच्चे पूर्ण रूप से सहायक हो सकेंगे, तथा खाद इत्यादि का पूरा उपयोग हो सकेगा। सारांश यह है कि भूमि का छोटे-छोटे ढुकड़ों में बिखरे होना खेती की उन्नति में बहुत बाधक है। इसमें सुधार अत्यन्त आवश्यक और पहली बात है।

यह तभी हो सकता है कि जब हर एक किसान को उसकी जमीन ( जो अभी अलग-अलग ढुकड़ों में बँटी है ) के बराबर का एक ही बड़ा खेत दे दिया जावे और आगे इस बात का प्रबन्ध कर दिया जाय कि एक निश्चित क्षेत्रफल के बाद जमीन के ढुकड़े नहीं किये जा सकेंगे। पहला प्रश्न जमीन के बिखरे हुए ढुकड़ों की चक्रबन्दी का है और दूसरा भविष्य में जमीन के बटवारे को रोकने का है।

चक्रबन्दी दो तरह से की जा सकती है—सहकारी चक्रबन्दी समितियों द्वारा और कानून के द्वारा। ( देखो चक्रबन्दी समितियाँ )। चक्रबन्दी का अर्थ यह है कि जमीन का इस प्रकार बँटवारा किया जावे कि किसान की जितनी कुल जमीन है वह एक चक्र में आ जावे। मान लो 'अ' किसान के एक ढुकड़े के पास 'क' 'ख' और 'ग' के ढुकड़े हैं। चक्रबन्दी का योजना के अनुसार 'अ' को 'क' 'ख' 'ग' के ढुकड़े दे दिये जावेंगे जो उन खेतों के

सहकारी चकबंदी समिति की स्थापना तभी हो सकती है कि जब सब लोग नये बँटवारे को मानें । किन्तु कानून बना कर जो चकबंदी की जाती है उसमें यदि अधिक लोग नये बँटवारे को मान लेते हैं तो वह चकबंदी की योजना गाँव भर में लागू कर दी जाती है ।

खेतों के बिखरे होने का मुख्य कारण यह है कि भारत में खेती योग्य भूमि का अकाल पड़ गया है । बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उदर-पूर्ति का दूसरा कोई साधन नहीं रहा । गृह-उद्योग-धंधे ( Cottage-industries ) मर चुके हैं और आधुनिक कारखानों में देश की केवल एक प्रतिशत जनसंख्या काम पा सकी है । इसका परिणाम यह हुआ है कि खेती पर जरूरत से ज्यादा लोग निर्भर हैं । दूसरे शब्दों में भूमि पर जन-संख्या का भार बेहद बढ़ गया है । भारत में आज हालत यह है कि फी किसान पीछे केवल अढ़ाई एकड़ भूमि का औसत पड़ता है ।

खेती की सफलता के लिए किसान के पास इतनी जमीन का होना नितान्त आवश्यक है कि जिस पर उसके श्रम और साधनों का पूरा-पूरा उपयोग होने की पूर्ण संभावना हो । भारत में एक किसान को कम से कम एक जोड़ी बैल तो रखने ही पड़ते हैं, इनके सिवाय एक औसत कुटुम्ब में पाँच प्राणी होते हैं; ऐसी हालत में खेती में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिये एक किसान के पास इतनी भूमि होना आवश्यक है कि जिस पर एक जोड़ी बैल और कुटुम्ब के सब व्यक्तियों के श्रम का पूरा उपयोग हो सके । इतनी भूमि को 'आर्थिकजोत' ( Economic holding ) कहते हैं ।

भारतीय किसान के पास इससे बहुत कम जमीन है और वह भी एक जगह (चक) में नहीं, छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी रहती है और दूर-दूर बिखरी होती है ।

जनसंख्या के बढ़ने और उद्योग-धंधों में जनसंख्या को काम न मिलने से प्रत्येक व्यक्ति को भूमि पर निर्भर होना पड़ा, जिससे भूमि का बँटवारा जरूरी हो गया । संयुक्त कुटुम्ब की संस्था के टूटने से भी बँटवारा जरूरी हो गया ।

उदाहरण के लिए हम एक सम्पन्न किसान को लेते हैं जिसके पास दस-दस एकड़ के चार खेत हैं और उसके चार लड़के हैं । उसके मरने पर हर एक लड़का प्रत्येक खेत का एक चौथाई भाग लेगा । क्योंकि चारों

खेतों की जमीन एक सी नहीं होती। इस प्रकार किसान के मरने पर १६ टुकड़े हो जावेंगे। और आगे चलकर इनके और भी अधिक टुकड़े हो सकते हैं !

अतएव हमारे सामने भूमि-सम्बन्धी दो समस्याये हैं। एक तो प्रति किसान भूमि का बहुत कम होना जिस पर, लाभदायक खेती नहीं हो सकती। दूसरी खेतों के बिखरे होने की समस्या। पहली समस्या तो तभी हल होगी जब कि देश में उद्योग-धन्धों की उन्नति हो और खेतों में लगे हुए जरूरत से ज्यादा लोग उनमें काम पा सकें। बिखरे हुए खेतों की समस्या चकबन्दी से हल हो सकती है। लेकिन चकबन्दी हो जाने से उस भूमि का आगे विभाजन नहीं होगा यह कोई ठीक नहीं। यदि एक बार चकबन्दी कर देने पर भूमि का फिर विभाजन हो जावे तो फिर किया-धरा सब नष्ट हो जावेगा। इसलिये जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा कानून बना दिया जावे कि एक सीमा के बाद भूमि का बँटवारा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए यदि १० एकड़ भूमि को 'आर्थिक जोत' (Economic Holding) माना जावे तो यदि किसी के पास केवल १० एकड़ भूमि है तो उसके मरने के बाद उसका बँटवारा न हो सके। लेकिन यह सब तभी हो सकता है जब कि देश में उद्योग-धन्धों की उन्नति हो और जरूरत से ज्यादा खेतों में लगी हुई जनसंख्या उनमें काम पा सके।

### सामूहिक सरकारी खेती

बिखरे हुए खेतों की समस्या को हल करने तथा वैज्ञानिक ढंग की खेती की सुविधा प्रदान करने का दूसरा व्यावहारिक तरीका सहकारी या सामूहिक खेती है। रूस और पैलेस्टाइन में सहकारी खेतों के द्वारा आश्चर्यजनक सफलता मिली है अतएव भारत में भी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। सहकारी खेती में सब किसान अपनी भूमि, श्रम और औजारों को मिलाकर एक बड़े फार्म के रूप में खेती करते हैं।

यह हम एक दूसरे स्थान पर लिख आये हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्यभारत, पूर्वी पंजाब, मध्यप्रदेश में केन्द्रीय सरकार का ट्रैक्टर विभाग बजर भूमि को तोड़कर उसे खेती योग्य बना रहा है। उस भूमि पर सहकारी खेती की जा रही है। उत्तर प्रदेश में गंगा, खादिर तथा नैनीताल की तराई में सहकारी

खेती का आरम्भ किया गया है इसके अतिरिक्त भाँसी जिले के नैनवारा तथा दारौना गाँवों में सहकारी खेतों का आरम्भ किया गया है । किन्तु सदस्य अभी तक सहकारी खेती के लिए उत्साह नहीं दिखलाते वे व्यक्तिगत खेती करना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बम्बई और बिहार में भी सहकारी खेती के प्रयोग हो रहे हैं ।

### पञ्च-वर्षीय योजना

भारत सरकार ने जो प्लैनिंग कमीशन बिठाया था उसका स्पष्ट मत है कि अन्ततः कृषि का नवीन सङ्गठन करने के लिए भारत को “सहकारी ग्राम व्यवस्था” को अपनाना चाहिये ।

समस्त गाँव की भूमि एक बड़ा फार्म या खेत होगी । उसकी व्यवस्था सहकारिता के आधार पर होगी । जो लोग उस गाँव की भूमि के स्वामी होंगे उन्हें भूमि के स्वामी होने के कारण प्रत्येक फसल पर “स्वामित्व लाभ” जो भी निश्चित कर दिया जावेगा मिल जायेगा । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि को सहकारी फार्म में मिलाना होगा और सामूहिक खेती करनी होगी । खेत पर भूमि के स्वामी तथा खेत-मजदूर सभी कार्य करेंगे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्यक्षमता के अनुसार मजदूरी दी जावेगी । भूमि के मालिकों को मजदूरी के अलावा “स्वामित्व लाभ” और मिलेगा ।

सहकारी ग्राम-व्यवस्था उस गाँव में लागू कर दी जावेगी जिसमें कम से कम दो तिहाई भूमि के स्वामी जिनके पास कम से कम गाँव की दो तिहाई भूमि हो इस व्यवस्था के पक्ष में हों ।

### खाद की समस्या (Manure)

फसल उत्पन्न करने से भूमि कमजोर पड़ जाती है । यदि खाद डालकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये न रक्खा जावे तो कुछ समय के बाद भूमि अनुत्पादक हो जावेगी । खाद का उपयोग केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के ही लिए नहीं किया जाता वरन् भूमि से अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है । गाँव में जितना भी कूड़ा, मैला, पशुओं का गोबर, पेशाब, घास, पेड़ों के पत्ते, बचा हुआ चारा हो, सब खाद के रूप में परिणत किया जा सकता है । परन्तु गाँवों में जो खाद की सामग्री उपलब्ध है वह अधिकतर या तो फेंक दी जाती है या नष्ट हो

जाती है। पशुओं का गोबर तथा पेशाब बहुत बढ़िया खाद में परिणत की जा सकती है। वास्तव में यदि देखा जाये तो गोबर और पेशाब किसान के पास यथेष्ट मात्रा में होती है और यदि थोड़ा सा परिश्रम करके खाद तैयार करले तो उसके खेतों की पैदावार बहुत बढ़ सकती है। परन्तु यह अत्यन्त मूल्यवान् खाद या तो कडे (उपली) बनाकर किसान अपने घर में ही जला डालता है अथवा बाजार और शहरों में बेचकर कुछ पैसा कमाता है। किसानों की स्त्रियाँ गोबर के कडे न बनावे तो जहाँ वे उसके द्वारा कुछ पैसों की बचत करती है उसके एवज में उन्हें अधिक फसल के रूप में कई गुना अधिक लाभ हो सकता है। वर्षा में जब कड़ा बन ही नहीं सकते तब किसान गोबर का उपयोग खाद बनाने में करता है और शेष आठ महीने वह कडे बनाकर जलाता है, यदि खेती की पैदावार को बढ़ाना है तो किसान को पशुओं का गोबर खेतों में डालना होगा। केवल गोबर ही नष्ट होता हो यही बात नहीं है। कूड़ा, चारा, पेड़ की पत्तियाँ तथा अन्य वस्तुएँ जिनकी खाद बनाई जा सकती है, वे भी गाँवों में नष्ट हो जाती हैं और उनकी खाद नहीं बनाई जाती। हवा, पानी तथा पशु इस मूल्यवान् खाद को नष्ट कर देते हैं। किसान जो भी खाद इस समय तैयार करता है वह ढेर लगा कर करता है। हवा कुछ खाद को उड़ा ले जाती है, वर्षा के दिनों में बहुत सा कूड़ा इत्यादि बह जाता है और पशु तथा मनुष्यों के पैरों से खाद इधर-उधर बिखरती है। साथ ही ढेर लगाकर अच्छी खाद तैयार नहीं होती है। खाद को तैयार करने का सबसे अच्छा उपाय गड्ढों में खाद तैयार करना है। इससे तीन बड़े लाभ होंगे। गाँव का कूड़ा, गोबर, पेशाब, चारा या घास पत्ती कुछ भी खराब नहीं जावेगा, एक बार वह गड्ढे में डाल दिए जाने पर सुरक्षित रहेगा। दूसरे, गाँव में गंदगी नहीं रहेगी। तीसरे, खाद अच्छी तैयार होगी।

खाद की समस्या को हल करने का सबसे उत्तम उपाय यह है कि किसान को गोबर जहाँ तक हो सके न जलाने के लिए कहा जावे और खाद के गड्ढों (Manure Pits) में खाद तैयार करने के लिए कहा जावे। लेकिन गाँव में ईंधन की बहुत कमी है। गाँव वालों से यह आशा करना कि वे ईंधन को मोल लेकर जलावेगे, भूल होगी। फिर जब गाँव में ईंधन के

लिए लकड़ी की कमी है तो यदि कड़े ( उपले ) जलाना बन्द कर दिया जावेगा तो फिर ईंधन का प्रबन्ध कैसे होगा। अतएव जब तक गाँवों में अधिक लकड़ी उत्पन्न नहीं कर दी जाती तब तक गोबर का जलाना बन्द नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि हर गाँव में ऊसर तथा बजर भूमि पर जङ्गल का मुहकमा ऐसे वृक्ष उत्पन्न करे जो जल्दी बड़े होते हों और गाँव की पचायत उस छोटे से जङ्गल के टुकड़े की देखभाल करे। उस जङ्गल के टुकड़े में जो घास और लकड़ी पैदा होगी, हर गाँव वाले को उसमें से अपने काम के लिए लकड़ी काटने और घास छीलने का अधिकार हो। उसमें कोई अपने पशु न चरा सके। इससे गाँव में ईंधन और चारे की समस्या हल हो सकती है और तभी गोबर खाद के लिए बचाया जा सकता है।

### मल की खाद

स्वास्थ्य के परिच्छेद में कहा जा चुका है कि यदि गाँव में एक और सार्वजनिक शौच कूप (Pit Latrines) बना दिया जावे तो गाँव गन्दगन्धि से भी बच सकता है। साथ ही कुछ खाद भी मिल सकती है। कुछ लोग मल की खाद को छूने से हिचकते हैं और उसे काम में नहीं लाते, किन्तु प्रचार करने से यह कठिनाई दूर हो सकती है। बड़े-बड़े नगरों में वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा मल को दुर्गन्ध रहित और सूखा बनाया जा सकता है क्योंकि वहाँ बहुत राशि में मल होता है।

### हरी खाद ( Green Manure )

किसान यदि चाहे तो जहाँ वर्षा अधिक होती हो अथवा जहाँ पानी आसानी से मिल सकता हो वहाँ हरी खाद का भी उपयोग कर सकता है। ढ़ैचा, सन, मूँगफली, गवार तथा कुछ दूसरी फसलें ऐसी हैं जिन्हे पैदा करके जोत देने में खेत उर्वर हो जाता है किन्तु यह खाद तभी उपयोगी हो सकती है जब कि भूमि में खूब नमी हो, बिना पानी के खाद देना हानिकारक है।

### अन्य प्रकार की खाद

पशुओं का मूत्र भी बहुमूल्य खाद है, किन्तु भारतीय किसान उसका तनिक भी उपयोग नहीं करता है। उसको चाहिये कि वह अपने पशुओं को

खेत पर ही बाँधे, यदि हो सके तो वह पशुओं के बाँधने के स्थान पर मिट्टी बिछा दिया करे और उस मिट्टी को खेत में डाले ।

यही नहीं घास-फूस, सूखी पत्तियाँ इत्यादि सभी को खाद में परिणत किया जा सकता है ।

### सिधरी ( विहार ) का कारखाना

भारत में भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद की बहुत अधिक आवश्यकता है । इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने विदेशी विशेषज्ञों के परामर्श से विहार में सिंदरी नामक स्थान में कृत्रिम खाद बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया है । इसको बनाने में ३८ करोड़ रुपए व्यय हुआ है । अब यह कारखाना लाखों टन खाद तैयार करने लगा है जो सस्ते दामों पर खेती के लिए दी जा रही है ।

### भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाये रखने के दूसरे साधन फसलों का हेर-फेर ( Rotation of Crops )

फसल उत्पन्न करने से भूमि के कुछ तत्व कम हो जाते हैं तो फसल कुछ अन्य तत्वों को भूमि में बढ़ा भी देती है । अस्तु, अनुभवी किसान फसलों को इस प्रकार उत्पन्न करता है कि जिससे जो तत्व एक फसल के कारण कम हो गये हैं वह दूसरी फसल पूरी कर दे । इसको फसलों का हेर-फेर कहते हैं । भारतीय किसान फसलों के हेर-फेर के सिद्धान्त को प्राचीनकाल से जानता है । लेकिन केवल फसलों के हेर-फेर से ही भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाये नहीं रखा जा सकता । हाँ भूमि की उपजाऊ शक्ति को तेजी से घटने से रोका जा सकता है । यही कारण है कि किसान एक खेत पर लगातार एक सी फसल कई वर्ष तक नहीं पैदा करता । यह बदलता रहता है ।

भूमि को आराम देने से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है क्योंकि भूमि वायु से नाइट्रोजन इत्यादि तत्वों को ले लेती है । लेकिन इस देश में घनी आबादी के लिए भोजन इत्यादि उत्पन्न करने के कारण भूमि को यथेष्ट आराम नहीं दिया जा सकता ।

युद्ध के उपरान्त देश में जो भोजन का अकाल पड़ा है उससे सरकार

तथा जनता सभी का ध्यान पैदावार बढ़ाने की ओर गया है और सरकार ने विशेषज्ञों को बुलाकर खाद के सम्बन्ध में जाँच करवाई है। अब सरकार के प्रोत्साहन से ऐसे कारखाने स्थापित करने का प्रयत्न हो रहा है जो नाइट्रोजन से खाद उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार देश में खाद की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

फिर भी जब तक हम किसान को अपने पशुओं के गोबर, घर के कूड़े, बचा हुआ घास-फूस तथा पशुओं के मूत्र से बढ़िया खाद बनाने के लिये उत्साहित नहीं करते तब तक खाद की समस्या हल नहीं हो सकती।

### पशुधन (Cattle)

किसान की सबसे महत्वपूर्ण पूँजी उसके गाय और बैल हैं। जब तक किसान के बैल कमजोर हैं और गाय यथेष्ट दूध नहीं देती तब तक खेती बारी की दशा सुवर नहीं सकती। गाय और बैलों की उन्नति कैसे हो सकती है, यह हम पिछले अध्याय में ही लिख चुके हैं।

### खेती के यन्त्र (Agricultural Machinery)

भारत के छोटे खेतों में ट्रैक्टर\* तथा अन्य बड़े-बड़े यन्त्र काम नहीं दे सकते, अतएव भारत में इनका अधिक प्रचार नहीं हो सकता। कारण यह है कि छोटे-छोटे खेतों पर बड़े-बड़े यन्त्र न तो लाभदायक ही सिद्ध होंगे और न किसान उन्हें रख ही सकता है। जो सैकड़ों वर्षों से भारतीय किसान अपना देशी हल तथा अन्य यन्त्र काम में ला रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि देशी औजार उसकी स्थिति को देखते हुए अधिक उपयोगी है। देशी हल तथा औजारों में निम्नलिखित गुण हैं। १—वे बहुत सस्ते हैं, निर्धन किसान हल तथा अन्य औजारों पर अधिक व्यय नहीं कर सकता। २— वे बहुत हलके होते हैं। किसान देशी हल को अपने कंधे पर उठा कर एक खेत से दूसरे खेत पर ले जा सकता है। ३—देशी हल तथा औजार बहुत सादे होते हैं। किसान को उनके उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ४—गाँव के बढई और लोहार देशी हल और औजारों की मरम्मत

---

\*ट्रैक्टर—भूमि को जोतने के लिये भाप या तेल से चलने वाली बड़ी मशीन।



भूली-भाँति कर लेते हैं। परन्तु आधुनिक यन्त्रों की मरम्मत गाँव के बटई और लोहार न कर सकेंगे। ५—देशी हल हलके होने के कारण किसान के कमजोर बैलों से खिंच जाते हैं परन्तु बहुत भारी हल या कोल्हू इन निर्बल बैलों से खिंच ही नहीं सकते।

यही कारण है कि आरम्भ में जब कृषि-विभाग ने विदेशी हलों और यन्त्रों का भारत में प्रचार करना चाहा तो वे सफल नहीं हुए। किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि देशी हलों, औजारों में तनिक भी सुधार की आवश्यकता नहीं। सुधार की आवश्यकता है, किन्तु ऊपर लिखी हुई बातों को ध्यान में रखकर ही सुधार करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि विभाग का इंजिनियरिंग विभाग ऐसे हलों और औजारों का निर्माण करे जो सस्ते हों, हलके हों और सादे हों। इस प्रकार के हलों और औजारों का आविष्कार करके जो ऊपर लिखी बातों को पूरा करे और भूमि को देखते हुए उपयोगी सिद्ध हों उन्हें अधिक संख्या में बनाने के लिए कारखाने खोले जावें, जिससे कि वे सस्ते से सस्ते दामों पर बेचे जा सकें। कृषि-विभाग ने अपनी पुरानी नीति को छोड़ कर अब यह नीति बनाई है, किन्तु इस दिशा में अधिक काम नहीं हुआ है। मैसूर, हिन्दुस्तान, हिसार, राजा इत्यादि कुछ हल हैं जिनका कृषि-विभाग प्रचार कर रहे हैं। परन्तु अभी इन हलों में भी सुधार की आवश्यकता है। कोल्हू, गुड तथा शक्कर बनाने के यन्त्र, चारा काटने के औजार, तथा अन्य प्रकार के औजार भी तैयार किए गये हैं, जिनका अधिकाधिक प्रचार करने की आवश्यकता है। हाँ, जब सहकारी फार्म (Cooperative Farm) स्थापित हों, तब बड़े यन्त्र काम दे सकते हैं।

### सरकार का केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग

भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेकर बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि यन्त्र मँगवाये हैं। यह विभाग प्रत्येक प्रादेशिक सरकार को यह यन्त्र वहाँ बजर भूमि खेती योग्य बनाने के लिए देता है। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और मध्यभारत में इन ट्रैक्टरों की सहायता से बजर भूमि को खेती योग्य बनाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त भारत में

जमींदारों ने ट्रैक्टरों का खेती में अधिकाधिक उपयोग करना आरम्भ कर दिया है ।

### बीज ( Seed )

यह तो सभी जानते हैं कि कि किसान खेत में जैसा बीज डालेगा, वैसी फसल तैयार होगी । खराब बीज डालकर कोई अच्छी फसल उत्पन्न नहीं कर सकता । इस समय अधिकतर किसान, महाजन अथवा गाँव के जमींदार से सवाए ढ्योढ़े पर बीज लेकर खेत में बोते हैं । महाजन खत्तियों में भरा हुआ रहो और घुना बीज किसान को उधार देता है । खराब बीज के कारण किसान की फसल भी अच्छी नहीं होती । बीज को समस्या को हल करने के लिये दो बातें मुख्य हैं । प्रथम अच्छा बीज उत्पन्न करना, दूसरे उस बीज को किसानों को देना । भिन्न-भिन्न प्रदेशों के कृषि-विभागों ने मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण फसलों के बीज की लगातार अनुसंधान करने के उपरान्त आशा-तीत उन्नति की है । प्रदेशों के कृषि-विभागों ने कपास, गेहूँ, गन्ना, चावल तथा जूट के बीजों में आश्चर्यजनक उन्नति की है किन्तु अभी मोटे अनाज ( मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ तथा भिन्न-भिन्न दालों ) तथा सन इत्यादि के उत्तम बीज तैयार नहीं किये गये हैं । उत्तम बीज तैयार करने का कार्य विशेषज्ञों का है, और आशा है कि धीरे-धीरे कृषि-विभाग ऊपर लिखी हुई फसलों के लिये उत्तम बीज उत्पन्न करेगा । परन्तु बीज की सबसे कठिन समस्या बीज का किसानों को देना है । यद्यपि कृषि-विभाग सीड-डिपो ( बीज भंडार ) खोल कर गाँव वालों को उत्तम बीज देने का कार्य कर रहा है । परन्तु यह सर्वमान्य बात है कि बीज देने का कार्य कृषि-विभाग पूरी तरह नहीं कर सकता । इस समय कृषि-विभाग अपने फार्मों पर, जमींदारों तथा किसानों के खेतों पर, अपना देख-रेख में उत्तम बीज को उत्पन्न करवा कर, अपने बीज-भंडारों के द्वारा उसे किसानों को बेच देता है । सहकारी समितियाँ तथा ग्राम-सुधार के कार्यकर्त्ता भी इस कार्य में कृषि-विभाग की सहायता करते हैं । परन्तु यह निश्चित है कि कृषि-विभाग प्रतिवर्ष असंख्य किसानों को उत्तम बीज यथेष्ट मात्रा में नहीं दे सकता ? अतएव प्रत्येक किसान को एक बार उत्तम बीज कृषि-विभाग से लेकर स्वयं प्रतिवर्ष अपना बीज तैयार करना चाहिये । जिस खेत पर बीज तैयार करना हो उसे अच्छी तरह से जोतना तथा

उस पर खाद डालना चाहिये । यदि प्रत्येक गाँव में किसान अपने लिये बीज तैयार कर ले तो अच्छे बीज की समस्या हल हो सकती है । परन्तु कुछ समय के उपरान्त उत्तम बीज भी खराब होने लगता है, अतएव चतुर किसानों को सतर्कतापूर्वक यह देखते रहना चाहिये कि उनका बीज खराब तो नहीं होता जा रहा है । यदि उन्हें बीज के खराब होने के चिह्न दृष्टिगोचर हों तो कृषि-विभाग से दूसरा उत्तम बीज लेकर फिर कुछ वर्षों तक उसे अपने खेतों पर पैदा करके प्रतिवर्ष बोते रहना चाहिये । किसान को अपने बीज को शुद्ध बनाने का सदा प्रयत्न करना चाहिये ।

कृषि-विभाग द्वारा दिया हुआ बीज कुछ अधिक कीमती होता है । किसान को इसकी चिन्ता न करनी चाहिये । बीज का थोड़ा अधिक मूल्य देकर भी उत्तम बीज खरीदना चाहिये । फिर वह स्वयं प्रति वर्ष बीज - बचा कर रख सकता है, या किसी ऐसे पड़ोसी से वह उत्तम बीज ले सकता है कि जिसने उसको बोया हो । जो कुछ भी हो किसान को बीज अच्छा ही डालना चाहिये ।

### सिंचाई (Irrigation)

भारत के अधिकांश प्रदेशों में खेती के लिये सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्षा यथेष्ट नहीं होती और यदि वर्षा होती है, तो वह वर्षा के केवल तीन या चार महीनों में, अतएव रबी की फसल बिना सिंचाई के हो ही नहीं सकती । आसाम, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमीघाट के समुद्रतट के मैदान को छोड़ कर किसी भी प्रदेश में खेती सिंचाई के बिना नहीं हो सकती । अधिकतर प्रदेशों में तो पानी का अकाल रहता है, परन्तु फिर भी किसान वर्षा से जितना लाभ उठाया जाना चाहिये, नहीं उठाता ।

### वर्षा का जल (Rain-water)

गाँवों में भूमि बहुत ऊबड़-खाबड़ होती है, कहीं-कहीं बड़े गहरे नाले बन जाते हैं और कहीं भूमि अधिक ऊँची और अधिक नीची होती है । इसका फल यह होता है कि वर्षा का जल भूमि पर गिरते ही बड़ी तेजी से बहता है । उन प्राकृतिक नालों तथा निचली भूमि के कारण उसकी तेजी और भी बढ़ जाती है । जहाँ ऊबड़-खाबड़ जमीन अधिक होती है वहाँ वर्षा के दिनों में ऐसा प्रतीत होता है कि मानों कोई बड़ी नदी तेजी से बहती हो । उस क्षेत्र

का सारा जल शीघ्रतापूर्वक बह जाता है और साथ ही वह भूमि के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है। पानी उस क्षेत्र पर अधिक देर तक नहीं ठहरता, अतएव भूमि वर्षा के जल को सोखने में असमर्थ रहती है। भूमि के अन्दर यथेष्ट जल न जाने से भूगर्भ में बहने वाला जल-स्रोत सूखता है, और अधिक गहराई पर चला जाता है जिसके कारण कुएँ वेकार हो जाते हैं। प्रदेश के ऊबड़-खाबड़ होने से केवल इतनी ही हानि नहीं होती। इससे भी भयंकर हानि यह होती है कि शीघ्रतापूर्वक बहने के कारण जल कटाव करता है, अर्थात् भूमि को काटता है ( Erosion of soil )। धीरे-धीरे और अधिक नाले बन जाते हैं और जल का उपद्रव और भी अधिक हो जाता है। कुछ समय के उपरान्त वह सारा प्रदेश ऊबड़-खाबड़ भूमि का रूप धारण कर लेता है और खेती के अयोग्य बन जाता है। जल के कटाव से भूमि की रक्षा करने का एकमात्र साधन यह है कि उस ऊबड़-खाबड़ प्रदेश में वृक्ष लगाये जावें और इस प्रकार जल को भूमि नष्ट करने से रोका जावे। इसके अतिरिक्त यदि गाँव की भूमि को समतल तथा चौरस करा दिया जावे और चारों ओर ऊँची मेड़ बना दी जावें तो वर्षा का जल बहुत देर तक पृथ्वी पर रहने के कारण भूमि उसे अधिक सोख ले। परन्तु यह तभी हो सकता है, जब कि सारा गाँव संगठन के रूप में इस कार्य को करे। इससे तीन बड़े लाभ होंगे, एक तो भूमि यथेष्ट जल पी लेगी जिससे सिंचाई की कम आवश्यकता होगी, दूसरे उस क्षेत्र के कुओं में सिंचाई के लिए यथेष्ट जल रहेगा, तीसरे भूमि का नाश नहीं होगा।

### कुओं के द्वारा सिंचाई ( Well Irrigation )

भारत में कुएँ सिंचाई के मुख्य आधार हैं। यद्यपि नहरों के द्वारा भी यथेष्ट सिंचाई होती है परन्तु कुओं का महत्व इस कारण है कि उनके द्वारा किसान सिंचाई के लिये स्वतंत्र हो जाता है। वह जब चाहे सिंचाई कर सकता है। कुओं का पानी नहर के पानी से फसल के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अतएव जब किसी भी प्रदेश में मीठा पानी साधारण दूरी पर मिलता है वहाँ कुओं के द्वारा ही सिंचाई होनी चाहिये।

जहाँ नहरे हैं वहाँ भी कुएँ खोदे जाने चाहिए जिससे किसान हर समय पानी पा सके ।

कुएँ से पानी निकालने के लिये भारत में रँहट तथा चरसा दो साधनों का उपयोग होता है । रँहट ( Persian Wheel ) से एक लाभ यह है कि एक ही आदमी रँहट चला सकता है यहाँ तक कि एक छोटा लड़का भी रँहट को चला सकता है । रँहट में लडके को केवल बैलों को हॉकने का ही काम होता है । परन्तु चरसा में दो आदमियों की आवश्यकता होती है । एक बैलों को हॉकता है, दूसरा चरसा ( पुर ) को लेता है । राजस्थान तथा मध्यभारत में चरसा ( पुर ) के निचले भाग में चमड़े का एक मोटा-नल और जुड़ा रहता है, उस नल का मुँह एक पतली डोरी से बंधा रहता है । डोरी का सिरा बैल हॉकने वाले के हाथ में रहता है । जब पुर कुएँ के ऊपर आ जाता है तो बैल हॉकने वाला उस डोरी को ढीला कर देता है और पुर का पानी उस चमड़े के नल द्वारा गिर पड़ता है । इस प्रकार पुर को लेने वाले मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती । फिर जो कुएँ बहुत गहरे नहीं हैं उन पर रँहट लगाना ही अधिक सुविधाजनक होता है ।

### उत्तर प्रदेश में ट्यूब वेल (Tube Wells in U. P.)

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने लगभग दो करोड़ रुपये व्यय करके १६५० ट्यूब-वेल खुदवाये हैं और भी खोदे जा रहे हैं । बदायूँ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद जिलों में बहुत बड़ी संख्या में ट्यूब-वेल खोदे जा रहे हैं और गंगा जी की नहर के जल से तैयार की हुई बिजली के द्वारा यह ट्यूब-वेल चलते हैं । ट्यूब-वेल लगभग एक हजार एकड़ भूमि को सिंच सकता है । ट्यूब-वेल के द्वारा सिंचाई करने में दो लाभ हैं । प्रथम तो किसान को जब वह चाहे तब सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है । नहर की भाँति वह इस आशा में बैठा नहीं रहता कि जब नहर में जल आवेगा तब सिंचाई हो सकेगी । इसका फल यह होता है कि जब नहर में पानी आता है तो किसान आवश्यकता से अधिक पानी खेत में देता है जिससे फसल को हानि पहुँचती है । क्योंकि किसान को यह ज्ञान नहीं होता है कि अब नहर में कब पानी आवेगा । नहर का पानी अनिश्चित है और ट्यूब-वेल का पानी निश्चित है । ट्यूब-वेल के द्वारा सिंचाई करने

पर जितना भी किसान लेता है सबका उपयोग हो जाता है, इस कारण किसान पानी को किफायत से खर्च करता है। ट्यूबवेल से एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि गाँवों में जहाँ पाने के लिए शुद्ध जल की कमी है वहाँ शुद्ध जल मिल सकेगा। यदि प्रत्येक ट्यूब-वेल पर रेडियो लगा दिया जावे तो गाँवों के नीरस जीवन में मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धन का एक अच्छा साधन उपलब्ध हो सकता है। ट्यूब-वेल के द्वारा एक लाभ और भी है— अर्थात् जिन जिलों में होकर नहरें गई हैं उनमें नहरों के दोनों ओर ट्यूब-वेल बना पानी नहरों में डाल दिया जाता है जिसमें नहरों में प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए यथेष्ट पानी हो जाता है। पश्चिमी जिलों में वर्षा कम होती है और साधारणतः नहरों में भी वहाँ के लिए यथेष्ट जल नहीं रहता। बात यह है कि पूर्वी जिलों में ही नहर का जल बहुत कुछ समाप्त हो जाता है। जब पश्चिमी जिलों में नहरें पहुँचती हैं तो उनमें यथेष्ट जल नहीं रहता। अब और जिलों में ट्यूब-वेल खोदे जावेंगे। प्रादेशिक सरकार अब इस योजना को पूर्वी जिलों में चला रही है।

### नहर के द्वारा सिंचाई ( Canal Irrigation )

नहरों के द्वारा सिंचाई उत्तर के प्रदेशों में बहुत होती है। पू० पंजाब तथा उत्तर प्रदेश बहुत कुछ नहरों पर ही अवलम्बित है। किसान नहर के पानी का कभी-कभी दुरुपयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक पानी खेत में दे देते हैं। कुएँ के पानी को किसान बहुत सावधानी तथा सतर्कता से खर्च करते हैं, किन्तु नहर के पानी के प्रति वे उदासीन रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है, कि प्रत्येक फसल के लिए प्रति बीघा आवपाशी की दर निश्चित कर दी गई है। उदाहरण के लिए यदि एक किसान ईख की सिंचाई करता है और प्रति बीघा कम पानी खर्च करता है तो उसकी आवपाशी प्रति बीघा उतनी ही देनी होगी जितनी कि एक दूसरा किसान देता है यद्यपि वह पहले किसान से कहीं अधिक पानी खर्च करता है। अतएव प्रत्येक किसान को यही लालच होता है कि वह अधिक से अधिक पानी खर्च करे इससे भूमि की हानि होती है। अनुमान किया जाता है कि उत्तर प्रदेश तथा पू० पंजाब में जितनी भी नहरें निकल सकती थीं निकाल दी गईं।

## तालाब ( Tanks )

पहाड़ी प्रदेशों में अधिकतर बाँध बनवाकर वर्षा के जल को रोक लिया जाता है और उससे सिचाई की जाती है। राजपूताने के दक्षिणी भाग, मालवा, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में अधिकतर तालाबों से ही सिचाई होती है, क्योंकि नहरे वहाँ निकाली ही नहीं जा सकतीं। कुओं से सिचाई अवश्य होती है परन्तु कुओं को खोदना तथा उनको बनाना इन पहाड़ी प्रदेशों में असाध्य है। राजस्थान तथा मध्य भारत में जहाँ राज्यों ने बड़े-बड़े बाँध और तालाब सिचाई के लिए बनवाये हैं वहाँ गाँव वालों ने सामूहिक रूप से भी छोटे-छोटे बाँध बनाकर सिचाई के साधन उपलब्ध कर लिये हैं। इन तालाबों की मरम्मत भी गाँव वाले मिल कर स्वयं करते हैं। साधारणतः यह नियम होता है कि गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को एक घन फुट मिट्टी बाँध पर डालनी पड़ती है। दक्षिण में ब्रिटिश शासन से पूर्व इस प्रकार के हजारों छोटे-छोटे बाँध ( पट बंधा ) गाँव वाले बना लेते थे किन्तु ब्रिटिश शासन काल में वे तालाब नष्ट हो गये। प्रयत्न करना चाहिये कि किसान इस प्रकार सामूहिक रूप से वर्षा के जल का जितना भी उपयोग कर सके उतना करे।

यदि कहीं भूमि बहुत ऊँची है और नदी, तालाब अथवा नहर बहुत नीचे पर हैं, वहाँ बिजली, आयल ऐंजिन अथवा रूँहट जो भी सुविधाजनक तथा प्राप्त हो, उसका उपयोग पानी को ऊपर उठाने में किया जा सकता है। बिजली का उपयोग तो उसी क्षेत्र में किया जा सकता है। जहाँ वह सस्ते दामों पर उत्पन्न की जाती हो। यह कार्य केवल सरकार कर सकती है। आइल ऐंजिन जमींदार तथा समृद्धिशाली किसान लगा सकते हैं। रूँहट का उपयोग प्रत्येक किसान कर सकता है।

यह अति आवश्यक है कि देश में खाद्य-पदार्थों की उपज बढ़ाई जाय। हमारे यहाँ खेती की एक मुख्य कठिनाई सिचाई भी है। नहरों और बाँधों की व्यवस्था करने में कई वर्ष लगेंगे। अतः इस बीच में तालाबों की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। सन् १९४८ से उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों की सरकारों ने तालाब खुदाई आन्दोलन आरम्भ किया है। पिछली कई

शताब्दियों से हमारे तालाबों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। अतः तालाब मिट्टी से भर गये हैं और टूटी-फूटी अवस्था में हैं। प्रादेशिक सरकार इन तालाबों की पुनः खुदाई और मरम्मत तथा नए तालाबों की खुदाई के लिये प्रयत्नशील है। वह देहातियों के सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ा रही है।

देश में उद्योग धंधे तथा खेती की उन्नति करने के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी नदी-योजनाओं को हाथ में लिया है जिनसे प्रचुर मात्रा में सिंचाई होगी तथा जलविद्युत् उत्पन्न होगी। इनमें दामोदर घाटी योजना ( बिहार में ), हीराकुंड योजना ( उड़ीसा में ), कोसी योजना ( बिहार और नैपाल में ), नायर बांध और रिहाड बांध ( उत्तर प्रदेश में ), भाखरा तथा नानगल बांध पूर्वी पञ्जाब में तथा तु गमद्रा योजना ( मद्रास और हैदराबाद में ) मुख्य हैं। इनका विस्तृत विवरण भारत का आर्थिक भूगोल में देखिये। इनके बन कर तैयार हो जाने पर लाखों एकड़ भूमि सींची जा सकेगी और खेती का विकास होगा। सिंचाई के अतिरिक्त इनके द्वारा जलविद्युत् गाँव-गाँव पहुँचा दी जावेगी।

### साख ( Credit )

प्रत्येक धन्धे में साख की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन-कार्य ( Production ) में लगे हुये प्रत्येक व्यक्ति को पूँजी ( Capital ) की आवश्यकता होती है। किसान को खेती के लिए ऋण लेना पड़ता है। परन्तु भारत में किसान इतना गरीब है कि उसे अनुत्पादक ( Unproductive ) तथा उत्पादक ( Productive ) सभी कार्यों के लिये महाजन से ऋण लेना पड़ता है। महाजन किसान की गरीबी का अनुचित लाभ उठा कर उससे बहुत अधिक सूद लेता है। ऋण इस लिए लिया जाता है कि उससे खेती की जावे और खेती के लाभ से सूद सहित ऋण चुका दिया जावे। परन्तु यदि सूद इतना अधिक हो जितना कि खेती से लाभ हो ही न सके तब तो ऐसा ऋण किसान को सदा के लिये ऋणी बना देता है। यही अवस्था भारतीय किसान की है। ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में 'ग्रामीण ऋण तथा उसके कारण' शीर्षक अध्याय में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा।



अतएव किसानों को साख का प्रबन्ध करने के लिये अपने-अपने गाँव में 'कृषि-सहकारी-साख-समिति, ( Co-operative Credit Society ) की स्थापना करना चाहिये। "कृषि-सहकारी-साख-समिति" के विषय में एक पृथक् अध्याय में विस्तार-पूर्वक लिखा जायगा।

## श्रम और संगठन (Labour and Organisation)

श्रम और संगठन के अन्तर्गत किसानों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, फसलों के शत्रु तथा पैदावार को बेचने की समस्याओं का वर्णन होगा। ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य तथा उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में हम पूर्व ही लिख चुके हैं। जब तक किसानों का स्वास्थ्य अच्छा न होगा और उन्हें शिक्षित नहीं बनाया जावेगा तब तक वे अच्छे खेतिहर नहीं बन सकेंगे।

## फसलों के शत्रु (Enemies of crops)

केवल अच्छे बीज, खाद और हल-बैल से ही खेती-चारी की उन्नति नहीं हो जावेगी। यदि एक ओर फसलों को अच्छा बनाने का प्रयत्न किया जावे और दूसरी ओर फसलों के शत्रु उसे नष्ट कर दे तो सारा प्रयत्न निष्फल हो जावेगा। अतएव फसलों को उनके शत्रुओं से बचाने की बहुत आवश्यकता है। फसलों के दो प्रकार के शत्रु होते हैं। एक तो फसलों के कीड़े जो फसल को नष्ट कर देते हैं दूसरे वे जङ्गली तथा पालतू पशु और पक्षी जो फसलों को खा जाते हैं।

फसलों के कीड़े बहुत भयंकर होते हैं। प्रत्येक फसल का कोई कीड़ा होता है। जिस क्षेत्र में भी कीड़ा लग जाता है उस क्षेत्र की फसल को वह नष्ट कर डालता है। फिर कोई खेत उससे बच नहीं सकता। कभी-कभी तो फसल के कीड़ों का ऐसा भयंकर प्रकोप हो जाता है कि साधारण प्रयत्न से वह जाता ही नहीं। तब कृषि-विभाग को ऐसे बीज उत्पन्न करना पड़ता है जिसमें वह कीड़ा नहीं लग सकता। भारत में ही केवल यह समस्या हो ऐसी बात नहीं है—जर्मनी और अमेरिका जैसे देश में भी फसल के कीड़ों की समस्या उठ खड़ी होती है।

फसल के कीड़े विदेशों से भी आ सकते हैं। इस कारण प्रत्येक देश ने ऐसे कानून बना दिये हैं कि जिससे ऐसी कोई खेती की पैदावार जिसमें बीमारी अथवा कीड़े लगे हों देश में आने से रोकी जा सकती है। सन् १९१४ में भारत में भी एक कानून बना दिया गया जिसके अनुसार यदि बन्दरगाह के अधिकारी किसी खेती की पैदावार को कीड़ों से युक्त पावे तो उसको देश के अन्दर न आने देवे। इस कानून के द्वारा विदेशों से कीड़ों का भारत में आने का भय तो नहीं रहा, किन्तु देश के अन्दर फसलों के कीड़े तथा बीमारियों की कमी नहीं है।

फसल के कीड़ों को नष्ट करने अथवा उन्हें उत्पन्न ही न होने देने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि विभाग तथा किसानों का पूरा सहयोग हो। यही नहीं; आवश्यकता पड़ने पर सारे गाँव को संगठित रूप में कीड़ों को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह ध्यान में रखने की बात है कि यदि इस वर्ष कुछ खेतों में कीड़ा है तो अगले वर्ष वह अन्य खेतों पर भी आक्रमण करेगा। टीड़ी और फसल के कीड़ों को कृषि विभाग के बतलाये हुए उपायों के अनुसार सामूहिक रूप से ही नष्ट किया जा सकता है। इस कार्य में सम्पूर्ण गाँव के सहयोग की आवश्यकता होती है।

साधारणतः फसल में बीमारी अथवा कीड़े लगने के वे ही कारण हैं जो कि मनुष्य के शरीर में रोग की उत्पत्ति के कारण हैं। जो खेत ठीक तरह से जोते नहीं जाते, जिनमें कम खाद डाली जाती है अथवा कम सड़ी खाद डाल दी जाती है, जिस खेत में निराई नहीं होती, आवश्यकता से अधिक अथवा बहुत कम पानी दिया जाता है, उस खेत में फसल निर्बल होती है और उस पर बीमारी तथा कीड़ों का आक्रमण शीघ्र होता है। किसान को निरन्तर फसल पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिये और जैसे ही उसे ज्ञात होता हो कि फसल में बीमारी या कीड़ा लग रहा है उसे तुरन्त कृषि-विभाग से सलाह लेकर उसका इलाज करना चाहिये।

फसल में कीड़ों के लगने का एक मुख्य कारण यह है कि किसान अथवा वे महाजन और जमींदार जो कि खत्तियों और कोठारों में बीज के लिए अनाज भरते हैं, बीज की सफाई का ध्यान नहीं रखते और उन खत्तियों या

कोठारों को ही साफ करते हैं। इसका फल यह होता है कि बीज खराब हो जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, और जब फसल तैयार होती है तो कीड़ा-करोड़ों की संख्या में बढ़कर फसल को नष्ट करता है। बीज तथा बीज-भंडार को कीड़ों से मुक्त करने का यह एक सरल तथा सफल उपाय है कि जहाँ बीज रखा जाता है उसे हर बार जब उसमें बीज भरा जावे साफ कर लिया जावे और बीज को भी साफ कर लिया जावे। इसके उपरान्त उस कोठार को चारों ओर से गीली मिट्टी से बन्द करके अंगीठी में जलते हुए कोयलों पर गधक डाल कर उसे कोठार में रख दिया जावे। जब खूब धुआँ भर जावे तो कोठार का दरवाजा बन्द कर दिया जावे। दो दिन बन्द रखकर कोठार को साफ किया जावे तब उसमें बीज भरा जावे।

परन्तु इतने पर भी यदि किसी के खेत में अथवा अधिक खेतों में कीड़े लग जावे तो उस समय से पूर्व जब कि वे अपनी वंश-वृद्धि करते हैं उनको नष्ट कर दिया जाना चाहिये। उनके अंडे तथा नर और मादाओं जिस प्रकार कृषि विभाग बतलाए अवश्य नष्ट कर डालना चाहिये। इन कीड़ों को नष्ट करने तथा टिड्डी के अंडों और असंख्य टिड्डियों को भूमि में खोद कर निकालने तथा उन्हें खाइयों में दबा कर मार डालने के लिए बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कृषि-विभाग को भिन्न-भिन्न फसलों के कीड़ों को कब और कैसे नष्ट किया जाना चाहिए इसका प्रचार करना चाहिए और गाँव के लोगों को मिलाकर कीड़ों के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। इस कार्य में गाँव के स्काउट ( बालचर ) तथा गाँव की पाठशाला के विद्यार्थियों से खूब सहायता मिल सकती है। गाँव के बालचरों और स्कूल के विद्यार्थियों को यह बतलाया जाना चाहिए कि इन कीड़ों को नष्ट करना गाँव की सबसे बड़ी सेवा है।

जिस खेत में कीड़ा लग चुका हो उसकी फसल काट लेने के उपरान्त उस खेत में आग लगा देनी चाहिए और दूसरे साल नया और अच्छा बीज मोल लेकर खेत में डालना चाहिये। इतना करने पर ही कीड़े को समूल नष्ट किया जा सकता है।

परन्तु जब कोई कीड़ा बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत दिनों तक पनपता रहता

है तब इस प्रकार सारे प्रयत्न करने पर भी वह दूर नहीं होता । उस दशा में कृषि-विभाग को ऐसा बीज उत्पन्न करना चाहिये कि जिसमें वह कीड़ा न लग सके ।

कीड़ों के अतिरिक्त जंगली पशु भी खेती का नुकसान करते हैं । बम्बई प्रदेश में इस समस्या पर विचार करने के लिये एक कमेटी बिठलाई गई थी । उसका अनुमान था कि केवल बम्बई प्रदेश में प्रतिवर्ष जंगली पशुओं के द्वारा सत्तर लाख रुपये की खेती की हानि होती है । सुअर, गीदड़, चूर, जंगली बिलाव, बन्दर तथा अन्य जंगली पशु खेती को नष्ट कर डालते हैं । जंगली पशुओं से फसल की रक्षा करने के दो उपाय हैं । ( १ ) खेतों के चारों ओर काँटेदार झाड़ी अथवा मिट्टी की ऊँची बाढ़ बनाई जावे जिससे कि जंगली जानवर फसल को नष्ट न कर सकें । ( २ ) गाँव वालों को ऐसे जानवरों को मारने के लिए बन्दूक के लायसेंस दे दिये जावें । किन्तु बाढ़ बनाना अथवा कोई काँटेदार झाड़ी खेतों के चारों ओर लगाना श्रमसाध्य तथा खर्चीला है । यदि खेत बिखरे हुए न हों, एक चक्र में हों तो किसान बाढ़ अथवा काँटेदार झाड़ी लगा सकता है ।

### खेती की पैदावार बेचने की समस्या (Marketing of Agricultural Produce)

किसान के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि वह खेत में अधिक पैदावार उत्पन्न करे । अच्छी फसल उत्पन्न करने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह अपनी पैदावार का अधिक से अधिक मूल्य भी प्राप्त करे । यदि किसान खेत में अधिक पैदावार उत्पन्न कर भी ले किन्तु उसको अपनी पैदावार का कम मूल्य मिले तो उसका परिश्रम और व्यय व्यर्थ जावेगा । अतएव किसान को अपनी पैदावार का अधिक से अधिक मूल्य मिलना चाहिये । परन्तु आज कल जैसी अवस्था है उसके कारण किसान को अपनी पैदावार को सस्ते दामों पर बेच देना पड़ता है जैसा कि क्रय-विक्रय सहकायी समितियों की आवश्यकता बतलाते हुये पहिले कहा जा चुका है ।

किसान की निर्धनता उसको सस्ते दामों पर अपनी पैदावार बेचने के लिए विवश करती है । यदि वह किसी महाजन अथवा व्यापारी का श्रृंगी

है तो उसको उस व्यापारी अथवा महाजन के हाथ पैदावार बेचनी होती है। कहीं-कहीं ऋण लेते समय यह बात तय हो जाती है, कि किसान फसल सस्ते दामों पर अपने महाजन को देगा। यदि किसान अपने महाजन को बेचने के लिये बंधा नहीं हो तो भी उसे लगान, आवपाशी तथा ऋण चुकाने के लिए फसल तैयार होते ही बाजार में बेचनी पड़ती है। उस समय भाव गिरा हुआ होता है। अतएव किसान को सहकारी विक्रय समितियों के द्वारा ही अपनी फसल बेचना चाहिये तभी उसको अपनी पैदावार का अच्छा मूल्य मिल सकता है।

### गाँवों की सड़के ( Village Roads )

इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य है। गाँवों में पक्की सड़कें तो हैं ही नहीं, अधिकांश गाँवों की कच्ची सड़कें भी इतनी खराब होती हैं कि गाँव से पैदावार का गाड़ियों में भरकर मंडियों तक लाना बहुत कठिन होता है। बरसात में तो वे दलदल के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती, गाँव की सड़कें खराब होने के कारण गाँव में गमनागमन के साधनों का नितान्त अभाव होता है। यह ध्यान में रखने की बात है कि जब तक गाँवों की सड़कों का सुधार नहीं होता तब तक गाँवों की आर्थिक दशा भी नहीं सुधर सकती। परन्तु गाँव की सड़कों को सुधारने का काम इतना खर्चीला है कि जब तक किसान और जमींदार कुछ स्वयं करने को तैयार न हों तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। किन्तु सड़कों को सुधारने के लिए सारे गाँव को संगठित रूप में प्रयत्न करना होगा। कहीं-कहीं एक से अधिक गाँवों के सहयोग की आवश्यकता होगी। सड़क सुधर जाने पर बैलों की टाँगें और गाड़ियों के पहिये नहीं टूटा करेंगे।

### मंडियों का पुनर्संगठन (Market Reorganisation)

मंडियों में किसान को कई तरह से लूटा जाता है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। दलाल अधिकतर व्यापारी को लाभ कराने का प्रयत्न करते हैं। किसान के दामों में से बहुत सा धर्मादा ( गऊशाला, पाठशाला, मन्दिर, प्याऊ, धर्मशाला इत्यादि के लिये ) तथा मनमाने खर्च काट लिये जाते हैं।

बहुत से स्थानों पर बाँट भारी रख लिए जाते हैं और तौलने में किसानों को धोखा दिया जाता है। कभी-कभी भाव तय हो जाने पर जब किसान गाड़ी खाली कर देता है और तौल शुरू हो जाती है तब यह कह कर कि अन्दर माल खराब निकला उसको मूल्य कम लेने पर विवश किया जाता है। इस प्रकार के अनेक दोष मंडियों में हैं। शाही कृषि कमीशन ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक प्रदेश में मंडी कानून ( Market Act ) बना कर इन दोषों को दूर कर दिया जावे। परन्तु इन दोषों के दूर हो जाने पर भी किसान को तो अपनी पैदावार को सहकारी विक्रय समिति के द्वारा ही बेचना चाहिये।

### किसान को सतर्क तथा परिश्रमी होना चाहिये

खेती में सफलता तभी मिल सकती है जब कि किसान उन सब बातों को अपनावे जिनसे अच्छी फसल उत्पन्न होने की सम्भावना हो और लगकर खेत पर परिश्रम करे। भारत में यद्यपि अधिकांश खेतिहर जातियाँ परिश्रमी हैं किन्तु हिन्दुओं की ऊँची कही जाने वाली जातियों के लोग अच्छे किसान नहीं होते। खेती एक बहुत महत्वपूर्ण धन्धा है। उसको नीचा नहीं समझना चाहिये। किसान को परिश्रम के अतिरिक्त बुद्धि से काम लेना चाहिये। उसे अपनी भूमि की उपजाऊ शक्ति को ध्यान में रखकर वही फसल बोनी चाहिये जिससे उसे अधिक लाभ हो। बाजार की माँग ( Demand ) को भी उसे ध्यान में रखना चाहिये। केवल उसे इसलिए कपास नहीं बोना चाहिये कि वह पहले भी कपास बोता था। उसे कपास की माँग और उसके मूल्य को देखकर ही उसे बोना चाहिये। फसलों के हेर-फेर ( Rotation of Crops ) का उसे पूरा ध्यान रखना चाहिये, जिससे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति घटने न पावे।

### अभ्यास के प्रश्न

१—भारत में खेती की दशा खराब क्यों है ?

२—बिखरे हुए छोटे-छोटे खेतों से क्या हानि होती है ?

३—खेतों की चकबन्दी से क्या लाभ हैं ?

४—किसान गोबर की खाद क्यों नहीं बनाता ? गडहों में खाद तैयार करने से क्या लाभ होगा ?

५—किसान खेती के बड़े-बड़े यन्त्रों और आधुनिक औजारों को काम में क्यों नहीं लाता ?

६—भारत में किसान की जरूरतों को देखते हुये कैसे खेती के औजार और यन्त्र उपयुक्त होंगे ?

७—किसान ज्यादातर कैसे बीज खेत में डालता है ? किसान को अच्छा बीज कहाँ से और कैसे प्राप्त हो सकता है ?

८—वर्षा के जल से भूमि का कटाव ( *Erosion of Soil* ) क्या होता है और उससे क्या हानि होती है ?

९—ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई से क्या-क्या लाभ हैं ? उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में ट्यूबवेल हैं ?

१०—नहर के पानी से जमीन कमजोर क्यों हो जाती है ?

११—फसलों के कौन से शत्रु हैं और उनसे क्या हानि होती है ?

१२—फसलों को उसके शत्रुओं से कैसे बचाया जा सकता है ?

१३—फसलों में कीड़े कैसे लग जाते हैं ?

१४—किसान अपनी पैदावार का अधिक से अधिक मूल्य क्यों नहीं पाता ?

१५—भारत में मंडियों के वर्तमान प्रबन्ध से किसान को क्या हानि है ?

१६—भारत में खेती की उन्नति किस प्रकार हो सकती है । समझा कर लिखिये ।

## तेइसवाँ अध्याय

### मुकदमेबाजी (Litigation)

आज भारत के ग्रामों में ईर्ष्या, द्वेष, कलह का साम्राज्य है। साधारण सी बातों पर फौजदारी हो जाना, लम्बे मुकदमों के कारण घर के घर तबाह हो जाना गाँवों में आये दिन की बात हो गई है। मुकदमेबाजी ग्रामीण के ऋणी होने का एक मुख्य कारण है। भारतीय न्यायालयों में किसानों को किस प्रकार लूटा जाता है यह किसी से छिपा नहीं है। मुकदमेबाजी एक ऐसा भयकर रोग है कि जिसके कारण गाँवों के लोग दिवालिये होते जा रहे हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, श्री एम० एल० डालिङ्ग का तो यहाँ तक कहना है “जिस प्रकार अंगरेजों का जातीय खेल क्रिकेट है उसी प्रकार मुकदमेबाजी भारतीयों का जातीय खेल प्रतीत होता है।” इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह रोग यहाँ बुरी तरह फैला हुआ है।

यह तो सर्वमान्य बात है कि जुर्म करने की भावना का उदय सामाजिक विषमता अथवा समाज की गिरी हुई दशा के कारण होता है। यदि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है वह अच्छा नहीं है तो वह मनुष्य भी अच्छा नहीं बन सकता। भारतीय ग्रामीण जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है उसका परिणाम इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है कि आपस में लड़े और आपस में मुकदमेबाजी करे। भारतीय ग्रामीण अधिकांश में अशिक्षित, ऋण के बोझ से दबा हुआ, अस्वस्थ, निर्धन, फिजूलखर्ची, खराब रस्मों को माननेवाला, कहीं-कहीं नशा पीने वाला, आलसी, मनोरंजन के साधनों से हीन, तथा अत्यन्त गन्दे स्थानों पर रहता है। इस प्रकार के वातावरण में रहकर उसका हमेशा शान्तिप्रिय रहना कठिन है। यही कारण है कि कृषक जो स्वभावतः शान्तिप्रिय होता है कभी-कभी कलहप्रिय हो उठता है और अपना सर्वनाश कर देता है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि गाँवों में मनोरंजन के तथा खेलने के साधन न होने के कारण उसका लड़ने तथा झगड़ने में भी कुछ मन बहलाव होता है, इसी कारण सीधा-सादा किसान कभी-कभी लड़ बैठता है। यदि गाँवों में मनोरंजन के साधन उपलब्ध



हो जावे और गाँवों की दशा में सुधार हो जाये तो लड़ाई-झगड़े तथा मुकदमे-वाजी में बहुत कमी हो सकती है ।

लड़ाई-झगड़े को दूर करने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं :—

(१) लाभदायक कार्य, सुव्यवस्थित मनोरंजन तथा खेल, (२) आकर्षक घर, और (३) संगठित गाँव ।

खेतों का सुधार होने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि किसान को ग्राम उद्योग धन्धे सिखाये जावे जिससे कि वह बेकारी के समय उन धंधों से कुछ कमा ले । इससे यह लाभ होगा कि वह काम में लगा रहेगा और जो साल में चार-पाँच महीने वह बेकार रहता है, वह न रहेगा । इसके अतिरिक्त मनोरंजन तथा खेल-कूद के साधन भी उसको मिलने चाहिये ।

### आकर्षक गृह (Attractive Homes)

केवल इतने से ही काम न चलेगा, हमको गाँव में रहने वालों के घरों को अधिक सुन्दर तथा आकर्षक बना देना चाहिये । जब मनुष्य का घर में मन नहीं लगता है, उसकी स्त्री गृहस्थी को बनाना नहीं जानती, खाना पकाना, घर को सुन्दर और साफ रखना तथा बच्चों का लालन-पालन करना नहीं जानती तथा पति के साथ सहयोग नहीं करती तो पुरुषों में लड़ाई-झगड़े की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । यदि घर सुन्दर और आकर्षक हो, गृह स्वामिनी घर का संचालन सभी प्रकार करती हो और गृहस्थी सुखमय हो तो कौन अपने स्वर्ग सदृश घर को छोड़ कर शराब पीने वाले अथवा लड़ाई-झगड़ा करने वालों में सम्मिलित होगा । सुखमय घर जुर्म तथा लड़ाई-झगड़े को कम करने का मुख्य साधन है ।

इसके अतिरिक्त दो बातें और हैं, गाँव वालों में आत्मसंयम (Self-Control) तथा स्वाभिमान लेश-मात्र भी नहीं रहा है । किसी भी जाति में यह दो गुण मिल-जुल कर रहने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । परन्तु यह गुण गाँववालों में अभी आ सकते हैं जब कि गाँव की स्त्रियाँ बच्चों का लालन-पालन करना जानती हों तथा वे शिक्षित हों, जिससे कि आरम्भ में ही

गाँव के वच्चों में आत्मसंयम, इत्यादि आवश्यक गुण उत्पन्न हो सकें। इस दृष्टि से ग्रामीण स्त्रियों के सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

घरों को अधिक सुन्दर बनाने के लिये भारत में गृह-वाटिका ( Home Garden Plot ) आन्दोलन चलना चाहिये। प्रत्येक घर के साथ एक छोटी सी वाटिका हो। उसमें तरकारी, फूल और फल के वृक्ष लगाये जावें। घर भर के लोग उसमें अवकाश के समय काम करें। गृह-वाटिका से घर अधिक सुन्दर बनेगा साथ ही मन बहलाव भी होगा।

### पंचायत अदालत

इस समय भारतीय ग्राम अत्यन्त गिरी हुई दशा में हैं। प्रत्येक सभ्य देश में गाँवों का एक संगठन होता है जो गाँव के सम्बन्ध की देखभाल करता है। भारत में ब्रिटिश शासन के पूर्व गाँव की पंचायत एक जीवित संस्था थी। तब गाँवों की दशा ऐसी खराब नहीं थी। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक चार-पाँच गाँवों में एक पंचायत अदालत स्थापित की जाय जो गाँव में लड़ाई-झगड़ों तथा मुकदमेबाजी को रोके और कोई झगड़ा हो भी जावे तो उसका निपटारा करे। यदि पंचायत अदालत ठीक तरह से काम करे तो गाँवों की दशा सुधर जाय और उनमें बहुत कम झगड़े हों और उनमें से भी अधिकांश का पंचायत ही निर्णय कर दे। निर्धन ग्रामीण उस लम्बी मुकदमेबाजी से बच जावें जो कि उनको तबाह कर देती है।

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पंचायत से पंचायत-अदालत के लिये पाँच पंच चुन लिये जाते हैं। जब कोई झगड़ा उठ खड़ा हो तो पहले तो पंच दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करते हैं और यदि समझौता न हो सके तो फिर पंचायत फैसला कर देती है। पंचायतों में वकीलों को आने की आज्ञा नहीं है।

अभी तक जो पंचायतें देश में स्थापित की गईं उनके पंचों को सरकार नामजद करती थी और उनको १० रुपये से अधिक जुर्माना करने का अधिकार नहीं था इस कारण वे अधिक सफल नहीं हुईं। अब पंचायत अदालत को एक सौ रुपये जुर्माना करने का अधिकार दे दिया गया है। हर्ष की बात है कि अब उत्तर प्रदेश के गाँव में हजारों पंचायत अदालतें स्थापित हो गई हैं। इनका कार्य अच्छी तरह से चल रहा है।

## अभ्यास के प्रश्न

१—भारत के गाँवों में लड़ाई-झगड़े बहुत होते हैं। इसका क्या कारण है ?

२—मुकदमेवाजी से गाँव वालों की क्या हानियाँ हैं और उनको कम करने का क्या उपाय है ?

३—गाँवों और गाँवों के रहने वालों को गिरी हुई दशा का लड़ाई-झगड़े और मुकदमेवाजी से क्या सम्बन्ध है ?

४—यदि गाँव में एक ऐसी पंचायत हो जिसमें सबकी श्रद्धा हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

५—शराबवन्दी में गाँवों में लड़ाई-झगड़े कहाँ तक बन्द हो सकते हैं ?

६—यदि किसानों के घर अधिक आकर्षक बन जावें तो उसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

७—गाँवों में घरों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किन बातों की जरूरत है ?

## चौबीसवाँ अध्याय

### ग्रामवासियों को ऋणमुक्त करना

भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या अत्यन्त भयंकर हो उठी है और आज सरकार, राजनीतिज्ञ और जनता सभी का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित हो गया है। भारत के गाँवों में रहने वाले किसान कर्ज के भयंकर बोझ से इस बुरी तरह से दबे हुए हैं कि साधारण रूप से उनके छुटकारे की कोई आशा नहीं हो सकती। ऋणी होने के कारण किसानों का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा चरित्र विषयक पतन हो रहा है। कहीं-कहीं तो उनकी दशा अपने महाजन के मोल लिए हुए दास जैसी हो गई है। यह निर्विवाद है कि देश की आर्थिक दशा सुधारने लिए इस समस्या को हल करना आवश्यक है। जब कि जनसंख्या का

एक बहुत बड़ा भाग दासता का जीवन व्यर्तित करता हो तब देश की आर्थिक उन्नति का प्रयत्न करना निष्फल है ।

सन् १९३० में जो केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी बैठाई गई थी उसने ब्रिटिश भारत के समस्त प्रदेशों के ग्रामीण ऋण का अनुमान लगाया है । उक्त कमेटी के हिसाब से समस्त ब्रिटिश भारत का ग्रामीण ऋण उस समय ६०० करोड़ रुपये था । किन्तु सन् १९३० से ही खेती की पैदावार का मूल्य बहुत घट गया और उसी अनुपात में ऋण का बोझ बढ़ गया । अर्थशास्त्र के विद्वानों का मत है कि सन् १९३६ में ग्रामीण ऋण उस समय से लगभग दुगुना अर्थात् १८०० करोड़ रुपये के लगभग होगा । ध्यान में रखने की बात है कि इन अंकों में देशी राज्यों के ग्रामीण ऋण के अङ्क सम्मिलित नहीं हैं । सन् १९१० में उत्तर प्रदेशीय बैंकिंग जाँच कमेटी के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण ऋण लगभग १४४ करोड़ रुपये था ।

सन् १९३६ में महायुद्ध आरम्भ हो गया जिसके फलस्वरूप खेती की पैदावार का मूल्य बेहद बढ़ गया । इससे कर्ज का बोझ कुछ हलका जरूर हुआ । अगर इस अवसर का लाभ उठाया जाता और सरकार इस तरफ ध्यान देती तो किसान का सारा कर्जा चुकाया जा सकता था । लेकिन किसान ने उस रुपये का उपयोग चर्दी खरीदने, कपड़े तथा अन्य वस्तुओं को मोल लेने, तीर्थ यात्रा, विवाह और भोजों में किया और कर्ज देने का पैसा ही बना रहा ।

कितने लोग कर्जदार हैं। कुछ अर्थशास्त्र के विद्वानों का मत है कि ६० से सत्तर प्रतिशत ग्राम निवासी कर्जदार हैं।

### महायुद्ध और ऋण

सन् १९३६ के उपरान्त जब से द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तब से खेती की पैदावार का मूल्य बहुत बढ़ गया है और कुछ अर्थशास्त्री यह मानने लग गये हैं कि किसान ऋण मुक्त हो गये हैं। परन्तु, हम जैसा ऊपर कह आये हैं, ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी यह मानना होगा कि ऋण का भार कुछ हलका अवश्य हुआ है। अभी कुछ दिन हुये मद्रास सरकार ने इस सम्बन्ध में एक जाँच करवाई थी। उससे यह ज्ञात हुआ कि २० प्रतिशत ऋण कम हुआ है और बड़े किसानों के ही ऋण में कमी हुई है छोटे किसानों की दशा वैसी ही है। हा, यदि इस समय सरकार ऋण की जाँच करवा कर उसे कानून बना कर घटा दे और उसकी अदायगी का कुछ प्रबन्ध करे तब समस्या हल हो सकती है। परन्तु यदि ऐसा कुछ न हुआ, किसान की आज की खुशहाली शादियों, सोना-चादी, तीर्थ-यात्रा, मेलों, तमाशों पर कम हो गई और आगे चल कर खेती की पैदावार का मूल्य कम हो गया तो फिर किसान कर्ज के बोझ से ऐसा दब जावेगा कि उसका बचना कठिन होगा।

### कर्जदार होने के कारण

#### १—पैतृक ऋण

किसान को कर्जदार बनाने में उसके बाप के समय का कर्ज बहुत सहायक होता है। बाप का ऋण चुकाना एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है। बाप के मरने पर महाजन पुत्र से पुराने कर्ज के लिये नया कागज लिखवा लेता है।

#### २—महाजन के लेन-देन करने का ढंग

महाजन इतना अधिक सूद लेता है कि यदि कोई किसान एक बार महाजन के चंगुल में फँस गया तो फिर उसका ऋण-मुक्त होना असम्भव हो जाता है। गाँवों में भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सूद की दर भिन्न है, परन्तु फिर भी साधारणतः यह कहा जा सकता है कि किसान को २५ से ७५ प्रतिशत का सूद देना होता है। इतना अधिक सूद किसान कैसे दे सकता है? फल

यह होता है कि ऋण बढ़ता जाता है । किसान जो कुछ देता है वह सूद में ही कट जाता है और किसान कभी भी ऋण से मुक्त नहीं हो पाता । किसान अशिक्षित होता है इस कारण कभी-कभी महाजन हिसाब में गड़बड़ कर देता है और किसान को धोखा दे देता है ।

३—किसान के पास खेती के लिये यथेष्ट-भूमि का न होना

साधारण किसान के पास इतनी भूमि नहीं कि वह उस पर खेती करके अपने कुटुम्ब का पालन कर सके । देश में उद्योग-धन्धे कम होने के कारण आवश्यकता से अधिक जनसंख्या खेती वारी पर अवलम्बित है । इस कारण खेती के योग्य भूमि की बहुत कमी है । केवल यही खराबी नहीं है, जो कुछ भी भूमि किसान के पास है वह भी एक स्थान पर न होकर दूर-दूर छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी होती है ( Fragmented Land holdings ) । इन बिखरे हुये खेतों के कारण वैज्ञानिक ढङ्ग से न खेती हो सकती है और न खेती में लाभ हो सकता है ।

### अनिश्चित खेती

भारत में खेती अत्यन्त अनिश्चित है, किसी साल वर्षा कम होने से, अथवा वर्षा अधिक होने से, ओला या पाला पड़ने से, या फसल के कीड़े लग जाने से अथवा अन्य किसी कारण से जब फसल मारी जाती है तो किसान को कर्ज लेना पड़ता है ।

### वैलों की मृत्यु

पशुओं की महामारी ( प्लेग आदि ) फैलने से भारत में प्रतिवर्ष लाखों पशु मरते हैं । किसान के बैल मर जाने पर उसे कर्ज लेकर नए बैल मोल लेने पड़ते हैं ।

### सामाजिक तथा धार्मिक कृत्यों में अधिक व्यय करना

भारतीय ग्रामीण विवाह, मृत्यु, जन्म तथा अन्य धार्मिक और सामाजिक कृत्यों पर कर्ज लेकर अधिक व्यय कर देता है । कुछ लोग इसको अत्यधिक कर्जदार होने का मुख्य कारण बतलाते हैं परन्तु इसमें अतिशयोक्ति है ।

### मुकदमेवाजी

मुकदमेवाजी किसान के श्रृंखली होने का मुख्य कारण है । किसान

कर्ज लेकर मुकदमे लड़ता है। भारत में मुकदमेवाजी का रोग ऐसी बुरी तरह फैला हुआ है कि इसके कारण लाखों परिवारों का सर्वनाश हो गया है। वकील, अदालतों के कर्मचारी तथा खर्चीला न्याय किसान को कर्जदार बना देता है।

### लगान और मालगुजारी

मालगुजारी उचित से अधिक है, क्योंकि खेती से लाभ बहुत कम है। जब कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं अथवा खेती की पैदावार की कीमत कम हो जाती है तो किसान को लगान देना कठिन हो जाता है। यद्यपि ऐसे समय कुछ छूट दी जाती है, परन्तु वह आवश्यकता से बहुत कम होती है। निर्धन किसान को महाजन से कर्ज लेकर लगान या मालगुजारी देनी होती है। क्योंकि जमींदार तथा सरकारी कर्मचारी उसे बहुत सख्ती से वसूल करते रहे हैं। भूमि की कमी होने के कारण कभी-कभी किसान लम्बे पट्टे लेता है और उसके लिए बहुत अधिक लगान देना स्वीकार करता है। कभी-कभी कर्ज लेकर वह भूमि मोज ले लेता है।

किसान फसल बोने के समय महाजन से सवाये अथवा ड्योढ़े पर बीज लाता है। महाजन पुराना सड़ा बीज दे देता है। खाद इत्यादि डालने के लिये भी यह कर्ज लेता है। फसल तैयार होने पर उसे अपनी पैदावार तुरन्त बेचनी पड़ती है क्योंकि लगान, सरकारी आबपाशी तथा महाजन अपने कर्ज के लिये जल्दी मचाते हैं। उस समय बाजार भाव मन्दा होता है। महाजन बाजार भाव से भी बहुत सस्ते दामों पर किसान की पैदावार मोल ले लेता है। किसान थोड़े दिनों ठहर सके तो उसे अपनी पैदावार का अधिक मूल्य मिल सकता है। जूट, गन्ना और कपास इत्यादि की फसलों में तो कारखाने वाले किसान को कुछ रुपये पेशगी कर्ज दे देते हैं और बहुत सस्ते दामों पर फसल को पहले से ही मोल ले लेते हैं।

अधिकतर किसानों की स्थिति यह है कि फसल काटने के उपरान्त सब लेनदारों का रुपया चुकाने पर उनके पास केवल आठ महीने का भोजन ही बच रहता है। पिछले चार महीनों में किसान को महाजन से सवाये या ड्योढ़े पर अनाज उधार लेना पड़ता है। कहीं-कहीं तो कर्जदारों की स्थिति मोल लिये हुये दासों से भी गई बीती हो जाती है।

सरकार द्वारा ऋण की समस्या को हल करने का प्रयत्न

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में दक्षिण भारत, अजमेर, मेरवाड़ प्रदेश तथा बिहार प्रदेश के छोटा नागपुर डिवीजन में किसान विद्रोह हो उठे। उन्होंने बहुत से महाजनों के घर जला दिये और उन्हें मार डाला। सरकार ने एक कमाशन बिठाया। कमीशन ने इन उत्पातों का मुख्य कारण किसानों की भयंकर कर्जदारी बतलाया। सरकार ने किसानों की रक्षा के लिए देशी कानून में सुधार किये और एक कानून बनाया जिससे अदालतों को यह अधिकार दे दिया कि वे किसी भी नालिश के मुकदमे में उचित सूद की ही डिगरी दे, फिर किसान ने महाजन को चाहे जितने अधिक सूद देने का वादा क्यों न किया हो। किन्तु इस कानून से कोई लाभ न हुआ क्योंकि अदालतों का न्याय खर्चोला है और किसान निर्धन है।

भारतीय सरकार ने किसानों में मितव्ययिता का भाव उत्पन्न करने के लिए पोस्ट आफिस सेविंग बैंक खोले। अशिक्षित किसान पोस्ट आफिस सेविंग बैंक से अधिक लाभ न उठा सका। सरकार ने कई बार सिविल ला में इस दृष्टि से सुधार किए कि किसानों को कुछ सुविधा दी जाये किन्तु कानून द्वारा सरकार किसानों का कुछ भी सहायता न कर सकी।

सरकार ने देखा कि किसान को खेती-बारी का धन्धा करने के लिए साख (कर्ज) की आवश्यकता होती है। किसान को दो तरह की साख चाहिये—थोड़े समय के लिए और अधिक समय के लिए। अस्तु, भारतीय सरकार ने दो कानून बना कर प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वे किसान की दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकावी दे सकती हैं। किन्तु तकावी से भी यह समस्या हल नहीं हुई और न किसानों ने तकावी का अधिक उपयोग ही किया। कारण यह है कि किसानों को तकावी पटवारी, कानूनगो तथा नायब तहसीलदार की सिफारिश से मिलती है इस कारण किसान को रुपया समय पर नहीं मिल पाता। आवश्यकता के समय तकावी न मिलने तथा वसूली में कड़ाई होने से तकावी का अधिक प्रचार नहीं हुआ।

कर्जदार होने के कारण किसानों के हाथ से भूमि निकल कर महाजनों के पास चली जाती थी और किसान उन पर मजदूरों की भाँति कार्य करता



था। पंजाब में इस समस्या को हल करने के लिए “पंजाब लैंड एलीनेशन ऐक्ट” पास करके गैर खेतिहर जातियों को खेती की भूमि लेने से वंचित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में इसी प्रकार का कानून लागू कर दिया गया है।

यह सब कुछ हुआ, परन्तु ग्रामीण ऋण की समस्या पूर्ववत् ही बनी रही। इसी बीच में इटली और जर्मनी की सहकारी साख समितियों को आश्चर्यजनक सफलता से भारत सरकार का ध्यान सहकारी साख आन्दोलन की ओर आकर्षित हुआ और सन् १९०४ से भारत में भी सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश किया गया। सहकारी साख आन्दोलन कहाँ तक सफल हुआ है यह तो अगले अध्यायों में लिखा जावेगा, किन्तु इतने वर्षों के अनुभव से यह तो सिद्ध हो ही गया है कि सहकारी साख समितियाँ किसान के पुराने कर्जों को अदा नहीं कर सकती। थोड़े समय के लिए खेती-बारी में जो ऋण की आवश्यकता होती है उसका प्रबन्ध ये साख समितियाँ सफलतापूर्वक कर सकती हैं। जब तक किसान पुराना ऋण नहीं चुकाता तब तक वह महाजन के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता।

पुराने ऋण को चुकाने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए अधिक समय तक का ऋण देने के लिए भूमि बंधक बैंक (Land mortgage banks) अधिक उपयुक्त हैं। ये बैंक किसान अथवा जमींदारों की भूमि को गिरवी रख उन्हें बीस या तीस वर्ष तक के लिये ऋण देते हैं और किस्तों में वसूल कर लेते हैं। ऋण देने के लिए बहुत पूँजी की आवश्यकता होती है। वह बैंक बंधक रखी हुई भूमि की जमानत पर डिबेचर (ऋण-पत्र) बेच कर इकट्ठी करते हैं। अभी भारत में थोड़े से ही भूमि बंधक बैंक स्थापित हुए हैं। परन्तु वे बैंक उन्हीं किसानों को ऋण दे सकेगे जो कि भूमि बंधक रख सकेंगे। बहुत से प्रदेशों में किसान का भूमि पर स्वामित्व ही नहीं है। वहाँ ये बैंक किसानों की सहायता न कर सकेंगे।

### ऋण-परिशोध

केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी की सम्मति में सरकार को निम्नलिखित योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए।

प्रादेशिक सरकार इस कार्य के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त करे जो

गाँवों में दौरा करके पता लगावे कि किसानों पर कितना ऋण है। इसके लिए एक कानून बनाकर महाजनों को विवश किया जावे कि वे किसान के ऋण का पूरा हिसाब बतावे तदुपरान्त वह कर्मचारी ऋण को चुकाने के लिए महाजन को कम से कम रुपया लेकर किसान को ऋणमुक्त करने के लिये राजी करे। जब यह निश्चय हो जावे कि महाजन कम से कम कितना रुपया लेकर किसान को ऋणमुक्त कर देगा, तब किसान को साख समिति का सदस्य बनवा दिया जाये। साख समिति किसान का कर्जा एक मुश्त अथवा किश्तों में चुका दे, तथा खेती-बारी के लिये किसान को आवश्यक साख (कर्ज) देती रहे।

यदि महाजन किश्तों में रुपया लेना स्वीकार करे तो किसान जितना स्वयं दे सके उतना चुका दे और शेष किश्तों को देने की जिम्मेदारी साख समिति ले ले। समिति किसान से किश्तें वसूल करती रहे। यदि महाजन एक मुश्त रुपया माँगे तो सरकार को उतना रुपया समिति को उधार दे देना चाहिए। साख समिति किसान से वार्षिक किश्तें लेकर सरकार का कर्ज चुका देगी।

यह भी सम्भव है कि महाजन कर्ज के इस प्रकार चुकाये जाने के लिये तैयार न हों और समझौता न करे। ऐसी परिस्थिति में कानून बना कर उन्हें विवश किया जावे।

कतिपय प्रदेशों में ऋण समझौता बोर्ड (Debt Conciliation Board) तथा भूमि बंधक बैंक (Land Mortgage Banks) साथ-साथ स्थापित किये गये हैं। ऋण समझौता बोर्ड सदस्य के ऋण के विषय में महाजन से समझौता करके रकम को कम से कम करने का प्रयत्न करता है और भूमि बंधक-बैंक सदस्य की भूमि को बंधक रख कर उस रकम को चुका देता है। तदुपरान्त किश्तों में सूद सहित सदस्य से रुपया वसूल कर लेता है। अभी ये संस्थाएँ बहुत कम संख्या में हैं और इन्हें कार्य करते अधिक दिन नहीं हुये हैं।

अभी कुछ वर्ष हुए हैं कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में कुछ कानून किसानों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ कानून इस सम्बन्ध में बनाये गए हैं। इन कानूनों के द्वारा ऋण के लिए भूमि जुर्का नहीं कराई जा सकती। अदालत सूद की दर निश्चित

करके किश्त बाँध देती है किन्तु इन कानूनों से किसानों का अधिक लाभ नहीं हुआ।

ग्रामीण ऋण की समस्या इतनी गम्भीर और महत्वपूर्ण है, साथ ही इतनी कठिन भी है कि वह साधारण प्रयत्नों से हल न होगी। इसके लिए कोई क्रान्तिकारी तथा साहसी प्रयोग करना होगा। इस दृष्टि से भावनगर के तत्कालीन दीवान सर प्रभाशकर पट्टनी ने राज्य भर के किसानों के ऋण की जाँच करवाई तो ज्ञात हुआ कि राज्य के किसानों पर छियासी लाख से कुछ अधिक ऋण है। उन्होंने राज्य भर के महाजनों को बुलवाया और उनसे बीस लाख रुपये लेकर किसानों को ऋणमुक्त कर देने को कहा। पहिले तो महाजन तैयार नहीं होते थे किन्तु जब उन्होंने देखा कि समझौता न करने पर राज्य ऐसे कानून बना देगा कि जिनके कारण किसानों से रुपया वसूल न हो सकेगा तो वे बीस लाख रुपये लेकर किसानों को ऋणमुक्त करने को तैयार हो गये राज्य ने एक मुश्त बीस लाख रुपये देकर किसानों को महाजनों के ऋण से मुक्त कर दिया। ध्यान रहे किसान प्रतिवर्ष लगभग पचास लाख रुपये तो केवल सूद में दे देते थे। राज्य अब किश्तों में वह रुपया लगान के साथ किसान से वसूल करता है। राज्य में सहकारी साख समितियाँ स्थापित की जा रही हैं और राज्य तकावी देता है जिससे कि किसान फिर महाजनों के ऋणी न हो जावें। इस प्रकार ऋण मुक्त होने का फल भावनगर में यह हुआ कि किसान स्वयं वैज्ञानिक ढंग की खेती करने लगे हैं। अच्छे हल, बैल, खाद तथा बीज का उपयोग किया जा रहा है और गाँव समृद्धिशाली बनते जा रहे हैं। शेष भारत में भी जब इसी प्रकार की कोई क्रान्तिकारी योजना काम में लाई जावेगी तभी ग्रामीण ऋणमुक्त हो सकेंगे। जब तक किसान ऋणमुक्त नहीं होते तब तक उनकी स्थिति में सुधार होना सम्भव नहीं है।

यद्यपि भावनगर राज्य की भाँति कोई क्रान्तिकारी योजना और प्रदेशों में काम में नहीं लाई गई परन्तु पिछले वर्षों में भी कुछ कानून बनाए गए हैं जिनसे कर्जदारों को बहुत लाभ और सुविधा हो गई है। इनमें नीचे लिखे मुख्य हैं :—

महाजन लायसेंस कानून ( Money-Lenders Act )—पश्चिमी बंगाल, आसाम, मध्यप्रदेश, बिहार, बम्बई, पूर्वी पंजाब में महाजन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कानून बनाये गये हैं। इन कानूनों की मुख्य बातें एकसी हैं।

कानून के अनुसार प्रत्येक महाजन को सरकार से एक लायसेंस लेना होगा। प्रत्येक लायसेंसदार महाजन को नियमानुसार हिसाब रखना होगा और प्रत्येक कर्जदार को निश्चित समय पर उसका हिसाब लिखा कर देना होगा। जब कभी कर्जदार कुछ रुपया महाजन को दे तो महाजन को उसको रसीद देनी होगी।

इन कानूनों के साथ ही प्रादेशिक सरकारों ने सूद की दर भी कानून से निश्चित कर दी है। यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सूद की दर भिन्न है। फिर भी पहले से सूद की दर बहुत कम हो गई है।

मद्रास और मध्यप्रदेश में कानून बना कर किसान के कर्ज को कुछ प्रतिशत कम कर दिया गया है। कुछ प्रदेशों में ऋण समझौता बोर्ड स्थापित करके किसान के ऋण की रकम को घटाने का प्रयत्न किया गया है।

किन्तु इन सुविधाओं से ऋण की समस्या हल नहीं हुई। आवश्यकता इस बात की है कि भावनगर राज्य की तरह ही सरकार इस समस्या को हल करने के लिये एक योजना तैयार करे और उसको शीघ्र ही लागू कर दे।

आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस समय ग्रामीण ऋण की जाँच करवाए। कानून बनाकर उसे उचित मात्रा में कम कर दे। कम करने में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि महाजन ने बहुत अधिक सूद लेकर अपनी रकम को बढ़ा तो नहीं लिया है। अस्तु कर्ज की रकम को सभी बातों को ध्यान में रखकर कम कर दिया जावे। जिन किसानों के बारे में यह प्रतीत हो कि वे दस वर्ष में भी घटी हुई रकम को अदा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कुछ भी बचत नहीं होती, उनको 'ग्रामीण दिवालिया कानून' ( Rural Insolvency Act ) बना कर दिवालिया करार दे दिया जावे और उन्हें फिर से नये तिरों से कार्य आरम्भ करने की इजाजत दी जावे। भूमि, बैलों की जोड़ी, खेतों के औजार, बीज, ६ महीने के खाने के अन्न को छोड़कर जो भी उनके पास हो उसको महाजनों में बाँट दिया

जावे और किसान को ऋणमुक्त कर दिया जावे। शेष किसानों की कम की हुई रकम सरकारी बाडों के रूप में किसानों के महाजनों को दे दी जाय। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उन महाजनों की कर्जदार हो गई और जब तक सरकार महाजनों का कर्जा न चुका सके तब तक उस पर २ प्रतिशत सूद देती रहे। सरकार यह रकम किसान से सूद सहित किश्तों में वसूल कर ले। इस प्रकार ऋण की समस्या को हल किया जा सकता है।

**महायुद्ध और ग्रामीण ऋण :**—महायुद्ध के फलस्वरूप खेती की पैदावार का मूल्य आवाश छूने लगा और किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी प्रतीत होने लगी। इससे अर्थशास्त्रियों की यह धारणा होने लगी कि या तो गाँव वालों का ऋण बिलकुल ही चुक गया होगा अथवा बहुत कम शेष रह गया होगा। परन्तु इस सम्बन्ध में सही आँकड़े उपलब्ध नहीं थे। केवल मद्रास में तथा अन्य स्थानों पर इस सम्बन्ध में कुछ जाँच की गई। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण ऋण २० प्रतिशत कम हो गया है। किन्तु कमी केवल बड़े किसानों और जमींदारों के ऋण में हुई वरन् किसी किसी दशा में छोटे किसानों और खेत मजदूरों का ऋण बढ़ गया है।

### अभ्यास के प्रश्न

१—गाँवों में किसान किन आदमियों और संस्थाओं से ऋण लेता है ?

२—भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो उठी है ?

३—किसान के कर्जदार होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

४—क्या ऋण लेना हर हालत में हानिकारक होता है ? भारतीय किसान किन-किन कार्यों के लिये ऋण लेता है ?

५—क्या यह सच है कि भारतीय किसान ऋण ही में जन्म लेता है और ऋण ही में मरता है ? इस भयंकर कर्जदारी का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

६—किसान के ऋणी होने से उसकी क्या हानि होती है ?

७—भारतीय किसान का जो निराशावादी दृष्टिकोण बन गया है उस पर उसके कर्जदार होने का क्या असर पड़ता है ?

८—“तकावां” क्या है और उससे किसान को कहाँ तक सहायता मिलती है ?

९—कैन्द्रीय बँकिंग जाँच कमेटी ने ऋण की समस्या को हल करने के लिये क्या उपाय बतलाया है ?

१०—भावनगर राज्य में ऋण की समस्या को कैसे हल किया गया और उसका फल क्या हुआ ?

११—भूमि बन्धक बैंक किसे कहते हैं ? वह क्या कार्य करता है ?

## पच्चीसवाँ अध्याय

### गाँव में आय के साधन और गमनागमन

गाँवों में खेती के सिवाय आय के दूसरे साधन नहीं के बराबर हैं। जन-संख्या के बढ़ने और भूमि की कमी के कारण प्रति किसान पीछे भूमि इतनी कम ( ढाई एकड़ ) है कि एक परिवार का उस पर पालन होना साधारण समय में भी असम्भव है। फिर भारत में हर तीसरे चौथे साल फसल नष्ट हो जाती है। सूखा, बाढ़, अतिवर्षा, टोडी, ओला, फसलों के रोग, पाला इत्यादि दैवी कारणों से फसले नष्ट हो जाती हैं और कहीं-कहीं तो भीषण अकाल पड़ जाता है। ऐसे समय में किसान की दशा अत्यन्त दयनीय हो जाती है। यह तो हुई उन सालों की बात जब कि फसल खराब हो जाती है। जब फसल ठीक होती है तब भी किसान के पास इतना नहीं होता कि वह परिवार का पालन-पोषण ठीक तरह से कर सके। इसलिए यह आवश्यक है कि खेती के अलावा किसान के पास आय के दूसरे भी साधन हों।

### ग्रामीण धन्धे

भारत का साधारणतः किसान वर्ष में ४ से ६ महीने बेकार रहता है कारण खेती का धन्धा ऐसा है कि इसमें वर्ष भर लगातार काम नहीं रहता। किन्हीं दिनों उसे बहुत अधिक काम करना पड़ता है, किन्हीं दिनों काम, और कभी वह बिल्कुल बेकार रहता है। गाँव के मजदूरों को तो वर्ष में ४ या ५ महीने से अधिक काम मिलता ही नहीं। यह माना हुई बात है कि कोई ६ महीने काम करके १२ महीने का भोजन नहीं पा सकता।

यूरोप तथा अमेरिका जैसे देशों में जहाँ किसान के पास बड़े-बड़े फार्म हैं किसान केवल खेती पर ही अवलम्बित नहीं रहता । वह ग्राम उद्योगों के द्वारा अपनी आय बढ़ाता है । ऐसी दशा में भारत में जहाँ भूमि का अकाल है किसान बिना ग्रामीण धन्धों के कैसे जीवित रह सकता है ? ग्रामीण धन्धों में निम्नलिखित गुण होने चाहिये :—

१—धन्धा ऐसा होना चाहिए जो खेती के काम में बाधक न हो अर्थात् जब खेतों पर अधिक काम हो तब उसको बिना हानि के छोड़ा जा सके ।

२—धन्धा ऐसा हो जिसमें अधिक कुशलता प्राप्त करने की जरूरत न हो । नहीं तो किसान के लिए उस धन्धे की शिक्षा की समस्या उठ खड़ी होगी ।

३—धन्धे में कच्चे पदार्थ की जो आवश्यकता हो वह गाँव से ही पूरी हो सके ।

४—धन्धे की चीज ऐसी होनी चाहिये कि जिसकी माँग सब जगह हो और जिससे माल के बेचने में कठिनाई न हो ।

५—धन्धा ऐसा होना चाहिये जिसके चलाने में अधिक पूँजी की जरूरत न हो ।

६—जहाँ तक हो ग्रामीण धन्धे ऐसे चुने जावे जिनकी होड़ मिलों में बने माल से न हो ।

ऊपर दिये हुये गुणों को ध्यान में रखते हुये नीचे लिखे धन्धे गाँव के लिये उपयुक्त हो सकते हैं ।

(१) दूध, घी, मक्खन का धन्धा, (२) मुर्गी पालने का धन्धा, (३) फलों का धन्धा, (४) तरकारी पैदा करना, (५) शहद उत्पन्न करना, (६) सूत कातने का धन्धा, (७) रेशम के कीड़े पालने का धन्धा, (८) भेड़ें पालने का धन्धा, (९) गुड़ बनाना, चावल कूटना, रस्सी बँटना, डालियाँ तैयार करना, (१०) गाड़ी चलाना, तेल पेरना इत्यादि ।

### ग्राम उद्योग सघ

महात्मा गाँधी के नेतृत्व में ग्राम उद्योग सघ की स्थापना हुई थी जो ग्रामीण धन्धों की उन्नति के लिये प्रयत्न कर रही है । आशा है कि इससे

गाँव वालों को आय का एक अच्छा साधन मिल जावेगा । सरकार का औद्योगिक विभाग भी इस ओर ध्यान दे रहा है ।

### गाँवों में आय के अन्य साधन

खेती की उन्नति तथा ग्रामीण धंधों के विकास से खेती में लगे हुए किसानों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है । परन्तु गाँवों की स्थिति में पर्याप्त सुधार तभी होगा जबकि वहाँ गृह-उद्योग-धंधे (Cottage industries) जैसे हाथ कर्घे से कपड़े बनाने का धंधा, बढईगीरी, लुहारी, पीतल के बरतन, मिट्टी के बरतन बनाने तथा अन्य धंधों की उन्नति की जावे । इसके लिए पूँजा (Capital), हल्के यंत्रों, जल विद्युत् तथा अच्छे मार्गों की आवश्यकता होगी । यदि ऊपर लिखी सुविधाएँ सरकार गाँवों को प्रदान कर दे तथा इनका सहकारी समितियों के द्वारा संगठन किया जावे तो गाँवों में गृह-उद्योग धंधे पनप सकते हैं और गाँवों के रहने वाले कारीगरों तथा अन्य व्यक्तियों की आय का एक अच्छा साधन प्राप्त हो सकता है ।

गाँव में एक वर्ग और है जो खेत-मजदूर कहलाता है । इनके पास खेती नहीं होती । ये लोग दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं । इनकी दशा अत्यन्त दयनीय होती है, वे अत्यन्त निर्धन होते हैं । उनकी दशा को तभी सुधारा जा सकता है कि जब इन्हें गृह-उद्योग धंधों में लगाया जावे या कानून से उन्हें उचित मजदूरी दिलवाई जावे ।

### गाँव में जाने की असुविधा



किन्तु केवल सड़कों से ही काम नहीं चलेगा । डाक, तार, तथा रेडियो की भी सुविधा गाँवों को मिलनी चाहिये जिससे वे दुनिया की हलचलों से परिचित हो सके ।

### अभ्यास के प्रश्न

१—किसानों को खेती के सिवाय दूसरे आय के साधनों की क्यों जरूरत है ?

२—ग्रामीण धंधों में कौन सा विशेष गुण होना चाहिये ?

३—सड़कों की उन्नति से गाँव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

४—कौन से ग्रामीण धंधे तुम अपने गाँव में चलाना चाहोगे । उनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक लिखो ।

## छब्बीसवाँ अध्याय

### कृषि-विभाग के कार्य तथा खाद्य समस्या

सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कृषि-विभाग की स्थापना सन् १८७५ ईसवी में हुई । तत्कालीन लैफ्टीनेन्ट गवर्नर सर जान स्ट्रैचे ने प्रयत्न करके प्रदेश में एक डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर और कामर्स की नियुक्ति करने की आज्ञा प्राप्त कर ली । डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को इस आशय की आज्ञा दी गई कि वह प्रदेश के किसानों को नये तरीके से खेती करने के लाभ बतलाये और ऐसी फसलों और छोटे-छोटे धंधों की उन्नति करने के लिये प्रयोग करे कि जिनके द्वारा किसानों को अधिक काम हो । आरम्भ में रेशम के कीड़े पालने तथा रेशम उत्पन्न करने के धंधे, सन, तथा तम्बाकू की ओर अधिक ध्यान दिया गया । उससे पूर्व ही प्रदेश में तीन माडल फार्म थे जो कि नव निर्मित कृषि विभाग ने ले लिये । रेशम के कीड़े का एक फार्म देहरादून में खोला गया तम्बाकू का फार्म गाजीपूर में और फलों का फार्म कुमायूँ की पहाड़ियों पर खोला गया । तम्बाकू और रेशम के फार्म असफल रहे किन्तु कुमायूँ का फार्म बहुत सफल हुआ । प्रदेश में आलू और फलों के व्यापार की जो आशातीत उन्नति हुई है उसका मुख्य कारण कुमायूँ का फार्म है ।

उत्तर प्रदेश के कृषि-विभाग को प्रदेश की सड़कों के किनारे पेड़ लगाने का भी कार्य सौंपा गया था जो कि आज तक कृषि-विभाग करता आ रहा है। सन् १८८० में कृषि-विभाग ने अपनी एक शाखा स्थापित करके पुराने कुओं के सुधार तथा नयों को खोदने का काम भी अपने हाथ में लिया। वेल बोरिंग ब्रांच ( Well Boring Branch ) किसी भी किसान को यह सलाह देती है कि इस क्षेत्र में कितनी दूरी पर पानी निकलेगा। यदि किसान चाहे तो वे कुये को खोद भी देते हैं।

इनके अतिरिक्त उस समय कृषि-विभाग ने ऊसर भूमि तथा पानी द्वारा काटी भूमि (Eroded Land) को खेती के योग्य बनाने, गाय और बैलों की नस्ल को सुधारने, कपास के तथा गन्ने के बीज को उन्नत करने का भी प्रयत्न किया। यद्यपि गाय और बैलों की उन्नति करने में सीधी सफलता नहीं मिली। किन्तु ऊसर भूमि के सुधार होने पर वहाँ चरागाह बन गये जिससे अप्रत्यक्ष रूप से गाय और बैलों का सुधार हुआ और प्रदेश में डेयरी का धंधा पनपा।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक इसी नीति के अनुसार कार्य होता रहा। इस बीच में केवल दो परिवर्तन हुये। कानपुर में कृषि स्कूल खोला गया। बाद को वही स्कूल कृषि कालेज में परिणत हो गया। कृषि-विभाग को अधिक आदमी देकर शक्तिशाली बनाया गया, तथा प्रदेश में फार्मों की संख्या बढ़ा दी गई।

सन् १९०५ में भारत सरकार ने घोषणा की कि वह २० लाख रुपये ( जो बाद को बढ़ाकर २४ लाख कर दिये गये ) प्रति वर्ष प्रदेशों में कृषि विषयक अनुसंधान, प्रयोग, प्रदर्शन, तथा शिक्षा के लिये देगी। इस सहायता से प्रत्येक प्रदेश में कृषि कालेजों की स्थापना की गई और उनके अध्यापकों के पदों पर भिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञ रखे गये। इन विशेषज्ञों का कार्य केवल कालेज के विद्यार्थियों को पढ़ाना ही नहीं था वरन् अपने विषय के अन्तर्गत प्रादेशिक समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान करना भी था। उदाहरण के लिए यदि कोई विशेषज्ञ फसल की बीमारियों की शिक्षा देता है तो वह प्रदेश में होने वाली फसलों की बीमारियों के सम्बन्ध में

अनुसंधान भी करता है। प्रत्येक बड़े क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा बतलाई हुई बात का प्रयोग करने के लिए एक प्रयोग करने वाला स्टाफ ( Experimental Staff ) रखा गया। इसका कार्य फार्मों पर विशेषज्ञों द्वारा बतलाई हुई बातों का प्रयोग करना और उस प्रदेश के लिए उपयोगी सिद्ध होने पर उस बात का गाँवों में प्रचार करना है। प्रचार-कार्य उन छोटे-छोटे प्रदर्शन फार्मों ( Demonstration Farm ) के द्वारा किया जाता है जो कि प्रत्येक जिले अथवा तहसीलों में स्थापित किए गए हैं।

### कृषि-विभाग का संगठन और उसका कार्य

यह तो पूर्व ही कहा जा चुका है कि कृषि-विभाग का प्रधान अधिकारी डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर होता है। डायरेक्टर विभाग का सारा काम संभालता है। कृषि विषयक शिक्षा देने के लिये कानपुर में एक प्रथम श्रेणी का कृषि कालेज ( Agricultural College ) है। कानपुर में कृषि कालेज में कृषि विषयक उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान (Research) कार्य भी होता है। बीजों का सुधार, खाद, फसल के कीड़े, भूमि तथा सिंचाई सम्बन्धी अनुसंधान कार्य इसी कालेज के विशेषज्ञ अध्यापक करते हैं। साधारण कृषि विषयक शिक्षा, ग्रामीणों तथा कृषि-विभाग के छोटे कर्मचारियों को देने के लिए प्रदेश में बुलन्दशहर तथा एक-दो अन्य स्थानों पर कृषि स्कूल खोले गए हैं।

समस्त प्रदेश को कुछ सर्किलों में बाँटा गया है। प्रत्येक सर्किल एक डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर की अधीनता में होता है। उसका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में स्थित प्रयोग फार्म ( Experimental Farms ), बीज फार्म ( Seed Farms ) तथा प्रदर्शन फार्म ( Demonstration Farms ) का प्रबन्ध करना तथा प्रदर्शन प्लॉट्स ( Demonstration Plots ) की देखभाल करना है। इसके अतिरिक्त अपने सर्किल में अच्छे बीज और खेती के औजारों की वेंचना तथा कृषि सुधार विषयक प्रचार करना भी उसके जिम्मे है। इस कार्य के लिए उसकी अधीनता में इन्स्पेक्टर और फील्डमैन रहते हैं जो इस कार्य को करते हैं।

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि उत्तर प्रदेशीय कृषि-विभाग तीन के फार्म रखता है, एक जिन पर विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान की हुई

बातों का प्रयोग किया जाता है, दूसरे जिन पर अच्छा बीज अधिक राशि में उत्पन्न करके किसानों को बेचा जाता है, तीसरे वे जिन पर अच्छी खेती करने का ढंग किसानों को बताया जाता है ।

प्रदर्शन फार्म और प्रदर्शन प्लॉट (Demonstration Farm and Demonstration Plot) का प्रबन्ध फील्डमैन करता है । किसी गाँव में किसी भी किसान को जिस प्रकार फील्डमैन कहे उस प्रकार खेती करने को राजी कर लिया जाता है । फील्डमैन अपनी देख-रेख में किसान से खेती कराता है । जब उस किसान की फसले अपने पड़ोसियों की फसलों से अच्छी होती हैं और उसे अधिक लाभ होता है तो गाँव के अन्य किसानों को फील्डमैन की बताई हुई बातों पर विश्वास हो जाता है और कृषि-विभाग के द्वारा बताए हुए सुधारों को अपना लेते हैं ।

कृषि-विभाग अच्छा बीज बेचने और उसको अपने सीड फार्म ( बीज उत्पन्न करने के फार्म ) पर उत्पन्न करने में अपनी बहुत शक्ति लगाता है । गेहूँ, गन्ना, कपास तथा अन्य फसलों के अच्छे बीज तैयार करने में कृषि-विभाग को बहुत सफलता मिली है । कृषि-विभाग उस अच्छे बीज को अपने फार्म पर तथा अपनी देख-रेख में किसानों के खेतों पर उत्पन्न करते हैं । किसानों को बीज बेचने के लिये कृषि-विभाग ने देहातों में बहुत बड़ी सख्या में बीज-भंडार ( Seed Depot ) खोले थे जहाँ से किसानों को बीज दिया जाता था । कृषि साख समितियों, रहन-सहन सुधार समितियों और ग्राम सुधार के आर्गनाइजर्स के द्वारा भी कृषि-विभाग किसानों को अच्छा बीज बेचता था । बीज के अतिरिक्त कृषि-विभाग अच्छे हल, कोल्हू तथा खेती के यन्त्र भी बेचता रहा है ।

रहा है। पिछले दिनों में कृषि-विभाग ने गन्ने की ओर विशेष ध्यान दिया है और यही कारण है कि गन्ने की पैदावार प्रदेश में बहुत अच्छी होने लगी है।

कृषि-विभाग के अतिरिक्त आल इंडिया कृषि कौंसिल भी है जो खेती के सम्बन्ध में अनुसन्धान भी करवाया करती है और कृषि-विभागों को सलाह-मशविरा देती है। यही नहीं, भारत सरकार को भी खेती के धन्धे के बारे में क्या नीति बरती जावे इस सम्बन्ध में कौंसिल सलाह देती रहती है। युद्ध के उपरान्त खेती की उन्नति करने की योजना बनाई गई है। खाद, अच्छे हल और पैदावार को बढ़ाने का प्रयत्न किया जावेगा।

### प्रादेशिक विकास योजना

#### ( Provincial Development Plan )

अब तक कृषि-विभाग, ग्राम-सुधार विभाग, सहकारी विभाग तथा पशु-विभाग जिलों, तहसीलों और गाँवों में अपनी खिचड़ी अलग-अलग पकाते थे। उनके जिला और ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं में कोई व्यावहारिक सहयोग नहीं स्थापित हो पाता था। खेती के तल पर किसान और काम करने वालों को उत्तम और टेकनिकल राय और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए अफसरों को उपयुक्त ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उन्हें काफी वेतन मिलता है। परन्तु अब तक यह अफसर किसान तक नहीं पहुँच पाते थे। इनका अधिकांश समय आफिस की खानापूरी तथा छोटे कर्मचारियों की देख-रेख में ही बीत जाता था। यह अति आवश्यक है कि यह कमी दूर की जाय।

अतः अब प्रादेशिक विकास बोर्ड के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में एक विकास अफसर नियुक्त किया गया है और प्रत्येक जिले में एक जिला-विकास-समिति स्थापित हो गया है, जो जिला विकास योजना निश्चित करेगा। इन विकास योजनाओं का एकीकरण प्रादेशिक विकास बोर्ड करेगा। जिला विकास अफसर जिला समिति की मदद करेगा और विकास योजना को कार्यान्वित करने का कार्य करेगा। उसके नीचे उपयुक्त विभागों के जिला इन्स्पेक्टर रहते हैं। प्रत्येक जिले में लगभग पन्द्रह गाँवों के विकास ब्लॉक बना लिये गए हैं। इस प्रकार के लगभग ८ सौ ब्लॉक बन चुके हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के कृषि-विभाग के पास जो ८ सौ बीज स्टोर्स थे वे इन ब्लॉक के

दिए बनाई गई बहुध्येयी सहकारी समिति को दे दिये गए हैं। इन ब्लाकों के अन्दर योजना को कार्य रूप में परिणत करने की जिम्मेदारी इन समितियों पर ही है। जिला उन्नयन अफसर का इन समितियों से सीधा सम्बन्ध है और यह आशा की जाती है कि यह अफसर सब प्रकार के इन्स्पेक्टरों को काम की एक योजना के अनुसार व्यवस्थित कर सकेगा। आरम्भ में इस विकास ब्लाक में तालाब की खुदाई, कम्पोस्ट की खाद उत्पादन, वृक्ष लगाने, डेरी की व्यवस्था तथा प्रौढ़ शिक्षा का कार्य किया जायगा।

---

### भारत में खाद्य पदार्थों की कमी

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व, यद्यपि साधारणतः लोग यह समझते थे कि भारतीय कृषि का धन्धा पिछड़ा हुआ है, उसमें उन्नति की आवश्यकता है प्रति बीघा पैदावार कम होती है। किन्तु उन्हें यह कल्पना भी नहीं थी कि भारत में खाद्य पदार्थों का ऐसा भयंकर टोटा भी हो सकता है कि विदेशों से खाद्य पदार्थ न आने पर यहाँ अकाल पड़ सकता है और भूख से मनुष्य मर सकते हैं। आज देश के सामने अनाज की कमी की भयंकर समस्या खड़ी है और प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का अनाज विदेशों से मँगाना पड़ रहा है।

वात यह थी कि सन् १९३६ के पूर्व भी देशों में यद्येष्ट अनाज उत्पन्न नहीं होता था। शहरों तथा मंडियों में काफी अनाज विकने को आ जाता था इस कारण किसी को इस कमी का आभास नहीं मिलता था। इसका मुख्य कारण यह था कि खेती की पैदावार का मूल्य बहुत गिरा हुआ था, २॥ और ३ ६० मन गेहूँ विकता था और लगान तथा सद की दर बहुत अधिक थी।

नहीं हुई। अस्तु, इसे इस बात की आवश्यकता नहीं रही कि वह भूखे रहकर अपना समय काटे और खेत की अधिकांश पैदावार बाजार में बेच दे। अब वह कुछ अधिक खाने लगा, साथ ही गेहूँ इत्यादि भी बहुधा खाने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ कि खाद्य-पदार्थों की कमी गाँवों से हटकर शहरों में पहुँच गई। शहरों में खाद्य पदार्थों का टोटा पड़ गया।

इसके अतिरिक्त बर्मा के जापान द्वारा अधिकृत हो जाने तथा स्वतन्त्र हो जाने के उपरान्त वहाँ गृह-युद्ध आरम्भ हो जाने के कारण वहाँ से चावल आना कठिन हो गया। फिर देश के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में वह प्रान्त चले गए जो खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति की दृष्टि से बहुत समृद्ध थे और भारत में वह प्रान्त आये जिनमें अनाज की कमी थी। फिर काश्मीर युद्ध तथा सैनिक आवश्यकताओं के लिए अधिक अनाज भर कर रखने के कारण देश में अनाज का टोटा पड़ गया। कंट्रोल की अव्यवस्था, चोर बाजार तथा भ्रष्टाचार के कारण स्थिति और भी भयावह हो उठी।

खाद्य-पदार्थों की कमी का अनुभव १९४२ में हुआ। “खाद्य पदार्थ अधिक उत्पन्न करो” आन्दोलन चलाया गया। कपास तथा तिलहन को पैदावार को कम करके अनाज को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ भूमि जो पहले कपास पैदा करती थी अनाज उत्पन्न करने के काम में आने लगी। “खाद्य पदार्थ अधिक उत्पन्न करो” आन्दोलन को थोड़ी सफलता हुई परन्तु अधिक सफलता नहीं मिली।

खाद्य पदार्थों की दृष्टि से जो बाहुल्य प्रदेश थे वहाँ से अनाज लेकर टोटे वाले प्रदेशों में अनाज भेजा जाने लगा। साथ ही खाद्य पदार्थों का राशनिंग भी स्थापित किया गया।

देश में अधिक खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने के लिए बजर भूमि को जो बेकार पड़ी थी खेती के योग्य बनाने के लिए भारत सरकार ने एक ट्रैक्टर विभाग खोला है। इस केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग से मध्य भारत, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पूर्वीय पंजाब तथा उत्तर प्रदेश को ट्रैक्टर दिये गये हैं और हजारों बीघा भूमि को खेती के योग्य बनाया जा रहा है।

भारत सरकार तथा प्रादेशिक सरकारों ने मिलकर खाद बनाने के दो कारखाने स्थापित करने का निश्चय किया है जो ४॥ लाख टन खाद

उत्पन्न करेंगे। एक बड़ा कारखाना सिदरी ( बिहार ) में ३८ करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है जो अब खाद बनाने लगा है।

### पंचवर्षीय योजना

भारत सरकार ने देश की गरीबी मिटाने के लिये जो पंचवर्षीय योजना स्वरूप की है उसमें खेती की उत्पत्ति को बढ़ाने का नीचे लिखा कार्यक्रम है।

बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं ( जैसे दामोदर, हीराकुड, भाखरा, नानगल इत्यादि ) से ८० लाख एकड़ नई भूमि सींची जावेगी और छोटी सिंचाई योजनाओं ( तालाब, ट्यूबवैल, तथा साधारण कुओं ) से ७० लाख एकड़ नई भूमि सींची जावेगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग की सहायता से ५५ लाख एकड़ परती तथा बंजरभूमि पर खेती की जावेगी। सिदरी (बिहार) का खाद का कारखाना बन जाने से खाद की सुविधा तो हो ही गई है।

इस प्रयत्न के फलस्वरूप खेती की पैदावार में सन् १९५८ तक नीचे लिखी वृद्धि होगी।

खाद्यान्न ( अनाज )	७२ लाख टन
जूट ( पटसन )	२० लाख गॉट्टे
कपास	१२ लाख गॉट्टे
तिलहन	३ लाख ७५ हजार टन
गुड़	६ लाख ६० हजार टन

७२ लाख टन अधिक अनाज उत्पन्न करने पर भी ३० लाख टन अनाज विदेशों से मँगवाना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि निरुक्त भविष्य में खाद्य-पदार्थों की दृष्टि से स्वावलम्बी होने की कोई भी आशा नहीं है। हाँ, कपास और जूट का दृष्टि से अवश्य भारत स्वावलम्बी हो जावेगा।

कृषि अनुसंधान कौंसिल का मत है कि देश में लगभग ३० प्रतिशत जनसंख्या को पूरा भोजन नहीं मिलता और जो भोजन भारतीय जनता को मिलता है, न तो वह यथेष्ट है और न पुष्टिकर। अतएव खाद्य पदार्थों में नीचे लिखी वृद्धि आवश्यक है। अनाज में १० प्रतिशत, दालों में २० प्रतिशत, घी-तेल इत्यादि में २५० प्रतिशत, फलों में ५० प्रतिशत, सब्जियों में १०० प्रतिशत, दूध में ३०० प्रतिशत, अंडे और मछलियों में ३०० प्रतिशत तथा चारे में ५५ प्रतिशत।



## समाज विकास कार्यक्रम

भारत में ग्रामों के विकास तथा खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन करने के लिए, तथा ग्रामवासियों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने के लिये भारत सरकार ने समाज विकास कार्यक्रम को स्वीकार किया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में समाज विकास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस समाज विकास कार्यक्रम का प्रभाव १७,५०० गाँवों और लगभग एक करोड़ बीस लाख ग्रामवासियों पर पड़ेगा।

भारत सरकार इस समाज विकास कार्यक्रम को संयुक्तराज्य अमेरिका की आर्थिक सहायता तथा फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से कर रही है। अमेरिका ने केवल आर्थिक सहायता ही प्रदान नहीं की है बल्कि टेक्निकल सलाह-कार भी दिए हैं जो कि इस समय समाज विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में भारत सरकार को सहायता दे रहे हैं।

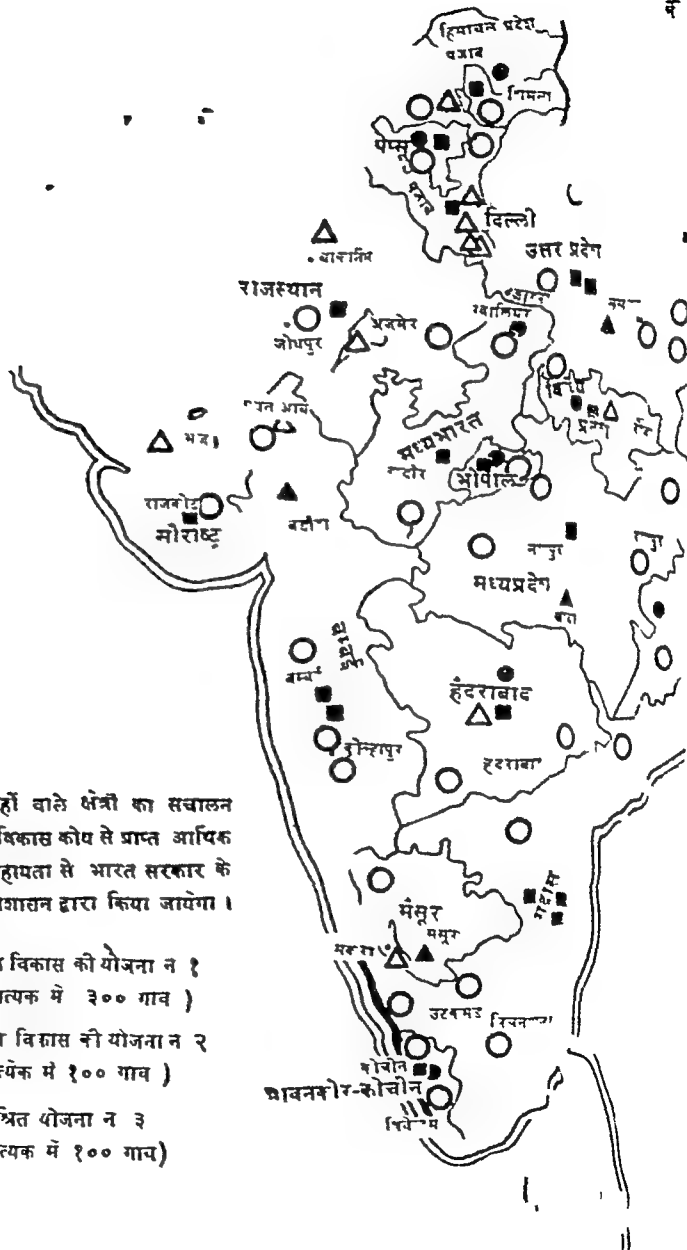
इस समाज विकास कार्यक्रम की योजना में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि ग्रामवासी यह अनुभव न करें कि उन्हें सुधारों को अपनाने के लिए विवश किया जा रहा है अथवा उन्हें उन पर लादा गया है। वस्तुतः सारे कार्यक्रम का सञ्चालन इस ढङ्ग से किया जावेगा जिससे ग्रामवासी स्वयं ही इस कार्यक्रम में सक्रिय भाग लें। उन्हें स्वयं करने, अथवा अनुभव बढ़ाने और वैयक्तिक सफलता और उन्नति की भावना को जाग्रत करने के लिये प्रोत्साहित किया जावेगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम में तीन प्रकार की योजनाएँ होंगी।

प्रस्तावित कार्यक्रम का लक्ष्य स्थूल रूप से प्रत्येक ग्राम में निम्न प्रकार होगा :—

पाने के साथ पानी की व्यवस्था करने के लिए दो कुये अथवा अन्य कोई व्यवस्था करना। जहाँ नल कूप (स्थूब-वैल) खोदे जा सकते हैं वहाँ सिचाई के लिए स्थूब वैल खोदे जावेंगे। अन्य प्रदेशों में सिचाई के लिए नहरों, तालाबों, तथा कुओं का निर्माण कराया जावेगा जिससे कि गाँव की कम से कम आधी भूमि के लिए सिचाई की व्यवस्था ठीक हो जावे। इसके अतिरिक्त यथासम्भव अधिक से अधिक परती भूमि पर खेती की जावेगी। गाँवों में सफाई रखने और पानी निकालने की नालियों का प्रबन्ध किया





निम्नांकित चिह्नों वाले क्षेत्रों का संचालन भारत-अमेरिकी विकास कोष से प्राप्त आर्थिक और तकनीक सहायता से भारत सरकार के समाज विकास प्रशासन द्वारा किया जायेगा।

- समाज विकास की योजना न १  
( प्रत्येक में ३०० गाव )
- △ समाज विकास की योजना न २  
( प्रत्येक में १०० गाव )
- मिश्रित योजना न ३  
( प्रत्येक में १०० गाव )





आवेगा । एक गाँव से दूसरे गाँव को मिलाने वाली सड़कें बनाई जावेंगी और प्रौढ़ शिक्षा को सुविधाएँ दी जावेंगी ।

इस कार्यक्रम में कृषि-उन्नति पर विशेष बल दिया जावेगा । यह कार्य ग्राम कार्यकर्त्ताओं ( जिनको ट्रेनिंग दी जावेगी ) द्वारा किया जावेगा । वे ग्रामीणों को आधुनिक कृषि उपकरणों, उत्तम बीज, खेत की खाद, हरी खाद की फसलों, रासायनिक खाद और सीधे सादे औजारों से काम लेने की विधियाँ बतलावेंगे ।

प्रत्येक १५ या २० गाँवों में जहाँ कोई मंडी नहीं है वहाँ एक मंडी खोली जावेगी । इस मंडी में एक दवाखाना और स्वास्थ्य केन्द्र होगा जिसका लाभ एक चलते-फिरते औषधालय के रूप में दूर-दूर तक के ग्रामों को मिल सकेगा । उसके साथ स्वास्थ्य-निरीक्षक, दाइयाँ तथा सफाई निरीक्षक भी होंगे । मंडी में पशुओं का दवाखाना तथा गाड़ियों और ट्रैक्टरों की मरम्मत के अलावा, खेती की पैदावार की खरीद बिक्री तथा खेती की पैदावार को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाने की व्यवस्था की जावेगी ।

ऐसा अनुमान किया जाता है इस कार्यक्रम के द्वारा पाँच वर्षों में इन गाँवों में खाद्य-उत्पादन में ५० प्रतिशत की वृद्धि होगी और प्रत्येक गाँव की नकद आमदनी में ३५ प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी जिसके फलस्वरूप ग्रामवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा होगा और खाद्य पदार्थों की कमी की समस्या हल हो सकेगी ।

### अभ्यास के प्रश्न

१—उत्तर प्रदेश में कृषि-विभाग कब खोला गया और आरम्भ में उसने क्या काम किया ?

२—आजकल प्रदेश में कृषि-विभाग कौन-कौन से कार्य करता है ?

३—प्रदेश में कृषि-शिक्षा का कहाँ-कहाँ प्रबन्ध है और इन कृषि स्कूल और कालेजों से क्या लाभ हैं ?

४—कृषि-विभाग के स्थापित होने से प्रदेश में खेती की क्या उन्नति हुई है ?

५—कृषि-विभाग अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये आविष्कारों का प्रचार किस प्रकार करता है ?

६—अच्छे बीज पैदा करने और उसके बेचने का प्रबन्ध इस प्रदेश में कैसा है ?

७—कृषि प्रदर्शनियों की क्या उपयोगिता है ?

८—भारत में खाद्य-पदार्थों का जो अभाव है उसी पर एक नोट लिखिए।

## सत्ताइसवाँ अध्याय

### ग्राम और जिले का शासन

अब हम ग्राम और जिले का किस प्रकार शासन होता है इस पर विचार करते हैं। अधिकांश गाँवों की दशा खराब है, पढ़-लिख कर सुयोग्य हो जाने पर लोग जाकर शहरों में बस जाते हैं, वे ग्रामों का ध्यान नहीं रखते। इसी से ग्रामों की सफाई, रहन-सहन आदि में यथेष्ट उन्नति नहीं हो पाती। देश का जो भला चाहते हैं उन्हें गाँवों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन करना चाहिये।

#### ग्राम-शासन : ग्राम के मुख्य कर्मचारी

हर गाँव में तीन कर्मचारी होते हैं—मुखिया, पटवारी और चौकीदार। पटवारी किसानों से लगान तथा सिंचाई (आबपाशी) की रकम वसूल करता है, और उसे तहसील में जमा कर देता है।

#### मुखिया

गाँव के किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मुखिया बना दिया जाता है। मुखिया गाँव की घटनाओं को चौकीदार के द्वारा पुलिस में रिपोर्ट करवाता है। उसका तहसील से भा सम्बन्ध होता है। दौरे के समय वह राज्य कर्मचारियों के साथ सहयोग करता है।

#### पटवारी

बड़े गाँव में एक ही गाँव का, और छोटे-छोटे गाँवों में दो-दो या अधिक का, एक पटवारा होता है। वह अपने गाँव के किसानों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों के कागज तथा रजिस्टर आदि रखता है। जब खेती में कोई तबदीली हो, कोई खेत या उसका हिस्सा बिक जावे,

या किसी खेत का मालिक बदल जावे या मर जावे तो पटवारी इस बात की रिपोर्ट तहसील में करता है। वह खेतों के नक्शे बनाता है। वह लगान का हिसाब रखता है। खेतों में कितनी पैदावार हुई है, कितनी भूमि पर अमुक फसल उत्पन्न की गई है, गाँव में कितने पशु हैं, इनके आँकड़े भी पटवारी ही रखता है।

### चौकीदार

चौकीदार गाँव में पहरा देता है और चौकसी करता है। वह पुलिस में प्रति सप्ताह यह खबर देता है कि गाँव में उस सप्ताह के भीतर कितने आदमी मरे, कितने बच्चों का जन्म हुआ; वह गाँव की चोरी, मारपीट तथा अन्य अपराधों की रिपोर्ट करता है।

### तहसीलदार

ऊपर बतलाये हुये गाँवों के कर्मचारी तहसील के अधीन होते हैं। तहसीलदार अपनी तहसील का प्रधान अधिकारी होता है। तहसीलदार के सहायक कर्मचारी नायब तहसीलदार, कानूनगो इत्यादि होते हैं। प्रत्येक कानूनगो को एक परगना दे दिया जाता है, वह उस परगने के पटवारियों के काम की देखभाल करता है। तहसीलदार प्रजा और अपने से ऊपर के अधिकारियों को एक दूसरे के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देता रहता है। उसका मुख्य कार्य तहसील की लगान वसूल करना है, जिसे वह अपने सहायक कानूनगोओं की सहायता से वसूल करता है। तहसीलदार फौजदारी के मामले भी सुनता है। उसे तीसरे या दूसरे दर्जे की मजिस्ट्रेट के अधिकार भी होते हैं। वह पचास से लेकर दो सौ रुपये तक जुर्माना और एक माह से छः माह तक की कैद की सजा दे सकता है। इन राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे विभाग हैं जिनका गाँव के शासन से तो कोई सम्बन्ध नहीं है वरन् गाँव की भलाई करना जिनका कर्तव्य है। इन विभागों के कर्मचारियों का भी गाँव से सम्पर्क रहता है, उदाहरण के लिए आपवाशी, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, ग्रामसुधार विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। इन कर्मचारियों का गाँव की सेवा करना मुख्य कार्य है।

---

मजिस्ट्रेट—वह कर्मचारी जिसे शासन तथा न्याय सम्बन्धी कुछ अधिकार प्राप्त हों।



## देहाती बोर्ड और जिला कौंसिल

देहातों में प्रारम्भिक शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का कार्य करने वाली मुख्य संस्थाएँ बोर्ड कहलाती हैं। इनके तीन भेद हैं। किसी-किसी प्रदेश में तो इनमें से तीनों ही प्रकार के बोर्ड हैं और कहीं-कहीं केवल दो या एक ही तरह के हैं।

१—लोकल बोर्ड—यह कुछ ग्रामों के समूह में होता है।

२—ताल्लुका या सब-डिवीजनल-बोर्ड—यह एक ताल्लुके या सब-डिवीजन में होता है। यह लोकल बोर्डों के काम की देखभाल करता है।

३—जिला बोर्ड—इसे किसी प्रदेश में जिला कौंसिल भी कहते हैं, यह एक जिले में होता है और जिले भर के लोकल-बोर्डों (या ताल्लुका बोर्डों) का निरीक्षण करता है।

इन बोर्डों का संगठन कुछ म्यूनिसिपैलिटियों की ही भाँति होता है। यद्यपि बोर्डों में अधिकतर चुने हुए सदस्य ही होते हैं, तथापि कहीं-कहीं नामजद सदस्य भी काफी होते हैं। किस जिला बोर्ड में कितने सदस्य हों तथा उसका सभापति चुना हुआ रहे या नियुक्त किया जावे, यह प्रत्येक प्रदेश के जिला बोर्ड कानून से निश्चित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सभापति चुना हुआ एव गैर सरकारी होता है।

### निर्वाचक और सदस्य

जिला बोर्डों के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचक या मतदाता नहीं हो सकते—(क) जो स्वतन्त्र भारत की प्रजा न हों (ख) जो अदालत से पागल ठहराये गये हों और (ग) जो इक्कीस वर्ष से कम के हों। इन्हें छोड़कर साधारणतया ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) निर्वाचक हो सकता है जो कि लगान अथवा कर देता हो। वह शिक्षित हो। शिक्षा कौन से दर्जे तक हो यह भी निश्चित है।

निर्वाचकों को चाहिए कि खूब सोच-समझ कर वोट दे। उन्हें ऐसे उम्मीदवार को ही अपना वोट देना चाहिये जो कि गाँव वालों की सच्ची सेवा करना चाहता हो और सदस्य बनने के सर्वथा योग्य हो और जिससे गाँवों का विशेष हित होने की आशा हो। किसी स्वार्थवश वा किसी प्रकार के लिहाज के कारण अयोग्य आदमियों को कभी वोट न देना चाहिये।

बोर्ड के चुनाव के लिये जिले को भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य बोर्ड में जाता है। बोर्ड के सदस्य गाँव के हित बहुत कुछ काम कर सकते हैं, उन्हें गाँव वालों की सेवा का बहुत अवसर मिलता है। यदि सच्चाई और ईमानदारी से सदस्य ग्रामवासियों की सेवा करना चाहे तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। अतएव उन्हीं लोगों को चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े होना चाहिए जो योग्य हों और समय देकर गाँव वालों की सेवा करना चाहे।

### जिला बोर्ड के कार्य

बोर्ड का कर्तव्य अपने ग्राम्य क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि के अतिरिक्त कृषि और पशुओं की उत्पत्ति करना है। इस प्रकार इनके मुख्य कार्य ये हैं :—१—सड़कें बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना। उन पर पेड़ लगवाना और उन पेड़ों की रक्षा करना। २—प्रारम्भिक शिक्षा का प्रचार और प्रबन्ध करना ( देहातों में प्राइमरी या मिडिल स्कूल जिला बोर्ड के ही होते हैं ) ३—चिकित्सा और स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना, चेचक या प्लेग आदि का टीका लगवाना, पशुओं के इलाज के लिये पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करना। ४—बाजार, मेला, नुमाइश या कृषि-प्रदर्शनी का प्रबन्ध करना। ५—पीने के पानी के लिये तालाब या कुएँ खुदवाना या उनकी मरम्मत करवाना। ६—कॉजी हौज अर्थात् ऐसे स्थान की व्यवस्था करना, जहाँ खेती आदि की हानि करने वाले जानवर रोक रखे जाते हैं। जिस आदमी का पशु नुकसान करते हैं वह उन्हें कॉजी हौज भेज देता है। जब पशु का मालिक उसे लेने जाता है तो उसे निर्धारित जुर्माना देना पड़ता है। ७—घाट, नाव, पुल आदि का प्रबन्ध करना।

### जिला बोर्डों की आय

स्वतन्त्र भारत में बोर्डों के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या इक्कीस करोड़ से भी अधिक है। उपर्युक्त कार्यों तथा इस जनसंख्या को देखते हुये उनकी कुल वार्षिक आय जो लगभग सोलह करोड़ रुपये है बहुत कम है। यह अधिकतर उस महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया गया है, और जो सरकारी वार्षिक लगान के साथ ही प्रायः एक

आना या अधिक फी रुपये के हिसाब से वसूल करके इन बोर्डों को दे दिया जाता है। इनके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिये सरकार बोर्डों को कुछ रकम कुछ शर्तों पर प्रदान करती है। आय के अन्य साधन, तालाब, घाट, सड़क पर महसूल, पशु चिकित्सा और स्कूल की फीस, काँजी हौज की आमदनी, मेले, नुमाइशों पर कर तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर हैं। प्रायः लोकल बोर्डों की कोई स्वयं आय नहीं होती। उन्हें समय पर जिला बोर्डों से ही कुछ रुपया मिल जाता है। वे उस रुपये को जिला-बोर्ड की इच्छा या सम्मति के विरुद्ध खर्च नहीं कर सकते।

### सरकारी नियंत्रण

डिप्टी कमिश्नर ( या कलेक्टर ) अथवा कमिश्नर इनके काम की देख-भाल करते हैं। कलेक्टर को इनके सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार हैं। जब वह समझे कि जिला बोर्ड का कोई काम या कोई प्रस्ताव आदि ऐसा है जिससे सार्वजनिक हित की हानि होती है तो वह उस काम को बन्द कर सकता है तथा उस प्रस्ताव को अमल में लाये जाने से रोक सकता है। यदि प्रदेशीय सरकार यह समझे कि कोई बोर्ड अपना कार्य ठीक तरह से नहीं करता तो वह उसे तोड़ सकती है। उस दशा में बोर्ड में नया चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिला बोर्डों के सम्बन्ध में एक नया कानून बनाने जा रही है। उसके अनुसार बोर्डों के कार्य में कलेक्टर या कमिश्नर को हस्तक्षेप करने का भविष्य में अधिकार नहीं रहेगा और न बोर्ड में नामजद सदस्य ही रखे जावेंगे। स्वायत्त शासन विभाग का मन्त्री ( Minister Local Self-Government ) ही बोर्डों का नियंत्रण करेगा।

### नागरिक भावों की आवश्यकता

हमें यह भी भली भाँति समझ लेना चाहिये कि यदि हमारे गाँव में अशिक्षा, गन्दगी और लड़ाई-झगडा रहेगा तो हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती। अतएव हमें अपने गाँव और जिले की भलाई का ध्यान रखना चाहिये। अस्तु, प्रत्येक गाँव के व्यक्ति को जिला बोर्ड के काम में दिलचस्पी लेना चाहिये और यह देखते रहना चाहिये कि निर्वाचित सदस्य गाँवों की भलाई के लिये क्या-क्या कार्य कर रहे हैं ? जब मतदाता ( वोटर ) इतने सतर्क रहेंगे तभी बोर्ड अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकेगा।

## जिले का शासन

यह तो हम पहले ही बतला चुके हैं कि ग्राम के कर्मचारी तहसीलदार के अधीन होते हैं। तहसीलदार सब-डिवीजनल आफसर के अधीन, और सब-डिवीजनल आफसर जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के अधीन होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट को पू० पंजाब, तथा मध्यप्रदेश में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं और शेष प्रदेशों में कलेक्टर कहते हैं।

मदरास प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में कुछ-कुछ जिलों का एक कमिश्नरी है। उसका प्रधान अधिकारी कमिश्नर कहलाता है। यह अपनी कमिश्नरी के जिलों के प्रबन्ध की देखभाल करता है। अब हम जिले का शासन कैसे होता है इसका वर्णन करते हैं।

### शासन-व्यवस्था में जिले का स्थान

स्वतन्त्र भारत में कुल मिलाकर करीब २५० जिले हैं। जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सरकारी प्रायः भिन्न-भिन्न हैं। तथापि राज्य की कल जैसी एक जिले में चलती हुई दिखाने देती है वैसे प्रायः अन्य जिलों में भी है। जैसे आफसर एक जिले में काम करते हैं वैसे ही औरों में भी हैं। जनता के काम-बाज का केन्द्र जिला होता है। ग्रामीण जो अधिकतर प्रवास-भीरु होते हैं उन्हें भी जिलों में काम पड़ता है। जिले के शासन प्रबन्ध का देखकर ही देश के शासन का अनुमान किया जा सकता है।

### जिला मजिस्ट्रेट के कार्य

पर दो साल की कैद और एक हजार रुपये तक जुर्माना कर सकता है। जिले की सब प्रकार की सुख-शान्ति का वही उत्तरदाता है। वही स्थानीय पुलिस की निगरानी भी करता है। इस बात का निश्चय करने में कि कहाँ पुल, सड़क, इत्यादि बनने चाहिये, कहाँ सफाई का प्रबन्ध होना चाहिए, तथा जिले के किन-किन स्थानों को स्थानीय स्वराज्य मिलना चाहिए, उसी की सम्मति प्रामाणिक मानी जाती है। जिले में जिस बात का प्रबन्ध ठीक न हो उसका सुधार करना, और हर एक बात की रिपोर्ट उच्च कर्मचारियों के पास भेजना, उसी का कर्तव्य है। जिले की आन्तरिक दशा जानने तथा उसे सुधारने के विचार से उसे देहात में दौरा करना होता है।

### जिले के अन्य कर्मचारी

जिले में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे शान्ति रखना, झगड़ों का फैसला करना, मालगुजारी वसूल करना, सड़क पुल आदि बनवाना, अकाल में लोगों की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, म्युनिसिपैलिटी, जिला बोर्डों की निगरानी रखना, जेलखाने और स्कूलों का निरीक्षण करना। इन विविध कार्यों के लिए जिले में कई अफसर रहते हैं, जैसे स्कूल के डिप्टी इन्स्पेक्टर या पुलिस का सुपरिन्टेन्डेन्ट या पुलिसकप्तान, अस्पताल का सिविल सर्जन, जेलों का सुपरिन्टेन्डेन्ट, निर्माण कार्य के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और न्याय कार्य के लिए जिला जज आदि होते हैं। ये अफसर अपने पृथक्-पृथक् विभागों के कर्मचारियों के अधीन होते हैं। परन्तु शासन के विचार से जिला जज और मुंसिफ आदि को छोड़ कर सब पर जिला मजिस्ट्रेट ही प्रधान होता है। जिला मजिस्ट्रेट के कार्य में सहायता देने के लिए डिप्टी और सहायक मजिस्ट्रेट भी रहते हैं।

प्रायः प्रत्येक जिले के कुछ भाग होते हैं जिन्हें सब-डिवीजन कहते हैं। हर एक सब-डिवीजन एक डिप्टी कलेक्टर अथवा अतिरिक्त असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन रहता है। सब-डिवीजनों के अफसरों के अधिकार जिला मजिस्ट्रेट की भाँति होते हैं।

### कमिश्नर

रहिले कहा जा चुका है कि मद्रास प्रदेश को छोड़ कर प्रत्येक बड़े

प्रदेश में कुछ कमिश्नरियाँ होती हैं। इनके प्रधान अफसर को डिवीजनल-कमिश्नर या कमिश्नर कहते हैं। वह शासन सम्बन्धी कोई विशेष कार्य नहीं करता। केवल अपने अधीन जिला अफसरों के कार्य की जाँच-पड़ताल करता है। जिलों से जो रिपोर्ट या पत्र आदि प्रदेशीय सरकार के पास जाते हैं वे सब कमिश्नर के हाथ से गुजरते हैं। कमिश्नर माल ( रेवन्यू ) के सुकदमों की अपील भी सुनता है। लगान के बन्दोबस्त में इसका काम केवल परामर्श देना है, पर विशेष दशाओं में उसे लगान की वसूली रोकने का अधिकार है।

कमिश्नरों को अपनी-अपनी म्युनिसिपैलिटियों के काम देखने-भालने के भी कुछ अधिकार होते हैं। परन्तु उनका विशेष सम्बन्ध लगान के प्रबन्ध के लिये होता है। पू० पञ्जाब और मध्य प्रदेश में सर्वोच्च अधिकारी फाइनैसियल कमिश्नर है और उत्तर-प्रदेश, बिहार और बंगाल में रेवन्यू बोर्ड है। रेवन्यू बोर्ड में एक से लेकर चार तक मेम्बर होते हैं। फाइनैसियल कमिश्नर और रेवन्यू बोर्ड कमिश्नरों और कलेक्टरों के कार्य की देखभाल करते हैं। माली मामलों में यह कमिश्नरों के निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं।

### अभ्यास के प्रश्न

१—गाँव के मुख्य कर्मचारी कौन से होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं ?

२—तहसीलदार और उसके अधीन कर्मचारी क्या काम करते हैं ?

३—जिला बोर्ड किसे कहते हैं और वह कैसे बनता है ?

४—जिला बोर्ड क्या-क्या काम करता है ?

५—जिला बोर्ड के पास खर्च करने के लिये क्या कहाँ से आता है ?

६—यदि तुम कभी अपने जिला बोर्ड के चेयरमैन चुने जाओ और बहुत-बहुत तुम्हारे पक्ष में हो तो तुम गाँवों की दशा सुधारने के लिये क्या करोगे ?

७—जिला का शासन किस प्रकार चलता है ? पटवारी या मुखिया का रूम क्या स्थान है ? ( १६४३ )

८—जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर क्या काम करते हैं ?

६—गाँव वालों का कौन से सरकारी विभागों से अधिक काम पड़ता है ?

१०—अपने जिले की शासन-व्यवस्था का विशद वर्णन कीजिये । ग्रामीणों के लिये चौकीदार, पटवारी और तहसीलदार का क्या काम और महत्त्व है ? ( १६४५ )

## अट्ठाइसवाँ अध्याय

### ग्राम-पंचायत

यद्यपि गाँव की दशा अत्यन्त गिरी हुई है और हानिकारक रूढ़ियों के कारण उनकी दशा और भी खराब हो गई है, फिर भी गाँवों में सामाजिक जीवन में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो आज भी नष्ट नहीं हुई हैं । यदि गाँव की उन अच्छी रस्मों के आधार पर गाँव में कार्य किया जावे तो वहाँ बहुत कुछ सुधार हो सकता है । गाँवों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिये यह आवश्यक है कि गाँव वालों के पारस्परिक सम्बन्ध को समझ लिया जावे ।

### गाँव वालों का पारस्परिक सम्बन्ध

गाँव में भ्रातृभाव तथा सहयोग की भावना अब भी बहुत कुछ अशों में शेष है । सारा गाँव एक बड़े कुटुम्ब के समान होता है और समय पड़ने पर सब लोग एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते हैं ।

यदि किसी किसान के यहाँ लडकी का विवाह होता है तो गाँव भर के लोग अनाज, लकड़ी, दही, दूध तथा टीके के रुपयों से उसकी सहायता करते हैं । विवाह का सारा कार्य विरादरी तथा गाँव की अन्य स्त्रियाँ मिलकर कर लेती हैं । पुरुष भी बारात की सेवा में भरसक सहायता देते हैं । खेतों की बोवाई, सिचाई और कटाई के समय भी किसान एक दूसरे का काम करते हैं जिससे कि काम हलका हो जाता है । प्रत्येक विरादरी की एक पञ्चायत होती है, जो कि अपनी विरादरी के सामाजिक जीवन का नियन्त्रण करती है । किसी-किसी प्रदेश में जहाँ कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव नहीं है, गाँव का सारा आर्थिक और सामाजिक संगठन ही सहयोग के आधार

पर खड़ा हुआ मिलता है। राजपूताने के गाँवों में सिचाई के लिए गाँव के तालाब की मरम्मत गाँव के प्रत्येक पुरुष और गाँव की बहू ( गाँव की लड़कियाँ इस श्रम से मुक्त हैं ) को करनी पड़ती है। गाँव के मन्दिर के व्यय के लिए घर पीछे पाव भर रुई, सवा सेर तेल और छटौंठ भर घी लिया जाता है। गाँव के झगड़ों का फैसला पंचायत करती है, और शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए, ग्राम-पंचायत घर के पीछे कर उगाहती है। एक प्रकार से सारा स्थानीय शासन ही गाँवों की पंचायत करती है। गाँव के लोग फिर चाहे वे भिन्न-भिन्न जातियों के ही क्यों न हों एक दूसरे को अपने भाई के समान ही मानते हैं। एक क्षत्रिय का लड़का भी एक कहार को जो उससे आयु में बड़ा है चाचा या दादा कहकर पुकारता है। पहले तो गाँवों का जीवन सुन्दर, मधुर और सहयोग का आदर्श जीवन था। किन्तु आधुनिक-काल में पश्चिमी सभ्यता के मूल आधार व्यक्तिवाद\* (Individualism) के प्रभाव के कारण तथा आर्थिक और सामाजिक पतन के कारणों से गाँवों का यह सुन्दर सामाजिक संगठन नष्ट होता जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि गाँवों को इन अच्छी रस्मों और भावों को नष्ट होने से बचाया जावे और गाँवों को नवजीवन प्रदान किया जावे।

### गाँवों की संस्थाएँ और उनका महत्व

भारतीय ग्रामों की मुख्य संस्था पंचायत थी। ब्रिटिश शासन के पूर्व पंचायत वस्तुतः गाँव का शासन करती थी और प्रत्येक गाँव इस दृष्टि से स्वावलम्बी था। ब्रिटिश शासन काल में उनका महत्व जाता रहा। पंचायत के विषय में नीचे विस्तारपूर्वक लिखा जाता है। भविष्य में सम्भवतः पंचायतें फिर महत्वपूर्ण हो जावेगी।

दूसरी महत्वपूर्ण संस्था जो किसी-किसी गाँव में पाई जाती है वह है सहकारी समिति। सहकारी समितियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। साख-समिति, उत्पादक-समिति, क्रय-विक्रय-समिति, रहन-सहन-सुधार-समिति तथा उपभोक्ता भंडार-समिति इत्यादि। सहकारी समितियाँ गाँव वालों को ऋण देने तथा

---

\* व्यक्तिवाद—इस सिद्धान्त को मानने वाले केवल अपने स्वार्थों की ओर ही ध्यान देते हैं।



उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयत्न करती हैं। इनके विषय में सहकारिता के अध्याय में विस्तारपूर्वक लिखा गया है।

थोड़े दिनों से गाँवों में प्रदेशीय सरकारों की ओर से ग्राम-सुधार का कार्य हो रहा है। जिस गाँव को ग्राम-सुधार कार्य के लिये छाँटा जाता है वहाँ एक ग्राम-सुधार पचायत का चुनाव कर लिया जाता है। आर्गनाइजर इन पचायतों के सहयोग तथा परामर्श से ग्राम-सुधार का कार्य करते हैं।

इनके अतिरिक्त किसी-किसी गाँव में स्वतन्त्र पचायतें होती हैं जो पुरानी पचायतों के अवशेष चिह्न मात्र होती हैं। वे सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होती हैं, परन्तु गाँव के सार्वजनिक कार्यों की देख-भाल करती हैं तथा उन पर नियन्त्रण रखती हैं। गऊशाला, मन्दिर, प्याऊ तथा कहीं-कहीं पाठशालाओं को भी ये पचायतें चलाती हैं। परन्तु इस प्रकार भी पचायतें बहुत कम हैं।

### पचायतें

प्राचीन काल में यहाँ प्रत्येक गाँव और नगर में प्रभावशाली पचायतें रहती थी, जो सारा स्थानीय शासन स्वयं करतीं और केन्द्रीय (Central) सरकार अर्थात् राजा के सामने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। पचायत स्थानीय रक्षा के लिए अपनी पुलिस रखती, स्वयं भूमि-कर वसूल करके राज-कोष में भेजती, गाँव और नगर की सफाई का प्रबन्ध करती थी। अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थान, जलाशयों तथा पाठशालाओं की देख-भाल तथा उनका पंचालन करती थी, और अपने गाँव नगर में छोटे-छोटे दीवानी और फौजदारी के झगड़ों का निपटारा करती थी। भारत में पचायतों का यहाँ तक विश्वास और प्रभाव था कि अब तक भी “पंच-परमेश्वर” की कहावत चली आती है। हिन्दू राजाओं के जमाने से ही यहाँ पचायतें थी, मुसलमानी अमलदारी में भी वे एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में रहीं। परन्तु अंग्रेजी शासन काल में उनकी आय तथा अधिकार प्रान्तीय सरकार ने ले लिए। पुलिस तथा फौजदारी अदालतें स्थापित कर दी गई जिससे पंचायतों का क्रमशः हास हो गया। अब भी कहीं-कहीं पचायतें हैं जो धर्मशाले, मन्दिर, जलाशय तथा अन्य धार्मिक हित के कार्य करती हैं, किन्तु ये प्राचीन व्यवस्था के स्मृति-चिह्न मात्र हैं।

कुछ वर्षों से भारतीय ग्रामों की इस संस्था का महत्व सरकार ने समझा है और पंचायतों को पुनः नवीन रूप से स्थापित करने का उद्योग किया जा रहा है। इनके सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रदेशों में नए-नए कानून बनाये गये हैं और धीरे-धीरे इनकी स्थापना की जा रही है।

### पंचायत की सफलता के उपाय

पंचायतों से ग्राम-सुधार तथा न्याय सम्बन्धी बहुत कुछ काम हो सकता है। लोगों का मुकदमेबाजी में जो अपरिमित धन और शक्ति नष्ट होती है। वह बहुत कुछ बच सकती है। हाँ, ऐसी संस्थाओं की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझे। वे अधिकारियों के दबाव में न रहे, अपने नैतिक बल से कार्य करें, तभी जनता का उन पर यथेष्ट विश्वास हो सकता है और उन्हें लोगों का समुचित सहयोग मिल सकता है। पंच ऐसे आदमी होने चाहिये जिनके लिये जनता की सम्मति हो, जिन्होंने सर्वसाधारण की सेवा की हो तथा भविष्य में भी जो लोक-हित के अभिलाषी हों। पंचों का कर्त्तव्य है कि वे अधिकार की भावना न रखकर अपने कार्य को कर्त्तव्य समझ कर सेवा भाव से काम करें; जनता के अधिकाधिक सम्पर्क में आवें, और उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों की यथेष्ट जानकारी रखें। अभी तक पंचायतों को बहुत कम अधिकार दिये गए थे इसी कारण उनका कोई विशेष महत्व नहीं था। जनता की माँग है कि भविष्य में पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जावें। सम्भवतः अब जब कि जनता के प्रतिनिध ही प्रदेश का शासन कर रहे हैं तब सब प्रदेशों में पंचायतों के अधिकार अवश्य बढ़ा दिये जावेंगे।

### उत्तर प्रदेश का पंचायत राज्य कानून

सन् १९४७ में उत्तर-प्रदेश का पंचायत-राज्य विधान स्वीकार हो गया और २७ दिसम्बर सन् १९४७ से लागू कर दिया गया। इस विधान के अनुसार गाँव की पंचायतों को गाँव के शासन में बहुत कुछ अधिकार मिल गये हैं और वे स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले रही हैं।

इस विधान के अन्तर्गत नीचे दी हुई संस्थाये स्थापित हो गई हैं जो गाँव का शासन प्रबन्ध करती हैं :—

### गाँव सभा

उत्तर-प्रदेश की सरकार ने गाँवों में गाँव सभाएँ स्थापित कर दी हैं। प्रत्येक गाँव सभा में वे सब प्रौढ सम्मिलित होते हैं जो उस क्षेत्र के स्थायी निवासी हों। लेकिन ऐसा कोई प्रौढ उसका सदस्य नहीं हो सकेगा यदि—

(क) उसका दिमाग खराब हो।

(ख) उसको कोढ़ हो।

(ग) वह दिवालियेपन से बरी नहीं किया गया हो।

(घ) सरकारी नौकर हो वा आनरेरी मजिस्ट्रेट, आनरेरी मुसिफ या आनरेरी असिस्टेन्ट कलेक्टर हो जिसके अधिकार क्षेत्र में किसी गाँव-सभा का क्षेत्र हो।

(ङ) उसे चुनाव सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दंड दिया जा चुका हो या।

(च) उसको किसी नैतिक अपराध में दंड दिया जा चुका हो या नेक चलनी के लिए जमानत जमा करने की आज्ञा दी गई हो।

गाँव सभा की वर्ष में दो बैठके होती हैं, एक खरीफ की बैठक दूसरी रबी की बैठक। आवश्यकता पड़ने पर सभापति स्वयं अथवा १ सदस्यों की लिखित माँग पर स्वयं बैठक बुला सकता है।

गाँव सभा की खरीफ की बैठक में सभा का बजट तैयार करके विचारार्थ उपस्थित किया जाता है तथा रबी की बैठक में वर्ष का हिसाब रक्खा जाता है।

गाँव सभा अपने सदस्यों में से एक को सभापति और दूसरे को उप-सभापति चुनती है जो तीन वर्ष तक अपने पद पर रहता है।

गाँव सभा अपने सदस्यों में से कम से कम ३० व्यक्तियों की एक “गाँव पंचायत” चुनती है जो सभा की कार्यकारिणी होती है। गाँव सभा का सभापति और उपसभापति क्रमशः गाँव पंचायत के सभापति और उपसभापति होते हैं।

### गाँव पंचायत के कार्य

(क) सड़कों को बनवाना, उनकी मरम्मत कराना, उनकी सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध करना।

(ख) चिकित्सा का प्रबन्ध करना।

( ग ) गाँव की सफाई करवाना तथा संक्रामक रोगों को दूर करने का उपाय करना ।

( घ ) जन्म, मृत्यु तथा विवाहों का रजिस्टर रखना ।

( ङ ) मेलों तथा बाजारों का प्रबन्ध करना ।

( च ) गाँव में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध ।

( छ ) चरागाहों को छोड़ना और उनका प्रबन्ध करना ।

( ज ) कुओं तथा तालाबों को सार्वजनिक उपयोग के लिए बनवाना तथा उनकी मरम्मत कराना ।

( झ ) खेती-बारी, व्यापार और उद्योग धंधों की उन्नति में सहायता करना ।

( ञ ) आग लग जाने पर लोगों के जीवन तथा उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना ।

( ट ) सूतिका ( बच्चा उत्पन्न कराने ) और शिशुओं का हित-साधन करना ।

( ठ ) खाद इकट्ठा करने के लिए स्थान नियत करना ।

( ड ) मार्गों पर तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगवाना ।

( ढ ) मवेशियों की नस्ल सुधारना, उनकी चिकित्सा और उनके रोगों की रोक-थाम करना ।

( ण ) गाँव की रक्षा करने तथा गाँव पंचायत की सहायता करने के लिए गाँव स्वयंसेवक दल का संगठन करना ।

( त ) गाँव में मनोरंजन के साधन उपलब्ध करना तथा पुस्तकालय इत्यादि स्थापित करना ।

### गाँव पंचायत के कर

इन कार्यों को करने के लिए गाँव सभा निम्नलिखित कर वसूल कर सकती है :—

( १ ) एक आना की रुपया मालगुजारी पर टैक्स किसानों से वसूल करेगी ।

( २ ) अधिक से अधिक ६ पाई की रुपया मालगुजारी पर जमींदार से वसूल करेगी ।

( ३ ) एक टैक्स खुदकाश्त या सीर पर भी लगाया जावेगा ।

( ४ ) एक टैक्स व्यापार, कारवार और पेशों पर जो ऐसी दर से अधिक न होगा जो नियत किया जावे, लगाया जावेगा ।

( ५ ) एक टैक्स उन इमारतों पर जो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में हों जो ऊपर दिये हुये कोई टैक्स न देते हों, लगाया जावेगा । उसकी दर सरकार नियत करेगी ।

करों द्वारा जो धनराशि इकट्ठी होगी वह "गाँव-कोष" में जमा की जावेगी और गाँव सभा द्वारा बजट की स्वीकृति हो जाने पर गाँव पंचायत द्वारा ऊपर लिखे कामों पर खर्च की जावेगी ।

'गाँव-पंचायत' पटवारी चौकीदार तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के कार्य से यदि असन्तुष्ट हो तो उनकी शिकायत उन विभागों के उच्च अधिकारियों से कर सकेगी और वह अधिकारी जाँच करने के उपरान्त अपना निर्णय गाँव-पंचायत के पास भेज देगा ।

### पंचायत अदालत

उत्तर-प्रदेश की सरकार ने जिले को बहुत से क्षेत्रों में बाँट दिया है और प्रत्येक क्षेत्र में एक 'पंचायत अदालत' स्थापित की गई है ।

किसी क्षेत्र की प्रत्येक 'गाँव सभा' उस क्षेत्र की पंचायत अदालत में पंचों की हैसियत से काम करने के लिए अपने सदस्यों में से पाँच सदस्य चुनती है । किसी क्षेत्र की सारी 'गाँव सभाओं' के चुने हुए पंचों का एक 'पंच मंडल' होता है ।

इस प्रकार सब चुने हुए पञ्च पञ्चायती अदालत के 'सरपञ्च' का काम करने के लिए अपने में से एक व्यक्ति को चुनते हैं ।

सरपञ्च प्रत्येक नुकदमे के लिए पञ्च मंडल में से पाँच पञ्चों का एक बेंच नियुक्त करता है । पञ्चायत अदालत में अभी तक कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता था किन्तु अब यह रोक उठा दी गई है ।

पञ्चायत अदालतों को माल, दीवानी तथा फौजदारी सभों के नुकदमे लेने का अधिकार है परन्तु कानून के अनुसार कुछ धाराये दे दी गई हैं केवल उन्हीं के अन्तर्गत अदालत नुकदमों का फैसला कर सकती है ।

इस विधान से गाँवों की दशा में विशेष सुधार होगा । गाँव वालों को

स्थानीय शासन के अधिकार प्राप्त होंगे और अदालतों में जाकर जो उनका भयंकर शोषण होता है, उनके समय और धन की जो बर्बादी होती है वह दूर होगी। काँग्रेस सरकार ने गाँव-पंचायत राज्य विधान बनाकर ग्रामीण जनता की बहुत भलाई की है।

## अभ्यास के प्रश्न

- १—जमींदार और किसानों का पहले कैसा सम्बन्ध था और आज कैसा सम्बन्ध है ?
- २—गाँवों के रहने वालों में भाई-चारे का जो सम्बन्ध आज तक चला जा रहा है उससे क्या हानि लाभ है ?
- ३—गाँव में महाजन का क्या उपयोग है ?
- ४—पञ्चायत किसे कहते हैं और वह क्या-कार्य करती है ?
- ५—उत्तर प्रदेश में पञ्चायतों को क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं ?
- ६—प्राचीन काल में पञ्चायतों का गाँव के संगठन में कैसा स्थान था ?
- ७—सरकार द्वारा स्वीकृत पंचायतों में छोटे-छोटे मुकदमों का फैसला किस प्रकार होता है ?
- ८—क्या पंचायतों के अधिकारों को बढाने की जरूरत है ? यदि है तो कौन से अधिकार उन्हें दिये जाने चाहिये ?
- ९—पञ्चायतों के कर्तव्य क्या हैं ? भारतीय ग्रामीण जीवन में उनका क्या महत्व है ?

## उन्तीसवाँ अध्याय

### सहकारिता तथा सहकारी साख समितियाँ

(Co-operation & Co-operative Credit Societies)

सहकारिता के मूल सिद्धांत ( Principles of Co-operation )

आधुनिक काल में समाज ने आर्थिक जीवन में प्रतिस्पर्धा या होड़ ( competition ) के सिद्धांत को अपना लिया है। जो निर्वल हैं उनके लिये समाज में कोई स्थान नहीं है। उदाहरण के लिये जुलाहा कपड़े की

मिल की प्रतिस्पर्धा में असफल होता है, किसान की महाजनी से ७५ प्रतिशत सूद पर ऋण मिलता है जबकि कोई सेठ अथवा जमींदार किसी बैंक से सात या आठ प्रतिशत पर ऋण पा सकता है। निर्धन मजदूर या किसान मजदूर किसी दूकान पर सौदा लेने जाता है क्योंकि वह पैसे दो पैसे का सौदा लेता है इस कारण दूकानदार उसे खराब चीज अधिक दामों पर देता है। धनी व्यक्ति अच्छी वस्तु सस्ते दामों पर पा सकते हैं क्योंकि वे अधिक खरीदते हैं। इसका अर्थ यह है कि निर्धन व्यक्ति फिर चाहे वह सम्पत्ति उत्पादन ( Production ) करने वाला हो अथवा उपभोग ( Consumption ) करने वाला हो वह आधुनिक प्रतिस्पर्धा के कारण लूटा जाता है। सहकारिता इन निर्धनों को भाई-चारे के आधार पर संगठित कराके उन्हें वे ही सुविधायें प्रदान करना चाहती है जो कि धनी और ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त हैं। उदाहरण के लिये सहकारिता आन्दोलन बहुत से जुलाहों को भाई-चारे के आधार पर संगठित करके उन्हें मिलों की प्रतिस्पर्धा में सफल बनाने का प्रयत्न करता है। निर्धन किसानों को साख-समिति स्थापित करके उन्हें उचित सूद पर ऋण दिलाने का प्रबन्ध करता है। सारांश यह कि आज के इस होड़ (प्रतिस्पर्धा) के जमाने में जो सुविधायें केवल धनी और समाज के सबल सदस्यों को ही प्राप्त हैं, सहकारिता आन्दोलन उन्हें सहकारिता संगठन के द्वारा निर्धन और समाज के निर्बल सदस्यों को भी पहुँचाता है।

यहाँ हम उदाहरण देकर यह समझाने की चेष्टा करेंगे कि सहकारिता किसे कहते हैं। सहकारिता का अर्थ है मिलकर एक साथ कोई काम करना। मान लो कि एक गाँव से पच्चीस किसान जिनके पास गाय या भैंस है अपना-अपना दूध शहर के हलवाईयों के पास प्रातः तथा सायंकाल ले जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पच्चीसों किसान प्रतिदिन तीन या चार घटे समय अपना थोड़ा सा दूध हलवाई के पास ले जाने में व्यय करते हैं। यदि यह नियम बना ले कि उनमें से केवल एक किसान प्रतिदिन बारी से सबका दूध शहर ले जावेगा तो हर एक दिन शेष चौबीस किसानों का तीन या चार घटा समय नष्ट होने से बच जावेगा और सबों का दूध भी यथासमय शहर पहुँच जाया करेगा। यही नहीं यदि वे पच्चीस किसान एक साथ मिलकर अपना दूध बेचे तो हलवाईयों से उन्हें दूध के अच्छे दाम मिल सकते हैं।

हम इस प्रकार के सगठन को सहकारी समिति कहेंगे। जुलाई के महीने में यदि तुम अपने दर्जे के लड़कों को इस बात के लिए राजी कर लो कि वे अलग-अलग अपनी पाठ्य-पुस्तकें शहर के बुकसेलरों से न खरीद कर एक साथ मिलकर प्रकाशकों से खरीदें तो तुम लोगों को पुस्तकें कम कीमत में मिल जावेगी और तुम्हारा यह सगठन विद्यार्थियों की सहकारी समिति कहा जावेगा। वस, अब तो तुम समझ हो गये होंगे कि किसी काम को एक साथ मिलकर करने को सहकारिता कहते हैं।

सहकारिता आन्दोलन क्या है, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जावेगा। कल्पना कीजिये कि एक अंधा भिखारी एक अनजान स्थान पर पहुँच जाता है और अंधा होने के कारण भीख माँगने का काम नहीं कर सकता। साथ ही वहाँ एक लूला व्यक्ति भी है जिसकी दोनों टाँगें बेकार हो गई हैं, इस कारण वह भी भीख माँगने से मजबूर है। अब यदि वे दोनों सहकारिता के सिद्धान्त को अपनावे और अंधा लूले को अपने कंधे पर बिठा ले तो लूले की आँखें और अंधे की टाँगें एक दूसरे से सहयोग कर उन दोनों का काम निकाल सकती हैं। सन्क्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जब हम भाईचारे के आधार पर संगठित प्रयत्न करें और होड़ (मुकाबिले) और शोषण को दूर कर दें तो हम उसे सहकारिता कहेंगे।

### भिन्न-भिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

ऊपर हम यह बतला चुके हैं कि सहकारिता का क्या अर्थ है। किसी ने ठीक ही कहा है कि “सहकारिता तू निर्धनों का बल है”। जो निर्धन हैं वे ही सहकारिता की शरण में आते हैं और अपना सगठन करते हैं क्योंकि ऐसा किये बिना आज की होड़ (मुकाबिले) में धनी और शक्तिवानों के विरोध में खड़े नहीं रह सकते। अतएव प्रत्येक आर्थिक कार्य के लिए सहकारिता आन्दोलन की सहायता की जा सकती है। यही कारण है कि हमें बहुत प्रकार की सहकारी समितियाँ देखने को मिलती हैं। नीचे हम मुख्य सहकारी समितियों का वर्णन करते हैं—

(१) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ या उपभोक्ता स्टोर (Co-operative Consumers' Stores)—जब ग्राहक स्वयं मिलकर अपनी



दैनिक आवश्यकता की चीजों को प्राप्त करने के लिए दूकान स्थापित करते हैं तो उसको उपभोक्ता स्टोर कहते हैं ।

(२) उत्पादक सहकारी समितियाँ—जब छोटे-छोटे कारीगर अथवा मजदूर या किसान आपस में सहकारिता के आधार पर संगठित होकर अपने धन्धे या खेती का संगठन करते हैं और बड़े पूँजीपति उत्पादकों की होड़ में खड़े रहने का प्रयत्न करते हैं तब उसे उत्पादक सहकारी समिति कहते हैं ।

(३) साख सहकारी समितियाँ—जब निर्धन किसान, कारीगर, अथवा मजदूर सहकारिता के आधार पर संगठित होकर साख ( कर्ज ) प्राप्त करने के लिये समिति का संगठन करते हैं तो उसे साख समिति कहते हैं ।

(४) अन्य प्रकार की समितियाँ—इनमें क्रय-विक्रय समितियाँ, भूमि की चक्रवन्दी समितियाँ, रहन-सहन सुधार समितियाँ, इत्यादि सभी अन्य समितियाँ आ जाती हैं ।

आगे हम इनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक लिखेंगे ।

### सहकारी साख समितियाँ

#### ( Co-operative Credit Societies )

सहकारी साख आन्दोलन की जन्मभूमि जर्मनी में दो प्रकार की साख समितियाँ कार्य कर रही हैं । १—रैफिसन ग्राम्य सहकारी साख समितियाँ जिनके जन्मदाता श्री रैफिसन महोदय थे । २—शुल्ज समितियाँ जो विशेषतः नगरों में मध्यवर्ग तथा छोटे-छोटे कारीगर और व्यापारियों के लिए स्थापित की गई । भारत में सहकारी आन्दोलन जर्मनी से नकल किया गया । इस कारण यहाँ भी दो प्रकार की सहकारी समितियाँ स्थापित की गई । प्रथम रैफिसन प्रणाली की कृषि सहकारी साख समितियाँ ( Agricultural Co-operative Credit Societies ) जो गाँवों में स्थापित की गई, दूसरी शुल्ज प्रणाली के पिपुल्स बैंक जो कि नगरों में स्थापित किये गये । गैर साख कृषि सहकारी समितियों के विषय में अगले परिच्छेद में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा । कृषि साख समितियों और पिपुल्स बैंकों ( नगर साख समितियों ) में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं :—

१—कृषि साख समितियों में हिस्से या तो नहीं होते अथवा बहुत कम

मूल्य के होते हैं। नगर साख समितियों में हिस्से अधिक मूल्य के होते हैं।

२—कृषि साख समितियों का दायित्व अपरिमित ( Unlimited liability ) होता है परन्तु नगर साख समितियों का दायित्व परिमित ( Limited liability ) होता है।

३—कृषि साख समितियों में लाभ नहीं बाँटा जाता ( किसी विशेष दशा में बाँटा जाता है ) नगर साख समितियों में लाभ बाँटा जाता है।

४—कृषि साख समितियों में किसी भी सदस्य को समिति का कार्य संचालन के लिये कोई वेतन नहीं मिलता परन्तु नगर साख समितियों में प्रबन्ध करने वाले सदस्यों को वेतन दिया जा सकता है।

रैफिसन और शुल्ज प्रणालियों को भारत की परिस्थिति के अनुसार कुछ संशोधन करके अपना लिया गया है। दोनों प्रकार की समितियाँ अपने सदस्य को उचित सूद पर ऋण देने का प्रबन्ध करती हैं।

### प्रारम्भिक कृषि सहकारी साख समितियाँ ( Primary Agricultural Co-operative Credit Societies )

सन् १९०४ में जब सहकारिता आन्दोलन का यहाँ आरम्भ हुआ तो उसका उद्देश्य केवल गाँव वालों की साख समस्या को हल कर देना था। अन्य धन्धों की भाँति खेती-बारी में भी पूँजी उधार लेने की आवश्यकता है। कृषक महाजन से पूँजी उधार लेकर उसका दास बन जाता

\*अपरिमित दायित्व ( Unlimited liability ) :—अपरिमित दायित्व वाली समितियों के सदस्य व्यक्तिगतरूप से समिति के सारे ऋण को चुकाने के लिये जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिये यदि एक साख समिति टूटती है और उस पर बाहर वालों का कर्जा चढ़ जाता है तो समिति के लेनदार ( Creditor ) किसी एक सदस्य से सारे कर्जे वसूल कर सकते हैं। परिमित दायित्व वाली समितियों के सदस्यों की ऋण चुकाने की जिम्मेदारी उनके हिस्से के मूल्य से परिमित होती है। यदि सदस्य ने अपने हिस्से का मूल्य चुका दिया है तो समिति का लेनदार सदस्य से कुछ वसूल नहीं कर सकता है।

है। अतएव पूँजी की समस्या को हल करने के लिए ही कृषि सहकारी साख समितियाँ स्थापित हो गईं। आरम्भ में साख की समस्या को हल करने की ओर विशेष ध्यान होने के कारण सहकारिता विभाग ने कृषि-सहकारी-साख समितियों को अधिक संख्या में स्थापित किया। इसी का फल है कि कृषि सहकारी साख समितियाँ अन्य सब प्रकार की समितियों से संख्या में अधिक हैं।

### कृषि साख समिति के उद्देश्य

कृषि साख समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को खेती बारी तथा अन्य उपयोगी कार्यों के लिये ऋण देना है। सदस्यों को ऋण देने के लिये समिति गाँव वालों से डिपॉजिट (जमा) लेती है अथवा सेन्ट्रल सहकारी बैंकों से ऋण लेती है। इसके अतिरिक्त कृषि साख समिति अपने सदस्यों के लिए बीज, खाद, हल तथा अन्य खेत के औजारों को खरीदती है, तथा वैज्ञानिक खेती किस प्रकार हो सकती है इसका प्रचार करती है।

### समिति की सदस्यता

समिति के कम से कम दस सदस्य होते हैं। यदि सदस्यों की संख्या दस से कम हो जावे तो रजिस्ट्रार\* उस समिति को तोड़ सकता है। समिति का सदस्य वही बनाया जाता है जिसका चरित्र अच्छा हो, जो ईमानदार हो, शराब न पीता हो और जुआ न खेलता हो। समिति के सदस्य बनाते समय उसके चालचलन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। कृषि साख समिति के सदस्य वे ही हो सकते हैं जो एक ही गाँव अथवा पास के गाँव में रहते हों अथवा एक ही जाति या पेशे के हों।

### अपरिमिति उत्तरदायित्व (Unlimited Liability)

कृषि साख समिति का उत्तरदायित्व अपरिमित होता है। अपरिमित उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य केवल अपना कर्जा चुकाने का जिम्मेदार नहीं होता परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उसे समिति का सारा कर्ज चुकाना होता है। उदाहरण के लिये मान लिया जावे कि अनन्तपूर नामक गाँव की साख समिति दिवालिया हो जाते हैं, समिति के अधिकतर

---

\*रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग का प्रधान कर्मचारी है जो समिति की रजिस्ट्री, आय-व्यय निरीक्षण, देख-भाल करता है और समितियों को तोड़ भी सकता है।

सदस्य अपना कर्ज अदा नहीं कर सकते । केवल दो या तीन सदस्य ही ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति है । ऐसी दशा में समिति के लेनदार (Creditors) उनमें से किसी एक से अथवा सबों से समिति का पूरा कर्जा वसूल कर सकते हैं । उन धनी सदस्यों को अपनी सारी संपत्ति बेच कर भी समिति का कर्ज चुकाना होता है ।

इसी कारण यह नितान्त आवश्यक है कि सदस्य एक दूसरे के चरित्र तथा माली हालत से भली भाँति परिचित हों । यदि सदस्य एक दूसरे को भली भाँति न जानते हों तो वे अपरिमित दायित्व स्वीकार न करेंगे । अपरिमित दायित्व के अनुसार प्रत्येक सदस्य समिति के ऋण को सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से चुकाने के लिये बाध्य है ।

जब कोई नवीन सदस्य समिति में आना चाहता है तो वह सर्व सम्मति से ही लिया जा सकता है । एक गाँव में अधिकतर एक ही समिति होती है किन्तु यदि गाँव बड़ा हो तो एक से अधिक समितियाँ भी हो सकती हैं ।

### समिति का प्रबन्ध

समिति के कार्य संचालन का पूर्ण अधिकार जनरल मीटिंग ( साधारण सभा जिसमें समिति का प्रत्येक सदस्य होता है ) को होता है । प्रत्येक सदस्य केवल एक वोट ही दे सकता है फिर उसके पास समिति के कितने भी हिस्से क्यों न हों । जनरल मीटिंग अपने में से एक पंचायत चुन देती है जो समिति का सारा कार्य करती है । पंचायत के पाँच या सात सदस्य होते हैं । जनरल मीटिंग सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना स्पष्ट मत दे देती है और साधारण नीति निर्धारित कर देती है । पंचायत वस्तुतः सारा कार्य करती है । पंचायत का चुनाव करने के अतिरिक्त जनरल मीटिंग डिपाजिट पर कितना सूद दिया जावे, सदस्यों से ऋण पर कितना सूद लिया जावे, अधिक से अधिक प्रत्येक सदस्य को उसकी हैसियत के अनुसार कितना ऋण दिया जा सकता है, तथा समिति सैन्ट्रल बैंक से अधिक से अधिक कितना ऋण ले—इन बातों का निश्चय करती है ।

### समिति की पंचायत के कार्य

१—पंचायत सदस्यों को हिस्से देकर उन्हें समिति का सदस्य बनाती है ।

२—गाँव से डिपाजिट आकर्षित करने का प्रयत्न करती है तथा सैट्रल अथवा जिला बैंक से ऋण लेने का प्रवन्ध करती है। पञ्चायत को समिति के सदस्यों से तथा अन्य ग्रामवासियों से अधिक से अधिक मात्रा में रुपया जमा करने को कहना चाहिये।

३—पञ्चायत यह भी निश्चय करती है कि किन सदस्यों को कितने समय के लिये कर्ज दिया जावे। पञ्चायत उस समय के अन्त में ऋण वसूल करती है।

४—पञ्चायत समिति के आय-व्यय का हिसाब रखती है।

५—पञ्चायत रजिस्ट्रार से समिति सम्बन्धी कार्यों में लिखा-पढी करती है।

६—सदस्यों के लिये सम्मिलित रूप से आवश्यक वस्तुएँ खरीदती है तथा उनकी पैदावार को बेचती है।

७—पञ्चायत सरपञ्च तथा मन्त्री का निर्वाचन करती है। सरपञ्च समिति के कार्य की देखभाल रखता है।

### समिति की पूँजी ( Capital )

कृषि साख समितियों की कार्यशील पूँजी ( Working Capital ) निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है :—

१—समिति प्रवेश फीस।

२—हिस्सों का मूल्य जो सदस्य देते हैं।

३—डिपाजिट जो सदस्यों तथा गैर सदस्यों से मिलती है।

४—सैट्रल बैंक या जिला बैंकों से लिया हुआ ऋण।

५—रक्षित कोष ( Reserve Fund )

प्रवेश फीस नाममात्र को एक रुपया ली जाती है जो कि शुरू के खर्च के काम आती है।

कुछ प्रदेशों में सदस्यों को हिस्से खरीदने पड़ते हैं और कुछ प्रदेशों में हिस्से नहीं होते। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में समितियाँ हिस्से वाली होती हैं। अन्य प्रदेशों में समितियाँ हिस्से तथा गैर हिस्से वाली दोनों ही प्रकार की होती हैं। उत्तर प्रदेश में एक हिस्सा दो रुपये का होता है। कम

से कम एक हिस्सा प्रत्येक सदस्य को लेना होता है। हिस्से का मूल्य छमाही एक रुपये की किश्त में दस वर्षों में चुका दिया जाता है।

साख समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रकम से अधिक के हिस्से नहीं खरीद सकता। प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का ही अधिकार होता है। समितियों को अधिकतर पूँजी के लिए सेन्ट्रल बैंकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि अभी तक वे डिपॉजिट अधिक आकर्षित नहीं कर सकी हैं। जितनी ही अधिक कोई समिति डिपॉजिट आकर्षित करे उतनी ही उसकी सफलता समझी जानी चाहिये, क्योंकि डिपॉजिट तभी अधिक जमा होगी जब कि जनता को समिति का भरोसा होगा और उसकी आर्थिक स्थिति में विश्वास होगा। जब तक कि साख समितियाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार डिपॉजिट आकर्षित करके पूँजी जमा नहीं कर सकती तब तक उनको निर्बल ही समझना चाहिये।

कृपि सहकारी साख समितियों में साधारणतः लाभ सदस्यों में बाँटा नहीं जाता। हाँ, जब रक्षित कोष ( Reserve fund ) एक निश्चित रकम से अधिक हो जावे तो प्रदेशीय सरकार से अनुमति लेकर तीन-चौथाई लाभ सदस्यों में बाँटा जा सकता है। फिर भी २५ प्रतिशत रक्षित कोष में जमा करना ही पड़ता है।

कृपि सहकारी साख समितियों का प्रबन्ध-व्यय लगभग कुछ न होने के कारण तथा लाभ न बाँटने के कारण रक्षित कोष यथेष्ट जमा हो जाता है। प्रत्येक साख समिति के लिए रक्षित कोष अत्यन्त आवश्यक है। जब तक कि समिति के पास यथेष्ट कोष न हो जावे तब तक वह सफल नहीं बन सकती। रक्षित कोष किसी अवस्था में भी सदस्यों को बाँटा नहीं जा सकता। उसका उपयोग समिति के कार्य में हानि हो जाने पर उसे पूरा करने में होना है। यदि समिति भंग हो जावे अथवा तोड़ दी जावे तो रक्षित कोष किसी अन्य सहकारी समिति को दे दिया जावेगा या रजिस्ट्रार की अनुमति से किसी सार्वजनिक हित के कार्य में व्यय कर दिया जावेगा।

साधनों से मिलने वाले धन से चलता है। समिति दूसरों पर निर्भर रहती है। यह कमजोरी शीघ्र से शीघ्र दूर होनी चाहिये। द्वितीय, यदि लाभ बँटने लेंगे तो आरम्भ से ही सदस्य लाभ के फेर में पड़ जायेंगे। इसी प्रकार रक्षित कोष जारी करने का अभिप्राय उससे सहकारी-आन्दोलन की वृद्धि करना था। इसी कारण रक्षित कोष अविभाजित रहता है।

### समिति के कार्यकर्त्ताओं का अवैतनिक होना

समिति के पञ्चों को कोई वेतन नहीं दिया जाता। यदि सदस्यों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि समिति का हिसाब इत्यादि रख सके, तो गाँव के किसी शिक्षित व्यक्ति को थोड़ा सा वेतन देकर वैतनिक मन्त्री रख लिया जाता है, किन्तु वैतनिक मन्त्री को समिति की मीटिंग में कोई सम्मति देने का अधिकार नहीं होता है। सदस्य मन्त्री को कोई वेतन नहीं मिलता। गाँव के पटवारी को कभी मन्त्री न बनाना चाहिये क्योंकि उसका गाँव में बहुत प्रभाव होता है और वह पञ्चों पर दबाव डाल सकता है।

### समिति की साख निर्धारित करना

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि जनरल मीटिंग समिति की अधिकतम साख निर्धारित करती है, उससे अधिक पञ्चायत ऋण नहीं ले सकती। समिति की साख निर्धारित करने के लिये सब सदस्यों की हैसियत का लेखा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है, सब सदस्यों की हैसियत के एक चौथाई से आधी तक समिति की साख मानी जाती है। किसी भी सदस्य की सम्पत्ति का पचास प्रतिशत से अधिक उसको उधार नहीं दिया जाता।

### समिति द्वारा ऋण देने का कार्य

कृषि साख सहकारी समिति केवल सदस्यों को ही ऋण देती है। जो भी सदस्य ऋण लेना चाहता है वह एक प्रार्थना-पत्र पञ्चायत को देता है। दरखास्त में उसे यह भी बतलाना पड़ता है कि वह किस कार्य के लिए ऋण लेना चाहता है। ऋण लेने वाले सदस्य को दो व्यक्तियों की जमानत देनी होती है। ऋण देते समय कर्ज लेने का उद्देश्य तथा सदस्य को चुकाने की शक्ति का अनुमान करके ही समिति कर्जा देना निश्चित करती है।

सहकारिता आन्दोलन का यह सिद्धान्त है कि ऋण अनुत्पादक कार्यों लिए न दिया जावे, किन्तु भारत में कृषि सहकारी साख समितियाँ

विवाह, श्राद्ध, तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिये भी रुपया उधार दे देती हैं। पञ्चायत का मुख्य कर्तव्य है कि वह इस बात की जाँच करे कि सदस्य ने जिस कार्य के लिए ऋण लिया है उसी पर व्यय कर रहा है अथवा नहीं। यदि सदस्य किसी दूसरे काम में रुपया लगावे तो पञ्चायत को रुपया वापस माँग लेना चाहिये। यदि पञ्चायत ऐसी रोक न लगावे तो गरीब ग्रामीण कोई भी कारण बता कर ऋण लेंगे और उसे अपनी वर्तमान अनुत्पादक आवश्यकता पर व्यय कर देंगे।

पञ्चायत ऋण देते समय ही सदस्य की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए किश्त बाँध देती है क्योंकि सदस्यों को किश्तों द्वारा ऋण चुकाने में सुविधा होती है। पञ्चायत को किश्ते समय पर वसूल करनी चाहिए, किन्तु फसल नष्ट हो जाने पर अथवा अन्य अनिवार्य कारण उपस्थित होने पर किश्त की मियाद बढ़ा दी जाती है।

समितियाँ अधिकतर नीचे लिखे हुए कार्यों के लिए ऋण देती हैं :—

१—खेती-बारी के लिये, मालगुजारी तथा लगान देने के लिये।

२—भूमि का सुधार करने के लिये।

३—पुराने ऋण को चुकाने के लिये।

४—गृहस्थी के कार्यों के लिये।

५—व्यापार के लिये।

६—भूमि खरीदने के लिये।

अब क्रमशः कृषि साख सहकारी समितियाँ पुराने ऋण को चुकाने के लिए तथा भूमि खरीदने के लिए कम ऋण देने लगी हैं क्योंकि समितियों ने अब यह नीति बना ली है कि वे अधिक समय के लिए कर्ज न देंगी।

समितियों का आय-व्यय निरीक्षण



सकते। आडिटर हिसाब की जाँच तो करता ही है परन्तु इस बात की भी जाँच करता है कि समिति नियमानुसार कार्य करती है या नहीं, परन्तु भारत में आय-व्यय निरीक्षण का कार्य भली भाँति नहीं होता। -

आय-व्यय निरीक्षण के अतिरिक्त साख समितियों की देखभाल तथा उनका नियंत्रण रजिस्ट्रार तथा उनके सहायक कर्मचारी और प्रदेशीय सहकारी यूनियन दोनों ही करते हैं।

### कृषि सहकारी साख समितियों को मिली हुई सुविधाएँ

यदि समिति ने किसी सदस्य को बीज या खाद उधार दिया है अथवा उसको मोल लेने के लिये रुपया उधार दिया है तो समिति को उसके द्वारा उत्पन्न की हुई फसल से अपना रुपया वसूल करने का प्रथम अधिकार होगा। सदस्य का कोई दूसरा लेनदार उस फसल को कुर्क नहीं करवा सकता। इसी प्रकार यदि समिति ने सदस्यों को बैल, खेती तथा अन्य धंधों में काम आने वाले यन्त्र, तथा धन्धों के लिए कच्चा माल उधार दिया है तो उन वस्तुओं पर, तथा उस कच्चे माल के तैयार किए हुए पक्के माल पर, समिति का प्रथम अधिकार होगा।

सहकारी समिति के लाभ पर इनकमटैक्स (आयकर) नहीं लिया जाता और न सदस्यों के लाभ पर टैक्स लिया जाता है। सहकारी समितियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनीआर्डर द्वारा रुपया भेजने पर पोस्ट आफिस एक रेट पर उनका रुपया भेज देता है।

समिति के सदस्य का हिस्सा उसका कोई लेनदार ( Creditor ) कुर्क नहीं करवा सकता। किसी भी सदस्य के जमा किये हुए रुपये तथा लाभ के हिस्से को समिति ऋण के बदले में ले सकती है, कोई दूसरा लेनदार उसे कुर्क नहीं करवा सकता।

रजिस्ट्रार को यदि विश्वास हो जावे कि समिति की दशा अच्छी नहीं है तो वह उसे भग कर सकता है।

### क्या कृषि साख समितियाँ सफल हो रही हैं ?

साख समितियाँ सफल हो रही हैं अथवा नहीं, इसमें कुछ मतभेद हो सकता है किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि वे अभी तक बहुत निर्बल हैं। वे वास्तव में सहकारी नहीं हैं। एक बार बैंकिंग के एक प्रसिद्ध

जानकार ने कहा था—“इन समितियों में सहकारिता के सिद्धान्तों की नितात अवहेलना की जाती है। ऋण ठीक समय पर कभी नहीं चुकाये जाते, आय व्यय-निरीक्षण ठीक नहीं होता तथा इन समितियों की देखभाल भी ठीक तरह से नहीं होती।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऊपर लिखे हुये दोष इन समितियों में अवश्य हैं। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि अधिक-तर सहकारी समितियों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, किन्तु सहकारिता आन्दोलन में लगे हुये कर्मचारी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। शाही कृषि कमीशन की सम्मति है कि आन्दोलन की आर्थिक स्थिति अच्छी है। हाँ, समितियों का कार्य दोषपूर्ण है।

सहकारी कृषि साख समितियों की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों को समझे। भारत में गाँव के सदस्य यह समझते हैं कि सहकारी साख समितियाँ सरकार द्वारा खोले हुए बैंक हैं जो उन लोगों को ऋण देते हैं। वे कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते कि यह हमारी समिति है और हम सम्मिलित साख के द्वारा उचित सूद पर पूँजी पा सकते हैं। जब तक सदस्यों में स्वावलम्बन का यह भाव जाग्रत नहीं होना तब तक सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सकता।

सहकारी साख समितियों को जो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी उसके तीन मुख्य कारण हैं—गाँव वालों का अशिक्षित होना, उनका एड़ी से चोटी तक मराज्जन का ऋणी तथा अत्यन्त निर्धन होना और योग्य कार्यकर्ताओं का अभाव। जब तक सेवा भाव के सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता इस आन्दोलन के लिये नहीं मिलते तब तक यह पूर्णतः सफल नहीं हो सकता।

लाभ—कृषि साख समितियाँ बहुत सफल नहीं हुई हैं इससे यह न समझ लेना चाहिये कि उनसे ग्रामीण जनता को कोई लाभ ही नहीं हुआ। कृषि साख समितियों के द्वारा गाँवों को बहुत कुछ आर्थिक लाभ हो रहा है। समितियों ने बहुत सी कार्यरत पूँजी (Working Capital) इकट्ठा कर ली है जो किसानों को उचित सूद पर दी जाती है। इन समितियों की पूँजी कुल ३० करोड़ रुपये में लगभग है। जहाँ साख समितियाँ खुल गई हैं उन जगहों में प्रतिनिधित्व के कारण मराज्जन ने भी सूद की दर घटा दी है।

साधारण किसानों में सहकारिता का ज्ञान बढ़ रहा है। सदस्यों में कृषायत-शारी उत्पन्न हो रही है और किसान स्वावलम्बी बन रहे हैं। अशिक्षित किसान जो कि साख तथा व्यापार के विषय में नितान्त अनभिज्ञ थे उनमें व्यापारिक ज्ञान बढ़ रहा है। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जहाँ कि वृद्ध पञ्चों ने इसलिये पढ़ना-लिखना सीखा कि वे समिति का कार्य भली भाँति कर सकें, कुछ शराब पीने वालों ने केवल इसलिये शराब छोड़ दी कि जिसमें वे समिति में लिये जा सकें। सहकारी साख समिति के कारण गाँव में भ्रातृभाव फैलता है। यदि प्रत्येक गाँव में एक सहकारी साख समिति की स्थापना हो जावे और सफलतापूर्वक कार्य करने लगे तो ग्रामीण जनता का उद्धार हो सकता है।

भारत में कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या ८५ हजार से अधिक है और उनके सदस्यों की संख्या ३५ लाख के लगभग है। इन समितियों की कार्यशील पूँजी (जिसमें हिस्सापूँजी, रक्षित कोष, डिपॉजिट और सेंट्रल सहकारी बैंको से लिया हुआ कर्ज सम्मिलित है) २४ करोड़ रुपये के लगभग है। इन अकों को देखकर साख सहकारी समितियों के विषय में निराश होने का कोई कारण नहीं है।

### बहु-उद्देशीय सहकारी समितियाँ

#### (Multi purpose Co-operative Societies)

कुछ समय से भारत में इस बात पर बहुत जोर दिया जाने लगा है कि गाँव में एक साख सहकारी समिति के स्थान पर एक बहु-उद्देशीय-सहकारी समिति हो जो गाँव की सर्वाङ्गीण उन्नति का प्रयत्न करे और केवल कर्जा देने का ही कार्य न करे। विद्वानों का कहना है कि केवल किसान को उचित सूद पर ऋण मिल जाने से ही उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो जावेगा। इसके लिये बहु-उद्देश्य-समितियों की स्थापना की आवश्यकता होगी।

बहु-उद्देश्य-समितियाँ खेती के धंधे के लिये साख देंगी, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी पैदावार को बेचने, उनके लिये बढिया हल, बैल, बीज और खाद खरीदने, किसानों की दैनिक आवश्यकता की चीजों को उन्हें ठीक मूल्य पर दिलाने के लिये उनसे आर्डर लेकर उन्हें

वे वस्तुएँ ठीक मूल्य पर देगी। मुकदमेबाजी को कम करने के लिये पंचायत-स्थापित करेगी। भूमि की चकबंदी करके, अच्छे बीज, औजारों और खाद का प्रचार करके खेती की पैदावार को बढ़ाने, खेती के अतिरिक्त बिक्री के समय में गौण तथा सहायक धंधों के द्वारा उनकी आय को बढ़ाने का प्रयत्न करेगी और जीवन सुधार को हाथ में लेकर स्वास्थ्य, ओषधि वितरण, उपचार, सामाजिक कृत्यों में अधिक धन व्यय न करने तथा गाँव में सफाई रखने का प्रवन्ध करेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि बहु-उद्देश्य-समिति गाँव की सभी मुख्य समस्याओं को हल करके गाँव वालों को सुखी और समृद्धिशाली बनाने का प्रयत्न करेगी। केवल साख ही नहीं देगी वरन् गाँव की आर्थिक दशा सुधारने और सामाजिक उन्नति करने का प्रयत्न करेगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गाँव की सभी समस्याओं के विरुद्ध एक साथ युद्ध छेड़ने से ही गाँव की सर्वाङ्गीण उन्नति हो सकती है।

सहकारिता आन्दोलन में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता इस बात पर एकमत हैं कि सहकारिता आन्दोलन के अधिक सफल न होने का एक यह भी कारण है कि उसने किसानों को कर्ज देने पर ही अधिक ध्यान दिया और किसान की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिये अन्य उपाय नहीं किये। अब भारत में सभी प्रदेशों में बहु-उद्देश्य-सहकारी समितियों की स्थापना की जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में बहु-उद्देश्य-सहकारी समितियाँ

उत्तर प्रदेश में बहु-उद्देश्य-सहकारी समितियों के द्वारा गाँवों की उन्नति करने का एक व्यापक रूप से प्रयोग चल रहा है।

उत्तर प्रदेश में एक विकास योजना (Development Plan) बनाई गई है जिसका आधार बहु-उद्देश्य-सहकारी समिति है। विकास योजना इस प्रकार है :—

प्रत्येक जिले में एक जिला विकास समिति स्थापित की गई जो कि जिले में विकास योजना को कार्यान्वित करेगी। इस समिति में जिले से सभी प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा उन विभागों के कर्मचारी जिनके विकास कार्य से सम्बन्ध है रखे गए हैं। ऊपर एक प्रदेशीय विकास बोर्ड है जो प्रदेश भर में इस कार्य की देखभाल करता है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव में एक बहु-उद्देश्य सहकारी-समिति स्थापित की गई है। जब गाँव के ७० या ८० प्रतिशत परिवार समिति के सदस्य बन जाते हैं तभी समिति स्थापित की जाती है।

बहु-उद्देश्य-सहकारी समिति गाँव में खेतों की उन्नति, दूध, घी के धंधे की उन्नति, पशुपालन में सुधार, सूत कातने तथा कपड़ा के बिनने के धंधे तथा अन्य सहायक तथा ग्रह-उद्योग धंधों का संगठन, गाँव की सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा इत्यादि का कार्य करती है। समिति राशन से मिलने वाले अथवा कंट्रोल के पदार्थों जैसे खाद्यान्न, कपड़ा, शक्कर, सीमेंट, लोहा इत्यादि वस्तुओं को अपने सदस्यों को देती है। सरकार इन पदार्थों को इन समितियों को दे देती है। पन्द्रह या बीस गाँवों के बीच में कृषि विभाग ने एक बीज गोदाम स्थापित कर दिया है। यह बीज गोदाम उस क्षेत्र की बहु-उद्देश्य-सहकारी समितियों को उत्तम बीज, हल, खाद इत्यादि देता है तथा खेती सम्बन्धी सलाह भी देता है। आगे चलकर योजना यह है कि उस क्षेत्र की १५ या २० समितियाँ मिल कर एक विकास यूनियन बना लेगी और यह यूनियन इस बीज भंडार को ले लेगी। यूनियन केवल इस भंडार में बीज, औजार खाद्य ही नहीं रखेगी वरन् चर्खा, कपड़ा, शक्कर, सीमेंट, तेल इत्यादि आवश्यक पदार्थों को भी रखेगी जो कि समितियों के सदस्यों को बेचे जायेंगे। एक प्रकार से वह उपभोक्ता स्टोर का भी काम करेगी और सदस्यों की खेती की पैदावार को बेचने का काम करेगी।

बहु-उद्देश्य-सहकारी समिति में गाँव के सभी परिवारों को सदस्य बनाने का प्रयत्न किया जावेगा और ७० या ८० प्रतिशत परिवारों के सदस्य बिना बने समिति स्थापित नहीं की जावेगी। प्रत्येक परिवार का मुखिया समिति का सदस्य होगा।

उत्तर प्रदेश में इस समय तक बीस हजार से अधिक बहु-उद्देश्य-सहकारी समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश में यह आन्दोलन अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। इस कारण बहु-उद्देश्य-सहकारी समितियाँ कहाँ तक सफल हुई हैं यह कहना कठिन है।

बहु-उद्देश्य-सहकारी समितियाँ अन्य सभी प्रदेशों में स्थापित हो चुकी हैं। पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, अजमेर मेरवाड़ा, बम्बई तथा मद्रास में भी स्थापित हो चुकी हैं।

## अभ्यास के प्रश्न

१—सहकारिता का क्या अर्थ है ?

२—उदाहरण देकर बतलाओ कि सहकारिता किसे कहते हैं ? मान लो कि एक गाँव में तीस किसान हर रोज अपना दूध बेचने पास के शहर में आते हैं। यदि वे आपस में समझौता कर ले कि पारी-पारी से एक किसान सबों का दूध गाँव से शहर ले जाकर बेच आया करेगा तो क्या इसको सहकारिता कहेंगे ?

३—कृषि साख समिति और 'पिपुल्स' बैङ्क (नगर साख समिति) का मुख्य कार्य क्या है और उसमें क्या अन्तर है ?

४—अपरिमित और परिमित दायित्व की व्याख्या कीजिए।

५—कृषि साख समिति का सदस्य कौन हो सकता है ? क्या भिन्न-भिन्न गाँवों में रहने वाले लोग एक कृषि साख समिति के सदस्य हो सकते हैं ?

६—साख समिति का प्रबन्ध किस प्रकार होता है ? जनरल मीटिंग और पचायत के कार्य बतलाइये।

७—कृषि साख समिति का लाभ सदस्यों में नहीं बाँटने से और समिति के टूट जाने पर रक्षित कोष को भी सदस्यों में न बाँटने से क्या लाभ है ?

८—साख समिति में यह नियम क्यों बनाया गया है कि सदस्य जिस काम के लिये कर्ज ले उसी पर खर्च करे ?

९—कानून के अनुसार कृषि साख समितियों को कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं ?

१०—क्या कृषि साख समितियाँ सफल कही जा सकती हैं ?

११—सहकारी साख समिति क्या है ? यदि आपसे एक ऐसी समिति स्थापित करने को कहा जाय तो आप कैसे आरम्भ करियेगा ? (१९४३)।

१२—सहकारिता के मुख्य सिद्धान्त क्या हैं ? इससे देश के ग्रामीणों को किसे किस प्रकार लाभ पहुँचा है ? (१९४५)।

१३—प्राइमरी कृषि साख समिति की व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिये। इन समितियों को किन साधनों से पूँजी मिलती है ? (१९४५)।

१४—किसानों को सहकारी समितियों से जो लाभ होते हैं उनकी सन्धे में विवेचना कीजिये (१९४६)।

१५—प्राइमरी कृषि साख समिति की व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का स्वरूपन कीजिये । किसानों को इनसे जो लाभ होते हैं उनकी विवेचना कीजिये । (१६४७)

१६—साख समिति और बहु उद्देश्य-समिति मे से आप किसे पसन्द करते हैं ? और क्यों ? आपके प्रदेश की सरकार इस ओर क्या कर रही है ?

## तीसवाँ अध्याय

### गैर साख कृषि सहकारी समितियाँ

( Agricultural Non-Credit Societies )

भारत मे जब सहकारिता आन्दोलन का आरम्भ किया गया था उस समय साख की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण समझी गई और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी । इसी कारण सन् १९०४ के कानून के अनुसार केवल साख समितियों के ही स्थापित करने का सुविधा प्रदान की गई । परन्तु आगे चल कर कार्यकर्ताओं को ज्ञात हुआ कि गाँव वालों का उद्धार केवल साख का प्रबन्ध कर देने से ही नहीं हो जावेगा । अपनी फसल बेचने मे, खेती के लिए आवश्यक चीजों को खरीदने मे, व्यापारी उनको लुटते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य कृषि-सम्बन्धी कार्यों को भी सहकारी समितियों के द्वारा सुविधापूर्वक किया जा सकता है । यही कारण है कि पिछले वर्षों में गैर साख कृषि सहकारी समितियों की अधिकाधिक स्थापना का गई है । फिर भी इन समितियों की सख्या साख समितियों को तुलना मे नहीं के बराबर है ।

साख ( Credit ) केवल किसान को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अतएव साख का प्रबन्ध हो जाने मे बहुत सी आवश्यकताओं मे से एक पूरा हो जाती है, किन्तु किसान की और भी आवश्यकताएँ हैं, जिनका पूरा होना आवश्यक है । सिंचाई, खेतों की चकबन्दी, स्वास्थ्य और सफाई की उन्नति, पशुओं के जीवन का बीमा, दूध का धन्वा, कृषि की आवश्यक वस्तुओं को मोल लेना तथा खेती की पैदावार को बेचना—ये कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनको सहकारी समितियों के द्वारा भली प्रकार हल किया जा सकता

है। कुछ वर्षों से कृषि विभाग तथा सहकारिता आन्दोलन में कार्य करने वालों ने इन समितियों का महत्व समझा है और अब उनकी संख्या बढ़ रही है।

अन्य देशों में प्रत्येक गाँव में सब कार्यों के लिए केवल एक सहकारी समिति के सिद्धांत को अधिकाधिक अपनाया जा रहा है। किसान की जितनी भी आवश्यकताएँ हैं उन सबको केवल एक सहकारी समिति ही पूरा करती है। उदाहरण के लिए एक समिति ही साख, क्रय-विक्रय, तथा स्वास्थ्य और सफाई का कार्य करती है, परन्तु भारत में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये भिन्न-भिन्न समितियाँ एक ही गाँव में स्थापित करने की पद्धति चल पड़ी है। सिद्धांत से एक समिति जो किसान की आवश्यकताओं को पूरा करती हो वह अधिक उपयोगी तथा साहूकार की शक्ति को नष्ट करने में अधिक सफल हो सकती है।

भारत में लगभग पाँच हजार गैर-साख कृषि सहकारी समितियाँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों में कार्य कर रही हैं। परन्तु अभी यह आन्दोलन निर्बल है।

### सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ

#### (Co-operative Sale and Purchase Societies)

किसानों के लिये साख के बाद, खेती की पैदावार को अच्छे मूल्य पर बेचना तथा आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर खरीदना महत्वपूर्ण कार्य हैं। भारत में किसान को बीज, यन्त्र, खाद, बैल, तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ गाँव के बनिये अथवा दूकानदार से खरीदनी पड़ती हैं। अधिकांश में वह ऊपर लिखी हुई वस्तुओं को उधार (Credit) खरीदता है और यदि वह साख समिति से ऋण लेकर भी इन वस्तुओं को खरीदे तो भी उसे उन वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। किसान बेचने की कला को भी नहीं जानता, इसलिए वहाँ भी वह गाँव के बनिये, तथा मंडियों के दलालों और व्यापारियों द्वारा लूटा जाता है, और उसको अपनी पैदावार का मूल्य कम मिलता है।

यदि हम चाहते हैं कि किसान की आर्थिक दशा सुधरे तो केवल साख का प्रबन्ध कर देने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए क्रय-विक्रय समितियों



की आवश्यकता होगी। नहीं तो जहाँ हम साख समितियों के द्वारा किसान को महाजन के हाथों से बचाते हैं वहाँ वही महाजन किसान को आवश्यक वस्तुएँ बेचने में और उसकी पैदावार खरीदने में लूटता रहेगा। इस कारण क्रय-विक्रय समितियाँ स्थापित किये बिना किसान की स्थिति सुधर ही नहीं सकती है।

### क्रय समितियाँ ( Purchase Societies )

किसान के लिये आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का कार्य तीन प्रकार की समितियाँ करती हैं। (१) सहकारी साख समितियाँ (२) सहकारी क्रय समितियाँ (३) सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ।

सहकारी साख समितियों के द्वारा यह कार्य अत्यन्त सफलतापूर्वक किया जा सकता है। समिति का जब कोई सदस्य किसी वस्तु को खरीदने के लिए ऋण ले तब उसे रुपया न देकर उसकी वह वस्तु खरीद कर दी जावे। कृषि साख सहकारी समितियाँ बीज, खाद और हल इत्यादि इकट्ठे खरीद कर सदस्यों को उचित मूल्य पर देती हैं।

जहाँ शुद्ध क्रय समितियाँ स्थापित की गई हैं वहाँ यह तरीका है कि समिति का मन्त्री सदस्यों से आर्डर, इकट्ठे कर लेता है। सब आर्डर इकट्ठे कर लेने पर चीज एक साथ मँगवा कर सदस्यों में बाँट दी जाती है। केवल नाम मात्र का कमीशन ले लिया जाता है। इससे यह लाभ होता है कि समिति थोक मूल्य पर वस्तुएँ खरीदती है और सदस्यों को वे वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिल जाती हैं। क्रय सहकारी समिति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मन्त्री अथवा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य बाजार का अध्ययन करते रहे। बाजार भाव के उतार-चढ़ाव का अध्ययन करने से यह लाभ होगा कि समिति मन्दी के समय उन वस्तुओं को खरीद कर रख लेगी जिनकी सदस्यों को बहुत आवश्यकता पड़ती है। समिति के कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आरम्भ से केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीदा जावे जिनकी सदस्यों में अधिक माँग हो।

क्रय समिति परिमित दायित्व ( Limited Liability ) वाली

॥परिमित दायित्वः—समिति के ऋण को चुकाने की सदस्यों की जिम्मेदारी हिस्से के मूल्य तक परिमित होती है।

होती हैं। प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक हिस्सा खरीदना पड़ता है। सब सदस्यों की एक साधारण सभा होती है जो फिर पंचायत अथवा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करती है। यह पंचायत ही समिति के कार्य का संचालन करती है। यदि समिति बहुत बड़ी होती है तो एक वैतनिक मैनेजर रखा जाता है, नहीं तो अवैतनिक मन्त्री ही कार्य चलाता है।

सदस्यों के आर्डर आ जाने पर मैनेजर उन आर्डरों को पञ्चायत के सामने रख देता है। पञ्चायत के आदेशानुसार मैनेजर पञ्चायत के एक सदस्य की सहायता से वस्तुएँ खरीदता है। समिति उन वस्तुओं को सदस्यों के हाथ बेच देती है। लाभ सदस्यों में खरीद के हिसाब से बाँट दिया जाता है।

शुद्ध क्रय समितियाँ भारत में बहुत कम पाई जाती हैं। बम्बई प्रदेश में कुछ क्रय समितियाँ खाद, बीज तथा खेती के यन्त्रों के खरीदने के लिये स्थापित की गई थीं किन्तु उनकी दशा अच्छी नहीं है, वे सफल नहीं हुई। इन समितियों की असफलता का मुख्य कारण दोषपूर्ण प्रबन्ध और सदस्यों की उदासीनता है। सदस्यों के उदासीन रहने का कारण यह भी है कि शुद्ध क्रय समितियाँ वर्ष में कुछ ही समय कार्य करती हैं! खेती के लिये आवश्यक वस्तुएँ खरीद लेने के उपरान्त उनका कोई कार्य नहीं रह जाता जो समितियाँ क्रय-विक्रय दोनों ही कार्य कर रही हैं वे कुछ सफल अवश्य हुई हैं।

### विक्रय समितियाँ ( Marketing Societies )

यह तो पूर्व ही कहा जा चुका है कि अधिकतर किसान ऋणी हैं, इस कारण वे अपनी फसल बेचने में स्वतंत्र नहीं होते। जो गाँव का साहूकार लेन-देन करता है वही फसल को खरीदता है। एक तो फसल काटने के कुछ दिनों बाद तक बाजार भाव वैसे ही गिरा रहता है, दूसरे साहूकार गाँव में अकेला खरीदार होता है; इसलिये यह बाजार भाव से भी कम कीमत पर फसल खरीदता है। कपास, तम्बाकू, जूट तथा अन्य कच्चा औद्योगिक माल खरीदने के लिये व्यापारी ( जो कि बड़े व्यापारियों के एजेंट होते हैं ) गाँव में जाकर फसल खरीदते हैं। ये व्यापारी विदेशों के भाव को भी भली-भाँति

जानते हैं। वे लोग किसानों की फसल को सस्ते दामों पर खरीदते हैं। जिन बड़े किसानों के पास पैदावार अधिक होती है वे पास ही मंडियों में अपनी पैदावार ले जाकर बेचते हैं। किन्तु इन मंडियों में भी किसान को लूटा जाता है। नियमानुसार चुगी तो उसे देनी पड़ती है। मंडी में गाड़ी खड़ी करने का किराया तथा दलाली भी वही देता है। दलाल अधिकतर व्यापारी से मिला रहता है, इस कारण किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कहीं-कहीं किसान को तौलाई भी देनी होती है और तौलाई में अधिकतर उसे धोखा दिया जाता है। मूल्य चुकाने के समय व्यापारी धर्म-शाला, गौशाला, प्याऊ, मन्दिर पाठशाला तथा अन्य ऐसे ही धार्मिक कार्यों के लिये प्रति रुपया कुछ पैसे काट लेता है। शाही कृषि कमोशन का मत है कि इस प्रकार किसान की पैदावार के मूल्य का १० या १२ प्रतिशत काट लिया जाता है। जब तक किसान को इस भयंकर लूट से नहीं बचाया जावेगा तब तक उसकी निर्धनता दूर नहीं हो सकती।

इसी उद्देश्य से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में क्रय-विक्रय समितियाँ स्थापित की गई हैं। परन्तु अभी तक इन समितियों की सख्या बहुत कम है और न यही कहा जा सकता है कि वे बहुत सफल हुई हैं। इनमें बम्बई प्रदेश की कपास और गुड, बङ्गाल की जूट और धान तथा बिहार और उत्तर प्रदेश की गन्ना बेचने वाली समितियाँ अधिक सफल हुई हैं। बम्बई के गुजरात और कर्नाटक प्रदेशों में कपास, गुड, धान, तम्बाकू, मिर्च तथा प्याज बेचने के लिये सहकारी विक्रय समितियाँ स्थापित की गई हैं, किन्तु इनमें कपास बेचने वाली समितियाँ ही सख्या में अधिक तथा महत्वपूर्ण हैं। एक समिति चार या पाँच गाँव की पैदावार को बेचती है। समिति के सदस्य उन्हें एक सा अच्छा बीज देते हैं। फसल काटने पर सदस्य अपनी कपास समिति को दे देते हैं। समिति उन्हें काम चलाने के लिए कुछ रुपया पेशगी दे देती है, और फसल को इकट्ठी करके अपने गोदाम में रखती है। समिति के कार्यकर्ता बाजार का अध्ययन करते रहते हैं और बम्बई तथा अन्य बाजारों में कपास को ऊँचे दामों पर बेच देते हैं। किसान फसल काटते ही उसे बेच देता है क्योंकि उसे रुपये की तुरन्त आवश्यकता होती है, परन्तु समिति कर सकती है, इस कारण उसे पैदावार का अच्छा मूल्य मिलता है। गुजरात

की समितियों ने एक संघ कायम किया है जो इन समितियों को देख-भाल करता है ।

बंगाल में जूट समितियों ने अपनी एक होल-सेल सोसायटी बनाई है । यह होल-सेल सोसायटी एक विशेषज्ञ नौकर रखती है जो कि बाजार भाव का अध्ययन करता है और होल-सेल सोसायटी से सम्बन्धित समितियों को सलाह देता है ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना बेचने वाली समितियाँ अधिक संख्या में स्थापित हो गई हैं । इन समितियों का मुख्य कार्य यह है कि कृषि विभाग के परामर्श के अनुसार गन्ने की खेती की उन्नति करना तथा मिल्सों से समझौता करके उनको सदस्यों की पैदावार बेच देना । गन्ने का मूल्य तो सरकार निश्चय करती है, इस कारण कीमत के तय करने में कोई अड़चन नहीं होती । अभी थोड़ा समय हुआ उत्तर प्रदेश में विशेष कर इटावा तथा पश्चिमी जिलों में बहुत बड़ी संख्या में धी समितियाँ स्थापित हो गई हैं । ये समितियाँ सदस्यों का धी इकट्ठा करके बेचती हैं ।

उत्तर प्रदेश में लगभग चार हजार गन्ना बेचने वाली सहकारी समितियाँ हैं जो अपने सदस्यों का गन्ना मिल्सों को बेचती हैं ।

गन्ना समितियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में लगभग एक हजार धी समितियाँ हैं जो आगरा, एटा, इटावा, मेरठ, मैनपुरी, बुलन्दशहर, बादा और जालौन जिलों में फैली हुई हैं । ये समितियाँ अपने सदस्यों का धी बेचती हैं । इन समितियों के दस हजार से ऊपर सदस्य हैं और प्रतिवर्ष लाखों रुपये का धी बेचती हैं ।

खेती की पैदावार विशेष कर अनाज को बेचने के लिए प्रदेश में दो सौ के लगभग सहकारी विक्रय यूनियन स्थापित की गई हैं जो सदस्यों की पैदावार को मंडी में बेचती हैं । ये विक्रय यूनियन मंडियों में स्थापित हैं ।

अनाज की विक्री के अतिरिक्त प्रदेश में आलू, फल और अड़ों की विक्री के लिये भी कुछ सहकारी विक्रय समितियाँ स्थापित हुई हैं ।

देहरादून में वासमती चावल की भी एक विक्रय समिति स्थापित हो गई है जो १५ गाँवों में उत्पन्न होने वाले वासमती चावल को बेचती है ।

इनके अतिरिक्त पू० पञ्जाब में कुछ सहकारी कमीशन शाप (दूकान) स्थापित

की गई हैं जो सदस्यों और गैर-सदस्यों की पैदावार को बेचती हैं। इनके अतिरिक्त पू० पञ्जाब में क्रय-विक्रय समितियाँ भी स्थापित की गई हैं जो अधिक सफल नहीं हुईं। मद्रास, मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर-प्रदेश में भी क्रय-विक्रय समितियाँ हैं किन्तु ये अधिक सफल नहीं हैं।

### विक्रय समितियों का संगठन

विक्रय समितियाँ परिमित दायित्व ( Limited Liability ) वाली होती हैं। प्रत्येक सदस्य को एक हिस्सा खरीदना होता है। किन्तु विक्रय समितियाँ तभी सफल होती हैं जब कि उनके सदस्य अधिक हों। इसी कारण विक्रय समितियाँ तीन चार गाँवों की पैदावार बेचती हैं। छोटी समितियों के सदस्य वे ही हो सकते हैं जो कि फसल स्वयं उत्पन्न करते हों। जो लोग कि कुछ बेचना नहीं चाहते उन्हें सदस्य नहीं बनाया जाता। सदस्यों की जनरल मीटिंग एक मैनेजिंग कमेटी का चुनाव करती है यही मैनेजिंग कमेटी समिति का कार्य संचालन करती है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि मैनेजिंग कमेटी में वे ही लोग रखे जावें जो व्यापार से परिचित हों। इन समितियों को अधिक राशि में वस्तुओं को बेचने से ही लाभ हो सकता है। इसलिये जितने भी अधिक सदस्य हों अच्छा है। प्रत्येक सदस्य केवल समिति के द्वारा ही अपनी फसल बेच सकता है स्वतन्त्र रूप से नहीं। इस नियम का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिये, नहीं तो उस गाँव के व्यापारी समिति को भंग करने के लिए सदस्यों को उनकी पैदावार का अधिक मूल्य देकर उन्हें फोड़ लेंगे।

फसल कटने पर सदस्य अपनी पैदावार समिति में जमा कर देता है। समिति उसे काम चलाने के लिए अनुमानतः आधा मूल्य उसी समय दे देती है और शेष पैदावार के विक्र जाने पर चुकाती है। समिति इकट्ठी वस्तु को बाजार में यथा समय अच्छे दामों पर बेचती है। समिति लाभ का २५ प्रतिशत नियमानुसार रक्षित कोष में जमा करती है, शेष सदस्यों में उनकी पैदावार के अनुपात से बाँट देती है। इन समितियों को व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस कारण अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इन्हें

होलसेल सोसाइटी\* बना लेनी चाहिये जिससे वे अधिक राशि में पैदावार को बेच कर व्यापारियों की प्रतिद्वन्द्विता में टिक सकें। यह होल-सेल सोसाइटी समितियों को व्यापारिक परामर्श देती रहेगी।

क्रय-विक्रय समितियों के सामने निम्नलिखित कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। (१) छोटी होने पर वे व्यापारियों की प्रतिद्वन्द्विता में टिक नहीं सकतीं। (२) इन समितियों में व्यक्तियों को सदस्य बनाने में यह खतरा है कि व्यापारी अपने आदमियों को उनका सदस्य बनाकर समिति को भंग करने का प्रयत्न करते हैं। अस्तु, केवल साख सहकारी समितियाँ ही उसके सदस्य बनाई जावे किन्तु यह नियम रक्खा जावे कि जो साख समिति के सदस्य नहीं हैं उनकी पैदावार को समिति कमीशन पर बेचेगी (३) इन समितियों के सामने पूँजी की समस्या भी खड़ी होती है। समिति की निजी पूँजी बहुत कम होती है और सेंट्रल सहकारी पूँजी के बराबर ही ऋण देते हैं किसान कुछ रुपया पेशगी चाहता है अतएव पूँजी की कमी रहती है।

क्रय-विक्रय समितियों को और सरकार तथा जनता दोनों को हो ध्यान देना चाहिये क्योंकि बिना उनके यथेष्ट सख्या में स्थापित किये किसान को दलालों तथा व्यापारियों की लूट से नहीं बचाया जा सकता। और जब तक उसे अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता तब तक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती।

**भूमि की चकवन्दी करने वाली समितियाँ**

( Consolidation of Land Holdings Societies )

यह तो पहले ही लिखा जा चुका है कि भारत में किसानों के पास जो भी भूमि है वह छोटे-छोटे खेतों में बँटी हुई है और ये खेत एक दूसरे से दूर हैं। बिखरे हुये छोटे-छोटे खेतों पर अच्छी तरह से खेती नहीं हो सकती क्योंकि किसान का इन बिखरे हुए खेतों पर खेती करने से बहुत सा समय, शक्ति, श्रम, तथा पूँजी नष्ट होती है। यदि सब खेत एक ही स्थान पर हों तो किसान कम लब्ध में अधिक पैदावार उत्पन्न कर सकता है।

---

\* होल-सेल सोसाइटी—यं.क. क्रि. करने वाली समिति जिससे गाव की समितियाँ सम्बन्धित होती हैं।

अर्थशास्त्र का कहना है कि जब तक बिखरे हुये खेतों की समस्या को हल नहीं किया जाता तब तक खेती का सुधार हो ही नहीं सकता । भारत मे सबसे पहले पू० पंजाब में सहकारिता विभाग ने चकबन्दी सहकारी समितियाँ स्थापित करके बिखरे हुये खेतों की समस्या को हल करने का सफल प्रयत्न किया । अब हम चकबन्दी सहकारी समितियों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से लिखते हैं ।

खेती की चकबन्दी करने का सिद्धान्त यह है गाँव मे जितने भी खेतों के मालिक हैं उन सबके खेतों को इस तरह अदल-बदल दिया जावे कि हर एक को अपने सब खेतों के बराबर ही जगह एक चक में या दो या तीन चकों में मिल जावे ।

### चकबन्दी समिति की स्थापना

किसी गाँव मे चकबन्दी समिति स्थापित करने के पहले सहकारिता विभाग के कर्मचारी गाँव मे जाकर किसानों को बिखरे हुये खेतों से होने वाली हानियाँ और चकबन्दी के लाभ समझते हैं । यदि सहकारिता विभाग का कर्मचारी प्रचार करने के बाद यह समझता है कि उस गाँव के लोग चकबन्दी कराने के लिये राजी हैं तो वह एक सभा करता है और गाँव वालों को बतलाता है कि चकबन्दी किस प्रकार की जावेगी । यदि सब गाँव वाले तैयार होते हैं तो समिति बना ली जाती है और पचायत चुन ली जाती है । समिति का सदस्य मौरूसी किसान हो सकता है ।

समिति के सदस्यों को निम्नलिखित बातें स्वीकार करनी पडती हैं :—

१—खेतों की चकबन्दी करने के लिये बिखरे हुये खेतों का नया बँटवारा होना जरूरी है ।

२—यदि नये बँटवारे को दो तिहाई सदस्य स्वीकार कर लेंगे तो वह बँटवारा सब को स्वीकार करना होगा ।

३—नये बँटवारे के अनुसार वह अपने खेतों को सदा के लिये छोड़ देगा ।

४—यदि किसी प्रकार का झगडा खडा होगा तो पंच नियुक्त कर दिये जावेगे और उनका फैसला सबको मानना होगा ।

चकबन्दी करने में भी कठिनाइयाँ पडती हैं । सर्वप्रथम सहकारिता

विभाग का कर्मचारी गाँव में कितनी प्रकार की भूमि है यह निश्चित करता है। नये बँटवारे में जमीन की भिन्न-भिन्न उपजाऊ शक्ति का ध्यान रखना पड़ता है। कुओं में किसानों का हिस्सा निर्धारित किया जाता है और पेड़ों (यदि खेतों पर हों) का मूल्य निश्चित करने के बाद नये बँटवारे का नकशा बनाया जाता है। यह नकशा सब सदस्यों के सामने रखा जाता है। यदि सब सदस्य नये बँटवारे को मान लेते हैं तब तो वह लागू हो जाता है, नहीं तो फिर से नया नकशा तैयार किया जाता है। इस प्रकार कभी-कभी तीन चार बार नकशे तैयार करने पड़ते हैं फिर भी सारा परिश्रम केवल एक किसान के हठ से नष्ट हो जाता है।

यद्यपि नियम २ के अनुसार यदि दो तिहाई सदस्य नये बँटवारे को मान ले तो बाकी को उसे मानना पड़ता है, परन्तु इस नियम को काम में नहीं लाया जाता और किसी को भी अपना खेत छोड़ने पर विवश नहीं किया जाता। ऐसा करने से काम बहुत धीरे होता है। पू० पञ्जाब में इस नियम को कड़ाई के साथ काम में लाने लगे हैं। जब नये बँटवारे को सब लोग मान लेते हैं तो उन्हें नये खेत दे दिये जाते हैं और उन खेतों की रजिस्ट्री करा दी जाती है।

किन्तु चकबन्दी कराने में बहुत सी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। जिस योजना में सब किसानों का राजी करना जरूरी हो उसका सफल होना सन्देहजनक हो जाता है। बुढ़े किसान अपने त्राप-दादों की जमीन छोड़ना ही नहीं चाहते, हर एक किसान को अपनी जमीन अधिक उपजाऊ मालूम होती है। जिस किसी के पास एक या दो खेत हैं उसे चकबन्दी से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। मौरूसी कार्रकार यह समझता है कि यदि उसने अपना खेत बदल लिया तो उसके सारे हक छिन जावेगे। गाँव का पटवारी भी चकबन्दी का विरोध करता है क्योंकि वह समझता है कि चकबन्दी हो जाने से उसकी आमदनी कम हो जावेगी। इन कठिनाइयों के रहते हुये भी यदि कार्यकर्ता धैर्य तथा सहानुभूति से कार्य करे तो वह किसानों को राजी कर सकता है।

चकबन्दी आन्दोलन का प्रारम्भ पू० पञ्जाब में हुआ और वही वह सब से अधिक सफल हुआ है। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के



पूर्व प्रतिवर्ष दो लाख एकड़ भूमि की पू० पञ्जाब मे चकवन्दी हो गई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तथा विजनौर जिलों मे चकवन्दी समितियाँ स्थापित की गई हैं जो सफलतापूर्वक चकवन्दी का काम कर रही हैं, किन्तु इनकी संख्या अधिक नहीं है। बड़ौदा और काश्मीर में भी चकवन्दी समितियाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

कुछ विद्वानों का कहना है कि बिखरे हुए खेतों की समस्या ऐसी विकट है कि केवल सहकारी चकवन्दी समितियों से ही वह हल न होगी, क्योंकि समितियों के द्वारा कार्य बहुत धीरे होता है। अतएव उनकी राय में सरकार एक कानून बनाकर बिखरे हुये खेतों की चकवन्दी कर दे। मध्यप्रदेश, पूर्वी पञ्जाब तथा उत्तर-प्रदेश मे इस आशय का एक कानून बनाया गया है।

### सहकारी कृषि समितियाँ

#### ( Co-operative Farming Societies )

चकवन्दी के पश्चात् भी खेतों का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं होगा कि बड़ी मात्रा की खेती की जा सके अथवा उन्नत कृषि साधनों का उपयोग किया जाय। इसके अतिरिक्त शरणार्थियों को खेती के क्षेत्र मे बसाने तथा देश की भोजन सम्बन्धी कमी पूरी करने के लिये अधिक भूमि में खेती करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का सरकार इस समय तराई, गंगा खादर और बुन्देलखंड के प्रदेशों मे ट्रैक्टरों द्वारा भूमि तैयार करके सहकारी ढग पर खेती करने के लिये किसानों को जमीन दे रही है। प्रत्येक किसान सहकारी कृषि समिति का सदस्य होता है। समिति उसके लिये बीज, औजार आदि का प्रबन्ध करती है तथा उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। किसान को अपने माल की बिक्री समिति के द्वारा ही करनी पड़ती है। समिति किसान को फसल-योजना का भी निश्चय करती है। गंगा खादर मे प्रत्येक परिवार को दस-दस एकड़ भूमि और बैल खरीदने के लिए पेशगी रुपये दिये गये हैं। प्रदर्शन और बीज के सहकारी फार्म खोले जा रहे हैं।

अन्य-प्रदेश मे जो सहकारी खेती के प्रयोग हो रहे हैं कुछ विद्वानों का कथन है कि इसके स्थान पर रूसी ढग पर कृषि व्यवस्था होनी चाहिये। उनके अनुसार सहकारी खेती असफल सिद्ध होगी। कम से कम उन क्षेत्रों

मे जहाँ खेती हो रही है इसकी असफलता रहेगी । दर असल सहकारी खेती का प्रयोग होना चाहिये । तभी सफलता का पता चलेगा ।

### रहन-सहन सुधार समितियाँ ( Better Living Societies )

रहन-सहन सुधार समितियाँ ( Better Living Societies ) सर्व-प्रथम पू० पञ्जाब मे स्थापित की गई और क्रमशः ये अन्य प्रदेशों मे स्थापित होती जा रही हैं ।

रहन-सहन सुधार समितियों का प्रधान उद्देश्य गाँवों में प्रचलित बुरी रस्मों को बन्द करना, सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों के लिए कर्ज लेकर फिजूल खर्च करने की आदत को रोकना, गाँव मे सफाई रखना, खेतीबारी को उन्नत करने के उपायों का प्रचार करना, कुओं की मरम्मत करवाना, गाँव की गलियों को ठीक करना, खाद के गड़हे बनवाना, ट्रैड दाइयों को गाँव मे रखना, घरों मे हवा तथा रोशनी के लिए खिड़की तथा रोशनदान लगाने का प्रचार करना, तथा जेवर पर व्यय न करने के लिए गाँव वालों को समझाना है ।

इन समितियों का संगठन बहुत सहल है । सदस्यों को हिस्सा नहीं खरीदना पड़ता और न समिति की कोई हिस्सा पूँजी (Share Capital) ही होती है । प्रत्येक गाँव का रहने वाला जो समिति के सिद्धान्त और नियमों का पालन करने को तैयार हो वह समिति का सदस्य बन सकता है । सदस्य को केवल नाम मात्र की प्रवेश फीस देनी होती है । सदस्यों से कोई चन्दा भी नहीं लिया जाता । साधारण सभा ( General Meeting ) जिसमे सब सदस्य होते हैं कुछ उपनियम बनाती है जिनका पालन प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य होता है । उदाहरण के लिए समिति यह निश्चय कर देगी कि शादी, मृत्यु तथा अन्य धार्मिक कार्यों पर अधिक से अधिक एक सदस्य कितना रुपया खर्च कर सकता है । जो भी सदस्य इस नियम की अवहेलना करेगा उसे दण्ड स्वरूप जुर्माना देना होगा । प्रतिवर्ष गाँव के सुधार के लिए समिति एक वार्षिक योजना स्वीकार करती है और उसके सम्बन्ध में नियमादि बना देती है । जो भी सदस्य उन नियमों का पालन नहीं करता उनको दण्ड दिया जाता है । एक वर्ष गाँव की सफाई का

प्रोग्राम बनाया जाता है, सदस्यों को अपनी खाद गड़हों में रखने के लिये कहा जाता है। रहन-सहन सुधार समितियाँ (Better Living Societies) वास्तव में ग्राम सुधार कार्य को करती हैं। इनके द्वारा ग्रामसुधार कार्य अधिक संगठित तथा सुचारु रूप से चल सकता है।

पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये समितियाँ अधिक सफल हुई हैं और सख्या में अधिक हैं। पू० पंजाब के सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार का कथन है कि जिन गाँवों में समितियाँ स्थापित हो गई हैं वहाँ के रहने वालों को उनके द्वारा हजारों रुपये की बचत होती है। जो भी इन समितियों के सदस्य होते हैं वे नियमानुसार इस प्रकार अपव्यय कर ही नहीं सकते, साथ ही वे अन्य किसी भी गाँव वाले के विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकते, जहाँ इस प्रकार अपव्यय किया जावे। इस प्रकार समिति का प्रभाव गैर-सदस्यों पर भी पड़ता है। पू० पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में ये समितियाँ गाँव की सफाई करवाती हैं, गलियों को साफ तथा एक सा करवाती हैं तथा गाँव वालों को हवा तथा रोशनी का महत्व बतलाकर मकानों में खिड़की और रोशन-दान लगवाती हैं। पू० पंजाब में ये समितियाँ जेवर के बनवाने का भी विरोध करती हैं क्योंकि इससे रुपये का नुकसान तो होता ही है, साथ ही चोरी का भी भय रहता है। उत्तर प्रदेश तथा पू० पंजाब दोनों ही में ये समितियाँ सदस्यों को खाद गड़हों में रखने के लिए विवश करती हैं जिससे कि गाँव गदा न हो और खाद उत्तम तैयार हो। पंजाब में एक समिति ने गोबर के कडे न बनाने का और सारे गोबर की खाद बनाने का निश्चय किया है। पू० पंजाब में तीन सौ से ऊपर रहन-सहन सुधार समितियाँ किसी न किसी रूप में ग्राम-सुधार कार्य कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश में रहन-सहन सुधार समितियों की सख्या पू० पंजाब से बहुत अधिक है और साथ ही वे पू० पंजाब से अधिक क्रियाशील भी हैं। ऊपर लिखे हुए कार्यों के अतिरिक्त वे कहीं-कहीं अस्पताल चलाती हैं, प्रौढ़ों के लिए रात्रि पाठशालाएँ खोलती हैं, ट्रेड दाइयाँ रखती हैं, अच्छा बीज खरीद कर बेचती हैं, और कुये बनवाती हैं। उत्तर प्रदेश में रहन-सहन सुधार समितियाँ प्रदेश के पूर्वीय भाग में अधिक हैं। उत्तर प्रदेशीय सहकारिता विभाग ने परतापगढ़ तथा मसौधा (फैजाबाद) में रहन-सहन सुधार समितियों (परतापगढ़

में १५० के लगभग तथा मसौदा में ७० के लगभग समितियाँ हैं जो ग्राम-सुधार कार्य करती हैं ) के द्वारा संगठित रूप में ग्राम-सुधार कार्य किया है और उनमें उसे सफलता भी मिली है ।

यदि देखा जावे तो रहन-सहन सुधार समिति अत्यन्त उपयोगी संस्था है और ग्राम-सुधार कार्य में इसका बहुत उपयोग हो सकता है ।

उपभोक्ता सहकारी भंडार-

(Consumers' Co-operative Stores)

मनुष्य समाज का प्रत्येक सदस्य उपभोक्ता है । प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, इस कारण प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ वस्तुओं का उपभोग करना होता है । यदि देखा जावे तो सम्पत्ति का उत्पादन करने वालों तथा उसको उपभोग करने वालों का घनिष्ठ सम्बन्ध है । एक दूसरे पर निर्भर हैं किन्तु उत्पादन करने वालों के बीच में इतने दलाल (middlemen) हैं कि वे एक दूसरे से बहुत दूर पड़ जाते हैं । व्यापारी ( दलाल ) वस्तुओं में उत्पन्न करने वालों को उनका जो मूल्य देते हैं उससे बहुत अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से वसूल करते हैं । यदि

एक पौड रूखा । २ पैसे प्रति सप्ताह किश्त लेकर दो वर्षों में २८ पौड पूँजी इकट्ठी की और आरम्भ में केवल पाँच वस्तुओं ( मक्खन, शक्कर, ओट का आटा, गेहूँ का आटा, तथा मोमबत्ती ) को बेचने का प्रबन्ध किया । स्टोर्स सौदा उधार नहीं देता था, किन्तु वस्तुयें शुद्ध तथा तौल में पूरी होती थी । प्रत्येक सदस्य का एक वोट था । लाभ खरीदारी के अनुपात में बाँटा जाता था । उदाहरण के लिए एक सदस्य ने वर्ष में पचास पौड की चीज और दूसरे ने सौ पौड की खरीदी तो दूसरे को दुगुना लाभ मिलता था । सदस्यों को उत्साहित किया जाता था कि वे अपने लाभ का हिस्सा स्टोर्स में जमा करा दें । इस प्रकार स्टोर्स की पूँजी बढ़ती गई । सदस्यों को उस जमा किये हुये रुपये पर सूद मिलता था ।

राकडेल स्टोर्स सफल हो गया, क्रमशः स्टोर्स सब वस्तुएँ सदस्यों को बेचने लगा । राकडेल स्टोर की इस आश्चर्यजनक सफलता को देखकर इंगलैंड में शीघ्र ही बहुत से स्टोर्स खुल गये ।

इन स्टोर्स की सफलता देखकर फुटकर विक्रेता ( दूकानदार ) चौंके और उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया । उन्होंने मिलकर थोक व्यापारियों पर जोर डाला कि वे स्टोर्स को अधिक मूल्य पर वस्तुएँ दें । अब सहकारी स्टोर्स के सामने एक कठिन समस्या उपस्थित हुई । किन्तु उन्होंने आपस में मिल कर होल-सेल सोसायटी स्थापित कर ली । होल-सेल सोसायटी सीधे कारखानों से वस्तुएँ मोल लेकर स्टोर्स को थोक मूल्य पर बेचती हैं । इस प्रकार स्टोर्स ने थोक व्यापारियों के लाभ को भी छीन लिया । प्रत्येक स्टोर्स इस होल-सेल-सोसायटी का सदस्य होता है । सोसायटी का वार्षिक लाभ स्टोर्स में अपनी खरीदारी के अनुपात में बाँट दिया जाता है । अन्त में होल-सेल सोसायटी ने उन वस्तुओं को जिनको स्टोर्स खरीदते थे स्वयं ही कारखाने खड़े करके बनाना आरम्भ कर दिया । बूट, साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, मोजे, वनियाइन, कपड़ा, फर्नीचर, सिगरेट, लोहे, टिन की वस्तुएँ छापेखाने, तेल, आटा, मक्खन, मोमबत्ती तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ बनाने के कारखाने खोले गये । सोसायटी ने अनाज, तरकारी तथा फल उत्पन्न करने के लिये फार्म खोले । आसाम में चाय के बाग मोल लिये । कहने का तात्पर्य यह है कि वह प्रत्येक वस्तु को स्वयं उत्पन्न करने लगी । इस प्रकार

उपभोक्ताओं ने स्टोर्स को स्थापित करके फुटकर दूकानदारी, थोक व्यापारियों तथा कारखाने के लाभ को भी छीन लिया ।

**सहकारी स्टोर्स ( भंडार ) के मुख्य-नियम**

(१) सहकारी स्टोर्स परिमित दायित्व ( Limited Liability ) वाली सस्था होती है ।

(२) प्रत्येक सदस्य को स्टोर्स के हिस्से खरीदने होते हैं, किन्तु वोट देने का अधिकार हिस्से के हिसाब से नहीं होता है । प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का ही अधिकार होता है ।

(३) प्रत्येक सदस्य को उन वस्तुओं को जो स्टोर बेचता है स्टोर से ही खरीदनी पड़ती है ।

(४) स्टोर उधार नहीं बेचता और बाजार भाव पर ही शुद्ध और अच्छी वस्तुएँ देता है । भाव में कमी नहीं करता ।

(५) एक चौथाई लाभ रक्षित कोष में जमा किया जाता है और शेष सदस्यों में उनकी खरीदारी के अनुपात में बाँट लिया जाता है ।

(६) सदस्यों की सभा जनरल मीटिंग कहलाती है । स्टोर्स की नीति वही निर्धारित करती है और उसका प्रबन्ध करने के लिये एक प्रबन्धकारिणी समिति ( Managing Committee ) चुन देती है । प्रबन्धकारिणी समिति स्टोर्स का प्रबन्ध करती है ।

**भारत में उपभोक्ता भंडार**

भारत में अभी तक उपभोक्ता स्टोर्स असफल हो रहे हैं । यदि कहीं-कहीं थोड़े से स्टोर्स सफल दृष्टिगोचर होते हैं तो भी आन्दोलन सफल नहीं कहा जा सकता । अधिकतर कालेजों और रेलवे के स्टोर्स सफल हुये हैं । इन स्टोर्स को दूकानदारों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती तथा उन्हें बहुत सी अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं ।

हो गये और बहुतों का दिवाला निकल गया। सन् १९३६ के उपरान्त युद्ध के कारण फिर हजारों की संख्या में स्टोर्स खुल गये हैं किन्तु कन्ट्रोलों के समाप्त हो जाने पर उनकी क्या दशा होगी यह कह सकना कठिन है। मद्रास में एक होल-सेल सोसायटी भी बन गई है।

### भारत में भंडारों की असफलता के मुख्य कारण

यह तो सर्वविदित है कि गनी व्यक्ति तो भंडार की ओर आकर्षित नहीं होते क्योंकि यदि उन्हें अपनी वस्तुओं की खरीदारी पर वर्ष के अंत में कुछ लाभ मिलता है तो वह उनके लिये कोई अधिक बचत नहीं होती। इंग्लैंड में स्टोर्स आन्दोलन ने अधिकतर मजदूरों और निचले मध्यवर्ग के लोगों को आकर्षित किया है। भारत में कारखानों के मजदूर अशिक्षित और निर्धन हैं इस कारण सङ्गठन के महत्व को नहीं समझते। वे अधिकतर दूकानदारों के ऋणी हैं। साथ ही वे स्थायी रूप से कारखानों में काम नहीं करते, कुछ वर्षों के बाद वे अपने गाँवों को चले जाते हैं। इस कारण वे स्टोर्स के हिस्से लेकर उसके सदस्य नहीं बनना चाहते।

रहा मध्यवर्ग, वह भी स्टोर्स की ओर आकर्षित नहीं होता क्योंकि व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रों में प्रत्येक वस्तु की इतनी अधिक दूकानें होती हैं कि थोक और फुटकर मूल्य में अधिक अन्तर नहीं होता, प्रत्येक दूकानदार महीने के अन्त में मूल्य लेता है और परचूनी वाले घर पर ही सामान पहुँचा देते हैं। ये सुविधाएँ स्टोर्स नहीं दे सकता।

भारत में सहकारी स्टोर्स के साथ पूँजी की भी कठिनाई होती है। सदस्यों के लिये हुए हिस्सों से इतनी पूँजी इकट्ठी नहीं होती कि काम चल जाये और सेंट्रल तथा डिस्ट्रिक्ट बैंक उन्हें ऋण नहीं देते। एक कमी और है जिसके कारण भारत में स्टोर्स आन्दोलन पनप नहीं सका वह है होल-सेल सोसायटी की कमी। स्टोर्स थोक व्यापारियों से माल खरीदते हैं पर थोक व्यापारी उनसे मूल्य अधिक लेते हैं इस कारण स्टोर्स को अधिक लाभ नहीं हो सकता। यदि होल-सेल सोसायटी स्थापित हो जावे तो थोक व्यापारियों का लाभ भी सदस्यों के लिये सुरक्षित किया जा सकता है।

ऊपर लिखे कारणों से स्टोर्स आन्दोलन भारत में न फैल सका, अब

हम उन कारणों को लिखते हैं जिनसे वे थोड़े से स्टोर्स जो खोले गए थे असफल हो गये।

स्टोर्स की असफलता का मुख्य कारण यह है कि सदस्य स्टोर आन्दोलन के मुख्य सिद्धान्त को भूल जाते हैं। वे समझते हैं कि स्टोर्स सस्ती चीजें बेचने के लिए खोला गया है। इसका फल यह होता है कि जब बाजार भाव सस्ता हो जाता है तो स्टोर्स की दशा खराब हो जाती है, और सदस्य स्टोर्स में चीजें न खरीद कर दूकानदार से खरीदने लगते हैं। स्टोर असफल हो जाता है।

सिद्धान्त तो यह है कि वस्तुएँ बाजार भाव पर बेची जायें किन्तु चीजें अच्छी हों और तौल में पूरी हों। असफलता का दूसरा मुख्य कारण है सौदा उधार देना। स्टोर को सौदा उधार देने के कारण थोक व्यापारियों से माल उधार लेना पड़ता है।

असफलता का तीसरा मुख्य कारण प्रबन्ध का ठीक न होना और व्यय का अधिक होना है। सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रबन्धकारिणी समिति तथा सदस्य स्टोर के कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते और न अपना समय ही देते हैं। फल यह होता है कि वैतनिक मैनेजर तथा सेल्समेन ही स्टोर के कर्ता-धर्ता बन जाते हैं।

१९३६ के उपरान्त महायुद्ध के कारण खाने-पीने की चीजों का दाम जब बहुत बढ़ गया और कहीं-कहीं उन वस्तुओं का मिलना भी कठिन हो गया तब सहकारी स्टोर्स स्थापित करने की ओर लोगों का ध्यान गया। इसी कारण पिछले दो तीन वर्षों में सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता स्टोर्स प्रत्येक प्रदेश में स्थापित हो गए हैं और होते जा रहे हैं। यह कहना कठिन है कि नियंत्रण के हटने पर जब सब चीजें आसानी से मिलने लगेंगी तब भी ये स्टोर्स रहेगे या दूट जावेगे।

मद्रास और बम्बई प्रदेशों में इन स्टोरों की होल-सेल यूनियन भी स्थापित हो गई हैं जो अपने सम्बन्धित स्टोरों के लिए थोक माल खरीदती हैं और स्टोरों को बेच देती हैं।

### मद्रास का ट्रिपलीकेन स्टोर

भारत में केवल ट्रिपलीकेन स्टोर ने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त  
 ग्रा० अ० शा०—२१



की है। यह स्टोर ६ अप्रैल १९०४ को खोला गया। आरम्भ में केवल आठ-आठ रुपये के दो कर्मचारी रखे गए। स्टोर के जन्मदाताओं ने स्टोर की देखभाल में बहुत समय देना शुरू किया। जहाँ तक हुआ व्यय कम किया गया। स्टोर सफल हुआ। आज स्टोर की बीस शाखाएँ काम कर रही हैं। ६ के पास अपनी निजी इमारतें हैं। स्टोर वर्ष में ग्यारह या बारह लाख रुपये की वस्तुएँ बेचता है। स्टोर की चुकाई हुई पूँजी एक लाख रुपये से अधिक है और रक्षित कोष ( Reserve Fund ) डेढ़ लाख रुपये के लगभग है।

मदरास और मैसूर में स्टोर कुछ सफल हुए हैं। बंगलोर का स्टोर भी एक अत्यन्त सफल सस्था है, परन्तु वह ट्रिपलीकेन स्टोर से छोटा है। भारत में स्टोर्स की संख्या बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में नए स्टोर्स खुल रहे हैं। भारत के अधिकतर स्टोर्स असफल हैं।

### महायुद्ध और स्टोर

द्वितीय महायुद्ध के समय भी कंट्रोल के कारण तथा आवश्यक वस्तुओं के न मिलने के कारण बहुत बड़ी संख्या में सहकारी उपभोक्ता स्टोर्स खोले गए थे। अभी यह कह सकना बहुत कठिन है कि जब यह कंट्रोल इत्यादि टूट जावेगे तब ये स्टोर्स व्यापारियों की होड़ में टिक सकेगे या नहीं। कम से कम इस समय तो प्रादेशिक सरकार की नीति राशन तथा कंट्रोल की वस्तुओं का वितरण उपभोक्ता स्टोर्स के द्वारा कराने की है। शहर और गाँव में स्थान-स्थान पर ये स्टोर खोले जा रहे हैं। सन् १९४८ के आरम्भ में जब कंट्रोल हटाया गया था, सरकार को विश्वास दिलाया गया था कि व्यापारी-गण अब धोखाधड़ी और बेईमानी नहीं करेंगे। परन्तु सरकार को धोखा हुआ और अब सरकार व्यापारियों के हित-अहित का ध्यान छोड़ कर सहकारी स्टोर्स की व्यवस्था कर रही है। उत्तर प्रदेश में कई हजार सहकारी स्टोर्स स्थापित किये जा चुके हैं परन्तु उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सहकारी शिक्षा का अभाव तथा कम प्रचार है।

### अभ्यास के प्रश्न

१—गैर साख कृषि सहकारी समितियों को क्यों स्थापित किया गया ? उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

२—केवल साख कृषि सहकारी समिति से ही किसान की सारी समस्याएँ क्यों हल नहीं हो सकती ?

३—गाँव वालों को गाँव के बनिये से चीजें खरीदने में क्या हानि होती है ? यदि वे क्रय-समिति बना लें तो उनको क्या लाभ होगा ?

४—यदि तुमसे कहा जावे कि तुम अपने गाँव में एक क्रय-समिति बनाओ तो तुम उसका संगठन किस प्रकार करोगे ?

५—क्रम-प्रमिति अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करती है ?

६—गाँव के महाजन बाहर से आने वाले व्यापारियों के एजेंट तथा मंडी में अपनी पैदावार बेचने से किसान की क्या हानि होती है ?

७—इस स्थिति में जिसमें कि किसान आजकल है वह अपनी पैदावार का उचित मूल्य क्यों नहीं पा सकता ?

८—विक्रय समितियाँ क्या कार्य करती हैं ? किसानों को विक्रय-समिति के सदस्य बनने से क्या लाभ होता है ?

९—विक्रय समिति का संगठन किस प्रकार होता है और वह किस प्रकार सदस्यों की पैदावार को बेचती हैं ?

१०—विक्रय-समिति को सफलतापूर्वक चलाने में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ पड़ती हैं ?

११—चक्रबन्दी समितियाँ किस प्रकार गाँव के बिखरे हुये खेतों की चक्रबन्दी करती हैं ?

१२—चक्रबन्दी समिति के स्थापित होने तथा उसके सफलतापूर्वक चक्रबन्दी करने में क्या-क्या अड़चनेँ आती हैं ? क्या इनके स्थान पर सहकारी कृषि समितियाँ स्थापित की जायँ ?

१३—रहन-सहन-सुधार समितियों का क्या उद्देश्य है और वे कौन-कौन से कार्य करती हैं ?

१४—रहन-सहन सुधार समितियाँ कहाँ-कहाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं ?

१५—इंग्लैंड में उपभोक्ता स्टोर आन्दोलन का विवरण लिखिए ।

१६—उपभोक्ता स्टोर जिन नियमों के अनुसार काम करता है उनको बतलाइये ।

१९६१-६२ के अग्रे अप्रैल १९०४ को खोला गया। आरम्भ में केवल आठ-आठ रुपये के दो कर्मचारी रखे गए। स्टोर के जन्मदाताओं ने स्टोर की देखभाल में बहुत समय देना शुरू किया। जहाँ तक हुआ व्यय कम किया गया। स्टोर सफल हुआ। आज स्टोर की बीस शाखाएँ काम कर रही हैं। ६ के पास अपनी निजी इमारतें हैं। स्टोर वर्ष में ग्यारह या बारह लाख रुपये की वस्तुएँ बेचता है। स्टोर की चुकाई हुई पूँजी एक लाख रुपये से अधिक है और रक्षित कोष ( Reserve Fund ) डेढ़ लाख रुपये के लगभग है।

मदरास और मैसूर में स्टोर कुछ सफल हुए हैं। बंगलोर का स्टोर भी एक अत्यन्त सफल सस्था है, परन्तु वह ट्रिपलीकेन स्टोर से छोटा है। भारत में स्टोर्स की संख्या बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में नए स्टोर्स खुल रहे हैं। भारत के अधिकतर स्टोर्स असफल हैं।

### महायुद्ध और स्टोर

द्वितीय महायुद्ध के समय भी कंट्रोल के कारण तथा आवश्यक वस्तुओं के न मिलने के कारण बहुत बड़ी संख्या में सहकारी उपभोक्ता स्टोर्स खोले गए थे। अभी यह कह सकना बहुत कठिन है कि जब यह कंट्रोल इत्यादि टूट जावेंगे तब ये स्टोर्स व्यापारियों की होड़ में टिक सकेंगे या नहीं। कम से कम इस समय तो प्रादेशिक सरकार की नीति राशन तथा कंट्रोल की वस्तुओं का वितरण उपभोक्ता स्टोर्स के द्वारा कराने की है। शहर और गाँव में स्थान-स्थान पर ये स्टोर खोले जा रहे हैं। सन् १९४८ के आरम्भ में जब कंट्रोल हटाया गया था, सरकार को विश्वास दिलाया गया था कि व्यापारी-गण अब धोखाधड़ी और बेईमानी नहीं करेंगे। परन्तु सरकार को धोखा हुआ और अब सरकार व्यापारियों के हित-अहित का ध्यान छोड़ कर सहकारी स्टोर्स की व्यवस्था कर रही है। उत्तर प्रदेश में कई हजार सहकारी स्टोर्स स्थापित किये जा चुके हैं परन्तु उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सहकारी शिक्षा का अभाव तथा कम प्रचार है।

### अभ्यास के प्रश्न

१—गैर साख कृषि सहकारी समितियों को क्यों स्थापित किया गया ? उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

२—केवल साख कृषि सहकारी समिति से ही किसान की सारी समस्याएँ क्यों हल नहीं हो सकतीं ?

३—गाँव वालों को गाँव के बनिये से चीजे खरीदने में क्या हानि होती है ? यदि वे क्रय-समिति बना ले तो उनको क्या लाभ होगा ?

४—यदि तुमसे कहा जावे कि तुम अपने गाँव में एक क्रय-समिति बनाओ तो तुम उसका संगठन किस प्रकार करोगे ?

५—क्रम-प्रमिति अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करती है ?

६—गाँव के महाजन बाहर से आने वाले व्यापारियों के एजेंट तथा मंडी में अपनी पैदावार बेचने से किसान की क्या हानि होती है ?

७—इस स्थिति में जिसमें कि किसान आजकल है वह अपनी पैदावार का उचित मूल्य क्यों नहीं पा सकता ?

८—विक्रय समितियाँ क्या कार्य करती हैं ? किसानों को विक्रय-समिति के सदस्य बनने से क्या लाभ होता है ?

९—विक्रय समिति का संगठन किस प्रकार होता है और वह किस प्रकार सदस्यों की पैदावार को बेचती है ?

१०—विक्रय-समिति को सफलतापूर्वक चलाने में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ पड़ती हैं ?

११—चक्रवर्दी समितियाँ किस प्रकार गाँव के दिखरे हुये खेतों की चक्रवर्दी करती हैं ?

१२—चक्रवर्दी समिति के स्थापित होने तथा उसके सफलतापूर्वक चक्रवर्दी करने में क्या-क्या अट्ठचने आती हैं ? क्या इनके स्थान पर सहकारी कृषि समितियाँ स्थापित की जायें ?

१३—रहन-सहन-सुधार समितियों का क्या उद्देश्य है और वे कौन-कौन से कार्य करती हैं ?

१७—भारत में उपभोक्ता स्टोर आन्दोलन क्यों असफल रहा ?

१८—उपभोक्ता स्टोर से क्या लाभ हैं ? यदि तुम्हारे स्कूल में विद्यार्थी उपभोक्ता स्टोर खोलना चाहे तो तुम उसके लिए कौन से नियम पसन्द करोगे ?

१९—निम्नांकित किसी सहकारी समिति को व्यवस्था और कार्य-प्रणाली का वर्णन कीजिये ।

(क) उपभोक्ता स्टोर ( १९४८ )

(ख) रहन-सहन सुधार-समिति ( १९४६ )

(ग) सहकारी कृषि-समिति ।

२०—तुम्हारे प्रदेश में कौन-कौन सी कृषि सहकारी समितियाँ चालू हैं ? वे किस प्रकार से ग्रामीणों की हालत सुधारने में सहायता करती हैं ? ( १९४४ )

२१—उपभोक्ता स्टोर या बिक्री समिति के सिद्धान्त समझाइए । ( १९४४ )

२२—औद्योगिक केन्द्रों में सहकारी उपभोक्ता स्टोरों की क्या आवश्यकता है ? आपके प्रदेश में ऐसे स्टोर क्यों सफल नहीं हुए हैं ? ( १९४३ )

## इकतीसवाँ अध्याय

### सहकारी समितियों के संघ

(Union of Co-operative Societies)

सहकारिता आन्दोलन सर्वसाधारण का आन्दोलन है । उसे बाहरी सहायता पर निर्भर न रह कर स्वावलम्बी बनाना चाहिये । साख समितियों को डिपाजिट आकर्षित करके कार्यशील पूँजी स्वयं इकट्ठी करनी चाहिए । परन्तु भारत में जब साख समितियाँ डिपाजिट आकर्षित करने में असफल रहीं तो सेन्ट्रल बैंक अथवा बैङ्किंग यूनियन की स्थापना करनी पड़ी । सहकारी समितियों की देखभाल साधारणतः उनकी पचायत को करनी चाहिये । किन्तु अशिक्षा के कारण जब पचायत अपना कार्य सुचारु रूप से न कर सकीं तो सुपरवाइजिंग यूनियन की स्थापना की गई जो अपने से सम्बन्धित समितियों की देखभाल करती हैं । किन्तु आय-व्यय निरीक्षण तथा सहकारिता के सिद्धान्तों की शिक्षा का कार्य तो सहकारी समितियों की सम्मिलित यूनियन ही कर सकती हैं ।

भारत में प्रत्येक प्रदेश में प्रदेशीय सहकारी यूनियन अथवा प्रदेशीय सहकारी इंस्टिट्यूट की स्थापना हो चुकी है। इन प्रदेशीय संस्थाओं का मुख्य कार्य प्रचार करना, समितियों का संगठन, साहित्य प्रकाशन, समितियों की देखभाल, तथा उनका निरीक्षण करना है।

भारत में दो प्रकार की यूनियन, गारंटी यूनियन तथा सुपरवाइजिंग यूनियन अधिक संख्या में स्थापित की गई हैं, अतएव हम उनके विषय में विस्तारपूर्वक लिखते हैं।

### गारंटी यूनियन (Guarantee Union)

गारंटी यूनियन सेन्ट्रल बैंक द्वारा साख समितियों को दिये हुये ऋण की गारंटी देती है। तीस या चालिस सहकारी साख समितियाँ मिलकर एक गारंटी यूनियन बनाती हैं। जो भी साख समिति गारंटी यूनियन की सदस्य बनती है वह अपनी साधारण सभा में निश्चय करती है कि यदि गारंटी यूनियन से सम्बन्धित कोई समिति अपना ऋण नहीं चुका पावेगी तो समिति एक निश्चित रकम तक उस दिवालिया समिति के ऋण को चुकाने की गारंटी देती है। इस प्रकार यूनियन से सम्बन्धित प्रत्येक समिति एक निश्चित रकम की गारंटी देती है। यह सब मिला कर यूनियन की गारंटी होती है और यूनियन साख समितियों के ऋण की गारंटी सेन्ट्रल बैंक अथवा बैंकिंग यूनियन को देती है।

गारंटी यूनियन का जन्म बर्मा में हुआ। तदुपरान्त बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, बरार, पू० बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा में भी इनका प्रयोग किया गया, किन्तु वे असफल रही, इस कारण वे क्रमशः टूट गई, और आगे फिर प्रदेशों में इस प्रकार की यूनियन स्थापित ही नहीं की गई। अन्य प्रदेशों में देशी राज्यों ने भी फिर इन्हें नहीं अपनाया। यह यूनियन वस्तुतः बेकार थी, क्योंकि कृषि सहकारी साख समितियाँ अपरिमित ऋणित्व वाली होती हैं, फिर गारंटी यूनियन की आवश्यकता ही कहाँ रहती है। अपने जन्मस्थान बर्मा के अतिरिक्त और कहीं भी अधिक दिनों वह गारंटी यूनियन नहीं रही। विद्वानों का मत है कि बर्मा में सहकारिता आन्दोलन की असफलता में इन यूनियनों का बहुत हाथ है।

### सुपरवाइजिंग यूनियन

सुपरवाइजिंग यूनियन के लिए निम्नलिखित कार्यों की आवश्यकता होती है :—कृषि सहकारी समितियों की देखभाल करना, उनकी उन्नति का मार्ग दिखलाना, अपने क्षेत्र में नवीन समितियों का संगठन करना तथा उनकी उन्नति करना, अपने से सम्बन्धित समितियों की पूँजी की आवश्यकता का पता लगाना, तथा उनके सदस्यों कि हैसियत का लेखा तैयार करके उनकी साख निर्धारित करना, समितियों को उनके कार्य-संचालन के विषय में उचित परामर्श देना, समितियों के सदस्यों तथा पंचों को सहकारिता की शिक्षा देने का प्रबन्ध कराना, समितियों को यदि आवश्यकता हो तो क्रय-विक्रय में सहायता देना और सेन्ट्रल बैंक से उनका सम्बन्ध स्थापित करना ।

सुपरवाइजिंग यूनियन से सम्बन्धित समितियाँ अपने प्रतिनिधियों को यूनियन की साधारण सभा में भेजती हैं । यूनियन की साधारण सभा एक कार्य-कारिणी समिति का निर्वाचन करती है । यह कार्यकारिणी समिति ही यूनियन का सारा प्रबन्ध करती है, और सम्बन्धित समितियों की देख-भाल के लिए एक सुपरवाइजर नियुक्त करती है । प्रत्येक समिति अपनी पूँजी के अनुसार यूनियन को चन्दा देती है । कृषि सहकारी समितियों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सुपरवाइजिंग यूनियन की बहुत आवश्यकता है ।

एक यूनियन एक ताल्लुके अथवा एक तहसील के बड़े क्षेत्र में कार्य नहीं करती । २० से ४० समितियाँ एक यूनियन से सम्बन्धित रहती हैं । मद्रास प्रदेश में चार सौ के लगभग यूनियन सफलतापूर्वक कार्य करती हैं । बिहार और उड़ीसा में दो प्रकार की यूनियन हैं, एक तो आय-व्यय-निरीक्षण करती हैं, दूसरी देख-भाल करती हैं । बम्बई में ये समितियाँ अधिक संख्या में हैं और सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । यहाँ यह प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रदेश में कोई कृषि सहकारी साख समिति ऐसी न रहे जो किसी न किसी यूनियन से सम्बन्धित न हो । पू० पञ्जाब और उत्तर प्रदेश में यूनियन नहीं है । वहाँ समितियों की देख-भाल का कार्य प्रदेशीय सहकारी यूनियन अथवा प्रदेशीय सहकारी इन्स्टिट्यूट करती है । प्रत्येक प्रदेश में यह सुपरवाइजिंग यूनियन प्रदेशीय सहकारी यूनियन अथवा इन्स्टिट्यूट से सम्बन्धित होती है । प्रदेशीय यूनियन इनका संगठन और देख-भाल करती है ।

## प्रदेशीय सहकारी यूनियन ( Provincial Co-operative Union)

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्येक प्रदेश में एक सहकारी यूनियन का इन्स्टिट्यूट है। पहले प्रदेशीय सहकारी यूनियन नहीं थीं। उस समय यह अनुभव हुआ कि सारे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन की उन्नति करने के लिए कोई सस्था होनी चाहिए। प्रदेश भर के गैर सरकारी सहकारी कार्यकर्त्ता आपस में मिल कर विभिन्न समस्याओं पर परामर्श और विचार नहीं कर पाते थे। न प्रदेशीय सहकारी विभाग के अतिरिक्त कोई उस आन्दोलन के सम्बन्ध में लिखित प्रचार करता था। सहकारी प्रचार कार्य को सदेह की दृष्टि से देखा जाता था। फिर सरकारी विभाग काम भी नगण्य प्रायः करते थे। “दिखावट अधिक, काम कम।” सहकारी शिक्षा का भी सरकारी ढंग से प्रबन्ध नहीं हो पाता था। अतः यह सोचा गया कि इन सब कार्य के लिए एक प्रदेशीय गैर सरकारी सहकारी व्यवस्था की जाय। अतः प्रदेशीय सहकारी यूनियन बनाई गई। वह प्रदेशीय यूनियन गैर सरकारी व्यक्तियों को जो इस आन्दोलन में सहानुभूति रखते हैं एक सूत्र में संगठित करती है। एक प्रकार से सहकारिता आन्दोलन का वह प्रदेश में नेतृत्व करती है। मुख्य कार्य ये हैं :—

( १ ) सहकारिता आन्दोलन की समस्याओं पर प्रकाश डालना। इसके लिए प्रतिवर्ष वह एक सम्मेलन करती है जिसमें प्रदेश के कार्यकर्त्ता भाग लेते हैं, और इस आन्दोलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करते हैं।

( २ ) पुस्तकें तथा पत्र निकाल कर तथा अन्य प्रकार से प्रचार-कार्य करना।

( ३ ) सहकारी शिक्षा का प्रबन्ध करना, इसके लिये वे कक्षाये तथा स्कूल खोलती हैं जिसमें सहकारिता की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है।

( ४ ) सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार तथा प्रदेशीय सरकार को सहकारिता सम्बन्धी मामलों में राय देती है।

---

\*प्रदेशीय सरकार का और न नियुक्त कर्मचारी जा प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को चलाता है।



(५) कहीं प्रदेशीय यूनियन सहकारी समितियों के निरीक्षण, सगठन तथा आय-व्यय-निरीक्षण का कार्य भी करती हैं।

### अभ्यास के प्रश्न

- १—गारटी यूनियन क्या कार्य करती है ? यह यूनियन असफल क्यों हुई ?
- २—सुपरवाइजिंग यूनियन के कार्यों का उल्लेख कीजिये ?
- ३—सुपरवाइजिंग यूनियन की क्यों आवश्यकता है ?
- ४—प्रदेशीय सहकारी यूनियन के मुख्य कार्य क्या हैं ?
- ५—प्रदेशीय सहकारी यूनियन की प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन की उन्नति करने के लिए क्यों आवश्यकता हुई ?

## बत्तीसवाँ अध्याय

### सेन्ट्रल सहकारी बैंक

(Co-operative Central Banks and Banking Unions)

आरम्भ में जब भारत में सहकारी साख-समितियाँ स्थापित की गईं तब यह आशा की जाती थी कि ग्रामीण जनता उन समितियों में रुपये जमा करेगी और समितियों के पास सदस्यों को ऋण देने के लिए डिपॉजिट द्वारा यथेष्ट पूँजी आ जावेगी। इस कारण सन् १९०४ के सहकारिता कानून के अनुसार केवल नगर तथा ग्राम्य साख समितियों की स्थापना का विधान किया गया। किन्तु यह आशा कि गाँवों के रहने वाले इन साख समितियों में रुपया जमा करेंगे पूरी नहीं हुई। इसके दो मुख्य कारण हैं, प्रथम किसान अधिकांश में निर्धन तथा ऋणी हैं, द्वितीय वे बैंकों में अपनी बचत का रुपया जमा करने के अभ्यस्त नहीं हैं। विभाग के रजिस्ट्रार—सरकार अथवा धनी व्यक्तियों से ऋण लेकर समितियों के लिए रुपये का प्रबन्ध करते थे। किन्तु इस प्रकार अधिक दिनों तक काम नहीं चल सकता था।

अस्तु, इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसे सहकारी बैंक खोले जावें जो सहकारी साख समितियों के लिए धन इकट्ठा करें। सन् १९१२ में दूसरा सहकारिता कानून पास हो गया और उसके अनुसार सेन्ट्रल बैंक

खोलने की सुविधा हो गई। अतएव सन् १९१२ के उपरान्त सहकारी सेन्ट्रल बैङ्क खोले गये।

सहकारी सेन्ट्रल बैङ्क दो प्रकार के होते हैं। ऐसे सेन्ट्रल बैङ्क जिनके सदस्य केवल सहकारी समितियाँ ही हो सकती हैं। दूसरे प्रकार के सहकारी बैङ्क वे हैं जिनके सदस्य व्यक्ति तथा सहकारी समितियाँ दोनों ही होते हैं।

पहले प्रकार के सेन्ट्रल बैङ्क जिनके सदस्य केवल सहकारी समितियाँ हो सकती हैं सहकारी बैंकिंग यूनियन कहलाते हैं। वास्तव में बैंकिंग यूनियन ही आदर्श सहकारी सेन्ट्रल बैङ्क है। क्योंकि उससे सम्बन्धित सहकारी समितियाँ ही सेन्ट्रल बैङ्क की नीति को निर्धारित करती हैं और बैङ्क का प्रबन्ध भी उन्हीं समितियों के हाथ में रहता है। भारत में बैंकिंग यूनियन संख्या में अधिक नहीं हैं, सेन्ट्रल बैङ्क ही संख्या में अधिक हैं।

सेन्ट्रल बैङ्क का क्षेत्र प्रत्येक प्रदेश में भिन्न होता है। उस क्षेत्र की समस्त सहकारी समितियाँ उन सेन्ट्रल बैङ्क से सम्बन्धित रहती हैं। कहीं-कहीं एक जिले में केवल एक ही सेन्ट्रल बैङ्क होता है, ऐसी दशा में उसे जिला सहकारी बैङ्क कहते हैं। उदाहरण के लिए “बरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैङ्क”। उत्तर भारत के प्रदेशों में अधिकतर एक तहसील के लिए एक सेन्ट्रल बैङ्क होता है।

### साधारण सभा (General Meeting)

सेन्ट्रल बैङ्क अथवा बैंकिंग यूनियन के हिस्सेदारों की सभा को जनरल मीटिंग या साधारण सभा कहते हैं। साधारण सभा के सदस्यों को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है। साधारण सभा ही बोर्ड आफ डायरेक्टर्स (Board of Directors) का चुनाव करती है।

#### बोर्ड आफ डायरेक्टर्स

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बैङ्क का प्रबन्ध करता है। डायरेक्टरों की संख्या अधिक होने के कारण बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अपने सदस्यों में से कुछ कमेटियाँ बना देता है जो बैङ्क का काम चलाती हैं।

बैङ्क का दैनिक कार्य अवैतनिक मंत्री, चेयरमैन अथवा मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर की सलाह से करता है। डायरेक्टरों की पीस अथवा वतन

कुछ नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में अधिकतर बैङ्क का चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य सहकारी कर्मचारी होता है। किन्तु अधिकांश प्रदेशों में चेयरमैन गैर सरकारी ही होता है। सेन्ट्रल बैङ्कों में भी बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में सहकारी साख समितियों के प्रतिनिधि ही अधिक संख्या में होते हैं।

### कार्यशील पूँजी (Working Capital)

सेन्ट्रल बैङ्क अथवा बैङ्किंग यूनियन की कार्यशील पूँजी ( Working Capital ), हिस्सा पूँजी ( Share Capital ), रक्षितकोष ( Reserve Fund ), डिपाजिट तथा ऋण ( Loan ) के द्वारा प्राप्त होती है।

साधारणतया सेन्ट्रल बैङ्क तथा बैङ्किंग यूनियन के हिस्सों का मूल्य ५० रु० से लेकर १०० रु० तक होता है। सहकारी साख समितियाँ अपने ऋण के अनुपात से हिस्से लेती हैं। सहकारी कानून के अनुसार सेन्ट्रल बैङ्क तथा बैङ्किंग यूनियन अपने वार्षिक लाभ का २५ प्रतिशत लाभ रक्षित कोष ( Reserve Fund ) में जमा करती है। हिस्सा पूँजी ( Share Capital ) तथा रक्षित कोष ( Reserve Fund ) बैङ्क की निजी पूँजी होती है। डिपाजिट ऋण ली हुई नहीं होती है।

किन्तु सदस्यों तथा गैर सदस्यों की डिपाजिट ही बैङ्किंग कार्यशील पूँजी का बड़ा भाग होती है। सेन्ट्रल बैङ्क तथा बैङ्किंग यूनियन दो प्रकार की डिपाजिट लेती है, मुहती ( Fixed ) तथा सेविंग्स। किसी-किसी प्रदेश में चालू खाता ( Current Account ) भी रखा जाता है, किन्तु चालू खाते में जोखिम अधिक है। इस कारण अधिकांश बैङ्क उसे नहीं रखते। डिपाजिट के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर सेन्ट्रल बैङ्क ऋण भी लेते हैं। अधिकतर सेन्ट्रल बैङ्क तथा बैङ्किंग यूनियन प्रदेशीय सहकारी बैङ्क से ऋण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रार की अनुमति से वे एक दूसरे को ऋण दे सकते हैं।

सेन्ट्रल बैङ्क अधिकतर अपने से सम्बन्धित सहकारी साख समितियों तथा गैर साख समितियों को ही ऋण देते हैं। किसी-किसी प्रदेश तथा चालू खाता में जमा करने वाला जब भी चाहे चेक द्वारा रुपया निकाल सकता है।

राज्य में व्यक्तियों को भी ऋण दिया जाता है, परन्तु अब यह रिवाज बन्द किया जा रहा है ।

अपरिमित दायित्व ( Unlimited Liability ) वाली साख समितियों को सेन्ट्रल बैंक प्रोनोट अथवा बाड पर ही ऋण दे देते हैं । अपरिमित दायित्व होने के कारण उनका प्रोनोट ही यथेष्ट जमानत (Security) है । सहकारी समितियों को प्रोनोट के अतिरिक्त कुछ सम्पत्ति भी गिरवी रखनी होती है ।

यह जानने के लिए कि प्रत्येक सहकारी साख समिति को अधिक से अधिक कितना ऋण देना उचित होगा, सेन्ट्रल बैंक अथवा बैंकिंग यूनियन अपने से सम्बन्धित साख समितियों की हैसियत के अनुसार उन साख समितियों की अधिकतम साख ( Maximum Credit ) निश्चय कर देती है । उससे अधिक ऋण साख समिति को नहीं दिया जाता ।

सेन्ट्रल बैंक अधिकतर एक दो वर्षों के लिये ऋण देते हैं । कहीं-कहीं अब भी पुराने कर्जों को अदा करने अथवा भूमि में सुधार करने के लिये पाँच से दस वर्ष तक के लिए ऋण दिया जाता है । किन्तु अब अधिक समय के लिए ऋण देने का कार्य केवल भूमि बंधक बैंक (Land Mortgage Bank) ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं ।

जब सेन्ट्रल बैंक अथवा बैंकिंग यूनियन के पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है तो वे प्रदेशीय बैंकों में जमा कर देते हैं । सेन्ट्रल बैंक तथा बैंकिंग यूनियन वार्षिक लाभ का २५ प्रतिशत रजिस्टर फंड ( Reserve Fund ) में जमा करके शेष हिस्सेदारों में बांट देते हैं । किन्तु इन बैंकों के वर्षान्तरों में अधिक से अधिक लाभ की दर भी निश्चित कर दी जाती है जिससे अधिक लाभ हिस्सेदारों को नहीं बाँटा जा सकता है ।

यह तो पूर्व ही कहा जा चुका है कि प्रदेशीय बैंक सेन्ट्रल बैंकों के अभिभावकों का कार्य करते हैं। सहकारी साख आन्दोलन का द्रव्य बाजार (Money market) से निकट सम्बन्ध स्थापित हो जावे, इसके लिए यह आवश्यक है कि सहकारी सेन्ट्रल बैंक अन्य बाहरी बैंकों से प्रदेशीय बैंक के द्वारा काम करे। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रदेशीय सहकारी बैंक सेन्ट्रल बैंकों तथा बैंकिंग यूनियन को आपस में एक-दूसरे से ऋण न लेने दे। क्योंकि इससे प्रदेशीय बैंक, सेन्ट्रल बैंकों का अनुशासन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। प्रदेशीय बैंकों को सहकारी साख समितियों से सीधा सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। सहकारी साख समितियों का प्रबन्ध सेन्ट्रल बैंक तथा बैंकिंग यूनियन से होना चाहिये और सेन्ट्रल बैंकों का सम्बन्ध प्रदेशीय बैंक से होना चाहिए।

प्रदेशीय बैंक अपनी कार्यशील पूँजी के लिए सहकारी साख समितियों, सेन्ट्रल बैंकों, और जनता की डिपाजिट पर निर्भर रहते हैं। जब प्रदेशीय बैंक सर्व-साधारण से डिपाजिट स्वीकार करते हैं, तब उन्हें जमा करने वालों को माँगने पर, देने के लिये नकद रुपया रखना पड़ता है। कुछ प्रदेशीय सरकारों ने नियम बनाकर कम से कम नकद रुपया कितना रखना चाहिये, यह निश्चय कर दिया है। जितने दिनों के लिये प्रदेशीय बैंकों की डिपाजिट मिलती है, उससे अधिक के लिये वे ऋण नहीं देते। प्रत्येक प्रदेश में प्रदेशीय बैंकों ने अधिक से अधिक समय निश्चित कर दिया है, जिससे अधिक के लिए वे डिपाजिट स्वीकार नहीं करते। अधिकांश प्रदेशीय बैंक चालू खाता (Current account) भी रखते हैं, केवल पू० पंजाब प्रदेशीय बैंक चालू खाता नहीं रखता। प्रदेशीय बैंक डिपाजिट लेने के अतिरिक्त, साधारण बैंकिंग कार्य भी करते हैं। बम्बई, मदरास तथा पू० पंजाब प्रदेशीय बैंकों ने लम्बे समय के लिये डिवेंचर (Debenture) भी बेचे हैं। अन्य बैंकों की भाँति प्रदेशीय बैंकों के सामने भी कार्यशील पूँजी (Working capital) की अधिकता तथा कमी की समस्या उपस्थित होती रहती है अतएव प्रदेशीय बैंक एक दूसरे को ऋण देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर थोड़े समय के लिये कुछ अधिक सूद देकर डिपाजिट बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।

नियमानुसार, इन प्रदेशीय बैंकों का आय-व्यय-निरीक्षण रजिस्ट्रार के द्वारा होना चाहिये, परन्तु किसी प्रदेश में रजिस्ट्रार ने पेशेवर आडिटरों के द्वारा प्रदेशीय बैंकों के हिसाब की जाँच करवाने की आज्ञा दे दी है। प्रदेशीय बैंक अपनी वार्षिक बैलेंस शीट तैयार करते हैं। कुछ समय हुआ जब “अखिल भारतीय प्रदेशीय सहकारी बैंक एसोशियेशन” (The All India Provincial Co-operative Banks Association) नामक संस्था को जन्म दिया गया है। इस एसोशियेशन का मुख्य कार्य यह है कि वह प्रत्येक प्रदेशीय बैंक की कार्यशील पूँजी की अधिकता तथा कमी के आँकड़ों को जमा करती है और सब प्रदेशीय बैंकों को सूचनार्थ भेज देती है। एसोशियेशन की बैठक दो वर्ष में एक बार होती है, जिसमें सहकारिता आन्दोलन सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार होता है। जब कभी प्रदेशीय बैंकों को सरकार का ध्यान किसी विशेष बात की ओर आकर्षित करना होता है, तो एसोशियेशन ही सरकार से उस सम्बन्ध में बातचीत करती है।

जब से भारत में रिजर्व बैंक खुल गया है तब से प्रदेशीय सहकारी बैंकों का सम्बन्ध रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) से स्थापित हो गया है। इसके पूर्व प्रदेशीय सहकारी बैंकों का सम्बन्ध इम्पीरियल बैंकों से था। आवश्यकता पडने पर सहकारी बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। भारत में ११ प्रदेशीय सहकारी बैंक हैं और उनकी कार्यशील पूँजी २४ करोड़ रुपये हैं।

### अभ्यास के प्रश्न

१—प्रदेशीय सहकारी बैंक क्या-क्या कार्य करता है ?

२—प्रदेशीय बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

\*रिजर्व बैंक:—यह भारत सरकार का बैंक है। इसका मुख्य कार्य सरकारी लेन-देन के काम को करना, मुद्रा (currency) को चलाना, अन्य बैंक का बैंकर बनना, तथा रुपये के विनिमय की दर को स्थिर रखना है। यह बैंक द्रव्य बाजार (money market) पर नियन्त्रण रखता है और दूसरे बैंकों को समय पर ऋण देता है।

३- प्रदेशीय बैङ्क अपने सम्बन्धित सेन्ट्रल बैङ्क को किस तरह सहायता पहुँचाता है ?  
 ४- प्रदेशीय बैङ्कों का संगठन किस प्रकार का है और वे अपनी कार्य-शैली को किस प्रकार इकट्ठा करते हैं ?

## चौतीसवाँ अध्याय

### सहकारिता आन्दोलन की दशा

भारत में सहकारिता आन्दोलन को आरम्भ हुये ४० वर्ष से ऊपर समय हो गया किन्तु हमारे गाँवों की दशा में कोई विशेष सुधार हुआ हो, ऐसा नहीं दिखाई देता । इसका कारण यह है कि सहकारिता आन्दोलन अभी कमजोर है । यह तो इसी से ज्ञात हो जाता है कि प्रतिवर्ष बहुत सी सहकारी समितियाँ दिवालिया हो जाती हैं और बहुतों की दशा अच्छी नहीं है ।

चालीस वर्षों में इस आन्दोलन को देश में एक मजबूत आन्दोलन बन जाना चाहिये था, समितियों की उन्नति होनी चाहिए थी, गाँव वालों को दूसरी तरह की सहकारी समितियों की माँग करना चाहिये थी, महाजन को सहकारी साख समितियों से डरना चाहिए था, समिति के सदस्यों की गरीबी कम होनी चाहिए थी । लेकिन ऐसा कुछ हुआ हो, यह दिखलाई नहीं देता । इससे ही यह जाना जा सकता है कि इस आन्दोलन की हालत अच्छी नहीं है ।

सहकारी समितियों की असफलता के नीचे लिखे मुख्य कारण हैं—

(१) किसान का कज से दबा होना । जब तक किसान का कर्ज से छुटकारा नहीं होता, तब तक वह अपनी उन्नति के किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं रख सकता ।

(२) गाँव वालों का अशिक्षित होना । समिति का काम करने के लिये शिक्षित होना जरूरी है । इसका फल यह होता है कि समिति का कर्ता-धर्ता निक मन्त्री हो जाता है, दूसरे सदस्य उसकी ओर से उदासीन हो जाते

हैं। गाँव और शहर, दोनों जगह सहकारी सिद्धान्तों की शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिये।

( ३ ) सहकारी समितियों और सहकारिता आन्दोलन पर सरकारी-देख-भाल बहुत ज्यादा है। सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार ही इस आन्दोलन का सर्वेसर्वा है। इसका फल यह होता है कि अशिक्षित किसान यह समझता है कि वे सरकारी बैङ्क हैं और हमें कर्ज देने के लिये खोले गये हैं। सहकारिता की यह भावना कि हम मिल कर स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों, इससे नष्ट हो जाती है।

( ४ ) सहकारिता आन्दोलन की एक कमजोरी यह भी रही है कि अभी तक सहकारी साख समितियों की ओर अधिक ध्यान दिया गया और गैर साख-समितियों की स्थापना की ओर कम ध्यान दिया गया। किसान को केवल साख की ही जरूरत नहीं है, वरन् उसको इस बात की भी जरूरत है कि उसकी पैदावार का उसे उचित मूल्य मिले और उसके काम में आने वाली चीजें भी उसे उचित मूल्य पर मिलें। हर्ष की बात है कि सहकारिता विभाग का इस ओर ध्यान गया है और गैर साख समितियाँ अधिक संख्या में स्थापित की जा रही हैं।

( ५ ) आन्दोलन की कमजोरी का एक वह भी कारण है कि सहकारिता विभाग के इन्स्पेक्टर\* और आर्गनाइजर‡ सहकारिता के सिद्धान्तों को बिना अच्छी तरह से सदस्यों को समझाए जल्दी में समितियों का संगठन कर देते हैं। इन कर्मचारियों का तबादला होता रहता है। अतएव यदि ऐसी कमजोर समितियाँ बाद को टूट जावें तो उन पर दोष नहीं आता। इसलिये अपने ऊँचे अफसरों को प्रसन्न करने के लिये वे जल्दी में बहुत सी समितियों का संगठन कर देते हैं।

( ६ ) कहीं कहीं पंच या सरपंच वेईमान होते हैं, और वे समिति के रुपये से स्वयं लाभ उठाते हैं।

( ७ ) कहीं-कहीं महाजन अपने आदमियों को समिति का सदस्य बना

---

\*यह सहकारी समितियों की देखभाल के लिये जिले में एक होता है।  
‡यह समितियों का संगठन करते हैं और जिले में कई होते हैं।



कर उसे हथियाने का प्रयत्न करता है और कहीं-कहीं कोई प्रभावशाली आदमी समिति को हथिया लेता है।

(८) साख समितियों से ऋण मिलने में कभी-कभी बहुत देर हो जाती है। साथ ही जब किसान साख समितियों से कर्ज लेता है तो यह बात छिपी नहीं रहती। भारतीय किसान यह नहीं चाहता कि लोग जाने कि वह कर्जदार है।

(९) सहकारी आन्दोलन तभी किसी देश में सफल हो सकता है जब किसानों को निःस्वार्थभाव से सेवा करने के लिए लोग इस आन्दोलन में आवें। लेकिन भारत के जो भी गैर सरकारी लोग इसमें आये, वे अधिकतर सरकार को प्रसन्न करने के लिए आये। देश में किसानों की सेवा करने की जिम्मे लगन है, वे इस आन्दोलन से दूर रहे हैं।

ऊपर दिये हुये दोषों से यह न समझ लेना चाहिये कि सहकारिता आन्दोलन से कोई लाभ ही नहीं हुआ। यह ठीक है कि अभी यह कमजोर है, फिर भी सहकारी समितियों से देश को बहुत लाभ हुआ है।

जहाँ साख समितियाँ हैं, वहाँ महाजन ने भी सूद की दर घटा दी है, किसानों में कमखर्ची की आदत पड़ रही है, बैङ्किंग के सिद्धान्तों की जानकारी बढ़ रही है, लड़ाई-झगड़े कम हुए हैं। किसानों की फसलों को बेचने और उचित मूल्य दिलाने का प्रयत्न किया गया है तथा अच्छे बोज का प्रचार किया गया है।

## अभ्यास के प्रश्न

१—निम्नांकित में से किन्हीं चार पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :—

(क) प्रदेशीय सहकारी बैङ्क (ख) सतुलित भोजन (ग) खेती (घ) खेतों की छोटाई (ङ) कृषि विभाग (च) रहन-सहन का तल (छ) उत्तर प्रदेश में भूमि व्यवस्था। (१९४३)

२—किसी पाँच पर नोट लिखिए :—

सुद्रा। बटाई प्रथा। ग्राम पंचायत। उपभोग। विलासिता की वस्तुएँ।  
ज। खेवट। शिकमी किसान। (१९४५)

३—निम्नलिखित विषयों में से चार पर टिप्पणी लिखिए :—  
सन्तुलित भोजन । छितरे खेत । घरेलू बजट । हाट और मेला । उत्पत्ति  
के साधन । सम्पत्ति । उपयोगिता । ( १६४५ )

४—किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखो :—  
सहकारी भूमिबन्धक बैंक । प्रदेशीय सहकारी यूनियन । गारटी यूनियन ।  
प्रदेशीय सहकारी बैंक । जीवन सुधार समिति । क्रय-विक्रय समिति ।  
( १६४५ )

५—निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर नोट लिखो :—  
(क) भाग (ख) वचत और गुप्त सचय (ग) अदल-बदल (घ) बटाई  
प्रथा (ङ) कुल सूद (च) बिखरे खेत (छ) राष्ट्रीय सम्पत्ति । ( १६४६ )

६—किन्हीं पाँच पर नोट लिखिए :—  
कीमत; बटाई प्रथा; बाजार; पूँजी; मुद्रा, रबी की फसल; ठेके की  
मजदूरी; कुल सूद । ( १६४१ )

७—निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखिए :—  
(क) पंचायत (ख) वेगार (ग) शिकमी किसान (घ) खसरा (ङ) खत्ती  
(च) अच्छा रहन-सहन का दर्जा (छ) बैंक (ज) हाट और मेला ।  
( १६४८ )